हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

11 मार्च, 2003

खण्ड–1, अंक–6

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार 11 मार्च, 2003

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(6) 1
नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए	(6) 20
तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	
अतारांकिंत प्रश्न एवं उत्तर	(6) 27
अनुपस्थिति की अनुमति	(6) 28
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/ विभिन्न मामले उठाना	(6) 29
वर्ष 2003–2004 के लिए बजट अनुमानों पर समान्य चर्चा	(6) 30
बैठक का समय बढाना	(6) 74
वर्ष 2003–2004 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(6) 74
बैठक का समय बढ़ाना।	(6) 80
वर्ष 2003–2004 के बजट पर सामान्य – चर्चा (पुनरारम्भ)	(6) 80

वैयक्तिक स्पष्टीकरण	(6) 105
(1) चौ० जय प्रकाश एम०एल०ए० द्वारा	(6) 105
(2) चौ० भजन लाल एम ०एल०ए० द्वारा	(6) 106
वर्ष 2003 – 2004 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(6) 107
बैठक का समय बढ़ाना	(6) 108
वर्ष 2003 – 2004 के बजट पैर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(6) 116
बैठक का समय बढ़ाना	(6) 116
वर्ष 2003–2004 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(6) 116
बैठक का समय बढ़ाना	(6) 125
वर्ष 2003 – 2004 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(6)125

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार 11 मार्च, 2003

हरियाणा विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हॉल, वि धान भवन, सैक्टर– 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9. 30 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री सतबीर सिंह कादियान) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः मैम्बर साहिबान, अब सवाल जवाब होंगे।

तारांकित प्रश्न संख्या– 1312

(इस समय माननीय सदस्य श्री हामिद हुसैन सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

Increase in Generation Capacity

***1364. @Shri Nafe Singh Jundla, Shri Ranbir Singh Maudola :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government for the generation of additional power in the State ; If so, the details thereof ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा): एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

राज्य सरकार ने सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए अधिकतम बिजली की उपलब्धता पर विशेष जोर दिया है। इस दिशा में निम्नलिखित प्रमुख कार्यवाहियाँ की गई हैंः –

1 14.4 मैगावाट पश्चिमी यमुना नहर हाईडल परियोजना चरण–2 पर निर्माण कार्य पूरा होने के करीब है तथा इस परियोजना के चालू होने से राज्य को अतिरिक्त रूप से 2 लाख यूनिट बिजली प्रतिदिन मिलेगी।

2. ताऊ देवी लाल थर्मल पावर स्टेशन, पानीपत में 250– 250 मेगावाट की दो यूनिटें जोड़ी जा रही है। इस उद्देश्य के लिए परियोजना को मैसर्ज भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड को टर्न– की आधार पर दिया गया है। ये यूनिटें राज्य की बिजली आपूर्ति में 100 लाख यूनिट प्रतिदिन जोड़ेगी।

3. यमुना नगर थर्मल पॉवर परियोजना (500 मैगावाट) का एक चरण ह०वि०उ०नि०लि० द्वारा प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

4. मैसर्ज इन्डियन ऑयल कॉपोरेशन, भारत सरकार की एक संयुक्त उद्यम कम्पनी ने पानीपत में एक 360 मैगावाट रिफाइनरी रैजीडयू पर आधारित थर्मल परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस उद्देश्य केलिए कम्पनी (आई०पी०पी०सी०एल०) के साथ एक एम०ओ०यू० पर हस्ताक्षर

किए गए हैं। इस परियोजना के वर्ष 2007–08 में पूरा होने की आशा है।

5. राज्य के अपने उत्पादन केन्द्रों की कार्य कुशलता को बेहतर प्रबन्धन अभ्यासों के माध्यम से तथा ताऊ देवी लाल थर्मल पॉवर स्टेशन, पानीपत तथा फरीदाबाद थर्मल पॉवर स्टेशन की वर्तमान यूनिटों को आधुनिकीकरण तथा नवीनीकरण द्वारा सुधारा जा रहा है। इसका अवलोकन निम्नवित किया जा सकता है: –

	2000–01	2001 –02	2002–03 (फरवरी तक)
उत्पादन मिलियन यूनिट में	3793	5311	5665

6. ताऊ देवी लाल थर्मल पॉवर स्टेशन पानीपत की 210 मैगावाट की यूनिट–6 का निर्माण कार्य तेजी से करके सितम्बर 2001 में चालू किया गया था। साथ ही पानीपत की 110 मैगावाट की यूनिट–2 का लाइफ एक्सटैन्शन (जीवन वृद्धि) तथा पुनर्वास कार्य जो 1999 के शुरू में ही ठेकेदार द्वारा छोड़ दिया गया था उसको पूरा करा लिया गया है तथा यह यूनिट बिजली के उत्पादन

के लिए जल्दी ही उपलब्ध हो जानी सम्भावित है। इससे राज्य की बिजली आपूर्ति में प्रतिदिन 20 लाख यूनिट और जुड़ जाएंगी।

7. राज्य सरकार 432 मैगावाट फरीदाबाद गैस पर आधारित परियोजना चरण–2 का 10वीं योजना अवधि कैं अन्दर ही क्रियान्वयन के लिए भारत सरकार तथा एन०टी०पी०सी० पर जोर डाल रही है।

8. राज्य सरकार ने राज्य में विभिन्न चीनी मिलों में उत्पादित बैगास से बिजली उत्पादन करने का निर्णय लिया है। बिजली निगमों को इन मिलों से फालतू बिजली खरीदने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार का प्रथम समझौता ह०वि०प्र०नि० तथा गोहाना कोआप्रेटिव शुगर मिल के मध्य हुआ है। इस स्रोत के माध्यम से 4 से 6 मैगावाट बिजली उपलब्ध होगी।

राज्य सरकार राज्य के अन्दर ही अधिकतम बिजली उत्पादन बढ़ाने तथा भविष्य में सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं को पर्याप्त गुणवत्ता की बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयत्न कर रही है। हरियाणा के उपलब्ध बिजली आपूर्ति के समग्र आकार को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार बाहर के नई केन्द्रीय उत्पादन परियोजनाओं, पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकों (आई०पी०पी०जी) इत्यादि से अधिक बिजली की आपूर्ति प्राप्त करने के भी प्रयास कर रही है।

श्री नफे सिंह जुंडला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सी०पी०एस० साहब से जानना चाहता हूँ कि जैसाकि उन्होंने अपने उत्तर में दर्शाया है कि पानीपत में 250– 250 मैगावाट की सातवीं और आठवीं दो यूनिट लगाई जा रही हैं वह कब तक बनकर तैयार हो जाएंगी, मैं जानना चाहता हूँ कि उन पर कितना खर्च आएगा और पिछली सरकारों में चाहे वह चौधरी बंसी लाल जी की सरकार थी, चाहे वह चौधरी भजन लाल की सरकार थी, उनके समय में कितनी बिजली जैनरेट की गई और मौजूदा सरकार यानी कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार ने कितनी अतिरिक्त बिजली जैनरेट की है उसका विस्तृत ब्यौरा दिया जाए और जितनी भी ज्यादा बिजली इस सरकार ने उन सरकारों से ज्यादा जनरेट की है वह सदन को बताई जाए यह मेरा सवाल है।

श्री राम पाल माजरा: स्पीकर सर, जिस प्रकार से मेरे माननीय साथी ने जानना चाहा है मैं बताना चाहता हूँ कि पानीपत की सातवीं और आठवीं यूनिट ताऊ देवी लाल थर्मल प्लांट के नाम से हैं वे यूनिट्स चालू होने की अनुसूची में हैं और 2004–05 में पूरी हो जाएंगी। इन्होंने यह भी जानना चाहा है कि विशेष तौर से कितनी बिजली पैदा करेंगे, मैं बताना चाहूँगा कि यह यूनिट 500 मैगावाट क्षमता की होगी 100 लाख यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से बिजली पैदा करेगी। इसी प्रकार से यह जानना चाहा है कि कितनी बिजली पैदा की गई और इस मामले में कितने प्रयास किए

गए और ऐडीशनल बिजली की यूनिट्स कब–कब शुरू हो जाएंगी, वह मैं बता देता हूँ पश्चिमी यमुना जलीय चरण 144 यह 3 लाख यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से बिजली पैदा करेगी और 2003–04 में शुरू हो जाएगी। यमुनानगर थर्मल परियोजना फेस–एक 500 मैगावाट क्षमता की होगी और 100 लाख यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से बिजली पैदा करेगी और 2005–07 में तैयार हो जाएगी। इसी प्रकार से यमुना नगर फेस– दो 500 मैगावाट क्षमता की होगी और 100 लाख यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से पैदा करेगी, यह 2005–07 में शुरू हो जाएगी इसी प्रकार मैसर्ज आई० ओ०सी० पैट्रो कोक आधारित परियोजना पानीपत में 2007–08 में पूरी हो जाएगी। इसकी क्षमता 360 मैगावाट की होगी और 30 लाख यूनिट्स बिजली प्रतिदिन के हिसाब से बनाएगी। फरीदाबाद गैस आधारित परियोजना चरण–दो 400 मैगावाट की क्षमता की होगी और 90 लाख यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से बिजली पैदा करेगी और 2006–07 में पूरी हो जाएगी। नाथप्पा झाकड़ी जलीय परियोजना यह 75 मैगावाट की होगी और 15 लाख यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से बिजली बनाएगी और यह 2002–03 में शुरू होगी। दुलहस्ती पन बिजली परियोजना 50 मैगावाट क्षमता की होगी और 10 लाख यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से बिजली पैदा करेगी, यह 2004–05 में पूरी हो जायेगी। इसी प्रकार से टिहरी पन बिजली परियोजना 50 मैगावाट क्षमता की होगी व यह 10 लाख यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से बिजली पैदा करेगी और 2008 –09 में पूरी हो जायेगी। इसी प्रकार से हिसार थर्मल पॉवर प्लांट की चरण– 1

पन बिजली परियोजना 2 लाख यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से बिजली पैदा करेगी। इसको 11वीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है। इसी प्रकार से स्पीकर सर, मेरे साथी ने यह जानना चाहा है कि कितनी बिजली पैदा की है। इस बारे में मैंने कल के प्रश्नकाल के दौरान और कालिंग अटैंशन मोशन के जवाब में काफी विस्तार से बताया था और उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने जवाब में पूरी जानकारी माननीय साथी को और सारे सदन को दी थी। 1998 –99 में बिजली की उपलब्धता 367 लाख मैगावाट थी जबकि 2002–03 में बढ़कर 525 लाख मैगावाट हो गई है जो 1998 – 99 के मुकाबले 43 प्रतिशत अधिक है। इस सर्कार ने आने के बाद बिजली के मामले में नये आयाम स्थापित किए हैं। पिछले दिनों पॉवर मिनिस्ट्री ने हरियाणा प्रदेश में एक सर्वे करवाया था और बिजली के काम को सभा प्रदेशों में असैस करवाया था, उसमें हरियाणा प्रदेश सारे देश में तीसरे स्थान पर रहा है। हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी की कड़ी मेहनत के कारण पावर मिनिस्ट्री ने एक चिट्ठी लिखी और इस पर कमौण्डेशन लैटर दिया। यह लैटर 2 मई को लिखा गया जिसमें लिखा है कि–

"Dear Chautala Ji,

Efforts made by Government of Haryana in bringing back financial

viability of the power sector is indeed laudable. I compliment you for your achievements in capacity addition in

this State sector and remarkable improvement in billing and collection by implementing distribution reforms.

Please convey my appreciation to your officers."

इसी प्रकार से दूसरा लैटर स्पीकर सर उनकी तरफ से फिर आया जिसमें लिखा था

"Dear Chautala ji,

Please convey our appreciation to all concerned for good work done. I am confident that under your dynamic leadership Haryana would fully achieve the objective of power sector reforms leading to commercial viability of the State power sector and supply of uninterupted reliable quality of power to all consumers.

With kind regards."

इसी प्रकार से एक ऐप्रीसिएशन लैटर जिसमें हरियाणा प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, वह प्राप्त हुआ है। इस बात के लिए स्वाभाविक है कि हरियाणा प्रदेश के मुख्य मंत्री बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने पावर सैक्टर में बहुत अच्छा काम किया है। स्पीकर सर, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, रोबर्ट फ्रोस्ट की इन लाइनों से प्रेरणा लेते थे और ये लाइनें हमेशा उनकी टेबल पर लिखी हुई होती थी और वे लाइनें थीं: –

"The woods are lovely, dark and deep,

But I have promises to keep,

And miles to go before I sleep,

And miles to go before I sleep."

इसी प्रकार से माननीय चौटाला जी कड़ी मेहनत करके, 18 – 18 घण्टे काम करके किस प्रकार से सारे विभागों के साथ कंसल्ट करते हैं यह आपने कल माननीय मुख्य मंत्री जी के जवाब में सुना होगा। चाहे खेलों का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे नहरों का मामला हो, उनमें अद्वितीय प्रगति की है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनका मोटो है इन्हीं शब्दों में कहना चाहूँगा– सुहानी मनोहर घनेरे हैं जंगल,

मगर मुझको आराम करना नहीं।

कि मैंने किसी को वायदा किया है,

अभी तो बहुत दूर जाना है मुझको,

अभी तो बहुत दूर जाना है मुझको।

श्री रणबीर सिंह मंदौलाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वर्तमान सरकार को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि आज की मुख्य जरूरत बिजली को ध्यान में रखते हुए इस सरकार द्वारा जो 792 मैगावाट बिजली का अधिक उत्पादन किया गया है और भविष्य में भी 2200 मैगावाट के करीब और पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके लिए माननीय मुख्य संसदीय सचिव महोदय ने जो विवरण दिया है इसके लिए दें उनका धन्यवादी हूँ। मैं अपने पूरक प्रश्न के माध्यम से मुख्य संसदीय सचिव महोदय से जानना चाहूँगा कि इसकी समयावधि क्या है? यह उत्पादन होने के बाद उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र को किस अनुपात में बिजली बांटी जायेगी।

श्री राम पाल माजराः मैंने उनकी समयावधि हरेक के साथ बताई है। जहां तक बंटवारे का सवाल है, इस मामले में उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र की बात नहीं है। बिजली आवश्यकता के मुताबिक दी जाती है। जिस प्रकार से पिछले दिनों किसानों को 11 घण्टे बिजली दी गई वह सारे प्रदेश में दी गई और पूरी वोल्टेज के साथ दी गई और उसके लिए हमने पूरे प्रयास किए। इस बारे में कालिंग अटेंशन मोशन पर भी और इसी प्रकार के बहुत से सवालों के जवाब में बहुत से रिप्लाई दिये जा चुके हैं। बहुत अच्छे ढंग से बिजली के मामले में हरियाणा प्रदेश की सरकार ने काम किए हैं।

श्री नफे सिंह जुण्डलाः अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से स्पैसीफिक प्रश्न यह था कि पिछली सरकारें चाहे वह भजन लाल की सरकार हो चाहे बंसी लाल की सरकार हो उनमें जो बिजली जैनरेट की गई और मौजूदा सरकार ने जितनी बिजली जैनरेट की है, उसका अन्तर जानने के लिए मैंने सवाल किया था क्योंकि बिजली हर आदमी की हर क्षेत्र में नैसैस्टी

बन चुकी है। बिजली के बगैर आज कोई काम नहीं चल सकता। पिछली सरकारों ने इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्यों स्टैप नहीं उठाए और अगर उठाए हैं तो क्या स्टैप उठाए हैं और मौजूदा सरकार ने इन तीन सालों में पिछली सरकारों के मुकाबले में कितने स्टैप उठाए हैं। मंत्री महोदय कृपा उनके अन्तर को दर्शाने की कृपा करें।

श्री राम पाल माजराः अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि वर्ष 1998—99 में हमने 43 प्रतिशत अत्याधिक बिजली दी और मैंने पिछली बार भी कहा था कि पिछली सरकार ने यमुना नगर थर्मल पॉवर प्लांट का ठेका इजरायल की आईजनबर्ग नाम की कम्पनी को दिया था जिसकी रैपुटेशन जीरो थी किसी ने उसको फाईनास नहीं किया। पानीपत की दूसरी यूनिट जिसका ठेका बंसी लाल जी ने ए०बी०बी० कम्पनी को 300 करोड़ में दिया था और आज जिसका कार्य 35 करोड़ में कर दिया गया है और कल ही उसने काम करना शुरू कर दिया है। जो काम 35 करोड़ में कर दिया गया है और कल ही उसने काम करना शुरू कर दिया है जो काम 35 करोड़ देने से बन जाये उसी काम के लिए इन्होंने 300 करोड़ रुपये दिये थे। इन्होंने तो सारे उल्टे काम किए। बिजली के मामले में तो इन्होंने कोई सुल्टा काम किया ही नहीं। इस सरकार ने तो सुधार ही किए हैं।

श्रीकृष्ण लालः अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने सवाल के जवाब में दर्शाया कि पानीपत थर्मल पॉवर प्लांट की दूसरी

यूनिट का बंसी लाल जी की सरकार ने 300 करोड़ रुपये में केवल 7 मैगावाट लोड फैक्टर बढ़ाने के लिए ठेका दिया था। लेकिन इस सरकार ने वह प्लांट 35 करोड़ में तैयार करके कल उसको सैक्रोनाइज कर दिया, जो लोड इस पर आ जाएगा। इसके अलावा जो 110 मैगावाट की पहली यूनिट है, इस सरकार ने उसकी ओवर हालिग कर दी है और वह आज 714 मैगावाट लोड पर चल रही है। क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो तीसरी और चौथी यूनिट 110– 110 मैगावाट की है उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई प्रपोजल बनाई है जिससे उसका लोड फैक्टर बढ़ाया जाए। दूसरा मेरा सवाल यह है कि पानीपत थर्मल पॉवर प्लांट के अन्दर जो लोड फैक्टर बढ़ा है उसके साथ जो स्थूल कंजम्पशन या ऑयल कंजम्पशन कम हुई है उससे सरकार को कितना लाभ हुआ है?

श्री राम पाल माजराः स्पीकर सर, सरकार ने बडी कार्य कुशलता से सारे थर्मल प्लांट्स को ठीक ढंग से चलाया है जिसकी वजह से 792 मैगावाट बिजली ज्यादा पैदा की गई, जबकि पिछली सरकार के समय में केवल मात्र 199 मैगावाट बिजली पैदा की जाती थी। स्पीकर सर, मेरे माननीय साथी ने यह ठीक प्रश्न पूछा कि स्थूल कंजम्पशन में कमी के कारण सरकार को कितना फायदा हुआ? इस बारे में मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहूँगा कि कोयले की खपत प्रति यूनिट 830 ग्राम से घटकर 772 ग्राम होने के कारण सरकार को 143 करोड़ 89 लाख

रुपये की बचत हुई। इसी तरह तेल की खपत प्रति यूनिट 12.70 मिली लिटर से घटकर 3.28 मिली लिटर होने से सरकार को 142.47 करोड़ रुपये की बचत हुई है जोकि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ऐग्जिलरी की खपत प्रति यूनिट 12.04 प्रतिशत से घटकर 10.57 प्रतिशत हो गई जिसके कारण 14.717 करोड़ यूनिट ऊर्जा की सिंचित बचत हुई जिसकी कीमत 3547 करोड़ रुपये बनती है। स्पीकर सर, सरकार को कुल मिलाकर 321. 83 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मुख्य संसदीय सचिव महोदय से पूछना चाहूँगा कि जो ऐग्जिस्टिग यूनिटस हैं हरियाणा प्रदेश में उनकी जैनरेशन की ऐक्चुअल कैपेसिटी कितनी है और उनसे इस समय कितनी जैनरेशन हो रही है? जैनरेशन के बारे में क्या कोई नैशनल रिस्वायर्ड रेशो है और यदि है तो क्या उसके लैवल से हमारे यहां बिजली कम पैदा हो रही है या अधिक पैदा हो रही है। कृपा इस बारे में बताया जाये।

श्री राम पाल माजराः स्पीकर सर, अभी मैंने जो प्लांट लोड फैक्टर के बारे में बताया है उसमें बताया गया है कि हमारे प्लांट किस लोड पर चल रहे हैं, किस कैपेसिटी से चल रहे हैं। स्पीकर सर, हमारे दूसरे यूनिट का प्लांट लोड फैक्टर सही नहीं चल रहा था, वह एक्चुअल कैपेसिटी से नीचे चल रहा था जिसकी रैनोवेशन करने के लिए पिछली सरकार ने 300 करोड़ रुपये का

टैंडर दिया था जबकि हमने इस प्लांट की रैनोवेशन 300 करोड़ रुपये की बजाय 35 करोड़ रुपये में करवाई है। अब यह प्लांट भी पूरी तरह से रैनोवेट हो गया है और सही प्लांट लोड फैक्टर पर चल रहा है। स्पीकर सर, हमारे सभी यूनिट्स का प्लांट लोड फैक्टर सही और अच्छे ढंग से चल रहा है जिसके कारण हमें 321 करोड़ रुपये अधिक की बचत हुई है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः स्पीकर सर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर भाई माजरा जी ने दिया है। इन्कीजिंग इन जैनरेशन कैपेसिटी के बारे स्पीकर सर, आपके माध्यम से मैं माजरा जी से जानकारी प्राप्त करना चाहूँगा और इन्होंने कई प्रश्नों के उत्तर में बताया भी है कि किस तरह से बिजली की जेनरेशन कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। मेरे अपने क्षेत्र बल्लबगढ़ के मुझेड़ी गांव में एन०टी०पी०सी० का गैस बेस्ट पॉवर स्टेशन है जहां पर हमारी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी ने विजिट भी किया था और वहां की मैनेजमैंट ने कमेटी को अवगत करवाया था कि उनके पास स्पेस, गैस वगैरा इतनी है कि इस पॉवर स्टेशन की बिजली की क्षमता कम से कम समय में और कम से कम पैसे में दुगुनी हो सकती है। इसलिए मेरा माजरा जी से कहना है कि क्या इस पॉवर स्टेशन की बिजली की क्षमता दुगुनी करने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है। क्योंकि कम से कम समय में और कम से कम पैसे में इस पॉवर स्टेशन की बिजली की क्षमता दुगुनी हो जायेगी और हरियाणा की जनता को बिजली मिलने लगेगी।

श्री अध्यक्षः माजरा जी, गुप्ता जी को भी सप्लीमैंटरी पूछ लेने दो। आप एक साथ जवाब दे देना।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, राम पाल माजरा जी एक सदस्य के प्रश्न के जवाब में एक बात कह रहे थे कि पिछली सरकार ने दूसरी यूनिट का प्लांट लोड सैक्टर 7 मैगावाट बढ़ाने के लिए 300 करोड़ रुपये का टैंडर दे दिया था और इन्होंने उस टैंडर को रद्द करके वह कार्य 35 करोड़ रुपये में पूरा करवा लिया।

श्री राम पाल माजराः स्पीकर सर, मैं गुप्ता जी को बताना चाहूँगा कि हमने उनका टैंडर रद्द नहीं किया बल्कि वे अपने आप ही काम बंद कर गये थे।

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर सर, ठीक है, वे अपने आप काम बंद कर गये होंगे लेकिन यह मामला बहुत सीरियस है कि पहली वाली सरकार ने 300 करोड़ रुपये में टैंडर दिया और मौजूदा सरकार ने वह कार्य सिर्फ 35 करोड़ रुपये में पूरा करवा लिया। स्पीकर साहब, मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि ये इस तरह की सारी बातें ठीक करने लग जाएं तो फिर इनका सारा घाटा पूरा हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि इस काम के लिए ये एक व्हाईट पेपर जारी करें। मेरा कहना है कि चाहे किसी भी सरकार ने यह 300 करोड़ का ठेका दिया, फिर काम बन्द हुआ तो

क्यों हुआ। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, इस बारे में मंत्री जी सदन में अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

श्री राम फल कुण्डू: अध्यक्ष महोदय, मेरा भी यही सवाल है कि जो यह 265 करोड़ रुपये का डिफरैंस है, उसका जवाब आना चाहिए और इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए कि श्री बंसी लाल जी ने किस नियम के तहत यह काम किया।

डॉ० मलिक चन्द गंभीरः स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि यमुनानगर में जो 500 मैगावाट का यूनिट बनाने जा रहे हैं क्या यह टोटल 500 यूनिट का ही एक यूनिट है या इसको और आगे भी बढ़ाया जायेगा। दूसरा मेरा सवाल यह है कि एक बार अनाउन्समेंट हुई थी कि वहां पर गैस बेस्ट प्लांट बनाया जायेगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात भी सरकार के अन्दर कन्सीड़ेशन है या नहीं ? यदि यह गैस बेस्ट प्लांट बनाया जाना अन्दर कन्सीड्रेशन है तो उस पर टोटल कॉस्ट क्या आयेगी, इस बारे में भी मंत्री महोदय स्थिति क्लीयर करने की कृपा करें।

श्री राम पाल माजराः स्पीकर साहब, मांगे राम गुप्ता जी बड़े कन्सर्न हैं। ये हर मामले में कहते हैं कि व्हाईट पेपर जारी होना चाहिए। इनकी जुबान व्हाईट पेपर जारी करने के लिए कहती रहती है। यदि सरकार कोई विकास के काम कर रही है तो भी कहते हैं कि व्हाईट पेपर जारी किया जाये। इसी प्रकार से हुड्डा

साहब भी कहते रहते हैं कि व्हाईट पेपर जारी हो जाये। (विघ्न) इनके लिए तो व्हाईट पेपर नहीं बल्कि ब्लैक पेपर जारी करना चाहिए। स्पीकर साहब यह काम ए०बी०बी० कम्पनी को दिया गया और उस ए०बी०बी० कम्पनी ने काम बन्द कर दिया जिसकी वजह से केस आर्बीट्रेशन में चला गया। दोनों पार्टियों ने अपने एडवाईजर नियुक्त किए हुए हैं। इस वक्त भी केस आर्बीट्रेशन में चल रहा है और आर्बीट्रेशन का जो फैसला होगा उसके मुताबिक ही कार्यवाही होगी। (विघ्न) आर्बीट्रेशन भी अपने आप में एक कोर्ट है। अब तो हम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही कोई कार्यवाही कर पाएंगे। (विघन)

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः स्पीकर साहब, मैंने भी एक सप्लीमैंटरी पूछी थी, उसका जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्षः बिसला जी, आपका गैस का जो सवाल है वह इस सवाल से रिलेटिड नहीं है। (विघन) आप तो बहुत सीनियर हैं। आप बैठ जायें। आप पूरी तैयारी करके नहीं आये हैं। आप बैठ जायें। (विघ्न)

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः स्पीकर साहब, आपने मेरे सवाल को दूसरे साथियों के साथ क्लब कर दिया। इस सवाल पर 4–5 साथियों ने इकट्ठे सवाल कर दिये। आपने भी कहा था कि मंत्री जी इकट्ठा जवाब दे देंगे। मेरे सवाल की कोई इन्फर्मेशन इन्होंने अभी तक नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष: आपका रिलेटिड सवाल नहीं है, आप बैठ जायें।

श्री राम पाल माजरा: स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से इनके सवाल का जवाब दे देता हूँ। मैं इनको बताना चाहूँगा कि इनका जो सवाल है कि क्या वहां पर गैस बेस्ट पॉवर प्लांट लगाया जायेगा, तो मेरा कहना है कि उसको अगली पंचवर्षीय योजना में टेक अप कर रहे हैं और हरियाणा सरकार केन्द्र सरकार पर और एन०टी०पी०सी० पर दबाव डाल रही है कि फरीदाबाद का दूसरा चरण शीघ्र आरम्भ करें क्योंकि वहां पर गैस की उपलब्धता है।

Cases Registered under PNDT Act

***1292. Sh. Banta Ram : Will** the Minister of State for Health be pleased to state the number of cases registered in the State under PNDT Act against the misuse of Ultrasound machines for gender determination?

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (डॉ० एम०एल० रंगा): श्रीमान, पी०एन०डी०टी० अधिनियम के अन्तर्गत लिंग जांच हेतु अस्ट्रासाउण्ड मशीनों के दुरुपयोगापी ०एन०डी०टी० अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के उल्लघन् के कारण 11 केसिज/शिकायत तथा 2 एफ०आई०आर० राज्य की विभिन्न जिला अदालतों में पंजीकृत हुए हैं।

श्री बंता राम बाल्मीकी: स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि ये केस कहां–कहां पर रजिस्टर हुए हैं और इनकी वर्तमान स्थिति के बारे में मंत्री महोदय स्थिति स्पष्ट करें।

डॉ० एम०एल० रंगा: अध्यक्ष महोदय, पी०एन०डी०टी० एक्ट 1994 में बना था और 1996 में सबसे पहले देश के अन्दर इसे हरियाणा प्रदेश में लागू किया गया था। इस एक्ट को लागू करने में हिन्दुस्तान के सभी प्रान्तों में हरियाणा प्रान्त पहला प्रान्त है जहां कि इस ऐक्ट के अन्दर एफ० आई०आर० दर्ज करवाई गई और कम्पलेंट रजिस्टर्ड करवाई गई। क्योंकि यह एक सामाजिक अभिशाप है। इस अभिशाप को समाप्त करने के लिए युद्ध स्तर का कार्य हरियाणा में पहली बार करने का बीड़ा हरियाणा सरकार ने उठाया है और पहली बार फरीदाबाद में 2 लोगों के खिलाफ अल्ट्रासाउण्ड मशीन पर जो लिंग जांच की जा रही थी, उनको चौक किया और हरियाणा पहला प्रान्त है जिसने एफ० आई० आर० दर्ज करवा कर केस रजिस्टर्ड करवाया है। हमारे यहां अब तक 11 कम्पलेंटस और 2 एफ०आई०आरज० दर्ज हुई हैं इनकी जिलावाईज स्थिति इस प्रकार है। फरीदाबाद जिले में 4 केस, गुड़गांव जिले में 4 केस, जिला रिवाड़ी में एक केस, भिवानी में एक, पानीपत में एक और रोहतक तथा हिसार जिलों में एक–एक एफ०आई० आर० रजिस्टर्ड हुई हैं। जहां तक वर्तमान स्थिति का ताल्लुक है, इनमें से जो 7 अल्ट्रासाउण्ड रजिस्टर्ड नहीं थे उनको हमने जब्त किया

है और हमने उनके अल्ट्रासाउण्ड के लाईसैंस कैंसिल किए हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ ये सारे केस न्यायालय में चल रहे हैं और न्यायालय के हिसाब से एक्ट के तहत जो प्रावधान है हमारे एक्ट में लिखा हुआ है कि यदि कोई लिंग जांच के लिए किसी को सलाह देता है, साथ जा कर करवाएगा और करने वाला उसके लिए 10 हजार रुपये का जुर्माना और तीन महीने की सजा का हमारे यहां प्रावधान है। इस एक्ट को लेटैस्ट हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी ने 17 जनवरी, 2003 को अमैंड किया है। भारत सरकार भी चाहती है कि इस सामाजिक बुराई को यथासम्भव तथा यथाशीघ्र समाप्त किया जाए और इसके तहत यह पाया गया है कि यह सजा बहुत कम है उन्होंने इस सजा को बढ़ा करके 10 हजार से 50 हजार रुपये का जुर्माना किया है और तीन महीने से 6 महीने की सजा का प्रावधान रखा है। इस प्रकार से करने से मैं मानता हूँ कि पी०एन०डी०टी० एक्ट के तहत भ्रूण हत्या तथा दूसरे केसों में भी कमी आएगी।

श्री पूर्ण सिंह डाबरा: अध्यक्ष महोदय, मैं अपकी मार्फत माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से जानना चाहूँगा कि इस मामले में जनता की अवेयरनैस के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है?

डॉ० एम०एल० रंगा: अध्यक्ष महोदय, सरकारें समय–समय पर कानून बनाती रही हैं। पूर्ववर्ती सरकार जो जबरदस्ती करती रहीं जिसके तहत नलबन्दी और नसबन्दी भी करती रहीं चाहे कोई बुढडा मरे या जवान मरे हत्या त्याई काम

होता रहा है, इस बात की धारणा को लेते हुए जिस प्रकार से इमरजैंसी में नसबन्दी की गई, नलबन्दी की गई उसको देखते हुए वर्तमान सरकार ने न किसी पर कोई जोर दिया और न ही कोई जबरदस्ती की। हमने एक ऐसी व्यवस्था की है कि लोग खुद इसको अपनाए। क्योंकि यह एक सामाजिक बुराई है और चाहे सत्ता पक्ष हों चाहे विपक्ष हों, चाहे दर्शकदीर्धा में बैठे हुए दर्शकगण हैं, चाहे प्रेस के लोग हैं, हम सब की यह जिम्मेदारी है कि इस सामाजिक बुराई को मिटाने के तहत हम युद्धस्तर पर कार्य करें। यह भ्रूण हत्या का जो कन्सैप्ट है, यह पी०एन०डी०टी० एक्ट को लागू करने का कन्सैप्ट है उसे स्वीकार करना हम सब की जिम्मेदारी है। जनसंख्या वृद्धि एक सामाजिक बुराई है जिसको पहली बार रोकने का बीड़ा वर्तमान सरकार के मुखिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उठाया है। 29 सितम्बर, 2002 को एक' ऐसी योजना हिन्दुस्तान में पहल करके हमने लागू की है, इस योजना का नाम देवीरुपक योजना है। इस योजना के तहत तीन चीजें की गई है। जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जाए भ्रूण हत्या कैसे रुके तथा विषम लिंग अनुपात को कैसे कम किया जाए। इस योजना के तहत जो दम्पत्ति विवाह के बाद एक पुत्री होने पर नलबन्दी या नसबन्दी करवाते हैं तो उनको 500 रुपये महीना बीस साल तक दिया जाएगा जो कि साढ़े सात लाख रुपया बनता है। इसी प्रकार से यदि एक लड़के के बाद कोई इस योजना के तहत नसबन्दी या नलबन्दी करवाते हैं उनको दो सौ रुपये प्रतिमास 20 साल तक दिए जाएंगे। इसमें ऐसी व्यवस्था भी है कि यदि किसी

के दो बालिकाएं होती हैं और वे दम्पत्ति नलबन्दी या नसबन्दी करवाते हैं तो उनको भी 200 रुपये प्रतिमास दिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ऐसा करने से हम जनसंख्या वृद्धि को रोक पाएंगे। आज के समय में हमारे पितृ प्रधान जो परिवार रहे हैं हमारे हिन्दुस्तान में यह सोच रही है कि पुत्र की लालसा में पुत्री को पैदा होते ही उसको समाप्त कर देते हैं। इस भ्रूण हत्या को हम इस योजना से रोक पाएंगे और दूसरे जो लिंग विषम अनुपात है आज के समय एक हजार लड़कों के पीछे 861 लड़कियां हैं। ठीक 10 साल के बाद हमारे 139 लड़के कुंवारे रह जाएंगे और यह अनुपात बराबर बढ़ता रहेगा। समाज के लिए एक चुनौती रखी है, इस चुनौती के लिए हमें सबका सहयोग अपेक्षित है और देवीरुपक योजना में सभी सहयोग दें ताकि हम इसमें पहल करके जनसंख्या वृद्धि, लिंग विषम अनुसार और आ हत्या को रोकें। (विघन)

10.00 बजे

श्री अध्यक्षः राम किशन फौजी जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (विष्य) आपका यह कोई तरीका नहीं है। आप जब चाहें बिना इजाजत के बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (विघ्न) रमेश खटक जी, आप अपनी सप्लीमैंटरी पूछें।

श्री रमेश कुमार खटकः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से यह पूछना चाहूँगा कि हरियाणा में

कितनी अल्ट्रासाउण्ड की मशीने हैं और उनमें से कितनी रजिस्टर्ड हैं।

डॉ० एम०एल० रंगाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को यह बताना चाहूँगा कि हरियाणा में कुल 825 अल्ट्रासाउण्ड की मशीनें हैं। जिनमें से 713 अल्ट्रासाउण्ड की मशीनों की रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। बाकी जो मशीनें हैं, वे इस वजह से रजिस्ट्रेशन होने से बची हुई हैं क्योंकि कई जगहों पर एक ही मशीन 2 जगह प्रयोग हो रही है। इसलिए यह 825 की संख्या बन गई है। हमने आदेश जारी कर दिये हैं कि अगर हरियाणा में कोई अल्ट्रासाउण्ड की मशीन बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही हैं तो उनको जप्त किया जाए और उनका लाईसैंस भी कैंसिल कर दिया जाए।

आई०जी० (से०नि०) शेर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि देवीरुपक स्कीम के तहत जिसके लड़की होती है उसको 500 रुपए प्रति माह और जिसके लड़का होता है उसको 200 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। लेकिन अगर उस बच्चे की किसी दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो क्या वह पैसा दिया जाना जारी रहेगा। इसके साथ ही यह जो राशि है इस बारे में मुख्य मंत्री जी ने बोलते हुए कहा था कि यह राशि 20 साल बाद इक्ट्ठी मिलेगी। मैं इस बारे में यह जानना चाहूँगा कि क्या उस राशि पर ब्याज मिलेगा जैसे कि

जी०पी०एफ० पर मिलता है। क्या आपकी सरकार द्वारा उसके इन्ट्रस्ट पर इन्हस्ट मिलेगा, जैसे कम्पाउंड इन्ट्रस्ट होता है।

डॉ० एम०एल० रंगा: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि यह राशि 20 साल बाद इक्ट्ठी नहीं मिलेगी। यह राशि 500 रुपए या 200 रुपए के हिसाब से उसके खाते में हर महीने में जमा होती रहेगी और बैंक में जो इन्ट्रस्ट मिलता है, वह उसको मिलता रहेगा। जहां तक इन्होंने बच्चे की दुर्घटना में मृत्यु हो जाए तो क्या यह राशि जारी रहेगी। अध्यक्ष महोदय, उस स्थिति में मैं इनको यह बताना चाहूँगा कि यह राशि 500 रुपए प्रति माह है हमने एक बच्चे के होने पर उस दम्पति को दी है और वह राशि उस दम्पति को मिलती रहेगी चाहे वह बच्चा रहे या न रहे।

श्री भागीराम: अध्यक्ष महोदय, अगर किसी के एक लड़की होती है और वह ऑप्रेशन करवा लेता है तो उसको 500 रुपए प्रति माह और अगर किसी के एक लड़का होता है और वह ऑप्रेशन करवा लेता है तो उसको 200 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। इसके अलावा आबादी ज्यादा न बड़े उसके लिए आप्रेशन करना भी बताया गया है। इसके साथ ही मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि हमारे विधान सभा के 3 सदस्य कुंवारे रह गए हैं, इनका क्या किया जाए। (हंसी)

वित्तमंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय, इनकी बातों से चिन्तित होकर हमें जब यह पता चला कि आज भी लोग कुंवारे रह रहे हैं, आज सैक्स रेशो कम हो गया है और हमारे विधान सभा के 3 सदस्य भी कुंवारे रह गए हैं तो इस बात की सीरियसनैस को देखते हुए इस सरकार ने चिन्ता जाहिर की है। हमने केवल विधायकों की ही नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश के नागरिकों के बारे में चिन्ता जाहिर की है। पोजिटिव इन्सर्टिव देकर, कोरसीव मईयरज न बढ़े इसलिए यह किया है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: प्रो० साहब, आप यह बताएं कि इन्होंने शादी करवायी नहीं या किसी ने इनकी शादी की नहीं?

प्रो० सम्पत सिंह: स्पीकर साहब, यह तो इनका पर्सनल मैटर है लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे होते हैं जो अपनी शादी करवाते नहीं हैं और बहुत से लोगों के मामले में यह होता है कि कोई उनकी शादी नहीं करता। इसलिए सरकार ने अपना कंसर्न फौलो किया है, अपनी चिन्ता जाहिर की है। केवल विधायकों की ही जिम्मेदारी नहीं है बल्कि प्रदेश के हर नागरिक के लिए सरकार ने अपनी चिन्ता जाहिर की है। चाहे विधायक हों, चाहे एम०पी० हों, चाहे किसान हों या चाहे लेबर हो, हर एक के लिए सरकार ने चिन्ता की है। स्पीकर साहब, आप तो हाउस के कस्टोडियन हैं इसलिए यह जिम्मेदारी आपकी है सरकार तो आपको पूरा स्पोर्ट करने केलिए तैयार है। इनकी शादी में जो थोड़ी बहुत तैयारी चाय पार्टी वगैरह की होगी उसका बन्दोबस्त

हम कर देंगे। अगर आप इनके लिए कोई अरेन्ज करेंगे तो हम यह खच करने के लिए तैयार हैं। (हंसी)

चौ० भजनलालः स्पीकर साहब, असम में भी एक सरकार ऐसी बनी थी जिसमें मुख्य मंत्री समेत 52 विधायक कुंवारे थे लेकिन एम०एल०ए० बनने के बाद उनकी शादी हो गयी थी। अब ये तीनों भी एम०एल०ए० बन गये हैं इसलिए इनकी शादी भी हो जाएगी।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, जब भजनलाल जी की वजारत में प्रो० छतरपाल सिंह वजीर थे तो इन्होंने उनकी भी हवाई जहाज में शादी करवा दी थी। (विघन) जब वह एम०एल०ए० बना था तो उस समय वह कुंवारा था लेकिन इन्होंने हवाई जहाज में उसकी शादी करवा दी थी।

श्रीमती सरिता नारायणः स्पीकर साहब, पुरुषों के लिए तो यहां पर सोचा जा रहा है लेकिन हमारी कुछ बहनें ऐसी भी हैं जिन्होंने अपनी शादी नहीं की और वे देश सेवा में लगी हुई हैं तो सरकार उनके लिए क्या कर रही है?

चौ० भजनलालः स्पीकर साहब, जो बहनें देश सेवा में लगी हुई हैं उन का तो किसी ने सोचा ही नहीं सरकार को उनके बारे में भी सोचना चाहिए। (विघन)

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, महिलाओं के मामले में आपको थोड़ा लिबर्ल रहना चाहिए। (विघन)

श्री भागी रामः अध्यक्ष महोदय, यह बात हंसी में टल रही है जबकि मामला बहुत सीरियस है। मेरा सवाल यह था कि एक तरफ तो कई कुंवारे आदमी हैं और दूसरी तरफ एक आदमी दो–दो, तीन–तीन औरतें अपने साथ रखता है और उनसे जो इललीगल औलाद पैदा होती हैं उनका सरकार क्या करेगी?

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, हिन्दू मैरिज एक्ट में दो पत्नियों वाली बात नहीं है।

श्रीमती अनीता यादवः स्पीकर साहब, जैसा अभी अनिल विज ने माना कि इनका तो खाता पीता एरिया है और ये बड़े रिच हैं यह बात ठीक है कि अम्बाला का एरिया बड़ा रिच है लेकिन इतने खाते पीते होने के बावजूद भी मैं नहीं समझ पायी कि इनकी शादी किसी ने क्यों नहीं की। मडोला जी जो बागड़ी एरिया में पैदा हुये हैं हो सकता है कि वहां पर एजुकेशन की कमी होने के कारण इनकी शादी न हो पायी हो और हो सकता है कि रामभगत जी जो नारनौंद हल्के से हैं, ने अटल बिहारी वाजपेयी का अनुसरण किया हो क्योंकि वे भी कुंवारे हैं। इसी तरह से जहां तक छत्तरपाल सिंह की बात है उनके बारे में बताया गया कि वे एम०एल०ए० बनने के समय अन–मैरिड थे लेकिन उनकी हवाई जहाज में शादी हो गयी थी तो हो सकता है कि इनकी भी इसी तरह से मैरिज हो रही हो इसलिए आप इस बात की इंक्वायरी करवा लें। (हंसी)

डॉ० एम०एल० रंगा: अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन का आभारी हूँ कि सभी माननीय सदस्यों ने इस गंभीर विषय पर पूरी गंभीरता दिखाई और इस गंभीर विषय को लेकर चिंता व्यक्त की है। मैं सभी सदस्यों से यह आश्वासन चाहूँगा कि यह जो हमारी देवीरूपक योजना है इसमें हमें अपना पूरा सहयोग दें। जहां तक हमारे तीन माननीय सदस्यों का मामला उठाया है यह उनका व्यक्तिगत मामला है लेकिन जो सैक्स रेशो घटती जा रही है उसके तहत हो सकता है कि इनको सुयोग्य वधू न मिली हो या इसमें समय लग रहा हो। यह चिंता का विषय है और इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है।

Laying of Sewerage in Kalayat Mandi

***1299. Ch. Jai Parkash :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to lay sewerage system in Kalayat Mandi, District Kaithal; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to be materialized?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा):

(क) जी हाँ श्रीमान।

(ख) कलायत मण्डी में मल निकास प्रणाली प्रदान करने का कार्य पहले से ही प्रगति पर है। बाहरी सीवर का शेष कार्य तथा डिस्पोजल कार्य सम्भवतः मार्च, 2004 तक पूरा हो जाएगा।

चौ० जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सी०पी०एस० साहब से जानना चाहता हूँ कि एक तो इन्होंने जो बताया हें कि सीवरेज का कार्य प्रगति पर है वह प्रगति पर नहीं है यह कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ है और जब वह बना था तो लो लाइंग एरिया की वजह से भरती ज्यादा हो गई थी और सारे पाइप नीचे दब गए थे क्या ये जो दबे हुए पाइप थे उनसे ही काम चलाएंगे और यह कब तक बनकर तैयार हो जाएगी, मैं बताना चाहूँगा कि इसके सेफ्टी टैंक भी नहीं बने हैं।

श्री राम पाल माजराः अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे माननीय साथी को बताया है कि यह कार्य मार्च, 2004 तक पूरा हो जाएगा। मैं बताना चाहूँगा कि यह दो डिपार्टमैंट्स की तरफ से डिपौजिट वर्क था। इसमें मार्किटिंग बोर्ड ने भी 42 लाख 18 हजार रुपया देना था और इसकी प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है इसी प्रकार से 18 लाख 1 हजार रुपये हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने इसमें जमा कराने हैं। उनकी तरफ से अभी प्रशासनिक स्वीकृति अपेक्षित है। इसमें पहले 20 लाख रुपये खर्च किए जा चुकेहैं।इस प्रकार से इसका कार्य जो मैंने समयावधि बताई है कि मार्च, 2004 तकपूरा कर लिया जाएगा। जो इन्होंने बताया है कि लो लाइंग एरिया होने की वजह से भरती ज्यादा होने की वजह से वहां पाइप

लाइन दब गई हैं। उसके लिए हम तकनीकी आधार पर दिखा लेंगे अगर उससे काम चलेगा तो चलाएंगे नहीं तो टैक्नीकल आधार पर जो राय होगी उसी मुताबिक किया जाएगा। जहां तक कलायत की बात है मैंने कल बताया था कि हमने घग्गर ऐक्शन प्लॉन बनाई है उसके तहत 21 शहरों का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है और वह भारत सरकार को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल करने के लिए भेजा गया है। सारे शहरों का 354.35 लाख का ऐस्टीमेट बना है उसमें कलायत को विशेषतौर से शामिल किया गया है उसका जो ग्रान्ड ऐस्टीमेट बनाया गया है, प्रोजैक्ट बनाया गया है 7 करोड़ 94 लाख उस पर ऐस्टीमेट बना है वह भारत सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा गया है और घग्गर ऐक्शन प्लॉन में शामिल है। मंडियों की जो बात बताई थी। इन मंडियों के बनने के बाद फिर उसमें सारे कस्बों को लिया जाएगा और उसका पूर्ण ऐस्टीमेट ग्रान्ड ऐस्टीमेट बनाकर, प्रोजैक्ट बनाकर भारत सरकार को भेजा हुआ है।

श्री बलवंत सिंह मायना: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सी०पी०एस० साहब से जानना चाहता हूँ कि कौन–कौन सी मंडियों में जनस्वास्थ्य द्वारा सीवरेज और पीने के पानी की व्यवस्था की जा रही है उसके बारे में बताए?

श्री राम पाल माजरा: स्पीकर सर, मंडी बोर्ड द्वारा जो पैसा जमा कराया गया है विभिन्न मंडियों में सीवरेज बिछाने और पीने के पानी के लिए उसका ब्यौरा निम्न प्रकार हैः –

हरियाणा राज्य विपणन बोर्ड के कार्य

क्रम संख्या	योजना का नाम	अनुमान राशि	उपलब्ध राशि	कुल व्यय (लाखों में)	भौगित प्रगति
1	2	3	4	5	6
	जिला अम्बाला				
1	अनाज मंडी मुलाना में नया ट्यूबवैल लगाना।	16.81	16.50	16.07	कार्य सम्पन्न हो गया है ।
2	गांव साह, जिला अम्बाला मण्डी में जल वितरण व मल योजना का कार्य।	34.89	31.50	24.51	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है ।
3	नई सब्जी मण्डी नारायणगढ़ में जल वितरण।	20.34	5.00	8.06	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है ।
4	अनाज मण्डी बराडा में नया ट्यूबवैल	7.70	7.70	-	कार्य पूर्ण हो चुका है

	लगाना।				।
5	अनाज मण्डी शहजादपुर में नया ट्यूबवैल लगाना।	7.60	5.00	-	कार्य प्रगति पर है ।
6	नई अनाज मण्डी अम्बाला शहर, चारा मण्डी में जल वितरण व मल योजना का कार्य।	23.80	23.80	-	कार्य प्रगति पर है ।
	जिला भिवानी				
1	नई सब्जी मण्डी गांव बराढ़ा जिला भिवानी में जल वितरण व मल योजना का कार्य।	7.84	4.00	2.30	40 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है ।
2	नई अनाज मण्डी तोशाम जिला भिवानी में जल वितरण व मल योजना का कार्य।	19.61	12.00	-	कार्य प्रगति पर है ।

	जिला फरीदाबाद				
1	अनाज मण्डी होडल में मल योजना का कार्य।	31.05	32.00	21.29	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है ।
	जिला गुड़गांवा				
1	अनाज मण्डी तावडू में जल वितरण व मल योजना का कार्य।	14.82	14.82	10.47	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है ।
2	नई अनाज मण्डी सोहना में नया ट्यूबवैल लगाना।	8.96	8.96	0.55	कार्य प्रगति पर है ।
3	अनाज मण्डी सोहना में मल योजना का कार्य।	6.65	6.65	1.14	15 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है ।
4	अनाज मण्डी नूह में जल वितरण व मल	46.27/42.99	10.00	-	कार्य प्रगति पर है ।

	योजना का कार्य।				
	जिला जीन्द				
1	नई अनाज मण्डी जीन्द में जल वितरण व मल योजना का कार्य।	45.16	45.00	32.99	75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।
2	नई अनाज मण्डी पीलू खेड़ा में जल वितरण व मल योजना का कार्य।	45.60	10.00	9.89	20 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।
3	अनाज मण्डी ढांड में जल वितरण व मल योजना का कार्य।	27.05	27.05	25.54	95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।
4	मण्डी कलायत में जल वितरण व मल योजना का कार्य।	60.01	30.00	19.62	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है।
	जिला करनाल				

1	अनाज मण्डी इन्दरी में जल वितरण व मल योजना का कार्य।	15.48	15.46	16.16	कार्य पूर्ण हो चुका है ।
2	अनाज मण्डी कुंजपुरा में जल वितरण व मल योजना का कार्य।	33.08	30.00	29.21	90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है ।
3	अनाज मण्डी करनाल में जल वितरण व मल योजना का कार्य।	181.12	125.00	126.181	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है ।
4	अनाज मण्डी असन्ध में जल वितरण व मल योजना का कार्य।	26.93	25.00	21.63	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है ।
5	अनाज मण्डी गांव निगदु जिला करनाल में जल वितरण व मल	16.91	16.91	19.26	कार्य पूर्ण हो चुका है ।

	योजना का कार्य।				
6	अनाज मण्डी गांव निगदु जिला करनाल में मल योजना का कार्य।	25.48	25.00	10.97	41 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है ।
7	अनाज मण्डी कुरुक्षेत्र में चोटांग नाला तक पाइप लाइन लगाना।	5.96	5.69	1.19	20 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है ।
8	अनाज मण्डी तरावड़ी जिला करनाल में मल वितरण व मल योजना का कार्य।	15.22	15.26	12.44	80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है ।
9	अनाज मण्डी घरोण्डा में पाइप लगाना।	2.19	2.19	2.82	कार्य पूर्ण हो चुका है ।
10	अनाज मण्डी बिआना जिला करनाल में जल वितरण व मल	30.60/ 29.60	29.60	-	कार्य प्रगति पर है ।

	योजना का कार्य।				
11	मण्डी लाडवा में मल योजना का कार्य।	7.13/ 5.76	-	-	अभी फण्ड जमा होने पर कार्य शुरू किया जाएगा ।
	जिला रोहतक				
1	सब्जी मण्डी झज्जर में जल वितरण व मल योजना का कार्य।	10.27	10.26	3.13	30 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है ।
	जिला सोनीपत				
1	अनाज मण्डी गन्नौर में जल वितरण व मल योजना का कार्य।	19.95	19.95	-	कार्य प्रगति पर है ।
2	अनाज मण्डी गोहाना में जल वितरण व मल	38.22	28.00	33.14	85 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है

	योजना का कार्य।				।
3	सब्जी मण्डी गोहाना में जल वितरण व मल योजना का कार्य।	25.81	25.81	-	कार्य प्रगति पर है ।
4	अनाज मण्डी सोनीपत में जल वितरण व मल योजना का कार्य।	20.74	15.00	-	कार्य प्रगति पर है ।
	जिला सिरसा				
1	मण्डी सिरसा में बरसाती पानी निकालने का कार्य	27.12	10.00	13.30	50 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है ।
2	नई अनाज मण्डी फतेहाबाद में बरसाती पानी निकालने का कार्य	37.79	20.00	-	कार्य प्रगति पर है ।
3	अनाज मण्डी औढा जिला सिरसा में	50.00	10.00	-	कार्य प्रगति

	जल वितरण व मल योजना का कार्य।				पर है ।
4	मण्डी ऐलनाबाद में जल वितरण व मल योजना का कार्य।	45.43	20.00	-	कार्य प्रगति पर है ।

Judicial Complex and Court of Sessions Judge at Panipat

***1475. Sh. Krishan Lal :** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration ofthe Government to construct the Judicial Complex at Panipat.

(b) whether there is also any proposal under consideration of the Government to establish the Court of Session Judge at Panipat ; and

(c) if so, the time by which the above-said proposals are likely to be materialized '?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा):

(क) हाँ, श्रीमान जी

(ख) नहीं, श्रीमान जी

(ग) क्योंकि 66.565 एकड़ भूमि जिस पर प्रस्तावित न्यायिक संव्यूह का निमार्ण किया जाना है, उस सम्बन्धी मामला रक्षा मन्त्रालय भारत सरकार के पास विचाराधीन है। अतः इस स्थिति में समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

श्री कृष्ण लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सी०पी०एस० महोदय से जानना चाहूँगा कि क्या हरियाणा सरकार ने मिनी सचिवालय और जुडिशियल कॉम्पलैक्स जो बनाने हैं उसके लिए डिफैंस डिपार्टमैंट से क्या कोई मीटिंग की है और यदि की है तो उसका पूरा ब्यौरा दें?

श्रीराम पाल माजराः अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की सरकार ने डिफैंस मिनिस्ट्री से सैद्धांतिक रूप से जो निवेदन किया है उसे उन्होंने स्वीकार भी किया है, ट्रांसफर ऑफ लैण्ड का मामला आया, अम्बाला में 181 एकड़ जमीन और एक एकड़ 6 मरला जमीन अधिगृहीत की गई है इसका कब्जा ले लिया गया है, यह जमीन रक्षा मंत्रालय को ट्रांसफर होनी थी, फिर रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 150 एकड़ जमीन और दो, जिसकी वजह से मामला सिरे नहीं चढ़ सका, उनसे बातचीत जारी है, उनसे मीटिंग हो रही है, मामला सिरे चढ़ने के नजदीक है। ज्यों ही मामला सिरे चढ़ जाएगा, जमीन ट्रांसफर हो जाएगी, डिफैंस महकमे को जमीन चली जाएगी। वह जमीन हमें मिल जाएगी और काम शुरू हो जाएगा।

श्री कृष्ण लालः अध्यक्ष महोदय, करनाल में मिनी सचिवालय बनना था वहां बाहर के लोगों के लिए और क्लाइंट के लिए कोई प्रोवीजन नहीं रखा गया था। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सी०पी०एस० महोदय से जानना चाहता हूँ कि भविष्य में कोई जुडिशियल कॉम्पलैक्स या मिनी सचिवालय बनाया जाएगा तो इसमें बाहर केलोगों के लिए या क्लाइंट्स के लिए कोई प्रोवीजन रखा जाएगा?

श्री राम पाल माजराः स्पीकर सर, ज्यों ही जमीन ट्रांसफर हो जायेगी, प्रोजैक्ट प्लॉन बनेगा, एस्टीमेट बनेगा और उसके अंदर वे सभी सुविधाएं दी जायेंगी जो दूसरे न्यायिक परिसरों में दी गई हैं। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को जानकारी देना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश में 19 जिलों में से तकरीबन 17 जिलों में न्यायिक परिसर बन चुके हैं। पंचकूला, कुरुक्षेत्र, कैथल, गुड़गांव, फतेहाबाद, भिवानी, नारनौल, यमुनानगर, जीन्द, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, हिसार, सोनीपत में न्यायिक परिसर बन चुके हैं। करनाल और अम्बाला में न्यायिक परिसर पूरे होने को हैं और फरीदाबाद में निर्माण कार्य तेजी पर हें। केवल झज्जर और पानीपत ये दो जिले रहते है। झज्जर में न्यायिक परिसर बनाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने शिलान्यास रख दिया है और पानीपत में ज्यों ही जमीन ट्रांसफर होगी तब वहां भी बना दिया जाएगा।

श्री नफे सिंह जुण्डला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माजरा जी से जानना चाहूँगा कि जैसे पंवार साहब ने कहा कि करनाल में लघु सचिवालय बनाया गया है और उसके साथ–साथ जुडिशियल कम्पलैक्स की बिल्डिंग भी तैयार होने जा रही है। लेकिन वहां पर लघु सचिवालय में बार का प्रावधान नहीं है इसलिए मुख्य संसदीय सचिव महोदय से मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या वहां बार कम्प्लैक्स बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहूँगा कि मौजूदा सरकार की एक सोच है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए केवल जिला लैवल पर ही सारी सुविधाएं प्रदान नहीं की गई बल्कि प्लांटेज को ध्यान में रखकर लिटिगेशन हाल बनाने की योजनाएं भी बनाई हैं। इसके अतिरिक्त वकीलों को सरकारी तौर पर निर्णय लेकर जमीन दी हैं ताकि वे चौम्बर बना सकें। इसके साथ–साथ वहां बार रूम और लाईब्रेरी की व्यवस्थाएं भी हैं। अध्यक्ष महोदय, इससे आगे हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि सब डिवीजन लैवल पर भी मिनी सचिवालय बनायें और जितने भी सरकारी आफिस हैं वे सब एक जगह हों ताकि आम नागरिक को किसी प्रकार की असुविधा न रहे। हमारी सरकार की यह पालिसी है कि हम जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखकर चलें और जनता की मूलभूत

जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं। जिस–जिस हिसाब से जो डिमांड्स सरकार के सामने प्रस्तुत की जाती हैं उन पर बाकायदगी से विचार विमर्श करके निर्णय लिये जाते हैं।

Antyodaya Anna Yojana Scheme

***1286. Sh. Tej Vir Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state the number of families in the State to whom the benefit of Antyodaya Anna Yojana Scheme is being given at present ?

मुख्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): श्रीमान जी 31. 01. 2003 को राज्य में 1,13,656 परिवार अन्त्योदय अन्न योजना का लाभ प्राप्त कर रहे थे।

श्री तेजवीर सिंह: सर, मैं मुख्य मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हूँ।

तारांकित प्रश्न संख्या– 1343

(इस समय माननीय सदस्य श्री रामबीर सिंह सदन में उपस्थित नहीं थे इसलिए यह प्रश्न पूछा नहीं गया।)

Widening of Palwal Yamuna Bridge Road

*** 1336. Shri Udai Bhan :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to repair or widen the Palwal Yamuna Bridge Road, if so the details thereof ?

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा): हां श्रीमान जी। कार्य पहले ही प्रगति पर है तथा सड़क को दिसम्बर, 2003 तक चौड़ा एवं मरम्मत करने की सम्भावना है।

श्री उदय भान: अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य संसदीय सचिव महोदय का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने कहा है कि दिसम्बर 2003 तक सड़क की मरम्मत करवा देंगे, लेकिन मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूँगा कि पलवल से अलीगढ़–बुलंदशहर के लिए मुख्य सड़क है, स्टेट हाई–वे है। इसकी हालत बहुत खस्ता है, इसमें चार–चार फुट के गड्ढे पड़े हुए हैं जिसके कारण सारे रास्ते में जाम लगा रहता है। इसके कुछ हिस्से में काम हुआ भी है लेकिन दो तीन महीने से काम बंद है। इसलिये मैं माजरा जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस सड़क को प्रियोरिटी के आधार पर जल्दी से जल्दी ठीक करवाया जायेगा क्योंकि दिसम्बर, 2003 तक का तो बहुत लम्बा समय है।

श्री राम पाल माजरा: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहूँगा कि पलवल से अलीगढ सड़क पर जीरो कि०मी० से 15.41 कि०मी० तक सुधार कार्यो पर 1,96.59 करोड़ रुपये की लागत की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और 53.76 लाख रुपये के कार्य इस सड़क पर किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त चालू वित्त वर्ष यानि 2002 –03 में इस सड़क पर 72.12 लाख रुपये खर्च किए जायेंगे और इस सड़क को टनाटन किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल समाप्त होता है?

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Providing of Housing Facilities

*** 1278. Shri Jasbir Mallour :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the percentage of police personnel of Haryana police force to whom the housing facility has, been provided together with the extent to which it is less than that of national average percentage ; and

(b) whether any steps have been taken by the State Government to provide housing facility to the personnel of the aforesaid police force ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला):

(क) हरियाणा पुलिस कर्मियों को 13.07 प्रतिशत आवासीय सहूलियत की व्यवस्था दी गई है जबकि राष्ट्रीय औसत 40 प्रतिशत है। अतः राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 26.93 प्रतिशत आवास की कमी है।

(ख) जी हां, राज्य सरकार पुलिस कर्मियों के लिए 1202 मकान वर्ष 2001 –02 और 2002 – 03 में बनाने हेतु 31. 55 करोड़ रुपये की स्वीकृति दे चुकी है।

Organisation of Health Camps

*** 1290. Shri Rajinder Singh Bisla :** Will the Minister of State for Health be pleased to state whether any Health Camp has been organised by the Health Departmant in the State during the last two years, if so, the number of patients to whom treatment have been provided therein ?

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (डॉ० एम०एल० रंगा) : जी हां, स्वास्थ्य विभाग द्वारा पिछले दो वर्षों में 453 हैल्थ कैम्पस लगाये गये, जिसमें कुल 2 ,47,680 मरीजों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई ।

Promotion of Cultivation of Medicinal Plants

*** 1302. Shri Ramesh Kumar KhatakShri Balwant Singh Sadhaura :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to promote the cultivation of medicinal plants in the State; if so, the details thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला):

1. हाँ श्रीमान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सौजन्य से वर्ष 1999–2000 से 2003 –04 तक पंचकूला जिले में 5.00 करोड़ रुपये की लागत से एक वनस्पति वन परियोजना चलाई जा रही है।

2. स्थानीय तथा बाहर से लाए हुए औषधीय पौधों के विकास के लिये खिजराबाद के नजदीक चूहड़पुर आरक्षित वन में

50 एकड़ क्षेत्र पर चौधरी देवी लाल हर्बल नैचुरल पार्क की स्थापना की गई है।

3. औषधीय पौधों के विकास तथा उत्पादन के लिए राज्य में औषधीय पौधारोपण बोर्ड की स्थापना की गई है। यमुनानगर तथा फरीदाबाद जिलों में औषधीय पौधों के संसाधन आधार को विकसित करने तथा औषधीय पौधारोपण द्वारा किसानों की आय में वृद्धि के लिए दो परियोजनाएं राष्ट्रीय औषधीय पौधारोपण बोर्ड की स्वीकृति के लिये भेजी गई हैं।

Illegal Possession on the Parks in Faridabad

*** 1368 Shri Krishan Pal :** Will the Minister for Town and Country Planning be pleased to state—

(a) The number of parks and green belts of sector-28, Faridabad which are under possession ; and

(b) if so, the steps so far taken or proposed to be taken to get the possession of the said parks green belts vacated.

नगर तथा ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीरपाल सिंह):

(क) फरीदाबाद सैक्टर– 28 के अनुमोदित नक्शो के अनुसार इसमें 63 पार्क/खुले स्थान हैं, इनमें से एक छोटी पार्क और एक खुले स्थान का अतिक्रमण किया गया है।

(ख) हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1977 के उपबन्धों के अनुसार अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किये गये हैं और उन्हें वहां से हटाने की आगामी कार्यवाही की जा रही है।

Number of Vultures

*** 1452. Shri Suraj Mal :** Will the Chief Minister be pleased to State whether it is a fact that the number of Vultures is declining in the State; If so; the reasons thereof, together with the remedial steps; if any, taken to save the species of Vultures?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला):

1. जी हां, श्रीमान् यह तथ्य है कि गिद्धों की संख्या राज्य में घट रही है। बाम्बे नैचुरल हिस्ट्री सोसाईटी के अनुसार गिद्धों की संख्या घटने का मुख्य कारण इसमें एक वायरस जैसी बीमारी होने की सम्भावना है।

2. बाम्बे नैचुरल हिस्ट्री सोसाईटी ने राज्य वन विभाग के सहयोग से रोग अनुसंधान एवं निदान की एक परियोजना के अन्तर्गत पिंजौर के नजदीक एक निदान केन्द्र स्थापित किया है।

3. इस तीन वर्षीय परियोजना के लिए ब्रिटेन सरकार की '' डार्विन इनिशिएटिव फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसिज '' नामक संस्था ने 110 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

Improvement in Voltage

***1318 Shri Balwant Singh Maina :** Will the Chief Minister be pleased to state--whether the State Government has taken any step to improve the voltage profile in the State, if so, the result thereof ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): एक विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

प्रसारण एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करके राज्य में वोल्टेज प्रोफाईल में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठा कर एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया गया है।

(1) पिछले 35 वर्षों के दौरान 37 नये ग्रिड उपकेन्द्र चालू किए गए हैं। वर्तमान 164 उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की गई है तथा 706 किलोमीटर प्रसार लाइनें बिछाई गई हैं। विस्तृत विवरण का निम्न प्रकार से अवलोकन किया जा सकता है: –

वर्ष	220 के०वी०		132 के०वी०		66 के०वी०		66 के० वी०		कुल उपकेन्द्र		टी० एल० कि० मी०	निवेश (रुपए करोड़ों में)
	नये	वृ	नये	वृ	नये	वृ	न	वृ	नये	वृ		

		ध्व		ध्व		ध्व	ये	ध्व		ध्व		
जुलाई 1999-2000	2	4	—	8	1	6	3	21	6	39	173	71.38
2000-2001	—	3	2	11	—	9	3	21	5	44	147	57.40
2001-2002	—	2	1	9	6	3	5	14	12	28	253	68.20
2002-2003 फरवरी तक	3	4	5	16	2	12	4	21	14	53	133	120.51
जुलाई 99 से फरवरी 03 तक	5	13	8	44	9	30	15	77	37	164	706	317.49

(2) हाई टैन्शन (एच०टी०) तथा लो टैन्शन (एल०टी०) कपैसीटर बैंकों की 1300 एम०वी०ए०आर० क्षमता प्रणाली में जोड़ी गई है।

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त 75 नं० नये ग्रिड उपकेन्द्र पर सहायक लाइनों के साथ निर्माण तथा 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 55 नं० वर्तमान उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि करने का कार्य चल रहा है जो अगले वर्ष के अन्दर पूर्ण हो जाएगा। विवरण का निम्न प्रकार से अवलोकन किया जा सकता है: –

श्रेणी	नए उपकेन्द्र (सं०)	क्षमता वृद्धि (सं०)
220 के०वी०	6	8
132 के०वी०	26	15
66 के०वी०	13	12
33 के०वी०	30	20
योग	75	55

(4) वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए एक वृहद कार्यक्रम शुरू किया गया है। द्विभाजिता त्रिभाजित किए गए तथा द्विभाजित 7 त्रिभाजित किए जाने वाले प्रस्ताव ओवर लोडिड 11 के०वी० फीडरों का विवरण निम्न प्रकार से दिया जाता है: –

अवधि	वर्तमान ओवर लोडिड 11	द्विभाजन के खाद 11 के०वी०

	के०वी० फीडरों की संख्या	फीडरों की संख्या
जुलाई 1999–03	89	247
प्रस्तावित	282	688

राज्य में वोल्टेज प्रोफाईल के सुधार का परिणाम

1. राज्य में क्षमता वृद्धि करने तथा प्रसार एवं वितरण प्राणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए चलाए गए कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की अच्छी किस्म देने और वोल्टेज प्रोफाईल में सुधार हुआ है। राज्य में विभिन्न स्थानों पर 15 प्रतिशत तक वोल्टेज प्रोफाईल में सुधार होना सम्भव हुआ है।

2. टी० एण्ड डी० हानियों में कमी आना। हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (एच०ई० आर०सी०) द्वारा किए गए गणना के अनुसार पिछले दो वर्षों में 4.44 प्रतिशत हानियों में कमी आई है।

3. वोल्टेज के सुधार के साथ साथ उपभोक्ताओं तक बिजली आपूर्ति की अच्छी किस्म में सुधार आया है जिसके परिणाम स्वरुप उपभोक्ता की सन्तुष्टी में वृद्धि हुई है।

4. नए प्रसार एवं वितरण कार्यों के परिणाम स्वरूप प्रणाली में ट्रिपिंग्स तथा ब्रेक डाऊन क्षेत्र में काफी कमी आई है।

5. वितरण ट्रांसफार्मरों के क्षति ग्रस्त हेने की दर वर्ष 1998–99 में 33.77 प्रतिशत थी जो चालू वित्तिय वर्ष के दौरान 12.03 प्रतिशत कम हो गई है।

Repair of Roads

***1348 Rao Narender Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to repair the following roads :-

1. from Narnaul to Mandhana upto Haryana Boundary via Kajinda, distict Mahendergarh ;

2. from Narnual to Mandhana upto Haryana Boundary via Seka, district Mahendergarh ;

3. from Dhani Faizabad to Niwaznagar distict Mahendergarh ;

4. from Mandlana to Hazipur upto Haryana Boundary district Mahendergarh ; and

5. from Lehroda to Luni Saluni district Mahendergarh.

(b) if so, the time by which these roads are likely to be repaired?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला):

(क) हां, श्रीमान जी।

(ख) इन सड्कों की मुरम्मत वर्ष 2003—04 में किये जाने की संभावना है।

Construction of Bye Pass in Jhajjar City

***1331 Shri Daryao Singh :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under construction of the Government to construct a bye-pass in Jhajjar City; if so, the time by which it is likely to be constructed ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): हां, श्रीमान जी। वर्तमान स्थिति में समय निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को इस बाई—पास के निर्माण के लिए सहमत होना है।

Releasing of Tubewell Connections

***1361 Shri Ramesh Rana :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the State Government has taken any steps to accelerate the pace for the release of new tubewell connections ; if so, the details there of ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): हां, श्रीमान जी। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान नये नलकूप कनैक्शनों को तेजी से जारी करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं आरम्भ की गई—

(क) केबल तथा एक पोल कनैक्शनों के लिए तत्काल योजना मई, 2000

(ख) एच०टी ० कनैक्शन देने के लिए तत्काल योजना '' अपना ट्रांसफार्मर अपनाइये '' सितम्बर, 2000।

(ग) ट्रांसफार्मर पर किसी भी भार को ध्यान न देते हुए केबल तथा एक पोल कनैक्शन देने के लिए तत्काल योजना मई, 2001.

(घ) सभी लम्बित पडी टैस्ट रिपोर्टों तथा आवेदनों को निपटाने के लिए 20,000 रुपये जमा 7,000 रुपये एल ०टी ० 'एच ०टी ० लाइन प्रति स्पैन के भुगतान पर नलकूप कनेक्शन देने के लिए दिनांक 28 – 9 – 2001 से योजना आरम्भ की गई।

Funds for Centraly Sponsored Scheme

***1389 Shri Pawan Kumar Diwan :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether the State Govt has received Additional funds and foodgrains from the Govt. of India under Sampuran Grameen Rozgar Yojna (SGRY) and Sawam Jayanti Gram Swarozgar Yojna (SGSY) during 2002-2003 ? if so, the details thereof ; and

(b) the positon of Haryana State in the implementation of major Centerally Sponsered Rural Development at the National level during the year 2001-2002, together with the total funds available and funds spent under the schemes during the said period ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला):

(क) हां, श्रीमान जी।

राज्य सरकार को 2002 – 2003 (जनवरी, 2003 तक) के दौरान की थत योजनाओं के अन्तर्गत भारत सरकार से 1457. 45 लाख रुपये की अतिरिक्त निधियां त था 57664 मीट्रिक टन गेहूँ प्राप्त हुआ है। ब्यौरा निम्न प्रकार से है: –

योजना	अतिरिक्त निधियां (रुपये लाखों में)	अतिरिक्त अनाज (मीट्रिक टन में)
सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	1309.14	57664
स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना	148.31	
	1457.45	57664

(ख) वर्ष 2001 –2002 के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा राज्य ने केन्द्र द्वारा मुख्य प्रायोजित योजनाओं जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे ० जी०एस०वाई ०), सुनिश्चित रोजगार योजना (ई ० ए ० एस ०) स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व– रोजगार

योजना (एस ० जी ०एस ० वाई ०) तथा इन्दिरा आवास योजना (आई ० ए ०वाई ०) के कार्यान्वयन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कथित वर्ष के दौरान 10621.58 लाख रुपये की कुल निधियां उपलब्ध थीं, जिनमें से 9312. 25 लाख रुपये खर्च किये गये।

Number of Persons in Women's Hockey

***1301 Shri Padam Singh Dahiya : Will** the Chief Minister be pleased to state the number of persons from Haryana who represented the Country in the Women's Hockey event during Commonwealth Games and Asian Games in 2002 ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): वर्ष 2002 में राष्ट्रमण्डल खेलों तथा एशियन खेलों के दौरान महिला हाकी खेल में हरियाणा राज्य की निम्नलिखित 4 महिला खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया

1. प्रीतम सिवाच 2. सुमन बाला 3. ममता खरब 4. सीता गुसाई

Atrocities Committed on Women

***1271 Shrl Nafe Singh Rathi :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the yearwise number of cases of atrocities committed on women registered in the State during the last 10 year ; and

(b) whether the Government intends to include the

domestic violence of Govt. employees as miscounduct in the service pales ?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला):

(क) वांछित सूचना सदन के पटल पर रखी जाती है। (ख) हां, श्रीमान् जी।

विवरण

अपराध का शीर्ष	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
दहेज हत्या	181	222	211	199	233	275	270	260	264	243
दहेज प्रताड़ना	351	439	492	554	614	1056	1368	1285	1514	1562
बलात्कार	229	254	310	358	399	355	376	411	398	363
अपहरण/अपनयन	211	252	280	299	323	388	377	309	310	298
छेड़छाड़	319	399	447	463	451	523	495	551	470	432
कुल	1291	1566	1740	1872	2020	2597	2886	2816	2956	2898

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Cancer Patient

142 Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister for Health be pleased to state whether any survey has been conducted to detect the patients of Cancer in the State during the year 2001-2002, if so, the number thereof ?

स्वास्थ्य राज्य मन्त्री (डॉ० मुनी लाल रंगा): जी नहीं, श्रीमान् जी।

Common Latrines

143 Shri Karan Singh Dalal : Will the Minister of state for Urban Development be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct common latrines in the following Areas of City Palwal, district Faridabad

(i) Line Pura

(ii) Kasbamohalla

(iii) Daya Basti

(iv) Jaindi Pura

(v) Seikh-Pura

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुभाष गोयल):

1 लाइनपुरा मौहल्ला में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करने का प्रस्ताव नगर परिषद् के विचाराधीन है।

2. कस्बा मौहल्ला में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है और नमी निरोधक परत स्तर तक पूर्ण हो चुका है।

3. दया बस्ती में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

4. जैंदी पुरा में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण के लिए प्रस्ताव नगर परिषद् के विचाराधीन है।

5. शेखपुरा में सार्वजनिक शौचालय के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

Ban on Registration of Deeds

***144 Shri Karan Singh Dalal :** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether it is a fact that there is ban on the Registration of deeds in the State ?

नगर तथा ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह): जी, नहीं।

Bonding of Sugarcane

146 Shri Karan Singh Dalai : Will the Minister for Co-operation be pleased to state :

(a) the total quantity of sugarcane bonded by the Co-operative Sugar Mill, Palwal for the year 2002-2003 ;

(b) whether the Sugar Mill is able to crush all the bonded sugarcane of the area ;

(c) whether any sugarcane of the farmers has been left unbonded ; if so, the quantity thereof ?

सहकारिता मंत्री (श्रीकरतारसिह भडाना):

(क) 2541 लाख क्विंटल

(ख) जी हां, श्रीमान

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(The Hon'ble member requested to the Hon'ble Speaker on 10-3-2003 in regard to withdrawal of his Unstarred Assembly Question No. 156. The Hon'ble Speaker acceded to the request of the Honble member on 11-3-2003, in file *No. Q.B. 14A/Un-std / March, 2003 to withdraw the Unstarred Question No. 156). (*with the branch)

अनुपस्थिति की अनुमति

Mr. Speaker Hon'ble Members, I have received a FAX message at 4.30 P.M. on 10th March, 2003 from Rao Inderjit Singh, M.L.A., which is as under :

"Dear Kadian Sahib,

May I request you to kindly excuse my absence from the Vidhan Sabha due to my being sick on account of my Viral Fever.

With regards,

Yours sincerely, Sd/-

(RAO INDERJIT SINGH)

Mr. Speaker : Is it the pleasure of the House that the leave of absence be granted to Rao Inderjit Singh, M.L.A. to remain absent for 10th, 11th and 12th March, 2003 during the current Budget Session of Haryana Vidhan Sabha.

Question is —

That permission for leave of absence be granted

The Motion was carried.

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव/विभिन्न मामले उठाना

कैप्टन अजय सिंह यादवः सर, मेरे दो कॉल अटैंशन मोशंज थे उनका क्या हुआ। (शोर एवं विघन)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियानः सर, मेरा भी एक काल अटैंशन मोशन बेरी कास्टीच्यूऐसी की सड्कों के बारे में था। (शोर एवं विष्य)

श्री कर्ण सिंह दलालः सर, मेरा भी एक काल अटैंशन मोशन था जिसमें मैंने लिखा है कि कैंसर की बीमारी से लोग मरते जा रहे हैं। उसका क्या हुआ? (शोर एवं विघ्न)

श्री अध्यक्षः आप सभी बैठिये। मैं सभी के काल अटैंशन मोशज के बारे में बता देता हूँ। कैप्टन अजय सिंह यादव का एक काल अटैंशन मोशन डी०एस०पी० की पोस्ट को एलाईड सर्विसिज एग्जामिनेशन में इंक्लूड करने के बारे में और दूसरा डिफैंस स्टडीज/ मिलिट्री सर्विसिज को ऑप्शनल सब्जैक्ट को ऐक्सक्लूड करने के बारे में था, ये दोनों डिस– अलाउ कर दिये गए हैं। इसी प्रकार से श्री कर्ण सिंह दलाल का एक काल अटैंशन मोशन जो कैंसर की बीमारी के फैलने के बारे में था, वह भी डिस–अलाउ हो गया है। इसी प्रकार से श्री रघुबीर सिंह कादियान

जी का एक काल अटैंशन मोशन बेरी कांस्टीच्यूऐंसी में रोड्स की रिपयेर के बारे में था, वह डिस– अलाउ कर दिया गया है।

श्री चन्द्र भाटिया: अध्यक्ष महोदय, मैं एक सार्वजनिक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाते हुए कहना चाहता हूँ कि चहल आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाही करने पर और उसे सार्वजनिक करने पर रोक लगाने के लिए बंसी लाल जी हाई कोर्ट में गए हैं। आज अखबारों में ऐसी खबर छपी है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूँगा कि वे एक लोक महत्व के मुद्दे पर जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं होने देना चाहते। उनकी नीयत साफ नहीं है। मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि इस विषय पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, यह जन–हित से जुड़ा हुआ बड़ा अहम मुद्दा है। इसका सम्बन्ध चौधरी बंसी लाल जी से है। उनको इस वक्त हाउस में होना चाहिए था। लेकिन वे चहल आयोग की रिपोर्ट से बहुत डरे हुए हैं, बल्कि कल से डरे हुए हैं। (विघन) जो आदमी गलत काम करता है उसको आगे आने वाली कठिनाईयों से दिक्कत का भय बहुत रहता है। चौधरी बंसी लाल जी ने पूरे प्रदेश को शराबबंदी की आडू लेकर के बर्बाद कर दिया। अगर मैं इसका विस्तार से फिर उल्लेख करूंगा तो हाउस का बहुत समय बर्बाद हो जायेगा। जो परिस्थितियां उस समय थीं, उससे पूरा सदन ही नहीं पूरा प्रदेश ही अवगत है और सरकार की कोई दुर्भावना नहीं थी।

चौधरी बंसी लाल जी की तरफ से गठित आयोग की रिपोर्ट आई और ऐसा अंदेशा था कि उस रिपोर्ट में सरकार के खिलाफ निर्णय था इसलिए उस रिपोर्ट को सदन के पटल पर नहीं रखा गया। उस वक्त चौधरी भजन लाल जी और हम लोग बड़ा जोर लगाने वाले थे कि इसको रखा क्यों नहीं गया लेकिन परिवर्तन के बाद जब हमारी सरकार बनी तो हमने जनहित के मुद्दे को ध्यान में रखकर ताकि लोगों को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया जा सके कि उसके पीछे कारण क्या है कौन दोषी है, सरकार को कितना आर्थिक नुकसान हुआ, इसकी वजह से कि कितना क्राईम बढ़ा है? प्रदेश की जो जर्जर हालत हुई है उस पर सरकार निर्णय ले सके इसके लिए हमने चहल आयोग का गठन किया और इस चहल आयोग को फेस करने की बजाय गवाहों को विन ओवर करने के प्रयास किए गए और हर–हबा इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट तकरीबन तैयार हो गई है और शायद सरकार के पास भी आ गई हो। उसके बारे में वे फिर कोर्ट में गए और एक अदालत में उस पर स्टे मिल गया। सरकार ने उसके ऊपर अपील की और इस अपील के मुताबिक यह निर्णय लिया गया है। पहले वाला जो फैसला था वह ठीक नहीं था और रिपोर्ट सरकार प्रस्तुत करने जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी इस सदन में कहा था कि इसको हम लीगली एग्जामिन कर रहे हैं। कल चौधरी बंसी लाल जी चले गए थे आज के अखबारों में खबर छपी है। हम अदालत का ऐहतराम करते हैं। हम जुडिशियरी का सदा इज्जत और सम्मान करते रहे हैं। जुडिशियरी इस मामले में क्या निर्णय दे, यह

अलग बात है लेकिन हम इसको लीगली एग्जामिन करके उसको पहले कैबिनेट में भेजेंगे उसके बाद रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। हमारी सरकार की पालिसी है कि जो भी आयोग मुकर्रर किया जाए उस आयोग की रिपोर्ट फौरन से पेशतर रखी जाए। कांग्रेस की हालत तो हमेशा ऐसी रही है कि इन्होंने हमेशा आयोगों का गठन किया लेकिन उन आयोगों की कोई भी रिपोर्ट कभी भी सदन के पटल पर नहीं रखी। हमने तो दुलीना काण्ड की रिपोर्ट ज्यों ही आई, उसे कोई भी देरी किये बिना सदन के पटल पर रख दिया। मैंने इस सदन में यह भी कहा था कि हम इस रिपोर्ट को लीगली एग्जामिन कर रहे हैं। बंसी लाल जी इससे बचने का प्रयास कर रहे हैं। कोर्ट क्या निर्णय ले, कोर्ट उनको क्या दे यह तो कोर्ट पर निर्भर करता है मैं इसमें नहीं जाना चाहूंगा लेकिन हम इसको लीगली एग्जामिन करके फिर कैबिनेट के माध्यम से सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे (विघन)

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात तो सुनें। (विघन)

श्री अध्यक्षः दलाल साहब, आपका यह नोटिस 10 बज कर 34 मिनट पर मिला है आप बात की जिरह पहले करते हैं इसलिए आप अभी बैठें (विघन) यह आप का अण्डर कसिड़ेशन है, बैठिए (विघन) दलाल साहब, अभी आप बैठें। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, अब आप बजट पर बोलें। (विम्न) हुड्डा साहब, बजट पर आप अपनी बात शुरू करें (विघन)दलाल साहब, आप बैठें।

वर्ष 2003 – 2004 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा

Mr. Speaker : Hon'ble Members, now, general discussion on the Budget Estimates for the year 2003-2004 will take place. Shri Bhupinder Singh Hooda may speak.

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। (विघन)

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, आप बोलना शुरू करें (विघन) आप उनकी बात न सुनें मेरी बात मानें और आप बोलना शुरू करें (विघन) वे कैसे कह सकते हैं कि आप बैठें। He cannot issue direction to you (विघन) उनकी डायरेक्शन आप क्यों मान रहे हैं (विघ्न) आप अपनी बात शुरू करें। दलाल साहब, आप बैठे। (विघ्न)

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, दलाल सहाब, प्वाटयंट ऑफ ऑर्डर पर खड़े हैं इसलिए आप उनकी बात मेहरबानी करके सुनें (विघन) प्वायंट ऑफ ऑर्डर रखना मैम्बर का अधिकार है। आप उनकी बात सुन लें और अगर ठीक न हो तो उनका प्यायंट ऑफ ऑर्डर रह कर दें। (विघन)

श्री अध्यक्ष: चौधरी भजन लाल जी, आप बैठें (विघन) हुड्डा साहब, आप बजट पर बोलें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आप इनको बिठाएं। (विघन)

श्री अध्यक्षः राम किशन फौजी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। हुड्डा साहब, आप बजट पर बोलें।

श्री राम किशन फौजीः ....

श्री अध्यक्षः फौजी जी, आप अपनी सीट पर बैठें। इनकी कोई भी बात रिकॉर्ड नहीं की जाए। (विघ्न) आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। आप बिना इजाजत के बोलने के लिए खड़े हो जाते हैं। (विघन) बैठिए बैठिए।

श्री राम किशन फौजीः ....

श्री अध्यक्षः फौजी जी, आप अपनी सीट पर बैठें। आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं की जा रही है। (विघ्न) कर्ण सिंह दलाल जी, आप भी अपनी सीट पर बैठें। (विघन)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (किलोई): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को जो इन्होंने बजट पेश किया है उसमें एक बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिस प्रकार से इन्होंने कास्मैटिक आकडे सदन में रखे हैं और बजट पेश करने पर इनकी पार्टी के लोगों ने तालियां थपथपाई उसके लिए इनकी होशियारी के लिए

मुबारिकबाद देता हूँ। (विघन) ये अपनी जगलरी में कामयाब हैं, होशियार हैं। लेकिन बजट को पढ़ने के बाद और उसमें दिए हुए सारे आकड़ों का आकलन करने के बाद उसमें क्या निकला है उस बारे में मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। वित्त मंत्री जी ने पिछली बार भी बजट पेश किया था और उसमें इसी प्रकार के कर मुक्त बजट का आश्वासन दिया था। अब की बार भी बजट में यही बात कही गई है। जब बजट का आकलन करते हैं तो उससे पता चलता है कि हम किस तरफ, किस दिशा में जा रहे हैं हमारी फाईनैशियल पोजीशन कहां जा रही है। मैं समझता हूँ कि यह जो बजट पेश किया गया है उससे यह प्रदेश दिवालियेपन की तरफ जा रहा है। इस प्रदेश पर 32 हजार करोड़ रुपए की लॉयबिलिटी का अमाउन्ट है। यह ठीक है कि इस सरकार ने देवीरुपक कार्यक्रम शुरू किया है लेकिन आज जो बच्चा हरियाणा में पैदा होगा वह 15 हजार रुपए का कर्जा लेकर पैदा होगा। (विघन) अध्यक्ष महोदय, अगर मैं कहीं पर गलत हूँ तो ये मुझे उस प्यॉयंट पर ठीक कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने लॉयबिलिटी 20 हजार 695 करोड़ रुप्रए की शो की है। जब ये सरकार में आए थे तो यह लॉयबिलिटी 12 हजार करोड़ रुपए की थी। यही लॉयबिलिटी 1996 में 6 हजार करोड़ रुपए की थी। अगर इसमें रेशो ऑफ इन्ट्रस्ट पेमेन्ट ऑफ रैवेन्यू देखें तो यह 1999 में 5 प्रतिशत ही था। अब यह बढ़कर 23 प्रतिशत हो गया है। अगर हम इसको देखते हैं तो आज हम दिवालिया होने के कगार पर खड़े हैं। हर बार ये जो प्लअल प्लॉन देते हैं और रिवाइज्ड छह और आर ई में

21 सौ करोड़ रुपये दिए हैं और वर्ष 2000– 2001 के बजट में जब हमने आकलन किया तो 76.6 करोड़ रुपये नॉन प्लान में खर्चा था और 324 करोड़ प्लॉन में खर्चा था। 2001 – 2002 में यह 78. 3 और 21 .7 था जबकि 2002– 2003 में यह 80.1 और 19.9 था। अध्यक्ष महोदय, अब जो कल इन्होंने बजट पेश किया है उसमें इन्होंने नॉन प्लॉन में 78. 3 दर्शाया है और प्लॉन में 21.3 दिखाया है। पिछले बार के तुजुर्बे के आधार पर, अनुभवों के आधार पर जिस प्रकार से इनका ट्रैंड चल रहा है उसको देखते हुए यह रेशो 82 तथा 18 हो जाएगी। पिछली बार के मुकाबले अगर आप देखें तो इस बार नॉन प्लान की रेशों में बढ़ौत्तरी है और अगर बढ़ौत्तरी है तो फिर विकास कहां से होगा, कहां हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी? अध्यक्ष महोदय, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसा इन्होंने कहा कि 20695 करोड़ रुपये की इनकी देनदारी है और 12000 करोड़ रुपये के करीब जो कॉरपोरेशंज वगैरह हैं, उनकी गारंटियां हैं इस तरह से 32 हजार करोड़ रुपये के करीब हमारी लॉयबिलिटीज बनती हैं। अध्यक्ष महोदय, 1999–2000 में 1800 करोड़ रुपये का एनुअल प्लॉन था जो कि वर्ष 2001 –2002 में 1811 करोड़ रुपये का हुआ और वर्ष 2002 –2003 में यह 1800 करोड़ रुपये का हो गया। इसमें अगर इन्क्रलेशन का हिसाब भी लगा लें तो इनके एनुअल प्लॉन की रियल वैल्यू 1400 करोड़ रुपये की ही आएगी। इसका मतलब क्या है? अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने बजट पेश किया है उसमें एनुअल प्लॉन 2100 करोड़ का लिया गया है तो इसका मतलब इससे ज्यादा यानी 2221 करोड़ रुपये

तो ब्याज का भुगतान है। जिस आर्थिक स्थिति से हम गुजर रहे हैं उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी? इन्होंने कहा कि मैं कर मुक्त बजट दे रहा हूँ। पिछली बार भी इन्होंने यही कहा था लेकिन उसके बाद क्या किया? कई तरह के कर लगाए गए। हाउस टैक्स में बढ़ौतरी इन्होंने की और जिस प्रकार से बिजली के रेट बड़े हैं वह सबको पता ही है। अध्यक्ष महोदय, हमारा पड़ोसी प्रदेश पंजाब है उसके मुकाबले में भी हमारे बिजली के रेट ज्यादा हैं इसी तरह से चण्डीगढ़ के डोमैस्टिक बिजली के रेट के मुकाबलें में भी हमारे रेट ज्यादा हैं। इन्होंने ट्रैक्टर्ज की रजिस्ट्रेशन में भी फीस बढ़ायी है और ट्रॉली पर भी टैक्स लगाया है। अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति, अपने घर से, अपने खेत से अगर मिट्टी भरकर ले जाएगा तो उस पर उसकी ट्राली पर टैक्स लगेगा जबकि ट्रैक्टर उसका है, ट्रॉली उसकी है और कस्सी भी उसकी ही है लेकिन इन्होंने उस पर भी टैक्स लगा दिए। इसी तरह से वाटर चार्जिज बढ़ा दिए लोकल एरिया डिवैल्पमैंट चार्जिज लगा दिए। अध्यक्ष महोदय, कोई भी वेलफेयर स्टेट हो उसमें दो महकमें ऐसे होते हैं जिनकी अहम भूमिका –होती है ये हैं शिक्षा एवं स्वास्थ्य। जिस तरह से इन्होंने शिक्षा का कम्यूनलाइजेशन किया उससे एक गरीब आदमी के बच्चे को इस प्रदेश में डॉक्टर और इंजीनियर बनने का मौका नहीं मिलेगा। इसी तरह से पंजाब के मुकाबले में हरियाणा में स्टैम्प डयूटी भी ज्यादा है। पंजाब में स्टैम्प डयूटी पांच परसैंट है जबकि हरियाणा में दस परसैंट है। इसी तरह से इन्होंने टोल टैक्स भी ज्यादा लगा दिया, ड्राईविंग लाईसैंस फीस

भी बड़ा दी, मोटर व्हीकल्ज रजिस्ट्रेशन फीस भी बढ़ा दी, मैक्सी कैब पर लगने वाली फीस भी बढ़ा दी और इसी तरह से हुड्डा के प्लॉटस पर भी स्टैम्प डयूटी बढा दी है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने वैट सिस्टम लागू करने की बात भी कही है इसका क्या नतीजा होगा। मैंने तो अखबारों में पढ़ा है। मैं कोई इकोनोमिस्ट नहीं हूँ। इसमें केन्द्र सरकार अभी तो आपको मदद देगी लेकिन इससे प्रदेश का और प्रदेश के आम आदमी का तो लौस होगा? मान लें एक गरीब आदमी अगर समोसा भी बनाता है तो उसको आप देखिए कि कहां कहां टैक्स देना पड़ेगा। उसको मैदे पर भी टैक्स देना पड़ेगा, घी पर टैक्स देना पड़ेगा और उसके बाद जब उसका समोसा बन जाएगा तो उस पर भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। हलवाई घी पर टैक्स देगा, मिठाई जो बनेगी उस पर भी टैक्स देगा। उससे स्टेट को क्या फायदा होने वाला है? मैं समझता हूँ कि हम और कमजोर हो जाएंगे? बिजली की बात बार–बार कहते हैं बड़े–बड़े दावे पेश किए कि 792 मेगावाट बिजली क्षमता इन्होंने बढ़ाई है लेकिन जब तक ट्रांसमीशन लौस पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक बिजली की लाभदायक जनरेशन कभी भी नहीं हो सकती। ट्रांसमीशन लौस 1998– 99 में 32.56 परसैंट थे, 2001 –02 मैं 40 परसैंट पर पहुंचे हैं यह सी०ए०जी० की रिपोर्ट में भी है। अब भी मैं समझता हूँ कि ये कामयाब नहीं हुए हैं। इस बार भी 40 परसैंट के करीब लाइन लौसिज गए होंगे। रैगुलेटरी अथोरिटी ने ट्रांसमीशन लौसिज 15.5 परसैंट निर्धारित किया है और इस प्रकार से बिजली का मुनाफा जो ये दिखाते हैं उसमें भी हमें ज्यादा

लागत करनी पड़ रही है, उसमें भी घाटा है। शिक्षा की बात इन्होंने कही है जैसा मैंने कहा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा ये अहम महकमें हैं। वैलफेयर स्टेट के लिए आम आदमी के लिए सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है। 1880 करोड़ रुपये का कुल व्यय इन्होंने प्रस्तावित किया है उसमें से बिल्डिंग्ज के लिए 3 करोड़ 5 लाख रुपया रखा है। आज हमारे प्रदेश में बहुत सारे ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जिनमें 5 कमरे, एक कमरा हैड टीचर के लिए एक स्टॉफ रूम, एक स्टोर रूम और एक वैलफेयर रूम है, यह जरुरी होते हैं लेकिन ऐसे बहुत सारे प्राइमरी स्कूल हैं जो कि 4 कमरों में चल रहे हैं। कई ऐसे प्राइमरी स्कूल्ज भी हैं जो बिना बिजली के चल रहे हैं और आगे आप कंप्यूटर लगाने की सोच रहे हैं। स्टूडैण्ट्स टीचर्स की रेशो 1.40 से बढ़ाकर 1:60 करने का सरकार विचार कर रही है इस बारे में चाहे वह कोठारी कमीशन की रिपोर्ट है, चाहे वह डॉ० राधाकृष्णन कमेटी की रिपोर्ट है। किसी भी रिपोर्ट में स्टूडैण्ट टीचर की रेशो 1: 40 से ज्यादा कभी जायज नहीं ठहराई। अब ये सरप्लस टीचर डिक्लेयर करेंगे जैसी चर्चा है ऐसी कोई स्कीम नहीं थी चाहे स्टॉफ सरप्लस है, विद्यार्थी पढ़ नहीं रहे इससे क्वालिटी ऑफ ऐजूकेशन गिरेगी और वह 1:60 रेशो से और गिरेगी। जो आप चाहते हैं केन्द्र से जो सर्वशिक्षा अभियान लेकर आए हैं उस पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है इसका क्या कारण है? क्यों आपकी क्वालिटी ऑफ ऐजुकेशन घट रही है जबकि उसके ऊपर आप जो व्यय कर रहे हैं वह बढ़ता जा रहा है। पिछली बार चर्चा थी कि आप सरप्लस पोस्टस क्रिएट करेंगे

और बजाय उसके आपने 5400 पद खत्म किए और अब की बार के बजट में 20,000 नयी रिकुटमैंट्स करने जा रहे हैं। आपने गोल्डन हैंड शेक जैसी कोई स्कीम बजट में नहीं दी है कोई आदमी 15 साल या 20 साल तक सरकारी नौकरी करे और उसको आल ऑफ–ए–सडन आप कहें कि घर चले जाओ, यह उचित नहीं है। गोल्डन हैंड शेक जैसा कोई प्रावधान आप उसके लिए नहीं कर रहे हैं। अब मैं मेडिकल के बारे में कहना चाहूँगा। स्वास्थ्य के बारे में कहना चाहूँगा। आपने उसका कॉमर्शियलाइजेशन बढ़ा दिया है। प्रदेश में 63 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 403 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 2299 हैल्थ सब–सैंटर हैं जो नागरिकों के स्वास्थ्य की देख– भाल करते हैं। नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल कैसे होगी। डॉक्टर को दिखा दिया, गरीब आदमी डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर का प्रबन्ध तो उसके लिए आपने कर दिया लेकिन आगे दवाई का प्रबन्ध भी तो करें। लेकिन अगर आप बजट में देखें तो पूरे बजट में जो व्यवस्था की है कि दवाइयों और मैटीरिटल और मैडीसिन पर खर्च के लिए केवल मात्र तीन करोड़ 20 लाख रुपये का प्रावधान किया है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रति व्यक्ति डेढ़ रुपये की दवाई आती है जबकि आज डेढ़ रुपये में कोई सिर के दर्द की गोली भी नहीं देता। इसका मतलब यह हुआ कि स्टेट के वैल्फेयर की तरफ गम्भीरता से आपने कोई कदम नहीं उठाया। तीसरी चर्चा आपने बड़े जोर शोर से ट्रांसपोर्ट विभाग के बारे में की कि हमने रोडवेज की नई बसें ला दी हैं इतना घाटा कम कर दिया है। लेकिन फाइनैंशियल मैनेजमेंट क्या है, घाटा

और भी कम हो सकता है। लेकिन अगर आपकी फाइनैंशियल मैनेजमेंट प्रोपर हो। ट्रांसपोर्ट महकमें में 30 प्रतिशत खर्चा डीजल पर आता है। स्थूल एफिशिएंसी को अगर देखा जाये तो रोडवेज में 4.44 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से नार्म्स फिक्स कर रखे हैं जबकि राजस्थान में स्टेट ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन ने 4.78 किलोमीटर प्रति लीटर के नॉर्म्स फिक्स कर रखे हैं जबकि टैस्ट चौक दर्शाते हैं कि एक डिपो से दूसरे डिपो तक की 4.09 से 4. 01 के बीच में रेन्ज निश्चित कर रखी है। नॉर्म्स के हिसाब से अगर देखा जाये तो राजस्थान में भी वही बसें चल रही हैं क्या हमारी बसों की क्वालिटी खराब है। इसमें भी करोड़ो रुपये का फर्क पड़ सकता है। अगर राजस्थान के नॉर्म्स यहां पर लागू किये जायें तो डीजल की बचत हो सकती है और इससे काफी फर्क पड़ेगा। राजस्थान की बराबरी तो आप करके देखें। (विघन) मेरे दिमाग में तो यही बात है कि राजस्थान में क्या क्राइटेरिया और हमारे यहां क्या क्राइटेरिया है? डीजल वितरण तो बसो में वही है फिर हमारे यहां कंजप्शन ज्यादा क्यों है? डीजल की खपत में कटौती करने के आप तरीके ढूंढें। असल में यह बजट hides high reveals less. इंवेस्टमैंट की जहां तक बात है पी०एस०यूज० के बारे में जो हमारी सैक्टरवाईज विभिन्न संस्थाओं, कम्पनीज और कारपोरेशन जिनमें कोआपरेटिव वगैरह भी शामिल हैं, के निवेश की स्थिति देखें 1998—99 में 2224 करोड़ रुपये के मुकाबले में अब निवेश 2843 करोड़ रुपये के करीब है जबकि रिटर्न घटा है। हमारी लागत 221 करोड़ रुपये से घटकर 1.81

करोड़ रुपये तक आ गई है। इन्वैस्टमैंट पर रिटर्न .10 से घटकर .06 आ गई है बोरोइंग पर जबकि हम इंट्रस्ट 11 प्रतिशत देते हैं चाहे हाई कोस्टिंग बोरोइंग बढ़ रही है लेकिन हमारी फाइनैंशियल मैनेजमेंट कमजोर पड़ती जा रही है और मुनाफा घटता जा रहा है। तीसरी आपने इम्प्लायमेंट के बारे में चर्चा की। पिछले बार आपने 5400 के करीब रिक्त पद ऐबोलिश किये हैं। आप बताएं कि भार बढ़ रहा है या घट रहा है? जबकि आपने वादा किया थाकि हम 70 हजार नई नौकरियां देंगे। आज चर्चा हुई कि 20 हजार नई नौकरियां दी गई। मुख्य मंत्री जी ने भी कहा था कि हम विदेशी दौरों पर गए आपने कहा कि उससे पूंजी निवेश हुआ और इतने लोगों को रोजगार मिल गया। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि रोजगार संख्या इम्पलॉयमैंट से देखें तो 31—12—2001 में 6,63,775 बेरोजगार थे जो आज बढ़कर 8,20,000 हो गए हैं। 20 प्रतिशत बेरोजगारों में वृद्धि हो गई है। आप पढ़े—लिखे बेरोजगार इसमें से निकालें तो 4,94,000 से बढ़ कर 5,96,000 हो गए हैं यानि 1,00,000 पढ़े लिखे बेरोजगार और बढ़ गए हैं। (विघ्न) मैं आपके दावों की बात कर रहाहूँ। आप कहतेहैं कि हमने लाखों लोगों को रोजगार दे दिया। जबकि बेरोजगारी बढ़ रही है घट नहीं रही, आपने बजट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया है जो बेरोजगारों को रोजगार दे सके इसलिए आप इस पर ध्यान दें।

11.00 बजे

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): आप इस बारे में सुझाव दें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अनइम्पलॉयमैंट अलाऊंसिज दें, बेरोजगारी भत्ते दे। (विघ्न) हमने रोहतक में मुख्य मंत्री जी का भाषण सुना (विघ्न) जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे खजाने लबालब भरे पड़े हैं मांगने वाले नहीं हैं, बजट देखें तो कर्ज से दबादब भरा पड़ा है (विघन) सैन्ट्रल स्पोंसर्ड कई स्कीमें होती हैं। अभी जो केन्द्र सरकार ने बजट पेश किया उन्होंने 'Implementation of Budget Announcement' का एकडॉक्यूमैंट साथ दिया इसमें तीन–चार स्कीमें थीं, एक ऐक्सीलरेटेड रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम की स्कीम थी उसमें हमने क्या कोई लाभ कमाया और हमें क्या कोई फायदा हुआ जबकि हमें उस स्कीम के तहत इन्ट्रस्ट में प्रदेश को मदद मिल सकती है लेकिन हरियाणा ने अभी तक उसका लाभ नहीं उठाया। दूसरी स्कीम अर्बन रिफॉर्म इन्सेंन्टिव फण्ड (URIF) साढ़े तीन हजार करोड़ की है उसमें उन्होंने Action Completed में कमैंट्स दिए हैं कि 'Consequent to initiative under APRA, APDRP, Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and West Bengal have enacted a legislation on anti-capitalisation. Punjab and Haryana have lesser implementation on it. इस स्कीम का आप भी लाभ उठा सकते हैं। इसी प्रकार से URIF स्कीम की भी बजट में कोई चर्चा नहीं की कि इसके अंतर्गत आपने इस बात का भी कोई लाभ नहीं

उठाया। आज केन्द्र सरकार से हमें जो मदद इस स्कीममें मिल सकती

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कह रहा कि ये अभी जवाब दें। जिस समय ये बजट पर बोलें उस समय जवाब दे दें। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सूखे की बात है, पूरा हरियाणा प्रदेश सूखे की चपेट में रहा। पीछे जब एन०डी०ए० सरकार के कृषि मंत्री हरियाणा में आये थे तब उन्होंने कहा था कि पूरा हरियाणा सूखे की चपेट में है। उन्होंने यह भी कहा कि सूखे से राहत के लिए हरियाणा की तरफ से केन्द्र से कोई क्लेम समय पर नहीं मांगा गया है अन्यथा वे क्लेम देते। अध्यक्ष महोदय, यह बात एन०डी०ए० के कृषि मंत्री जी ने कही थी जिनकी सरकार को मुख्य मंत्री जी भी केन्द्र में समर्थन दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कल एक सवाल के जवाब में कहा गया कि किसानों को छ करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में दिए गये हैं जबकि अखबारों में आपने भी पड़ा होगा कि सोनीपत जिले के एक गांव के किसानों को मात्र एक रुपया, दो रुपया और सात रुपये मुआवजे के रुप में मिले हैं। इससे ज्यादा किसानों का और अपमान क्या होगा। रिवाड़ी जिले में सूखा राहत के लिए 69 हजार रुपये, पानीपत जिले में 56 हजार रुपये सूखा राहत के रूप में दिये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, पूरा प्रदेश सूखे की चपेट में था और केन्द्र की तरफ से हमें कोई राहत नहीं मिली क्योंकि हमारी सरकार ने राहत के लिए मांग ही नहीं की। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त कृषि के बारे में भी

इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। वर्ष 2001 –02 के दौरान कृषि पर कुल व्यय 951 .84 करोड़ रुपये का था और वह अब घटाकर 576 करोड़ रुपये अंकित किया गया है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और बीच में सूखे की चपेट में भी आ गया फिर भी बजट में कृषि के कुल व्यय में कमी कर दी गई। सूखे की चपेट का असर केवल पैदावार पर ही नहीं पड़ा बल्कि किसान का पशुधन जैसे गाय, भैंस आदि भी जो 20– 20 हजार रुपये की कीमत के थे वे आधे दाम पर किसानों को मजबूर होकर बेचने पड़े हैं लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं दी गई। किसी को भी उसमें मदद नहीं मिली। यहां पर हाउस में पानी की चर्चा बड़े जोर–शोर में हुई। सभी ने इस बात को माना और इस बात से मैं भी सहमत हूँ जो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि एस०वाई०एल० हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए एक जीवन रेखा है। इन्होंने एक बात कही, मैंने भी पहले कहा था और आज भी खुल कर कहता हूँ कि यह समय है कि हम सब को एक होकर इस मामले पर लड़ना चाहिए इसके लिए हम तैयार हैं लेकिन आप लोगों की नीयत साफ होनी चाहिए इस मामले में नीयत ठीक नहीं है, इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि केन्द्र की सरकार की भी नीयत साफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज का फैसला आ गया और केन्द्र सरकार को इस एस०वाई०एल० नहर को बनाने के लिए डायरेक्शन देकर बाध्य किया लेकिन केन्द्र सरकार भी ध्यान नहीं दे रही। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि इस नहर पर जल्दी से जल्दी कार्य शुरू किया जाये। अब जो बजट केन्द्र सरकार ने पेश

किया है उसमें एस०वाई०एल० के बनाये जाने वाले हैड में केवल एक करोड़ रुपये रखे हैं जबकि इस पर 700 करोड़ रुपये पहले ही लग चुके हैं। पिछली बार आपने इसके लिए 10 करोड़ रुपये की अनाउंसमेंट की थी। इस बार आपने केवल इसके लिए एक करोड़ रुपये रखे हैं। यह क्या दर्शाता है, आपकी एस०वाई०एल० के बारे में क्या नीयत है। इस मामले में सारे प्रदेश की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इस बारे में मुख्य मंत्री जी की तरफ से कोई सुझाव नहीं . आये, हम सहयोग क्या करें? आपने इस विषय पर पहले सबको भूलवाया था। हमने आपको इसके लिए अधिकृत किया और विधान सभा ने युनानिमसली आपको अधिकृत किया लेकिन एक साल तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। आप भी प्रधान मंत्री जी से मिलकर आये हैं। कोर्ट का फैसला आपके हक में है, लेकिन आपकी तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरे साथियों ने एक सवाल उठाया और कहा कि आप एक बात स्पष्ट करें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो आधार राजीव लौंगोवाल समझौता है, क्या आप उसके हित में हैं या विरोध में। इस बारे में मुख्य मंत्री जी ने कोई

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कह रहा कि ये अभी जवाब दें। जिस समय ये बजट पर बोलें उस समय जवाब दे दें। अध्यक्ष महोदय, जहां तक सूखे की बात है, पूरा हरियाणा प्रदेश सूखे की चपेट में रहा। पीछे जब एन०डी०ए० सरकार के कृषि मंत्री हरियाणा में आये थे तब उन्होंने कहा था कि पूरा हरियाणा सूखे की चपेट में है। उन्होंने यह भी कहा कि

सूखे से राहत के लिए हरियाणा की तरफ से केन्द्र से कोई क्लेम समय पर नहीं मांगा गया है अन्यथा वे क्लेम देते। अध्यक्ष महोदय, यह बात एन०डी०ए० के कृषि मंत्री जी ने कही थी जिनकी सरकार को मुख्य मंत्री जी भी केन्द्र में समर्थन दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, कल एक सवाल के जवाब में कहा गया कि किसानों को छ करोड़ रुपये मुआवजे के रूप में दिए गये हैं जबकि अखबारों में आपने भी पड़ा होगा कि सोनीपत जिले के एक गांव के किसानों को मात्र एक रुपया, दो रुपया और सात रुपये मुआवजे के रुप में मिले हैं। इससे ज्यादा किसानों का और अपमान क्या होगा। रिवाड़ी जिले में सूखा राहत के लिए 69 हजार रुपये, पानीपत जिले में 56 हजार रुपये सूखा राहत के रूप में दिये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, पूरा प्रदेश सूखे की चपेट में था और केन्द्र की तरफ से हमें कोई राहत नहीं मिली क्योंकि हमारी सरकार ने राहत के लिए मांग ही नहीं की। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त कृषि के बारे में भी इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। वर्ष 2001 –02 के दौरान कृषि पर कुल व्यय 951 .84 करोड़ रुपये का था और वह अब घटाकर 576 करोड़ रुपये अंकित किया गया है। हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और बीच में सूखे की चपेट में भी आ गया फिर भी बजट में कृषि के कुल व्यय में कमी कर दी गई। सूखे की चपेट का असर केवल पैदावार पर ही नहीं पड़ा बल्कि किसान का पशुधन जैसे गाय, भैंस आदि भी जो 20– 20 हजार रुपये की कीमत के थे वे आधे दाम पर किसानों को मजबूर होकर बेचने पड़े हैं लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं दी गई। किसी

को भी उसमें मदद नहीं मिली। यहां पर हाउस में पानी की चर्चा बड़े जोर–शोर में हुई। सभी ने इस बात को माना और इस बात से मैं भी सहमत हूँ जो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि एस०वाई०एल० हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए एक जीवन रेखा है। इन्होंने एक बात कही, मैंने भी पहले कहा था और आज भी खुल कर कहता हूँ कि यह समय है कि हम सब को एक होकर इस मामले पर लड़ना चाहिए इसके लिए हम तैयार हैं लेकिन आप लोगों की नीयत साफ होनी चाहिए इस मामले में नीयत ठीक नहीं है, इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं कि केन्द्र की सरकार की भी नीयत साफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज का फैसला आ गया और केन्द्र सरकार को इस एस०वाई०एल० नहर को बनाने के लिए डायरेक्शन देकर बाध्य किया लेकिन केन्द्र सरकार भी ध्यान नहीं दे रही। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि इस नहर पर जल्दी से जल्दी कार्य शुरू किया जाये। अब जो बजट केन्द्र सरकार ने पेश किया है उसमें एस०वाई०एल० के बनाये जाने वाले हैड में केवल एक करोड़ रुपये रखे हैं जबकि इस पर 700 करोड़ रुपये पहले ही लग चुके हैं। पिछली बार आपने इसके लिए 10 करोड़ रुपये की अनाउंसमेंट की थी। इस बार आपने केवल इसके लिए एक करोड़ रुपये रखे हैं। यह क्या दर्शाता है, आपकी एस०वाई०एल० के बारे में क्या नीयत है। इस मामले में सारे प्रदेश की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इस बारे में मुख्य मंत्री जी की तरफ से कोई सुझाव नहीं . आये, हम सहयोग क्या करें? आपने इस विषय पर पहले सबको भूलवाया था। हमने आपको इसके लिए अधिकृत किया और विधान

सभा ने युनानिमसली आपको अधिकृत किया लेकिन एक साल तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। आप भी प्रधान मंत्री जी से मिलकर आये हैं। कोर्ट का फैसला आपके हक में है, लेकिन आपकी तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई। मेरे साथियों ने एक सवाल उठाया और कहा कि आप एक बात स्पष्ट करें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो आधार राजीव लौंगोवाल समझौता है, क्या आप उसके हित में हैं या विरोध में। इस बारे में मुख्य मंत्री जी ने कोईजवाब नहीं दिया। मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि वित्त मंत्री जी ने यह कहा कि हम लौंगोवाल समझौते के विरुद्ध हैं। यह बात इन्होंने वही कही जो पंजाब का वकील कहता है। पंजाब का सरकारी वकील मि० धवन कहता है कि– It is true, as is contended by Dr. Rajiv Dhawan that the aforesaid agreement was entered into by Sant Harchand Singh Longowal, the then President of the Shiromani Akali Dal and as such, has no constitutional sanctity to bind the State of Punjab. But having regard to the fact that in terms of Paragraphs 9.1 and 9.2, a tribunal was constituted and even the provisions of the Inter-State Water Disputes Act were amended, thereby granting Parliamentary recognisition to the so called agreement, the terms of the said agreement cannot be thrown out as a piece of paper only. सुप्रीम कोर्ट के जज ने राजीव लौंगोवाल ऐकोर्ड कोही अपने फैसले का आधार बनाया है जिसमें हरियाणा के लिए यह नहर जीवन रेखा कही गयी है। आप असैम्बली में उठ कर कहते हैं कि वह तो पीस आफ पेपर था। मैं कहना चाहता हूँ कि आपको ऐसे शब्द नहीं निकालने चाहिए जिससे हरियाणा का पक्ष

कमजोर हो। अगर आप यही बात सुप्रीम कोर्ट में कह दो तो हम तो गए यह ठीक है कि पंजाब का रिव्यू पैटीशन गिर गया। बार–बार चर्चा होती है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार यानि कैप्टन अमरेन्द्र सिंह जो हैं, एक साल तक उन्होंने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की और कोर्ट के आदेश की अवहेलना की। यह बात ये बार–बार कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि यह किस की जिम्मेवारी है? अगर कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने कोर्ट के फैसले की अवहेलना की है तो कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के खिलाफ आप कोर्ट में क्यों नहीं गए। यह काम तो सरकार करेगी, सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। हम साथ देंगे जहां हरियाणा का हित होगा, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर साथ देंगे लेकिन आप नीयत साफ करके आयें। लेकिन नीयत साफ आपकी है नहीं जैसे कि हमारे साथी ने सवाल उठाया कि जो हाजिर पानी है हरियाणा में उसका बंटवारा न्यायोचित नहीं है और एस०वाई०एल० आने के बाद न्यायोचित बटवारा रुक नहीं सकता क्योंकि वह पानी इलाके में आना है क्योंकि खुद मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि वह सारा पानी इसी इलाके में आना है। पंजाब सरकार कोर्ट में कहती है ... .

श्री अध्यक्षः आप शॉर्ट करें। (विघन)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आप जब भी कहेंगे मैं बैठ जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि व्यास का 162 एमएएफ पानी आज भी हरियाणा में जा रहा है। एसवाईएल

का पानी जिस–जिस इलाके में आना है वहां पर नहीं आ रहा है। एसवाईएल के खुदने का मतलब यह है कि पानी का नियन्त्रण तथा बंटवारा करना पड़ेगा और इस बारे में इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है क्योंकि मुख्य मन्त्री जी ने बोलते हुए इस बात का उल्लेख किया था। दिवंगत चौधरी लहरी सिंह जी हमारे नेता थे। इन्होंने मेरे पिता जी का और एक दो पुराने मन्त्रियों का भी जिक्र किया था (विघन) ये 1962–63 की बात कह रहे थे, इन्हें यह बात भी मालूम होनी चाहिए कि 1962–63 से पहले जब भाखड़ा का पानी आया और सतलुज का पानी आया, उस समय चौधरी लहरी सिंह ही वह व्यक्ति थे जिनकी वजह से आपके खेतो में पानी आया। जिस पानी का आज झगड़ा है इण्टर वाटरट्रीटी से मिला व्यास और रावी का पानी, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पण्डोह तथा पौंग डैम की फाउंडेशन हुई थी वह उस समय हुई थी जब मेरे पिता जी सिंचाई मंत्री थे उनको भी ऐप्रिसियेट करना चाहिए था। मैं यह नहीं कहता कि क्योंकि वे मेरे पिता जी थे इसलिए उनको ऐप्रिसियेट करना चाहिए लेकिन इस तरह से नाम लेकर ऐप्रिसियेट नहीं किया गया। मैं बुजुर्गों का नाम लूंगा तो ठीकनहीं रहेगा मेरे पास भी बहुत मसाला है लेकिन मैं ऐसी बातों में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं कोई भी नैगेटिव बात नहीं करता। समय आने पर सारी बातें कहूँगा (विघन) इस काटैक्सट में इस समय मैं कुछ नहीं कहूँगा (विघ्न)। जो व्यक्ति जैसा होता है दूसरों के बारे वैसा ही सोचता है। मैं एस०वाई०एल० के मामले में कह चुका हूँ हम तैयार हैं और अब याचिका से काम नहीं चलेगा। मुख्य मन्त्री

जी, केन्द्र सरकार ने एक करोड़ रुपया रखा है लेकिन आपके रैजोल्यूशन से या याचिका से कुछ होने वाला नहीं है। असैम्बली में रैजोल्यूशन बार–बार हो चुके हैं। अब यह बार–बार नहीं चलेगा अब याचिका नहीं अब युद्ध होगा यह फैसला करके चलें। जीवन होगा या मरण होगा तभी आपको पानी मिलेगा अन्यथा हरियाणा को पानी नहीं मिल सकता है 1 हम तैयार हैं इस बात के लिए जहां चलना है चलिए हम आपके साथ चलेंगे। सरकार हम से को– ऑप्रेशन मांग रही है हम इनके साथ हैं जहां चलना है चलिए। एस०वाई०एल० हमारी जीवन रेखा है इसी बात का फैसला करें। दिल्ली के तीन तरफ हरियाणा पड़ता है (विघ्न) हमें तो तभी से याद है। हमारी तो बहुत दिनों की बात है लेकिन आप तो याद करके भी भूल रहे हैं। तीन साल पहले जब आपकी सरकार आई वहां पर प्रकाश सिंह बादल मुख्य मंत्री रहे लेकिन उसके बाद कहीं पर भी इस नहर की कोई चर्चा नहीं हुई। अगर हमारी भी यही नीयत होती तो हम भी ऐसी बात ही करते लेकिन आज पंजाब में कैप्टन अमरेन्द्र सिंह कांग्रेस के मुख्य मन्त्री हैं लेकिन हम तो चुप नहीं बैठे। हम तो कहते हैं कि चलो लड़ो, कन्टैम्पट ऑफ कोर्ट करो, पंजाब से लड़ी, कस्सी ले कर चलो, हम तैयार हैं और इस लड़ाई में हम आगे रहेंगे (विघन) एक साल के लिए कोर्ट ने कहा था और मुख्य मन्त्री जी ने ही अपनी मीटिंग में कहा था कि अभी एक साल रुको। हम तो उसी समय ही कह रहे थे लेकिन ये कहने लगे कि 14 जनवरी तक हमको इन्तजार करना चाहिए। हमने उसी समय कहा था कि आज समय है। इसमें कोई दो राय नहीं कि

आज नहीं तो कभी नहीं। अगर अब भी हमने रावी व्यास का अपने हिस्से का पानी नहीं लिया तो फिर कभी मिलने वाला नहीं है जैसे कि देश के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने आपके हक में फैसला कर रखा है और इसमें कमैंट्स कर रखे हैं। केन्द्र सरकार के बारे में भी कर रखा है उसकी नीयत भी दर्शा रखी है। जजमैंट में जब उनकी नीयत आपके सामने आ गई है तो अब इस बात की इन्तजार करने की कोई जरूरत नहीं (विघ्न)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियानः ....।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आप सीट पर बैठ जाएं। इनकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं की जाए। हुड्डा जी, आप इनको इनकी सीट पर बिठाएं। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः रघुबीर सिंह जी, आप बैठें। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, इनको हमारी बातें सीरियसली सुननी चाहिएं।

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको यह बताना चाहूँगा कि हम इनकी हर बात को सीरियसली सुन रहे हैं और नोट भी कर रहे हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, कल मुख्य मंत्री जी ने कहा कि कोई एक भी ऐसा वाक्य बता दो कि कोई इन्डसट्रियलिस्ट हरियाणा से भागा हो। अध्यक्ष महोदय, यह अखबार में छपा हुआ है ‘‘ भारतीयों विदेश छोड़ कर कभी भारत

न आना। '' अध्यक्ष महोदय, यह कहां का केस है, यह हरियाणा की औद्योगिक नगरी धारूहेड़ा का है वहां पर दूध, पनीर, नमकीन का करोड़ों रुपए का प्लांट लगाया गया था किन्तु अफसरशाही ने इतना जलील किया कि मदन अरोड़ा वापिस बिस्तरा बांध कर अमेरिका जाने के लिए तैयार हो गया। उसकी पूंजी लुटी, उसने अपमान के घूंट पीए। प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री के कार्यालय में दर्खास्त दी लेकिन उसको कहीं से भी न्याय नहीं मिला। इससे आगे वह क्या उम्मीद रखता? (विघन) अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा था कि एक भी केस बता दो वही मैंने बताया है।

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो बजट एट–ए–ग्लांस में दर्शाया है कि इन्होंने कर–मुक्त बजट पेश किया है। (शोर एवं व्यवधान) आपने पिछले बजट को कर–मुक्त बजट कहा था और अब की बार भी कर मुक्त बजट कहा है। लेकिन आपने जो बजट पेश किया है यह क्या दर्शाता है, वह मैं अध्यक्ष महोदय, के माध्यम से बताना चाहूँगा। टैक्स रैवेन्यू में 2002–03 के जो रिवाइज्ड एस्टीमेट थे। वह 6187 करोड़ रुपये के थे, 2003– 04 का बजट ऐस्टीमेट आप दे रहे हैं वह 6952 करोड़ रुपये का दे रहे हैं। अब सरकार यह बताए कि रैवेन्यू का इन्तजाम कौन से हैड से करेगी, कौन से करों से यह पैसा आएगा या पिछली बार की तरह नए टैक्स लगाएंगे। आज ये कहते हैं कि हमने कर–मुक्त बजट दिया है और बाद में टैक्स पर टैक्स लगाते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को यह बताना चाहूँगा,ये मेरे बड़े

भाई हैं कि आज प्रदेश ' और ' का राज चलने वाला नहीं है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब ने आज प्रदेश में. और ऊ शब्द कहें हैं ये दोनों शब्द रिकार्ड न किये जाएं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, ... हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई अनपार्लियामैंटरी शब्द नहीं कहे हैं, यह तो अरोड़ा साहब ने कहा है कि सरकारी अफसर मुझे .... रहे हैं। अब आप ही बताएं कि यह ' नहीं हो रही है तो क्या हो रहा है। मुख्य मंत्री महोदय ने कल चुनौती देते हुए कहा था कि एक भी ऐसा कोई केस है तो बताएं तो मैंने इनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए यह केस बताया है। जब यहां पर महेन्द्र चौधरी का सवाल उठा तो लोगों की जुबान बन्द करने के लिए लोगों को गुमराह करने के लिए इन्होंने कण्डेला के बारे में कह दिया कि उसकी इन्क्वायरी करवाओ। हम कहते हैं कि उसकी इन्क्वायरी करवाओ। हमने कोई ऐसा काम किया ही नहीं है। हमने कोई दिया ही नहीं है। इकट्ठा दिया है तो पार्टी के साथियों ने दिया है और जिस दिन मैं जीन्द से आया था। उस दिन मैं पार्टी अध्यक्ष के नाते किसानों के घर जाकर देकर आया हूँ आप लोगों की तरह चोरी की आदत नहीं है। चौधरी देवी लाल के ट्रस्ट से पता नहीं क्या–क्या किया है। आप तीनों केसों की इन्क्वायरी सी०बी०आई० से करवाओ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस तरह से आप हमें गुमराह नहीं कर सकते हैं। इस

तरह से कास्मैटिक बजट देने से हरियाणा प्रदेश का फायदा होने वाला नहीं है और लिपिस्टिक–पाऊडर लगाकर हरियाणा की जनता का फायदा होने वाला नहीं है। (विघन) आपने बजट पर लिपिस्टिक–पाऊडर लगाया है। अध्यक्ष महोदय, आज इस प्रदेश को इन्होंने अन्दर से खोखला कर रख दिया है। ये आने वाली सरकारों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर रहे हैं। इस प्रदेश में हर व्यक्ति का जीना दूभर हो जाएगा। किसान को, व्यापारी को, कर्मचारी को और गरीब मजदूर को कोई सुविधा दी हो तो ये बताएं। अध्यक्ष महोदय, कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे थे और वे अपनी मांग कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय, कर्मचारी हर सरकार के वक्त में हड़ताल पर बैठते हैं और उन कर्मचारियों की क्या मांग होतो है, उन कर्मचारियों की मांग होती है कि हमारा वेतन बढ़ाओ। लेकिन आज उनकी यह मांग होती है कि हमारे को नौकरी से मत निकालो। वे आज अपना वेतन बढवाना तो भूल गये। इसी तरह से पहले किसान अपना संघर्ष किस बात के लिए करते थे, वे अपना संघर्ष दाम बढ़वाने के लिए करते थे लेकिन आज वे किस बात के लिए धरने पर बैठ रहे हैं, वे इस बात के लिए धरने पर बैठे हैं, गोलियां खा रहे हैं बेकसूर मर रहे हैं कि जो वायदा सरकार ने उनसे किया है उसे पूरा करें और उनका अनाज खरीद लें। अध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थितियां इन्होंने पैदा कर दी हैं। आगे और क्या होने जा रहा है वह भी सब देखेंगे। यह बड़ा गंभीर विषय है इसलिए इनकों इस बात को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। प्रदेश में अर्थ–व्यवस्था मजबूत हो इसके

लिए अगर इनको विपक्ष का सहयोग चाहिए कोई विपक्ष के रचनात्मक सुझाव चाहिएं तो इसके लिए हम तैयार हैं लेकिन इस प्रदेश को बर्बाद करने में हम इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हुआ अपना स्थान लेता हूँ।

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने रचनात्मक सुझावों की बात की। हालांकि ये अपने सुझाव अपनी स्पीच में नहीं दे पाए कोई बात नहीं ये लिखकर दे दें। हमने पहले भी कहा था कि आप सुझाव दे देना। (विघन) हुड्डा साहब, आपने अपनी स्पीच समाप्त करने की बात कही है इसलिए ही मैंने आपको टोका है बीच में मैंने आपको नहीं टोका। हम तो बार बार कह रहे हैं कि आप सुझाव दें। हमने इससे फालतू तो कुछ नहीं कहा है। जो थोड़े बहुत सुझाव आपने दिए हैं हम उनको मान लेंगे लेकिन अर्थव्यवस्था के बारे में, कर्मचारियों के बारे में एवं किसानों के बारे में आपने कोई सुझाव नहीं दिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे यह पूछना चाह रहा था क्योंकि अभी इनके बोलने का टाईम है कि ये वैट के बारे में बताएं कि इसके बारे में इनकी पार्टी का स्टैंड क्या है ये क्लीयर इस बारे में बताएं क्योंकि ये विपक्ष के नेता हैं और इनकी पार्टी के अध्यक्ष भी यहां पर बैठें हैं इसलिए ये दोनों मिलकर बता सकते हैं कि वैट के बारे में इनका और इनकी पार्टी का क्या स्टैंड है? अध्यक्ष महोदय, एक बात तो ये यह क्लीयर कर दें ताकि गवर्नमैंट को आसानी रहे। इसके अलावा दूसरी बात ये

यह भी क्लीयर कर दें कि बिजली, पानी एवं सफाई आदि के शुल्क के बारे इन्होंने यह कहा है कि सरकार ने सर्विस चार्ज लिए हैं तो ये यूजर्स के बारे में भी अपना स्टैंड हमें बता दें। अगर ये ऐसा इन बातों के बारे में बता देंगे तो उससे हम भी लाभान्वित होंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो सुझाव देने के लिए कहा है तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि यह बजट पेश करने के बाद हमारे सुझाव क्यों मांग रहे हैं यह तो कोई तरीका नहीं होता। केन्द्र में भी बजट पेश करने से पहले ही सबके सुझाव मांगे जाते हैं।

प्रो० सम्पत सिंहः कोई बात नहीं, आप अब अपने सुझाव दे दें, हम अब मान लेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अभी तो समय इस बात को देखने का है कि जो सुझाव हमने दिए हैं उन पर आप कितना अमल करते हैं उसके बाद हम देखेंगे। जहां तक इन्होंने वैट की चर्चा की तो इस बारे में मेरा मानना है कि इसको लागू करने से पहले आप कृपया इस पर फिर से सोच विचार करें कि क्या हमारे हित में है और क्या हमारे हित में नहीं है।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, इनको सुझाव देना चाहिए था। हुड्डा साहबसे यह पूछा गया था कि इनकी पार्टी की वैट के मामले में पालिसी क्या है इनसे इनकी

व्यक्तिगत राय इस बारे में नहीं पूछी गयी थी। ये विपक्ष के नेता हैं ये अपनी पार्टी के नेता हैं इसलिए इस नाते ये इस बारे में स्पष्ट कर दें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार है उन्होंने भी वैट लागू करने के मामले को तीन महीने के लिए डैफर किया है इसलिए यह तो सटेट टू स्टेट की बात है कि हमारा इस मामले में क्या हित है? जिस तरह से दिल्ली की सरकार ने तीन महीने के लिए इसको डैफर किया है उसी तरह से आप इसको डैफर करके सोच विचार कर सकते हो। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा था कि मैं कोई आर्थिक विशेषज्ञ नहीं हूँ। मैंने अखबारों में पढ़ा था कि कल एक व्यापारी का व्यान आया था कि इससे एक हजार करोड़ रुपये का नुक्सान होगा।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने इतना पुअर प्रदर्शन किया है कि इसी सदन में इनकी बैंचों के आदमी उठकर ट्रेजरी बैंचिज पर आकर गए हैं। हालांकि हम दल बदल को बढ़ावा देने के पक्ष में नहीं हैं लेकिन इनकी बेलगामी की वजह से, इनकी बातों की वजह से सदन में ही इनके सदस्य परेशान होकर दल बदलू हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष: अब श्री जाकिर हुसैन बोलेंगे।

राव नरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, हमने आपको लिस्ट दी हुई है ज्यके मुताबिक ही बुलवाएं। एक आवाजः श्री जाकिर हुसैन जी तो इस समय हाउस में नहीं हैं।

श्री अध्यक्षः नरेन्द्र सिंह, आप बैठ जाएं। अब अगले मैम्बर श्री चन्द्र मोहन बोलेंगे।

एक आवाजः श्री चन्द्र मोहन जी भी हाउस में नहीं हैं।

श्री अध्यक्षः मैं पहले उन मैम्बर्ज को बोलने का समय देना चाहता हूँ जो गवर्नर साहब के अभिभाषण पर नहीं बोल सके हैं। पार्टी का नेता अपने एम०एल०एज० के नाम न दे तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनको बोलने का मौका दूं।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे अनुरोध है और हमने पहले भी कहा था कि हम आपके आभारी हैं कि आपने सबको खुलकर बोलने का मौका दिया। पहले उन मैम्बर्ज को अवसर दिया जाए जो गवर्नर साहब के अभिभाषण पर नहीं बोले हैं। अध्यक्ष महोदय, जिनको अब तक बोलने का अवसर नहीं दिया है, उनको आप अवसर दें।

श्री अध्यक्षः अब श्री अनिल विज बोलेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पालः अध्यक्ष महोदय, मैं गवर्नर महोदय के ऐड्रस पर नहीं बोला हूँ इसलिए मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया जाए। मैंने अपनी पार्टी की तरफ से अपना नाम दिया है।

श्री अध्यक्षः भारतीय जनता पार्टी के तीन विधायक राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल चुके हैं इस प्रकार आपकी पार्टी के फिफ्टी परसैंट विधायक बोल चुके हैं '।

श्री कृष्ण पालः अध्यक्ष महोदय, पार्टी के नेता को तो बोलने का मौका मिलना चाहिए। हम सरकार की सहयोगी पार्टी हैं, मेरे बोलने में दिक्कत क्या है। सरकार के लोग भी बोले हैं। इंडिपैंडैंट्स को भी आपने बोलने का मौका दिया है।

श्री अध्यक्षः आपके बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। समय आने मर आपको भी बुलवाएंगे। सरकार की तरफ से अभी तो सिर्फ राम बीर सिंह ही बोले हैं। अनिल विज को गवर्नर साहब के एड्रैस पर बोलने का समय नहीं मिला था इसलिए उनको बोलने का अवसर दिया है। आपको गवर्नर साहब के एड्रैस पर बोलने का मौका दिया था लेकिन आप बोलना नहीं चाहते थे। सबको बुलाया है आप उस समय सदन छोड्कर चले गए थे हम तो आपको भी बुलवाना चाहते थे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः अध्यक्ष महोदय, आप कृष्ण पाल गुर्जर को हिदायत दें। इन्होंने यह कहा है कि आप इंडिपैंडैंट्स को बोलने का समय देते हैं। मेरा आपके माध्यम से

निवेदन है कि हम डायरैक्ट जनता के प्रतिनिधि हैं, कभी इनको कोई गलतफहमी हो। अगर कोई गलतफहमी है तो ये इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़कर देख लें, इनकी जमानत जब्त हो जाएगी।

श्री कृष्ण पालः अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्षः कृष्ण पाल गुर्जर की कोई बात रिकॉर्ड न की जाए।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः अध्यक्ष महोदय, ये इस्तीफा देकर चलें जाएं इनको पता लग जाएगा। मेरा हल्का इनके साथ लगताहै। इनके हल्केकी जनता परेशान हो चुकी है सारे हल्के का इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। (शोर एवं व्यवधान) (विघन)

श्री अध्यक्षः आप बैठिये। कृष्णपाल जी जो कह रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाये। बिसला जी आप बैठिये। Please sit down कैप्टन अजय सिंह जी आप बैठ जाइये। बिसला जी आप बैठें अनीता जी आप भी बैठें, जयप्रकाश जी आप भी बैठें। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, मेरा आप से भी निवेदन है और हाउस के सभी मैम्बरान से भी निवेदन है कि गवर्नर साहब के एड्रैस पर विदआउट इंट्रप्शन अच्छी तरह से हर मैम्बर ने अपनी बात कही है और जो मैम्बर रह गये आपने उनको भी बुलवाने का प्रयास किया अगर वह नहीं बोलना चाहते या जो हाजिर नहीं थे वह एक अलग बात है। जिस हिसाब से लिस्टें आपके पास आई

हुई हैं आप बुलवा भी रहे हैं, टाइम भी दे रहें हैं बजाए बहसबाजी के जिसको आप टाईम दे रहें हैं। वह खड़ा होकर अपनी बात करे,अपने हल्के की मांग रखे, तो हाउस के टाईम का यूटीलाईजेशन भी अच्छी तरह से हो सकता है, अब कोई आदमी अलग से अपनी इम्पोटैंस जाहिर करना चाहता है कि मैं बोल रहा हूं आपको क्या दिक्कत हो रही है आपको फलाना क्या हो रही है। यहां सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कोई सहयोगी सरकार को सुझाव दे या कोई आलोचना करे या विपक्ष के सदस्य भी हमें सुझाव देगें तो हम सहर्ष उसको स्वीकार करेंगे और उसका जवाब भी देंगे हमें कोई आपत्ति नहीं हैं। हम उनका पूरा जवाब देंगे। लेकिन इस बात को जाहिर करने के लिए कि जैसे इनको टाईम नहीं दिया जा रहा है। ऐसा कहकर अपनी बात को ज्यादा अहमियत देने का ये माननीय सदस्य प्रयास कर रहे हैं, हमें किसी बात की कोई चिन्ता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वह सहयोगी सदस्य है या विपक्ष का सदस्य है, सुझाव अच्छे आयेंगे तो उन पर पूरा गौर करेंगे, आलोचना होगी तो उसका पूरा जवाब देंगे लेकिन हाउस का डैकोरम स्पीकर सर बनायें ताकि हाउस का समय नष्ट न हो। एक—एक मिनट कीमती है, प्लीज जिसे आप कहें वही सदस्य खड़ा होकर बोले। (विघन)

श्री अध्यक्षः आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ (विघन)

श्री कृष्ण पालः स्पीकर सर, आप मेरी बात तो सुनिये।...
..

श्री अध्यक्षः आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ (विघन) कृष्ण पाल जी, आप बैठ जाइये।

चौ० भजन लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की।

श्री अध्यक्षः आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ (विघ्न) कृष्ण पाल जी आप बैठ जाइये। चौधरी भजनलाल जी आप बैठिये। Ch. Bhajan Lal Ji, I warn you, इनकी कोई बात रिकार्ड न की जाये।

चौ० भजन लालः ....

श्री कृष्ण पालः स्पीकर सर, आप मेरी बात तो सुनिये। .
....

श्री अध्यक्षः आप बैठ जायें। गवर्नर एड्रैस पर कुल चर्चा 646 मिनट हुई जिसमें से इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी को 55 मिनट्स, कांग्रेस पार्टी को 293 मिनट्स, भारतीय जनता पार्टी को बा मिनट्स और इंडीपैंडैंट्स को 94 मिनट्स का अलग–अलग समय दिया गया। (विघन) कृष्ण पाल जी, आपने समय मांगा है आपकी चिट मेरे पास आई हुई है यह जरूरी नहीं कि आप के कहने से आपको अभी बुलवाया जाये। यह आपका अधिकार नहीं

है, यह मेरा अधिकार है। आप बैठें, आपकी चिट मेरे पास है। आपने अपना अकेले का नाम दिया है।

श्री कृष्ण पालः स्पीकर सर, आप मेरी बात तो सुनिये। मेरा आपसे निवेदन है कि आप विपक्ष को तो बुलवा सकते हैं लेकिन सहयोगियों को न बुलवाने का मतलब क्या होता है, आपको बुलवाने में विपक्ष का तो डर नहीं है, मेरा डर सता रहा है।

श्री अध्यक्षः कोई दिक्कत नहीं है बोलने की, मुझे कोई डर नहीं है आप इस तरह नहीं किया करें, आप बैठ जायें। (विघन) आपको बुलवाया जायेगा। आपको गवर्नर एड्रैस पर बुलवाना चाहते थे लेकिन आप उस समय सदन में प्रैजेंट नहीं थे। आप बैठते तो हैं नहीं आपके पार्टी के आधे सदस्य बोल चुके हैं, आप तो पार्टी के नेता हैं, आपने अभी अपना नाम दिया है समय आने पर आपको भी बोलने का समय दिया जायेगा। अभी आप बैठें।

प्रो० सम्पत सिंहः मैं जो कह रहा था वही बात फिर आ रही है कि उस से क्या डर है, फलाने से डर है। मैं बताना चाहता हूँ कि हमें किसी से कोई डर नहीं है (शोर) मैं क्लीयर करना चाहता हूँ कि हमें कोई डर नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ये काम आपका है कि आपको किस टाईम किस मैम्बर को बुलवाना है, ये आपका अधिकार है, हमारा भी अधिकार नहीं है कि हम हस्तक्षेप करें कि आप ट्रेजरी बैंच से बुलवा रहे हैं, सहयोगी से बुला रहे

हैं, इंडीपैंडैंट से बुलवा रहे हैं। सबसे पहले आपने विपक्ष के नेता को बुलाया। उसके बाद इंडीपैंडैंट का नाम लिया, उसके बाद जो सूची आपके पास है जिसको आप उचित समझें उसको बुलवाएं यह आपका अधिकार है कि कब किसको बुलाना है? ये यहां तमाशेबाजी कर रहे हैं कि उससे डर, फलाने से डर, इस सरकार को किसी से कोई डर नहीं है। जहां तक सरकार का सवाल है तो सरकार को किसी से कोई डर नहीं है, डर उसे हुआ करता है जिसके मन में चोर होता है या जिसने गलत काम कर रखा हो उसके मन में चोर होता है। सरकार के दिमाग में कोई डर नहीं है। यह पब्लिक की सरकार है, पब्लिक के प्रति हमारी जिम्मेदारी है, देनदारी है, हमारा दायित्व बनता है कि विपक्ष, सहयोगी, सरकारी पक्ष अगर कोई बात रखेगा तो हम उसकी एक–एक बात का जवाब देंगे। (शोर) हमें किसी का कोई डर नहीं है।

श्री कृष्ण पालः डर नहीं है तो मुझे बुलवाते क्यों नहीं?

श्री अध्यक्षः यह कोई जरूरी है क्या आपका मैटर ऑफ राइट ज्यादा है, आप सुप्रीम नहीं हैं, आप भी एम०एल०ए० हैं। आप बैठें, I warn you (शोर एवं व्यवधान) आप व्यवस्था बनाएं रखें, अनिल विज को बोलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पालः शोक प्रस्ताव में विपक्ष के बाद आप मेरा नाम लेते हैं फिर बजट परिचर्चा में आप मुझें क्यों नहीं बुलवाते। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप व्यवस्था को बनाए रखे। मैंने आप को मना नहीं किया। आपको भी बुलवायेंगे। (शोर)

चौ० जय प्रकाशः अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी कह रहे थे कि पार्टी के नेता ने जो नाम दिए हैं उस हिसाब से बुलवाएंगे। अध्यक्ष महोदय, फिर आपको अपने हिसाब से बुलवाने का अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्षः मैंने हुड्डा साहब को बुलाया और पार्टी के नेता ने जो लिस्ट दी है उसके हिसाब से ही बुलवाएंगे। (शोर)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः हमने लिस्ट दी है।

श्री अध्यक्षः जय प्रकाश जी, बैंठें। हुड्डा साहब बैठें। जो लिस्ट मेरे पास है उसमें आपने' अपना नाम टॉप पर लिखा है। सदन के नेता खड़े हैं, इसलिए आप बैठें। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों की जिम्मेदारी है किये चेयर का ऐहतराम करें। यह बात ठीक है लायक और नालायक की परिभाषा स्पीकर ने करनी है। वे करेंगे भी कि कौन लायक है और कौन नालायक है, यह आपका काम नहीं है। आपकी पार्टी ने लिस्ट दी है। अध्यक्ष महोदय ने एक फैसला दिया है कि जो लोग गवर्नर एड्रैस पर नहींबोल पाए पहले उनको समय दिया जाएगा। जो लिस्ट आपकी आई है उस लिस्ट के मुताबिक

सब बोल चुके हैं। मैं अध्यक्ष महोदय की फ्राकदिली की दाद दूंगा कि जो लिस्ट दी गई, वे सब बोल चुके हैं।

चौ० भजनलाल: क्या आपके पास कॉपी आ गई है।

श्री अध्यक्ष: कॉपी मेरे पास है, 15 मैम्बर्ज बोल चुके हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: मैं कह रहा हूँ इन्होंने उसके बाद जाकिर हुसैन, चन्द्र मोहन और फिर बलबीर पाल शाह का नाम लिया।

चौ० भजन लाल: जानबूझकर ऐसे नाम लिए गए हैं। (शोर)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: इसके अलावा तो सारे बोल चुके हैं। लिस्ट जानने न जानने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, उसके बाद सदन का सम्मानित सदस्य जय प्रकाश उठकर यह कहे कि हमारी लिस्ट के हिसाब से बुलवाया जाएगा, यह आपका अधिकार नहीं है। मैं सदन से पूछता हूँ कि ये अधिकार स्पीकर के पास है या उसके पास है? ये चेयर की अवमानना है, सबसे पहले मुझे इस प्रश्न का जवाब दिया जाए कि क्या यह अधिकार किसी सदन के एक सदस्य को होगा कि स्पीकर को होगा ?कोई सदस्य यह कहे कि आपका अधिकार नहीं है पहले इसका फैसला किया जाए?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: हुड्डा साहब, पहले स्पीकर साहब रूलिंग दे रहे हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: स्पीकर सर, मैं इस बात से असहमत नहीं हूँ कि यह अध्यक्ष महोदय की डिस्कीशन पर है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, प्लीज आप बैठें। कौल एंड शकधर की बुक में यह रूलिंग है कि (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: ....

श्री अध्यक्ष: हुड्डा साहब, आप चेयर की इजाजत के बगैर बोल रहे हैं, इसलिए आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं की जा रही 1 प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) हुड्डा साहब, आपको पूरा समय दिया गया है आप बोल चुके हैं, प्लीज आप बैठें और मेरी बात सुनें। (शोर एवं व्यवधान) जय प्रकाश जी ने प्वायंट रेज किया है। (शोर एवं व्यवधान) आप मेरी बात तो सुनें।

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब ने कहा कि आप पार्लियामैंट प्रैक्टिस पर ध्यान दें। आप इनको यह भी बता दें कि कौल एंड शकधर की बुक पार्लियामैंट प्रैक्टिस पर ही है। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह आपका अधिकार है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भजन लाल जी आप मर्यादाएं न तोड़ो। (शोर एवं व्यवधान) आप बैठिये और मर्यादा में रहें।

चौ० भजनलाल: स्पीकर सर, यह आपका अधिकार है कि आप किसको बुलायें और किसको न बुलायें। लेकिन हमारी पार्टी से बुलाने के लिए आज आपको नाम दिये गये हैं, उनमें से बुलायें। हमारी पार्टी के बाकी के सदस्य कल बोल लेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker : At page No. 814 of the Practice and Procedure in Parliament by Kaul and Shakdhar, it is mentioned -

"The Speaker determines the order in which he would call upon members to speak : a member cannot indicate the order in which he should be called.

List of spokesmen are supplied by whips of the parliamentary party and groups to enable the Speaker to select members so as to ensure a well-regulated and balanced debate. He is, however, not bound by such lists."

चौ० भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में समझता हूँ। (शोर एवं व्यवधान) और इस बारे में बताता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अगर समझते हैं, तो अपनी पार्टी के दूसरे सदस्यों को भी समझाओ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः ....

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, आप चेयर की इजाजत के बगैर बोल रहे हैं, इसलिए आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं की जा रही। Don't waste the time of the House. प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के लिए कुल 646 मिनट का समय रखा गया था, जिसमें से अकेली कांग्रेस पार्टी को 293 मिनट बोलने का समय दिया गया था। बी०जे०पी० को या मिनट का और इण्डियन नैशनल लोकदल जो यहां सबसे बड़ी पार्टी है उसको 55 मिनट का समय दिया गया। बजट पर भी आप सबको पूरा समय दिया जायेगा लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपनी बात बोलकर आप चले जायें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः स्पीकर सर, हमें उम्मीद है कि सदन का जो पैमाना है, वह पूरे सदन पर बराबर लागू होगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, जो दूसरी पार्टीज के सदस्य हैं, क्या उनको समय नहीं दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० जय प्रकाशः ....

श्री अध्यक्षः जय प्रकाश जी चेयर की आज्ञा के बिना बोल रहे हैं, इसलिए इनकी कोई बात रिकॉर्ड न की जाये। (शोर एवं व्यवधान) गुप्ता जी प्लीज आप बैठें।

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर सर, ऑन ए ज्वायंट ऑफ ऑर्डर। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर सर, ऑन ए प्वायंट ऑफ ऑर्डर।

Mr. Speaker : Gupta Ji, I warn you. आपको बोलने की कोई परमिशन नहीं दी गई, प्लीज आप बैठें। आप बहुत सीनियर मैम्बर हैं, आप ऐसा करें, यह अच्छी बात नहीं है। अनिल विज जी, आप बजट पर बोलिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विजः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री मांगे राम गुप्ताः स्पीकर सर, ऑन ए प्वायट ऑफ ऑर्डर। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, मैं रूलिंग दे चुका हूँ प्लीज आप बैठें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, गुप्ता जी को आप प्वायंट ऑफ ऑर्डर पर तो बोलने दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः स्पीकर सर, गुप्ता जी का प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। (शोर एवं व्यवधान) **श्री अध्यक्षः** हुड्डा साहब, प्लीज आप बैठें और हाउस की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दें। (शोर एवं व्यवधान) अनिल विज जी, आप बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० भजन लालः ....

कैप्टन अजय सिंह यादवः ....

श्री अध्यक्षः प्लीज आप सभी बैठें। (शोर एवं व्यवधान)। जो भी माननीय सदस्य चेयर की आज्ञा के बिना बोल रहे हैं, उनकी बात रिकॉर्ड न की जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज (अम्बाला छावनी): अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के भाई मेरे बोलने का विरोध कर रहे हैं या कृष्ण पाल गुर्जर जी का समर्थन कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: गुप्ता जी, प्लीज आप बैठें। (शोर एवं व्यवधान) (Gupta ji, I warn you again) (शोर एवं व्यवधान) जिन सदस्यों को पहले समय नहीं दिया गया है, पहले उनको समय देंगे। अगर समय बचेगा तो दूसरों को बुलवाएंगे। (विघ्न) अनिल विज जी, आप बोलिये।

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो लगातार चौथा बजट हरियाणा विधान सभा में पेश किया है उस पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, किसी भी सरकार के लिए जो सबसे ज्यादा कठिन काम होता है वह अपने संसाधन की व्यवस्था करना ही सबसे कठिन काम होता है। इसी प्रकार से किस–किस मद से साधन आयेगा और उन साधनों को किस प्रकार से हमने खर्च करना है ये सब बातें यानी खर्च करने की जो आवश्यकताएं हैं, उनकी कितनी जरूरतें हैं इन सब बातों को देखना होता है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन कितने हैं और उन साधनों की जो प्रायोरिटीज है वह तय करना किसी भी वित्त मंत्री के लिए सबसे ज्यादा और सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि वित्त मंत्री जी ने इस मुश्किल काम को बहुत ही आसानी से सुलझाने की कोशिश की

है। वित्त मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसकी दिशा और दशा क्या है यदि इसका अवलोकन करना चाहते हैं तोजो आर्थिक सर्वेक्षण 2002 –03 विधानसभा के पटल पर रखा है, प्रस्तुत किया है हमे उसका अवलोकन करना चाहिए। यदि हम उसका अवलोकन करें तो हमें बजट की दिशा और दशा केबारे में सही जानकारी हासिल होती है। वर्ष 2002 – 03 का जो आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया हैउसमें यह जानकारी होती है कि जो हमारा स्टेट ग्रीस डैमोस्टिक प्रौडक्ट है जो स्टेट जी०डी०पी० है It has registered an increase of 5.1%. It is very saiisfactory. क्योंकि यह देश का जो जी०डी०पी० है, उससे बेहतर है और जो आर्थिक सर्वेक्षण देश का प्रस्तुत किया गया है, उससे बेहतर है। अगर हम इसके कारणों पर गौर करें तो यह जी०डी०पी० में इन्कीज क्यों हुआ किस आधार पर हुआ इस को भी देखना चाहिए। आप देखिए कैसे हालात रहे कि वर्षा की भी स्थिति खराब रही लेकिन उसके बावजूद भी ट्रेड में 99 परसैंट की वृद्धि दर्ज की है। हमने ट्रांसपोर्ट सैक्टर में 11.4 परसैंट की वृद्धि दर्ज की है। इसी प्रकार से कन्स्ट्रक्शन सैक्टर में 68 परसैंट की वृद्धि दर्ज की है जो बहुत ही संतोषजनक है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी व्यक्तिगत सोच है कि बजट हर वर्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए जब तक कि 3–4–5 वर्षों तक एक ही प्रकार का बजट एक ही दिशा में पेश न करें तब तक हम मनवांछित नतीजे हासिल नहीं कर सकते हैं। इसके आर्थिक सर्वेक्षण का और अध्ययन किया गया और इसका सैक्टर वाईज अध्ययन किया गया। प्राइमरी सैक्टर में

क्या हुआ, और सैकेण्डरी सैक्शन में क्या हुआ और तृतीय सैक्शन में क्या हुआ। इन तीनों सैक्शनों के बहुत ही संतोषजनक आकड़े इस आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्तुत किए गए हैं। प्राइमरी सैक्टर में 0.8 परसैंट की ग्रोथ दर्ज की गई है जिसमें एग्रीकल्वर व लाईव स्टाक आदि आते हैं। सैकेण्डरी सैक्शन में मैन्यूफैकचरिंग व कन्क्रक्शन आदि के काम आते हैं उसमें 5 परसैंट की ग्रोथ रजिस्टर की गई है और तृतीय सैक्टर में जिसमें व्यापार व बर्किंग आदि आते हैं में 8.7 परसेंट की ग्रोथ रजिस्टर की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं वित्त मंत्री महोदय और सरकार के प्रमुख श्री ओम प्रकाश चौटाला को भी मुबारिकबाद देना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हमने महत्वपूर्ण ग्रोथ रजिस्टर की है। खाली शिक्षा ही नहीं हमने और सैक्टर्ज में भी सफलता प्राप्त की है। जैसे जो हमारा रैवेन्यू रिसीट है उसमें भी हमने काफी अच्छी मैनेजमैंट से सफलता प्राप्त की है। अगर हम आकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2000–2001 में जो 5421 करोड़ टैक्स रैवेन्यू थे 2002 –2003 में बढ़ कर 6187 करोड़ रुपये हो गया है यानि 765 करोड़ रुपये की हमने इसमें वृद्धि हासिल की है। इसी प्रकार से नॉन टैक्सिज रैवेन्यू में भी जो 2179 करोड़ रुपये था वह 2000–2002 में 2594 करोड़ रुपये तक इन्क्रीज हो गया यानि 415 करोड़ रुपये की वृद्धि हमने वसूल की है। तो इस सरकार के कार्य हम देखें और बजट की सारी व्यवस्था को देखें, बजट–ऐट–ए ग्लांस देखें तो सब से बड़ी बात जो इसमें देखी वह फिस्कल डैफीसिट की देखी। फिस्कल डैफीसिट को लगातार कम करने के प्रयत्न किये जा रहे

हैं और उसमें सफलता भी हासिल हो रही है। आज इकोनोमी में इकोनोमिस्ट वर्ल्ड ओवर सब स्थानों पर फिस्कल डैफीसिट को कम करने की वकालत करते हैं और यह विचार करते हैं कि फिस्कल डैफीसिट को किस प्रकार से कम किया जाए। इसकेलिए मैं हरियाणा सरकार को मुबारिकबाद देनाचाहता हूँ। तमाम विकास की गतिविधियों को बढ़ाते हुए भी तमाम कामों को करते हुए भी सरकार ने तमाम खर्चों के बढ़ते हुए इन्होंने फिस्कल डैफीसिट को कम करने की कोशिश की है। वर्ष 2001 – 2002 में फिस्कल डैफीसिट 2739 करोड़ था जो रिवाईज्ड ऐस्टिमेट 2002 –03 के हैं वह घट कर 2202 करोड़ रुपये रह गये हैं। यानि 537 करोड़ रुपये का फिस्कल डैफीसिट इस वर्ष के आकड़ों में हमने कम करने में सफलता प्राप्त की है। यह बहुत बड़ी अचीवमैंट है और बहुत बड़ी सफलता है। इसी प्रकार से जो वर्ष 2002 – 2003 में हमारी रिवाईज्ड फिस्कल डैफीसिट 2202 .68 करोड़ रुपये है। इसके आगे बजट ऐस्टिमेटस जो बनाए गए 2002 – 2003 में उसमें भी उसको कम करने की प्रस्तावना की गई है जो 2135 करोड़ रुपये के फिस्कल डैफीसिट को खत्म करने की बात की गई है यह एक बहुत ही लाभ वाला बजट है जो अच्छी सोच वाला बजट होने की बात है। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बेहतर विकास के लिए एक नई सोच रख कर इस बजट को बनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद वित्त मन्त्री का काम आता है। हमारे संसाधन जो हमने जैनरेट किए हैं यह बहुत अच्छे हैं। हमने मेहनत से और अपनी बैटर मैनेजमैंट से टैक्स रैवेन्यू को

बढ़ाया है। अब यह सरकार पर निर्भर है कि वह इस पैसे को किस स्तर पर खर्च करें। अध्यक्ष महोदय, आप मानेंगे कि आज जो बजटरी सैंस है, जो बजटरी पालिसी है, वह बदल रही है। इसी तरीके से अगर केन्द्रीय बजट का अवलोकन करें तो आप पाएंगे कि पिछले बजटों से यह बजट थोड़ा हट कर है, उसमें अलग दिशा की बात कहने की कोशिश की गई है। पहले इंफसिज दिया जाता था सेविंगज की तरफ लेकिन इस बार केन्द्रीय बजट में भी जो सेविग डिपोजिट हैं उन पर इन्ट्रस्ट रेट कम किये जा रहे हैं और जो एक्साईज ड्यूटी है या दूसरी चीजें हैं, उनको कम किया जा रहा है ताकि लोग अधिक से अधिक खरीददारी कर सकें। ऐसी इकोनोमी बनाने की कोशिश की जा रही है जिससे हमारा इकोनोमिक ग्रोथ बड़े ताकि हमारी इकोनोमी खड़ी हो तथा हमारी इकोनोमी विश्व की बढ़ती हुई इकोनोमी के साथ मुकाबला कर सके। इसके लिए जो प्रबन्धान है, वित्तीय प्रबन्धान है और हमारी जो बजटरी सोच है कि हम इस पैसे को किस प्रकार से खर्च करें ताकि हमारे प्रदेश की जो इकोनोमी है, जो हमारे प्रदेश की अर्थ व्यवस्था है, वह और तरक्की कर सकें। इस बारे में अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सरकार को अत्यधिक ध्यान अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की ओर देना चाहिए। हमें यह जानकर बहुत खुशी है कि वित्त मंत्री जी ने अपने संसाधनों से जो बजट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है उसको बड़े बेहतर तरीके से किया है। अपने जो संसाधन हैं हमने जो प्लान 18 सौ करोड़ रुपए का बनाया है उसका 43 प्रतिशत खर्चा है यानि कि 911 करोड़ रुपए का खर्चा करने का

प्रावधान वित्त मंत्री जी ने किया है ताकि हम बेहतर तरीके से लड़के बना सकें, बेहतर तरीके से इरिगेशन कर सकें, हम बेहतर तरीके से बिजली की व्यवस्था कर सकें और हम बेहतर तरीके से ट्रांसपोर्टेशन मुहैया करवा सकें। हमारा इन्फ्रास्ट्रक्टर जितना अच्छा होगा उतने ही अधिक हम अच्छे उद्योग धंधे लगा सकेंगे, अपने यहां पर और अधिक लोगों को आकर्षित कर सकेंगे, अगर हम और अधिक उद्योग धन्धों को आकर्षित करते हैं तो ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकेंगे, अगर हम अधिक लोगों को रोजगार देंगे तो हम ज्यादा पैसा लोगों की जेबों में दे सकते हैं। लोगों की जेबों में ज्यादा पैसा होगा तो वे ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा चीजें खरीदेंगे। जब ज्यादा चीजों की डिमान्ड होगी तो कारखानों में अधिक डिमाण्ड आएगी। अधिक डिमाण्ड आएगी तो ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रदेश की बेहतर वित्तीय स्थिति होगी। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने इस सैक्टर में 911 करोड़ रुपए का प्रावधान करके पहले भी और आज भी बाकी प्रदेशों से बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर दिया है। आज हम दिल्ली के आस–पास के बाकी स्टेट्स से कम्पैरिजन करें तो हम उनसे काफी बेहतर हैं। आज उससे भी बेहतर बनने के लिए देश का नम्बर एक का स्टेट बनने के लिए वित्त मंत्री जी ने इन्फ्रास्ट्रक्चर के सैक्टर में जो यह प्रावधान किया है यह बहुत ही बढ़िया है और मैं इसके लिए इनका आभार प्रकट करता हूं।

12.00 बजे

इसके साथ ही मैं दूसरे सैक्टर सोशल सर्कल के बारे में कहना चाहूँगा। आज जो सोशल सैक्टर है क्या हम अपने बुजुर्गों की, विधवाओं की, विकलांगों की परवाह कर रहे हैं क्या हम उनके लिए कुछ करके देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज की जो अन्य सोशल जरूरियात हैं तो एक सोशल स्टेट की जिम्मेवारी है जिनके लिए हम काम करें? क्या हम वह कर रहे हैं, उसके लिए क्या इस बजट में कोई प्रावधान किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, बजट का 2 .4 प्रतिशत सोशल सैक्टर के लिए निर्धारित किया गया है जोकि 890.23 करोड़ रुपये बनता है। जोकि सोशल सैक्टर में बुढ़ापा पैंशन में जाएगा, विकलांगों के लिए जाएगा. जो नई योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनके लिए जाएगा। सोशल सैक्टर में, एजुकेशन सैक्टर में, लोगों की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए और हैल्थ के लिए सरकार ने यह प्रावधान किया है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट जो प्रस्तुत किया है उसमें जो खर्चे और आमदनी के अनुपात को किस तरह से कम किया जाए उसको किस तरह से ऐडजस्ट किया जा सकता है इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे सम्पत सिंह जी ने इस बजट में प्रस्तुत की है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन से हमारा यह बजट सैशन आरम्भ हुआ है, इस सैशन में पहले ही दिन से हमारे सभी साथियों ने एस०वाई०एल० के मामले पर बहुत चिन्ता व्यक्त की है। मैंने इस बारे में यह नोट किया है कि इस बारे में चर्चा बाकी मामलों को पीछे छोड़ते हुए एक नम्बर पर थी। हमारे वित्त मंत्री

जी ने जो बजट पेश किया है इसमें भी एस०वाई०एल० के बारे में जिक्र किया है। यह बात निश्चित तौर पर यह इशारा करती है कि हम एस०वाई०एल० के लिए गम्भीर हैं, चिन्तित हैं और हम चाहते हैं कि इस बारे में शीघ्र अति शीघ्र हमारे हिस्से का पानी जो है, वह हमें मिले। हमारे हिस्से का पानी जो हमें नहीं मिल रहा है, जो हमारा हिस्सा हमसे छीन लिया गया है, जो हमारा हिस्सा राजनीति का शिकार हुआ है, वह हिस्सा हमें शीघ्र अति शीघ्र मिले। यही हम सब चाहते हैं। लेकिन मैं इस बात के ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहूँगा।

श्री उपाध्यक्ष: अनिल विज जी, मैं आपकी ही नहीं बल्कि सदन के सभी सदस्यों की जानकारी के लिए कहना चाहूँगा कि व बजट से रिलेटिड चर्चा ही करें।

श्री अनिल विज: उपाध्यक्ष महोदय, एस०वाई०एल० के बारे में बजट में लिखा हुआ है आप कहें तो मैं यह पढ़कर सुना दूं। मैं बजट पर ही बोल रहा हूँ। (विघन) उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस मामले का हल राजनीति से ऊपर उठकर ही करना चाहिए। मुझे इस बात की हैरानगी होती है कि मेरे इस तरफ के साथी एस०वाई०एल० का इतना ज्यादा जिक्र करते रहे हैं लेकिन 15 जनवरी की तिथि आने तक इन्होंने कोई भी प्रयत्न नहीं किया है। यह कोशिश नहीं की कि इसी बिल्डिंग में पंजाब के मुख्य मंत्री बैठते हैं जो हमारे हरियाणा के एस०वाई०एल० के पानी को रोकते हैं। उनको जाकर हम कह सकें

कि हमारे हिस्से का पानी हमें दो। इन चीजों से जब तक हम पीछे नहीं हटते हैं, इन चीजों से जब तक हम ऊपर नहीं उठते हैं, तब तक कामयाब नहीं हो सकते हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि अगर हम प्रधान मंत्री जी से मिलने के लिए जाएंगे तो हम सब इकट्ठे जाएंगे, अलग– अलग नहीं जाएंगे, अगर हम कोई कार्यक्रम करेंगे किसी कार्यक्रम का या आन्दोलन का आयोजन करेंगे तो इकट्ठा करेंगे। जब तक ऐसा नहीं करेंगे, तब तक एस०वाई०एल० का पानी हम आसानी से हरियाणा में नहीं ला सकते हैं। इसलिए हमें सब को राजनीति से ऊपर उठकर इस पर काम करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, अभी वैट प्रणाली लागू करने का भी जिक्र किया गया। बजट में भी इसका प्रावधान किया गया है किएक अप्रैल से वैट प्रणाली लागू की जाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, वैट प्रणाली एक यूनिवर्सल मान्यता प्राप्त सिस्टम है काफी सोर देशों ने इसको लागू किया है इसलिए हमारे देश में भी इसको लागू करने के लिए सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों के लेवल पर, फाईनांस मिनिस्टर्ज के लैवल पर कई मीटिंग्ज हुई और यह तय किया गया कि सारे देश में वैट प्रणाली एक अप्रैल से लागू करेंगे। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इसको लेकर कुछ लोगों के मनों में भ्रांतियां हैं इसलिए इसके बारे में हमें जरूर विचार करना चाहिए। मैं इस बारे में एक सुझाव देना चाहता हूँ। सरकार की तरफ से कहा गया कि इसको एक अप्रैल से लागू करेंगे जबकि पंजाब ने कहा है कि वे इसको तीन महीने बाद लागू करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इसको जब भी लागू किया जाए चाहे वह एक अप्रैल से लागू किया जाए चाहे तीन

महीने बाद लागू किया जाए और चाहे उसके बाद लागू किया जाए लेकिन सारे देश में एक समान तारीख से ही इसको लागू किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसमें बहुत सारी कठिनाइयां ज्येका अन्देशा बना रहेगा। अभी तो कई स्टेट्स ने अपने बिल भी प्रस्तुत नहीं किए हैं। पारित नहीं किए हैं। इसलिए जब भी इसको लागू किया जाए तो वह एक समान तारीख से ही लागू किया जाना चाहिए। अगर पंजाब या दूसरे स्टेट्स इसको तीन महीनों के बाद लागू करेंगे तो हमें भी इसको तीन महीनों के बाद ही लाग करना चाहिए तभी इसका कुछ फायदा हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लागू होने में कुछ और भी कठिनाइयां हैं। अगर हम इसको एक अप्रैल से लागू करते हैं तो हमें यह तय करना होगा कि जिन दुकानदारों की दुकानों में जो अभी तक माल पड़ा हुआ है पहले उस बारे में सोचा जाए? यह ठीक है कि वैट प्रणाली लागू होने से सारे कागज हट जाते हैं, एस०टी० – 14 एवं एस०टी– 15 इत्यादि सारे फार्म हट जाते हैं यानी कुछ नहीं देना पड़ता लेकिन फिर भी इसको लागू करने से जो कठिनाइयां उत्पन्न होने का अंदेशा है उनके बारे में विचार किया जाना चाहिए। यह भी कहा गया कि सी०एस०टी० को भी खत्म कर दिया जाएगा। जहां पर भी कोई खरीदेगा वहां पर वैल्यू ऐडेड टैक्स लगेगा इसलिए इसमें बहुत काम कम हो जाते हैं जैसे कोई कागज रखनेका, किसीतरह का फार्म लेने काकाम नहीं रहेगा यानी सारी चीजें कम हो जाएगी। लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जैसे किसी सिस्टम को चेंज करने में कठिनाइयां आती

है तो इसमें भी अगर चेंज करेंगे तो कठिनाइयां आएंगी इसलिए इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस बारे में एक सुझाव है कि इसके लिए स्थान–स्थानपर कुछ सेमीनार्ज आयोजित किए जाने चाहिएं और लोगों की जो इस बारे में भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए प्रयत्न एवं प्रयास किए जाने चाहिएं। लोगों की जो इस बारे में अनर्गल एवं बेमतलब की बातें हैं, जब उनको इस बारे में समझाया जाएगा तो वह इस बारे में समझ जाएंगे हालांकि जब इस बारे में लोगों से बात की जाती है तो वे कहते हैं कि यह तो बहुत आसान हो गया है लेकिन कहीं–कहीं इसके लागू करने से पहले ही इसके विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गये हैं इसलिए हम लोगों को इस बारे में समझा सके इसके लिए प्रयत्न एवं प्रयास होने चाहिएं कि क्या–क्या इसके प्रावधान हैं, क्या–क्या इसका लाभ होगा और क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि लोग समझ सकें। उपाध्यक्ष महोदय, यकीनी तौर पर वैट सिस्टम लागू होने से एक व्यापारी के लिए एक ट्रेडर्ज के लिए काफी सहूलियतें हो जाती हैं क्योंकि अभी तो उसको तरह–तरह के फार्म रखने पड़ते हैं और दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं इसलिए इसको लागू करने से उनको काफी मदद मिलती है।

श्री उपाध्यक्षः विज साहब, अब आप वाईंड अप करें।

श्री अनिल विजः उपाध्यक्ष महोदय, मैं वाईंड आप कर देता हूँ। मैं ' सरकार आपके द्वार ' जो कार्यक्रम प्रदेश में चलाया

जा रहा है इसकी भी सराहना करता चाहता हूँ। इसी तरह से पीने के पानी की प्रदेश में व्यवस्था की जा रही है। खासकर मेरे शहर में कैनाल बेस्ट वाटर सप्लाई की स्कीम बनायी जा रही है, मैं उसकी भी सराहना करना चाहता हूँ। सरकार ने शहरों के सौन्दर्यीकरण के लिए भी नयी सोच पैदा की है, स्थान–स्थान पर अच्छे सुन्दर पार्क बनाये जा रहे हैं, इससे शहरों का दर्जा बढ़ा है, शहरों की सुन्दरता बढ़ी है और अब लोग शहरों को चाहने लगे हैं। जिस तरह से शहरों से डेयरियों को बाहर निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है या जो कूड़ा कचरा है, उसके प्रबन्धन की जो व्यवस्था की जा रही है उसके लिए भी मैं सरकार की सराहना करना चाहता हूँ। शहरों में जो सूअर एवं जानवर घूमते हैं, उनको निकालने के जो प्रयत्न और प्रयास किए गए हैं, वह भी सराहनीय हैं। इसी तरह से सरकार ने पहले यमुना ऐक्शन प्लॉन बनाया और अब घग्गर ऐक्शन प्लॉन बनाया है। घग्गर के साथ लगते जितने भी शहर हैं उनमें बेहतर सीवरेज मुहैया करवाने के लिए 354 करोड रुपये की जो योजना बनायी गयी है उसके लिए भी मैं सरकार का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सरकार विदेशी निवेश को आकर्षित करने के भरसक प्रयत्न कर रही है। मुख्य मंत्री जी को जितना समय मिलता है बाहर जाकर, विदेशों में जाकर वहां से व्यापारियों को आमंत्रित करने का प्रयत्न करते हैं। एक बार मुझे भी इनके साथ जाने का अवसर प्राप्त हुआ। कई साथी बहुत कुछ बातें करते है और कई बार हमारे मन में भी आ जाता था कि ऐसे ही घूमने चले जाते हैं मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैंने

देखा कि यह एक बहुत कठिन काम है। दूसरे देशों में जाकर वहां के सारे व्यापारियों को इकट्ठा करना और उन्हें अपने प्रदेश के बारे में समझाना कि हमारा प्रदेश दिल्ली के साथ लगता प्रदेश है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ लगता है दिल्ली के साथ है और इन्फ्रास्ट्रक्चर सबसे बैटर है और यहां-यहां हम इंडस्ट्रियल एरिया डिवैल्प कर रहे हें इन सब प्रयासों से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब भी कोई बाहर का उद्योगपति हिन्दुस्तान में उद्योग लगाने की सोचेगा तो वह हरियाणा प्रदेश के बारे में विचार जरूर करेगा। (थम्पिंग) इसके लिए सरकार ने फौरेन इन्वैस्टर्स प्रमोशन बोर्ड भी गठित किया है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार पेड लगाने के बारे में बहुत अच्छा काम कर रही है और लगभग 4 करोड़ पेड़ू लगाने का भी सरकार ने काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक सुझाव और देना चाहता हूँ आजकल डीलिमिटेशन का चर्चा चल रहा है। सारे विधान सभा और संसदीय क्षेत्रों का डीलिमिटेशन किया जा रहा है उन सब विधान सभा और संसदीय क्षेत्रों जो बेतरतीबी से बढ़ गए हैं कोई विधान सभा क्षेत्र 2 लाख जनसंख्या वाला है किसी का एक लाख जनसंख्या वाला है। मैंने इस बारे में पिछली सरकार के समय में भी सुझाव दिया था। मैं चाहता हूँ कि सरकार उस पर विचार करे। यह एक बहुत अच्छा प्रयास है कि सारे विधान सभा क्षेत्रों को और संसदीय क्षेत्रों को एक समान किया जा रहा है। इसके साथ ही मैं यह भी चाहूँगा कि हम अपनी प्रशासनिक इकाइयों को भी बराबर करने पर जरूर विचार करें। अगर एक संसदीय क्षेत्र 10 लाख जनसंख्या वाला है तो सभी में

दस लाख जनसंख्या हो और जितने भी हमारे जिले हैं उनका एक जिला बनाएं। एक सब–डिवीजन बनाएं तो उससे आसानी होगी। जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें केन्द्र को ऐसा कानून पारित करना चाहिए। (विघन) हर डिस्ट्क्ट लोकसभा क्षेत्र के बराबर होना चाहिए। हर सब–डिवीजन विधान सभा क्षेत्र के बराबर होना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में डी०सी० के साथ एम०पी० का आफिस होना चाहिए और सब डिवीजन में एस०डी०एम० के साथ विधायक का आफिस होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः विज साहब, आप बजट पर ही बोलें। आपका सुझाव आ गया है। तीन लाख जनसंख्या वाले विधानसभा क्षेत्र भी हैं, बिसला जी बैठे हैं।

श्री अनिल विजः उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव दे रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्षः सुझाव दे दिया है, अब इसे ज्यादा टच न करें। आप समअप करें।

श्री राजेन्द्र सिंह बिसलाः अध्यक्ष महोदय, विज साहब बड़े ही काबिल और विद्वान विधायक हैं, इनको बोलने दें।

श्री उपाध्यक्षः भजन लाल जी, आप बैठे–बैठे न बोलें। आप बैठे–बैठे दूसरों की वकालत न किया करें।

चौ० भजन लाल: मैंने क्या किया है, मैंने क्या बोला है। आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, मैं कभी भी ऐसी बात नहीं करता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है चौधरी भजन लाल जी, इस सदन में कई मर्तबा मुख्य मंत्री भी रहे हैं, अपोजीशन के नेता भी रहे हैं इनको तो चेयर का सम्मान करना चाहिए 1

चौ० भजन लाल: मैं सबसे पुराना भी हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: भजन लाल जी, आपको तो कम से स्म ष्मे का सम्मान करना चाहिए। आप इस तरह से तल्खी में कैसे कह देते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि बेयर की अवमानना यह सदन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० भजन लाल: मैं कभी भी चेयर की अवमानना नहीं करता हूं। मैं किसी को बीच में इन्टरवीन भी नहीं करता हूँ। लेकिन कोई बगैर मतलब की बीच में टोका टाकी करे, ऐसा कैसे करेंगे। (शोर एवं व्यवधान) आप पहली बार तो आए हो, मैं आपसे सीखूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: पहली बार आपकी कृपा से चुनकर नहीं आया हूँ (शोर एवं व्यवधान) आप कैसे धमका सकते हैं, जब तक मैं इस चेयर पर हूँ। मैं जो चेयर के नियम हैं., उनके हिसाब से

ही इस हाउस को चलाऊंगा, आप बैठें। आप बैठे–बैठे ऐसे नहीं बोल सकते।

चौ० भजन लालः रहने दो, आप ऐसे नहीं चला सकते।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः उपाध्यक्ष महोदय, जो भजन लाल जी ने जो धमकी भरे और अपमानजनक शब्द कहें हैं ये कार्यवाही से निकाले जाने चाहिए। हम चेयर को अपमानित नहीं होने देंगे। हम ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं करेंगे। चौधरी भजन लाल जी आप संयम में रहें वरना आपके खिलाफ ऐक्शन लिया जायेगा।

चौ० भजन लालः मैंने क्या कहा है?

श्री उपाध्यक्षः आप बैठिये। आप बैठे–बैठे किसी मैम्बर को सर्टीफिकेट नहीं देंगे। I will not tolerate. मैं बिलकुल टोलरेट नहीं करूंगा। (विघ्न) आप कैसे कर देंगे। इस कुर्सी पर आप बैठे हैं या मैं? आपके रहमोकरम से यह कुर्सी नहीं मिली है।

चौ० भजन लालः इनके रहमोकरम पर मिली है।

श्री उपाध्यक्षः चौधरी भजन लाल जी, हम आपको मान देते हैं, ख्य भी मान दें। आप बैठे– बैठे न बोलें। अनिल विज जी, आप कन्टीन्यू कीजिए।

श्री अनिल विजः उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव दे रहा था कि सब जिलों और सभी सब–डिवीजन को एक समान किया जा सकता है। इसी प्रकार से मैं यह भी चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल

पर जो डी०सी० का दफतर होता है उसी के साथ एम०पी० का दफतर भी होना चाहिए और इस प्रकार से सब डिवीजन के दफतर के साथ एम०एल०ए० का आफिस भी होना चाहिए। ताकि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वे और सरकार के अधिकारी मिलजुल कर एक जगह ठीक ढंग से अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर सकें और उनका समाधान कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, बजट में इम्पलईज केबारे में कुछ अधिक नहीं कहा गया है। मैं इसके बारे में काफी कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन समय की अधिकता नहीं है इसलिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। इम्पलाईज के लिए एक–दो काम क्तने की बहुत आवश्यकता है। एक तो सभी कर्मचारियों के लिए परमानैंट ट्रांसफर पालिसी जरूर बनानी चाहिए जैसी कि एजूकेशन में बनाई है और उसमें काफी सफलता भी प्राप्त हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा ट्रांसफर पालिसी कर्मचारियों के लिए जरूर बनानी चाहिये और हमें उनकी हाउसिंग व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देना चाहिये। वह यह कि जहां कर्मचारी रहते हैं उस स्थान पर उनके लिए हाउस की व्यवस्था कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल अपने हल्के की बात अवश्य रखना चाहूँगा।

श्री उपाध्यक्षः आप ब्रीफली कहें।

श्री अनिल विजः उपाध्यक्ष महोदय, जो जरूरी बातें हैं वहीं कहूँगा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे अम्बाला में कई ऑयल डिपो के कई बडे–बडे जिनमें कई लाख गैलन तेल आता है जोकि शहर

के बीच में आ गये हैं यह कभी दुर्घटना का कारण हो सकती है। उससे सारे शहर के लिए समस्या हो सकती है। इसके लिए मैंने एक प्रश्न भी दिया था शायद उसका नम्बर नहीं आ सका। इसके बारे में सरकार को विचार अवश्य करना चाहिए और उनको शहर से बाहर निकालने का समय रहते प्रयत्न किया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, अम्बाला कैंट अनाज मण्डी शहर के बीच में है, अन्य किसी शहर में ऐसे नहीं है, वहां नई अनाज मण्डी बनाने का प्रोसैस चल रहा है और उसके लिए भूमि अधिगृहीत की जा रही है लेकिन काफी धीमी गति से कार्य चल रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हुड्डा के लिए सैक्टर आ रहे हैं और उनके लिए भूमि ऐक्वायर करने की प्रक्रिया चल रही है जिसमें नई अनाज मण्डी, चारामण्डी और सब्जी मण्डी बनाने केलिए स्थान दिया जाना है। फ्लड से बचाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे लिए बहुत प्रयत्न किया है, उसको जल्दी किया जाये। हम काफी इससे बच गये हैं लेकिन अभी भी एक काम होना बाकी है जो गुडुगुडिया नाला है मैं चाहता हूँ कि उसको वाईडन किया जाये और उसकी आगे की निकासी का इन्तजाम किया जाये ताकि वह टांगरी नदी में जाकर गिर सके। हमारे शहर में ज्यूडिशियल कम्पलैक्स नहीं हैं। यह एक महत्वपूर्ण शहर है यहां कमिशनरी हैं अम्बाला कमिश्नरी एक समय मे लोग आप जानते हैं कि दिल्ली से अम्बाला कमिश्नरीमें आते थे। अम्बाला कैंट में ज्यूडिशियल कम्पलैक्स बनाने के लिए किसी लैवल पर प्रक्रिया चल चुकी है केवल सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ क्योंकि अम्बाला

कैंट केलोगों को छोटे–छोटे कामों के लिए अम्बाला सिटी में जाना पड़ता है। वहां पर जजिज का स्टॉफ है, लेकिन बिल्डिग नहीं है।इसके लिए जल्दी बिल्डिग बनाई जाये नहीं तो कहीं और किराये की बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया जाये ताकि लोगों को सहूलियतें मिल सकें। पिछले सैशन में भी बात आई थी कि जी०टी० रोड पर ओवर ब्रिज देंगे। अम्बाला शहर में हरियाणा का सबसे बढिया ओवर ब्रिज बना है लेकिन उस पर किसी कारण से लाइटें लगनी रह गई जिसकी वजह से आये दिन वहां दुर्घटनाएं होती हैं। मैं चाहूँगा कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार सड्कों की तरफ बहुत ध्यान दे रही है। आज हरियाणा के किसी भी कोने में जाये वहां सड्कों पर काम चल रहा है। मुझे बाकी शहरों का तो पता नहीं लेकिन मेरे शहर की जो इंटरनल रोडस हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। मैं चाहूँगा कि मुख्य मंत्री महोदय, उसके लिए किसी विशेष पैकेज की घोषणा करे। उपाध्यक्ष महोदय, एक और बहुत बडी समस्या आई है कि अभी सरकार ने कुछ कालोनियों को अथोराइज्ड घोषित कर दिया दूसरे शहरों की तो मुझे जानकारी नही लेकिन मेरे शहर की कुछ कालोनियां जो अन– अथोराइज्ड से अथोराइज्ड हो गई हैं उनमें लगभग 90 प्रतिशत लोगों ने डिवेल्पमैंट चार्ज पे करके अपने नक्शे पास करवाकर मकान बनाये। वे हर साल हाउस टैक्स देते हैं इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरे शहर की कालोनियों को भी बाकी शहरों की तरह डिवैल्प किया जाये।

श्री उपाध्यक्षः अनिल विज जी, आप वाईण्ड अप करें।

श्री अनिल विजः उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट का समय और लूंगा। हमने डिवैल्पमैंट चार्ज लिए हुए हैं तो हम डिवैल्पमैंट करने से कैसे इंकार कर सकते हैं। हमें पता चला है कि आप डिवैल्पमैंट नहीं कर सकते। हमने सबसे डिवैल्पमैंट चार्ज लिए हुए हैं। 90 प्रतिशत लोगो ने डिवैल्पमैंट चार्ज दे रखें हैं इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे। हमारे शहर पर मुख्य मंत्री जी की बड़ी कृपा है। उन्होंने नेताजी के नाम से हमारे शहर में एक पार्क का निर्माण करवाया है, बहुत लोग उसका फायदा उठा रहे हैं लेकिन मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उसकी व्यवस्था के लिए किसी न किसी विभाग कौ जिम्मेदारी दी जाये। उपाध्यक्ष महोदय, अम्बाला–साहा सड़क को चौड़ा रमने का फैसला किया गया है उसके टैण्डर भी हो चुके हैं, लगभग नौ करोड़ रुपये से उसको चौड़ा किया जा रहा है मैं चाहूँगा कि उसके बीच में जो टांगरी ब्रिज है उसको भी चौडा किया जाए क्योंकि बजट में सड्कों और ब्रिजों के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रोवीजन किया गया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि टांगरी के ब्रिज को चौड़ा करने की ओर सरकार ध्यान दे। इन्हीं शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री उपाध्यक्षः मेरी सभी सम्मानित सदस्यों से गुजारिश है कि कृपया बजट तक ही सीमित रहे।

श्री कृष्ण पाल (मेवला महाराजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया। इसके लिए धन्यवाद। कल काबिल वित्त मंत्री प्रो० सम्पत सिंह जी ने बजट रखा और कर रहित बजट रखा, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ लेकिन साथ–साथ मैं उनसे यह आश्वासन भी चाहता हूँ कि हर वर्ष की भांति बजट के बाद हरियाणा के लोगों पर, विभिन्न वर्गों पर कर न थोपे जायें। हर वर्ष बजट में दर्शाया जाता है जैसा कि इस बार दिखाया गया है कि 780.53 करोड़ रुपये के घाटे से बजट शुरू है और समाप्त 670.96 करोड़ रुपये पर होना दर्शाया गया है। लेकिन हर वर्ष होता क्या है कि घाटा बजाय कम होने के बढ़ जाता है इसी तरह वर्ष 2001 –02 और इसी तरह 2002–03 में है। इस तरह बजटों में होता रहा है। मैं समझता हूँ कि बजट में जहां कर नहीं लगाया गया है वहीं हरियाणा के किसी भी वर्ग को कोई राहत देने का काम भीनहीं किया गया है। अच्छा होता अगर हरियाणा के किसान को, व्यापारी को, मजदूर को, उद्योगपति को और कर्मचारी को कोई राहत दी जाती जैसे केन्द्र सरकार ने एल०टी०सी० को दोबारा शुरू किया है। सम्पत सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हरियाणा में एल०टी०सी० कब शुरू करने जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश कृषि पर आधारित प्रदेश है जहां 75 प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित हैं। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बजट ऐट ऐ ग्लैंस में देखने से पता चलता है कि वर्ष 2001 – 2002 में टोटल बजट का 5 प्रतिशत रखा गया था, पिछले वर्ष 3.28 प्रतिशत टोटल बजट का

रखा गया था और इस वर्ष यह सिर्फ 3 प्रतिशत ही रखा गया है। इस बारे में हुड्डा साहबने भी बताया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। एग्रीकल्चर के लिए 2000– 01 में 951 .84 करोड़ रुपये, 2001 –02 में 943.65 करोड़ रुपये रखा गया था बह भी इस साल कम करके 527.43 करोड़ रुपये कर दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त ग्रामीण विकास के लिए भी बहुत कम पैसा रखा गया है। यहां पर ज्यादातर सदस्य गांवों की पृष्ठभूमिसे संबंधित हैं लेकिन यह बड़े अफसोस की बात है कि ग्रामीण विकास के लिए इस वर्ष लगभग 80 करोड़ रुपये की राशि पिछले वर्ष के मुकाबले कम रखी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बजट में और पैसे का प्रावधान किया जायेगा ताकि हरियाणा के किसानों को राहत मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य–मंत्री जी ने कल राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के उत्तर में कहा था और वित्त मंत्री जी ने भी बजट में कहा है कि हरियाणा के अन्दर पिछले तीन साल में 24 हजार नलकूपों के कनैक्शन दिए गये हैं। लेकिन सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण,जो पृष्ठ 28 पर है, दर्शाता है कि वर्ष 1996 – 1997 में 366540 नलकूपों के कनैक्शन थे और वर्ष 2002 –03 में 368920 नलकूपों के कनैक्शन हैं यानि की 2380 नलकूपों के कनैक्शन बड़े हैं (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, हमारे तो समझ नहीं आता कि इन्होंने कितने कनैक्शन काटे और कितने कनैक्शन दिए। यदि पिछले तीन साल की बात करें तो इस सरकार के समय में

छः या साढ़े छः हजार नलकूपों केकनैव्यान बड़े हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इनके आकड़े मेल नहीं खा रहे, क्याइस बारे में वित्तमंत्री जी अपने जवाब में स्थिति स्पष्ट करेंगे कि कहां छः या साढे छः हजार कनैक्शन और कहां 24 हजार कनैक्शन। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, बजट में यह भी कहा गया है कि हरियाणा में पिछले तीन सालों से काफी उद्योग आये हैं लेकिन जो औद्योगिक बिजली के उपभोक्ता हैं उनके बारे में इसी पृष्ठ संख्या 28 पर छठे नम्बर पर दर्शाया गया है कि 1996–97 में 77422 औद्योगिक बिजली उपभोक्ता थे और अब 64314 औद्योगिक बिजली उपभोक्ता हैं। यानि 13 हजार औद्योगिक बिजली उपभोक्ता कम हुए हैं, यह सर्वेक्षण की रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा।

श्री उपाध्यक्षः आप यह नहीं मानते कि यहां कनैक्शन नहीं मिले। (शोर एवं व्यवधान) आप दोनों चीजों को जोड़े मत। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि उद्योग आये हैं तो औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं की संख्या क्यों नहीं बढ़ी ? सरकार कह रही है कि पिछले तीन सालों में हरियाणा में बहुत अधिक औद्योगीकरण हुआ है लेकिन मैं कहना यह चाहता हूँ कि जितने उद्योग आये हैं उससे ज्यादा उद्योगों का पलायन भी हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सर्वेक्षण दर्शा रहा है मैं नहीं कह रहा। (शोर एवं व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जब सरकार की तरफ से जवाब आ रहा

था उस समय मैंने इनको इंटरवीन नहीं किया फिर ये अब मेरे को इंटरवीन क्यों कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्षः गुज्जर साहब, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आप सदन में उपस्थित ही नहीं थे। उस समय चेयर मैं कर रहा था। मेरी यह इच्छा थी कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मैं आपको बोलने का समय दूं लेकिन आप सदन में नहीं थे। आप चाहें तो रिकॉर्ड देख ले।

श्री कृष्ण पालः उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय मुख्य मंत्री जी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जवाब दे रहे थे उस समय मैं सदन में उपस्थित था। उस समय मुख्य मंत्री जी ने हमारे बारे में काफी कुछ कहा लेकिन हमने उनको बीच में इंटरवीन नहीं किया।

श्री उपाध्यक्षः गुजर साहब, आप चेयर को एड्रैस करके बोलें, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा।

प्रो० सम्पत सिंहः डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा निवेदन है कि कृष्ण पाल जी चेयर को एड्रैस करें यानि डिप्टी स्पीकर साहब को एड्रैस करके अपनी बात करें तो कोई नहीं टोकेगा। अगर किसी इन्डीविजुअल मैम्बर पर या किसी की तरफ इशारा करते हों तो नैचुरल है, स्वाभाविक है कि उसका रिऐक्शन होता है। आप चेयर को एड्रैस करें। आप जो कह रहे हैं, मैं आपकी एक–एक

बात को नोट कर रहा हूँ और बाकायदा आपकी एक–एक बात का जवाब देंगे।

श्री कृष्ण पालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि जो औद्योगिक उपभोक्ताओं के कनैक्शंज हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। पिछले तीन सालों में जहां वर्ष 2000–01 में 70710 औद्योगिक उपभोक्ता थे वहां अब 2002 –03 में 64300 यानि वर्ष 2000–01 के मुकाबले लगभग सवा छह हजार औद्योगिक उपभोक्ता कम हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह इनका आकड़ों का खेल कुछ समझ में नहीं आता, ये बताते कुछ हैं और दर्शाते कुछ हैं। इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो बजट रखा है उस का घाटा किस तरह पूरा किया जा सकता है, उस बारे में मैं पहला सुझाव देना चाहूँगा कि अगर सिंगल टैण्डर सिस्टम समाप्त कर दिया जाये तो यह घाटा घट सकता है। इसी तरह से कोलोनाईजर्ज हैं उनसे ई०डी०पी० प्राप्त कर ली जाये तब भी यह घाटा घट सकता है लेकिन आज सरकार जो विकास का दावा कर रही है, इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इसमें सबसे बड़ा योगदान केन्द्र में अटल जी की सरकार का है। जब से हरियाणा बना है तब से केन्द्र में अटल जी की सरकार आयी है पिछले 4 सालों में हरियाणा को इतना पैसा मिला है जितना पिछले 35–37 सालों में नहीं मिला। (विघन) उपाध्यक्ष महोदय, बाकायदा मेरी पार्टी की सरकार है, उसका योगदान है। इसमें मेरी पार्टी के नेता का योगदान है। (विघन)

श्री उपाध्यक्ष: कृष्ण पाल जी, आप बैठिये। पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर कुछ कहेंगे। **प्रो० सम्पत सिंह:** डिप्टी स्पीकर, अदरवाईज तो हम सब बातों का यानि सारी बातों का जवाब देंगे लेकिन क्योंकि इन्होंने पोलिटिकल बात बीच में छेड़ दी जबकि इस वक्त यह बात इनकी तरफ से कहने को बनती नहीं। इन्होंने कहा कि केन्द्र में हमारी पार्टी की सरकार है, मैं कहना चाहूँगा कि बिलकुल इनकी पार्टी की सरकार नहीं है। वहां पर एन०डी०ए० की सरकार है और एन०डी०ए० के एजेंडे पर काम कर रही है और हम भी बिना शर्त उसमें सहयोगी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी हरियाणा प्रदेश की पूरी मदद कर रहे हैं, हरियाणा प्रदेश के मुख्य मंत्री जी, वाजपेयी जी और केन्द्रीय सरकार सब के आपस में मधुर सम्बन्ध हैं, उसके आधार पर जितनी मदद हम चाहते हैं उतनी मदद हमें मिल रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है लेकिन कृष्ण पाल जी यह कहें कि मेरी पार्टी की सरकार है या मेरी वजह से कुछ हो रहा है इस तरह की या ऐसी कोई बात नहीं है। बाकायदा केन्द्र सरकार एन०डी०ए० के एजेंडे पर काम कर रही है और सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम कर रही है। आपस के रिश्ते जो मुख्य मंत्री जी ने बनाये हैं उनकी बदौलत यह सारी चीजें हो रही हैं।

श्री कृष्ण पाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से कहूँगा कि इन सब बातों का जवाब तो ये अपने

बजट भाषण में दे दें तो अच्छा रहेगा। (विघ्न) मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही।

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर साहब, अगर ये बजट पर बोलें तो हम बीच में नहीं बोलेंगे और उसका जवाब बाद में देंगे। अगर ये पोलिटिकली बातें कहेंगे तो उसका जवाब मौके पर दे देंगे। **श्री कृष्ण पालः** मैंने तो यह कहा है कि केन्द्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधान मंत्री हैं। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप अपने आपको बजट तक ही सीमित रखें। आप हरियाणा के बजट पर बोलें।

श्री कृष्ण पालः मैं बजट पर ही बोल रहा हूँ। मैं यह कह रहा हूँ कि प्रदेश में सरकार ने जो अच्छे कार्य किए हैं। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः आप उस बात को बार–बार मत दोहराओ। (विघ्न) आप किसी बात की रैपिटीशन न करें। (विघ्न)

श्री कृष्ण पालः उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में क्या हो रहा है, माल किस का – कमाल किसका। माल केन्द्र सरकार का और कमाल चौटाला साहब का।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः उपाध्यक्ष महोदय, यह कौन माल वाले आ गए पता नहीं, समझ में नहीं आता कि कहां से माल

लेकर आए। मैं सदन की जानकारी के लिए विषय से अलग हट कर भी एक बात बताना चाहता हूँ। इस बात की कल भी बड़ी चर्चा रही थी और निरन्तर चर्चा हो रही है। सूखा राहत के नाम पर भी बहुत चर्चा की गई तथा यह भी जाहिर करने की कोशिश की गई कि सूखा कहां पड़ा, कितना पड़ा और कितनी राहत घोषित की गई। ज्यों–ज्यों सूखा पड़ा त्यों त्यों उसके मुताबिक कैबिनेट ने निर्णय लिया। एक वक्त ऐसा आया था कि पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश को हमने सूखाग्रस्त घोषित किया था। चौधरी अजीत सिंह केन्द्रीय कृषि मन्त्री का हवाला देकर बड़ी हंसी की गई तथा सदन में भी और सदन के बाहर भी बहुत कुछ कहा गया। जहां कहीं जब कभी भी कृषि मन्त्रालय की मीटिंग बुलाई गई और अगर कृषि मन्त्री द्वारा कोई मीटिंग बुलाई गई तो हमारे कृषि मन्त्री उस मीटिंग में गए। सैक्रेटेरियेट लैवल पर कैबिनेट सैक्रेटरी ने कोई मीटिंग बुलाई तो हमारे चीफ सैक्रेटरी तक उस मीटिंग में गए। अगर केन्द्र सरकार ने कृषि मन्त्रियों की मीटिंग बुलाई तो उसमें भी हमारे कृषि मन्त्री गए और मैमोरैंडम भी दिए गए। प्रभु की कृपा टाइम पर हुई। हम आस्तिक लोग हैं इनकी तरह नास्तिक नहीं हैं हम तो भगवान पर भरोसा रखते हैं और प्रभु की कृपा हुई तथा पूरा हरियाणा प्रदेश सूखे की मार से बचा। मैंने पहले भी कई मर्तबा कहा था कि जो लोग पहले कहते थे कि सूखे के नाम पर मांगा था तो मैंने कहा था कि फ्लड के नाम पर भी मांगेगे और तब ऐसी बारिश हुई कि इन बैंचों पर बैठे हुए लोगों ने कहा कि अम्बाला और यमुनानगर में फ्लड आ गयो है इसलिए उन

लोगों की मदद की जाए। फ्लड के नाम पर राहत दी गई थी। मैंने यह भी कहा था फिर सूखा राहत के नाम पर पैसे दिए जाएंगे। फिर इनको पीड़ा होगी कि उस इलाके में ले गए उसको कम दे दिया उसको घट दे दिया। आज भी विपक्ष के नेता के पास कहने को तो कुछ था नहीं इसलिए इन्होंने यह कहा कि मुआवजे के नाम पर एक रुपये या दो रुपये दिए। इनको कोई ज्ञान नहीं है इन्होंने तो पेट्रोल पम्प और गैस ऐजेंसियां ही दिलाई हैं। (विघन) हुड्डा साहब, एक मिनट आप मेरी बात तो पहले सुन लें मुझे बीच में बोलते हुए टोके नहीं, यह अच्छा नहीं लगता है। उपाध्यक्ष महोदय, इनको बिठाइये। कहने वाले को थोड़ा सुनने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। (विघ्न) हुड्डा साहब, आपके पैट्रोल पम्प हैं मैं सबूत के साथ कहता हूँ कि आपके पेट्रोल पम्प हैं कोई साले के नाम से या किसी और के नाम से और चाहे कोई बेनामी पेट्रोल पम्प है (विघन) मैं सबूत के साथ कहता हूँ (विघन) आपके पास पेट्रोल पम्प है या नहीं है (विघन) हुड्डा साहब, इस तरह से ठीक नहीं लगता आप आराम से बैठे। (विघन) उपाध्यक्ष महोदय, इनको ज्ञान नहीं है कि एक एक किल्ले में एक एक एकड़ में कितने–कितने हिस्सेदार जमीन में होते हैं। उनके हिस्से के मुताबिक ही उनको उनका हिस्सा दिया जाता है। ऐसे गांव भी बहुत हैं जिन गांवों को पूरे के पूरे दो लाख रुपये मिले और उन लोगों ने कहा कि हम लोग गांव के विकास में पैसा खर्चने पर सहमत हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश की परम्परा रही है हम दूसरे के बुरे में भी बराबर की भागीदारी करके उनकी भी

मदद करते रहे हैं अगर कोई नहीं चाहता तो न ले लेकिन सरकार ने अपने साधनों से ऐसा किया। यह प्रचारित किया जा रहा है कि माल किसी का कमाल किसी का। प्रदेश के दो मुख्य मंत्री बैठे हैं लेकिन चौधरी बंसी लाल जी शायद यहां पर नहीं हैं वे लॉबी में कहीं कन्वैसिंग करते होंगे, उनको भी इस बात का ज्ञान है कि हर रियासत को उसके हिस्से के मुकाबले नैचुरल कैलेमिटी फण्ड मिलता है और उसी फण्ड के द्वारा यह पैसा दिया जाता है। केन्द्र सरकार की तरफ से सूखे के लिए राहत के नाम पर एक दुवन्नी नहीं मिली है। प्रधान मंत्री जी ने भी बहुत घोषणा की थी कि हम सूखे के नाम पर बहुत कुछ देने जा रहे हैं और उपाध्यक्ष महोदय, इस बहुत कुछ के नाम पर कान्फ्रैंस बुला कर यह कहा गया था कि व्याज ख्य किए गए हैं और हमारे प्रदेश की सरकार के पास चिट्ठी है और उस चिट्ठी में लिखा है कि यह जो ब्याज का पैसा है यह प्रदेश की सरकारें वहन करेंगी। ये सीमा में रह कर बात करें बजट से आगे जाने का प्रयास न करें। जो पैसा है हमने अपने सीमित साधनों का उपयोग करके दिया है उसके लिए राजनीतिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है ये राजनैतिक हैसियत देखकर बात करें। (विघ्न)

चौ० भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुनें। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः भजन लाल जी, आप बीच में किस लिए खड़े हो गए हैं आपको पहले मौका मिला था और फिर भी बोलने के लिए मौका मिलेगा इसलिए अभी आप बैठें। (विघन)

श्री कृष्ण पालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को कहना चाहूँगा, इन्होंने मेरी हैसियत की बात की है। मेरी हैसियत मुख्य मंत्री जी तय नहीं करते हैं 1 (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः कृष्ण पाल जी, आप बजट पर बोलें। (विघन)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः इसको फिर वहम हो गया है। मैंने इसका नाम तक नहीं लिया है। मैंने कहा है कि अपनी हैसियत में और अपनी औकात में रहें। इसका मतलब आपको अपनी औकात का ज्ञान हो गया है। (विघन) मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहता किसी का नाम लेकर के बात कहने में यकीन नहीं रखता हूँ। लोग अपनी हैसियत को स्वयं पहचानें, इसी में उनकी भलाई है। (विघन)

चौ० भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, इनको भी सभ्य भाषा बोलनी चाहिए। इन्होंने अभी जिस भाषा का प्रयोग किया है क्या वह सभ्य भाषा का प्रयोग किया है? (विघन)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः ये तो नए आए हैं और काफी बाद में आए हैं। मैं क्या इनसे सीखूंगा। मैंने तो आपसे सीखा है। आप सदन के पुरानें सदस्य रहे हो। आप मेरे से दो वर्ष पहले

आए थे। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है और आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। (विघन) चौधरी भजन लाल जी, आपसे और चौधरी बंसी लाल जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है (विघन) अब मैं इनसे सीखूंगा क्या, अपनी हैसियत बिगाडूंगा। यह कोई बात है। (विघन)

श्री कृष्ण पालः उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी मेरे ऊपर चक्रे कितना गुस्सा कर लें मैं उखडूंगा नहीं। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः आप अपनी बात करें और बजट पर बोलें। (विघन)

श्रीकृष्ण पालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि ख्य मंत्री जी मेरे ऊपर चाहे कितना गुस्सा कर लें मैं इनसे उखडूंगा नहीं। क्योंकि–

'' बरसात में तालाब भी हो जाता है कमजर्फ,

बहार आने से कभी समन्दर नहीं होता। '' (विघन)

श्री उपाध्यक्षः कर्ण सिंह दलाल जी, आप अपनी सीट पर बैठें। इनको वकील की कोई जरूरत नहीं है। (विष्य) कर्ण सिंह जी, आप अपनी सीट पर बैठ जाएं। (विघ्न) रघुबीर कादियान जी, आप अपनी सीट पर बैठें। सदन का डैकोरम बनाएं रखें। (विघ्न)

श्री कृष्ण पाल: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरे बोलने पर किसी को गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: आप समय का भी ध्यान रखें।

श्री कृष्ण पाल: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सारा समय तो इन्होंने बीच में टोका टाकी करके ले लिया है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं और उसमें से हरियाणा को भी पैसा मिलता है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 50 सालों की तुलना में एन०डी०ए० की सरकार ने चार साल में अटल जी के नेतृत्व में दो काम किए हैं वह बहुत ही बेहतरीन किए हैं। उसकी मिसाल आज कहीं पर भी नहीं मिलती है। चाहे प्रधान मंत्री सड़क योजना हो, चाहे 60 हजार करोड़ रुपए की ग्रामीण जल योजना हो या कोई दूसरी योजना हो उन योजनाओं के द्वारा गरीब लोगों को दो रुपए किलो गेहूँ और तीन रुपए किलो चावल मिलते हैं ये फैसिलिटी पांच करोड़ लोगों को मिलती है। इन्दिरा आवास योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना और फसल बीमा योजना हो। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंह: आप प्रदेश से रिलेटिड बात करें।

श्री उपाध्यक्ष: कृष्ण पाल जी, आप जो स्कीमें बता रहे हैं क्या इनके बारे में आपके पास हरियाणा से रिलेटिड फिग्गर्ज हैं।

श्री कृष्ण पालः उपाध्यक्ष महोदय, इन स्कीमों का पैसा हरियाणा में भी आता है। (विघन) वही तो मैं बोल रहा हूँ। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, इस पर एतराज तो कांग्रेस पार्टी को होना चाहिए इनको नहीं होना चाहिए। केन्द्र की नीतियों पर ऐतराज तो कांग्रेस की सरकार को होना चाहिए। इनको पता नहीं क्यों ऐतराज हो रहा है? हमारे सहयोगियों को पता नहीं क्यों ऐतराज हो रहा है?

श्री उपाध्यक्षः क्या आप यह चाहते हैं कि आपको बार–बार लोग इन्टरवीन करें। (विघन) फिर आप क्यों ऐसी बात करते हो जिससे वे आपको इन्टरवीन करें। आप आपने हल्के की बात रखें।

श्री कृष्ण पालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं वही तो कह रहा हूँ कि 50 वर्षों में 1.86 करोड़ टैलीफोन कनैक्शन लगे हैं और केन्द्र में हमारी सरकार के चार वर्षों में 285 करोड़ टैलीफोन कनैक्शन लगे है। (विघन) उपाध्यक्ष महोदय, अब इसमें इनको क्या दिक्कत हो गई?

श्री उपाध्यक्षः कृष्ण पाल जी, आप एक मिनट बैठें। (विघन) गोयल साहब प्लीज नो। (विघन) बलबीर सिंह जी आप बोलें।

श्री बलबीर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित साथी को बताना चाह रहा हूँ कि पहले भी केन्द्र में

अटल जी के नेतृत्व वाली सरकार थी। हरियाणा प्रदेश में चौधरी बंसी लाल जी की सरकार थी। सम्मानित साथी कृष्ण पाल जी मंत्री थे, ये पहले मंत्री की कुर्सी पर थे अब इनकी कुर्सी बदल गई है। यह उस समय साढ़े तीन साल में सड़क का एक टुकड़ा भी नहीं बनवा पाए थे। अगर बनवाया हो तो बताएं। यह एक मिसाल है। इन्होंने तो एक काम किया था वह यह किया था कि इनकी बसों में दारू की थैलियां बिका करती थीं। यह तो इनका काम था।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जो काम हरियाणा प्रदेश में हो रहा है वह आदरणीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार द्वारा हो रहा है। सैन्टर की जिन योजनाओं के बारे में सम्मानित साथी ने कहा है जैसे कि इन्दिरा आवास योजना, जवाहर लाल आवास योजना जो हैं वे तो पहले से चल रही हैं। इसकी प्रोपर मिसाल यह थी कि बी.जे.पी. की जब केन्द्र में सरकार बनी थी तो उस वक्त केन्द्र की सरकार की तेरहवीं मनी थी। अब तो एन.डी.ए. की सरकार है। बी.जे.पी. का इसमें कोई खाता नहीं है। बी.जे.पी. के नाम से तेरहवीं मर्क थी। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः पहलवान जो, बैठिए। हां जा कृष्ण पाल जी, आप बोलिए।

श्री बलबीर सिंहः बी०जे०पी० की केन्द्र में जो सरकार बनी थी उसकी तेरहवीं मन गयी थी अब तो केन्द्र में एन०डी०ए०

की सरकार है बी०जे०पी० की नहीं। बी०जे०पी० की सरकार की तो तेरहवीं मनी थी।

श्रीकृष्णलालः उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सम्मानित सदस्य बलबीर सिंह जी ने मेरा नाम लिया है और कहा है कि बसों में शराब बिकती थी। उपाध्यक्ष महोदय, किसी की बस में कौन सी सवारी दो बोतल लेकर बैठ जाएं इस बारे में क्या कुछ कहा जा सकता है। यह हो सकता है। (विघ्न) मैं मान रहा हूँ सवारी से दो बोतल शराब पकड़ी गयी हो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जून 2001 में इंग्लिश वाइन पर जो बीस परसैंट ऐक्साइज ड्यूटी लगायी गयी थी उसे अक्टूबर, 2001 में .... कैबिनेट ने समाप्त कर दिया।

प्रो० सम्पत सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, ये शब्द रिकॉर्ड नहीं किए जाने चाहिएं।

श्री कृष्ण पालः उपाध्यक्ष महोदय, यह रिकॉर्ड की बात है।

श्री उपाध्यक्षः मोटी रकम वाली बात रिकॉर्ड न की जाए। गुज्जर साहब, आप बजट पर ही बोलें। (विघ्न)

श्री कृष्ण पालः उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने मेरा नाम लिया है। (विघन)

श्री उपाध्यक्षः उन्होंने आपकी बात को ही क्लीयर किया है। (विघन)

श्रीकृष्ण पालः उपाध्यक्ष महोदय, बलबीर सिंह जी, फरीदाबाद में भी पहलवानों को लेकर खानें लूटने चले थे और कई महीने लूटी भी थी। (विघन)

श्री बलबीर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, चोर ने चोर ही दिखा करे। दलाल साहब चोर और ये भी चोर हैं। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लिया गया है। मेरा पर्सनल नोम लिया गया है।

श्री कर्ण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदय, बलबीर सिंह चोर है इसका बाप चीर है फिर यह हमें कैसे कहते हैं कि चोर हैं। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः आप सभी बैठें।

श्री कृष्ण पालः उपाध्यक्ष महोदय, उधर नहीं बल्कि इधर तो अलीबाबा और चालीस चोर बैठे हैं। (विघन)

श्री उपाध्यक्षः गुज्जर साहब, आप कोई इस तरह का शब्द न बोलें जो एक दूसरे के लिए अनपार्लियामैंट्री हो। (विघन)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वातावरण में किसी प्रकार की तल्खी और कटुता नहीं आनी चाहिए। यह ठीक है कि कुछ

एक आपत्ति है। अगर कर्ण सिंह दलाल की हैसियत उन्होंने छोटी की है चोर बताया है तो मैं कहना चाहूँगा कि इनकी हैसियत तो उन्होंने छोटी नहीं की बल्कि इनकी हैसियत ऊंची ही की है।

श्री कर्ण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदय, चोर को चोर ही नजर आते हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः इनकी हैसियत उन्होंने कम बतायी है यो तो उससे भी ऊंचे हैं। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः दलाल साहब, आप बैठिए। उन्होंने आपको चोर नहीं कहा है। (विघन) **श्री ओम प्रकाश चौटालाः** उपाध्यक्ष महोदय, मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि जिनको आपने बोलने का अवसर दिया, वही बोल रहे हैं। कृष्ण पाल जी ने कहा कि अली बाबा चालीस चोर इधर बैठे हैं उधर नहीं तो ये स्पष्ट कर दें कि अली बाबा चालीस चोर कौन हैं और उनके समर्थक कौन ई?

श्री कृष्ण पालः उपाध्यक्ष महोदय, समझने वालों ने समझ लिया इसलिए स्पष्ट करने की जरूरत ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्षः गुज्जर साहब, आप कोई भी ऐसे सुन्दर वाक्य न बोलें जिनका आपके द्वारा जबाव न दिया जा सके।

प्रो० सम्मत सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, इनको क्लीयर करना ही पड़ेगा। अब इस तरह की बकवास नहीं चलेगी।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः बहुत दिन तक इसको बर्दाश्त कर लिया इसलिए अब इसको क्लीयर करना ही पड़ेगा। असैम्बली की प्रोसीडिंग्ज में यह बात दर्ज है। इन्होंने क्या तमाशा बना रखा है। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः आप सभी बैठ जाएं। गुजर साहब, आप बोलें। आप या तो अपनी बात क्लीयर करें या अपने शब्द वापस लें।

श्री कृष्ण पालः इनको भी अपने शब्द वापस लेने चाहिएं जो इन्होंने मेरे बारे में कहे हैं। **श्री उपाध्यक्षः** गुजर साहब, आपने ही उनको पहले फरीदाबाद में खानें लूटने की बात कही है।

श्री कृष्ण पालः नहीं नहीं, मैंने तो बाद में यह बात कही है। (विघन)

श्री उपाध्यक्षः कृष्ण पाल जी, आप वही भाषा बोलें जिसको कि आप क्लीयर कर सकें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पालः उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तब यह बात कही, जब इन्होंने दारू की बात शुरू की थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है मैं फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि सम्मानित सदस्य ने इधर हाथ करके यह कहा है कि अली बाबा और चालीस चोर इधर बैठे हैं, इसको ये स्पष्ट करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्णपालः उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्ट करने की जरूरत ही नहीं है, समझने वालों ने समझ लिया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः यह स्टेज नहीं है, यह राजनीतिक मंच नहीं है, यहां सम्मानित सदस्य जो बात कहता है वह जिम्मेदारी के साथ कह सकता है।

चौ० भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि अलीबाबा और चालीस चोर वाली जो बात कृष्ण पाल गुज्जर ने कही है वह हाउस की कार्यवाही में से निकालनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः यह बिलकुल नहीं निकलनी चाहिए यह तो स्पष्ट करना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान) यह मामला इस किस्म का है यह क्लीयर करना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० भजन लालः यह बात कार्यवाही में से निकालनी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्षः कर्ण सिंह जी, आप बैठ जाएं। अजय सिंह जी, आप बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, जैसे इन्होंने बलबीर सिंह जी का जिक्र किया। अगर कोई मैम्बर पर्सनल ऐलीगेशन लगाता है तो उससे उसका स्पष्टीकरण ले लें, इसमें कोई दिक्कत

नहीं है। लेकिन यह कहना कि अलीबाबा और चालीस चोर तो यह 41 आदमियों पर कलैक्टिवली चार्ज लगाया है इसका इनको बताना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा। एक तरफ तो ये इस तरह की बातें करते हैं। इनको बताना पड़ेगा कि वह कौन है?

श्री उपाध्यक्षः कृष्ण पाल जी, आप स्पष्ट करें।

श्री कृष्ण पालः उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कह दिया है और समझने वालों ने समझ लिया है। पहले बलबीर सिंह ने चोर कहा है।

श्री उपाध्यक्षः यह कोई पब्लिक प्लेटफार्म नहीं है। यहां आप ऐसी बातें नहीं कह सकते हैं। यह हाउस है। मेरी सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि बैठे—बैठे न बोलें। (शोर एवं व्यवधान) जो शब्द आपने कहे हैं पहले आप उनको स्पष्ट करें।

श्री कृष्ण पालः मैंने कहा है कि थानों में लूट हो रही है। चोर मैंने नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्षः सबसे पहले आपने कहा था कि बलबीर वहां पर पहाड़ों को लूटने चला गया।

श्री कृष्ण पालः मैने चोर नहीं कहा था। चोर इन्होंने कहा था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः आप दोनों की बात चल रही थी लेकिन आपने जो 41 आदमियों पर सामूहिक आरोप लगाया है उसका स्पष्टीकरण दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पालः अगर वे चोर नहीं हैं तो बुरा क्यों मान रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंहः इस तरह की बात नहीं चलेगी। कहीं कुछ, कहीं कुछ। यह इनको स्पष्ट करना पड़ेगा। इन्होंने जो किया है। That was all personal attack. He will have to explain that. लेकिन ये तो क्लैक्टिव कह रहे हैं जो इन्होंने कहा that was all personal attack.

श्री उपाध्यक्षः आप इस बात को न दोहरायें। सबको पता है किस ने क्या कहा है। आपने जो सैटेंस कहा है या तो उसको वापस लें या यह स्पष्ट करें कि जिन 41 सदस्यों के नाम आपने लिए हैं उनको कोट करो या अपने शब्द वापस लें बस ये दो ही चीज हैं। आपने बलबीर सिंह का नाम लिया और उन्होंने आपका नाम लिया आप बराबर हो गये लेकिन आपने हाउस के या सदस्यों के नाम लिए हैं। आपने सदस्यों पर आक्षेप लगाया है (विघन)

श्री कृष्ण पालः अगर वे नहीं हैं तो इस बात को सीरियसली क्यों ले रहे हैं?

श्री उपाध्यक्षः आप ऐसा नहीं कह सकते।

प्रो० सम्पत सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, नहीं हैं, इसलिए सीरियसली ले रहे हैं।

श्री उपाध्यक्षः या तो जो 41 सदस्यों के बारे में कहा है या तो उनके नाम बतायें या आप अपने शब्दों को वापस लो।

श्री कृष्ण पालः अगर वे नहीं हैं तो इस बात को सीरियसली क्यों ले रहे हैं?

प्रो० सम्पत सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, इधर–उधर नहीं चलेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्षः आपने जो हाउस में जिम्मेवारी के साथ बात की है आप जिम्मेवारी के साथ उसको स्पष्ट करें।

श्री कृष्ण पालः इनके सदस्यों ने कुछ नहीं कहा।

श्री कर्ण सिंह दलालः जब बलबीर सिंह ने इनका नाम लिया है।

श्री उपाध्यक्षः आप बैठें। इन्होंने जो वा आदमियों के बारे कहा है उस बात को स्पष्ट करें।

श्री कृष्ण पालः पहले उन्होंने आरोप क्यों लगाया?

श्री उपाध्यक्षः कृष्ण पाल जी, ऐसे काम नहीं चलेगा हाउस में जो भी बात कहें वह जिम्मेवारी के साथ कहें।

श्री कृष्ण पालः इन्होंने भी तो जिम्मेवारी के साथ कही है।

श्री उपाध्यक्षः शिकायत तो आपने की है।

श्री कृष्ण पालः उन्होंने शिकायत की है कि बसों के अन्दर शराब बेची जाती थी।

श्री उपाध्यक्षः जिन 41 सदस्यों के बारे में कहा है या तो उनके नाम बतायें या आप अपने शब्दों को वापस लें। (विघ्न)

श्री कृष्ण पालः दो सदस्य जो महत्व रखते हैं अन्य सभी सदस्य भी वही बराबर महत्व रखते हैं। या सदस्य भी वही महत्व रखते हैं। केवल संख्या से महत्व कम नहीं हो जाता।

श्री उपाध्यक्षः 41 के नाम बतायें या फिर आपने सभी 90 सदस्यों पर ऐलीगेशन लगाया है।

श्री कृष्ण पालः मैंने तो नाम नहीं लिया इन्होंने तो हमारा नाम भी लिया है। (विघ्न)

प्रो० सम्पत सिंहः डिप्टी स्पीकर सर, ये जो चाहते हैं अपनी जबान से कहें। ये कहते हैं कि मैंने नाम नहीं लिया। इन्होंने नाम लिया है। बात क्लीयर हो गई है। लेकिन इन्होंने जो ऐलीगेशन लगाया है उन 41 आदमियों के नाम क्लीयर करें अदरवाईज 90 के 90 सदस्यों को इन्होंने हर आदमी को चोर

बनाकर छोड़ दिया है इसलिए स्पष्ट करें कि वे 41 कौन हैं ये स्पष्ट कर दें इससे क्लीयर हो जायेगा।

चौ० भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने नाम नहीं लिया इन्होंने तो यह कहा है कि 40 चोर हैं और एक अली बाबा। मैं यह कहता हूँ कि ये शब्द कार्यवाही से निकलवा दिये जायें और असैम्बली का माहौल ठीक करके हाउस को चलाया जाये।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः क्या इनको ऐसी बात कहने का अधिकार है ? जब तक ये अली बाबा चालीस चोर का, एक–एक करके नाम नहीं गिनाएगे कि इन 90 में से कौन या होंगे क्योंकि इन्होंने 9० के 9० चोर बताए हैं। भजन लाल जी, आप कहते हैं कि 90 नहीं बताए। कैसे नहीं बताए। जब तक 41 के नाम क्लीयर नहीं होंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि इन 90 में से या कौन से हैं। ये क्लीयर करना पड़ेगा, एक आदमी को यह कहने का अधिकार नहीं है इसलिए इनको स्पष्ट करना पड़ेगा या फिर इनको माफी मांगनी पड़ेगी। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० भजन लालः इन्होंने नाम नहीं लिया, इन्होंने हाथ करके बताया है।

श्री ओमप्रकाश चौटालाः हां–हां, हाथ करके बताया है, हाथ तो पत्रा नहीं कहां चला जाता है, हाथ तो इस सिरे से उस सिरे तक चला जाता है। मेरा उपाध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि या तो ये स्पष्ट करें या इनको माफी मांगनी पड़ेगी। (शोर)

डॉ० रघुबीर सिह कादियान: अध्यक्ष महोदय ....

श्री उपाध्यक्ष: रघुबीर कादियान साहब, आप बैठें, आपको भी सदन के समय की चिंता होने लगी।

श्री कृष्ण पाल: अध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूँ। (शोर एवं व्यवधान)?

श्री उपाध्यक्ष: कृष्ण पाल जी, आप वरिष्ठ मैम्बर हैं जो कहते हैं उसको जिम्मेवारी के साथ निभाएं।

श्री कृष्ण पाल: मैं कई बार कह चुका हूँ जिस तरह बलबीर जी ने सीधा नाम लेकर दो सदस्यों को चोर कहा।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी आपस में जो बात हुई उस का तो हो गया, आपने इनको कहा उन्होंने आपको कहा, इन्होंने जो एक दूसरे को गलत शब्द कहे वे कार्यवाही से निकलवा दिए गए। आपने जो 41 आदमियों पर आक्षेप किया है उनको क्लीयर करें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कर्ण सिंह दलाल: अध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कहनी है। (शोर एवं विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिए।

श्री कृष्ण पाल: यह हाउस शांतिपूर्ण ढंग से चलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः इसमें आपकी भी जिम्मेवारी है, मेरा तो पूरा प्रयास है कि हाउस शांतिपूर्वक चले। (शोर)

श्री कृष्ण पालः इनको इसके लिए इतना सीरियस नहीं होना चाहिए। मैंने तो कहावत के तौर पर लिया था। (शोर)

श्री उपाध्यक्षः आप जो मर्जी आए वह कह देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूँ।

श्री उपाध्यक्षः पहले आप स्पष्टीकरण दें।

श्रीकृष्ण पालः इससे ज्यादा और क्या स्पष्टीकरण होगा? (शोर) माफी तो ये मांगे, मैं माफी नहीं मांगता। (शोर)

श्री उपाध्यक्षः आप अपने शब्द पर स्टैण्ड करते हैं क्या?

श्री कृष्ण पालः मैं स्टैण्ड नहीं करता। मैंने तो इतिहास की कहावत कही है कि हरियाणा में आम लोग कहते हैं कि हरियाणा में ऐसा हो रहा है। (शोर)

श्री उपाध्यक्षः ये शब्द क्या आपके नहीं हैं? लोगों की बात आप नहीं कह सकते। यहां आप द्वारा कही गई बात कृष्ण पाल के नाम से दर्ज है। सुनी सुनाई बात आप यहां नहीं कह सकते। आप ओथ लेकर यहां आए हैं।

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राम पाल माजरा): उपाध्यक्ष महोदय, एक दिन मैंने प्रश्नोत्तर– काल में मामूली सी बात बहन जी को कही थी कि आपने क्या पढ़ा? उस पर इस तरफ से सारे बैंचिज ने अफसोस प्रकट किया था। इसलिये ये शब्द भी इनको वापिस लेने चाहिये या इनको माफी मांगनी चाहिए। (शोर)

राव दान सिंहः आपने डांटकर यह बात कही थी।

श्री राम पाल माजराः मैंने तो कहा था कि जो रिप्लाई गया था क्या वह आपने पढ़ा? जब इन्होंने कहा आप इसको महसूस करें तो मैंने महसूस किया। आज ये ऐसी बात कहते हैं, इन्होंने या आदमियों को इतना कह दिया साथ में आपको भी शामिल कर लिया। फिर भी ये कांग्रेस के साथी कृष्ण पाल को कह रहे हैं कि न तो आप इस शब्द को वापस लें और न माफी मांगे। इनकी दोगली नीति इनको परेशान करेगी? कृष्ण पाल जी, आपसे तो इतना ही कहूँगा और सही सुझाव देता हूँ कि तेरा पीछा छूटे तो छुड़वा ले नहीं तो तेरे साथ बहुत बुरी होगी।

श्री कृष्ण पालः उपाध्यक्ष महोदय, इस मुख्य मंत्री के रहते मेरा हरियाणा से पीछा नहीं छूट सकता, मैं तीन सालों से भुगत रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः आप दो बातों में से एक बात करें। मैं चेयर पर रहूँ या न रहूँ मैं परवाह नहीं करता। आप दो में से एक क्लीयर करें या तो आप स्पष्टीकरण देकर उन 41 आदमियों के

बारे में पूरा साफ और जिम्मेदारी से क्लीयर करें या अपने शब्द वापिस लें।

श्री कृष्ण पालः मैंने पहले भी कह दिया और अब भी कह रहा हूँ कि हरियाणा में आम कहावत है। मैंने वही बात कह दी। मैं यह बात भी कहूँगा कि जो ऐसे हैं वे अपने आप में आत्ममंथन कर लें और जो ऐसे नहीं है उनको मेरी बात से ठेस लगी है तो मैं इसके लिए महसूस करता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे जिम्मेवारी से नहीं बचा जा सकता। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः कृष्ण पाल जी, आप अपने ऐसे शब्दों को वापिस लें, तभी आगे बात होगी। पब्लिक की कही बात आप यहां नहीं कह सकते। लोग तो पता नहीं बाहर किस के बारे में क्या कहते हैं, वे बातें आप यहां नहीं कह सकते। यहां तो वे बातें आपकी तरफ से कही मानी जायेंगी।

श्री कृष्ण पालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं माफी (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः कृष्ण पाल जी, मैं आपसे शब्द वापिस लेने की बात कह रहा हूँ माफी की बात नहीं कर रहा, या आप स्पष्टीकरण दें।

श्री कृष्ण पालः ....

श्री उपाध्यक्षः कृष्ण पाल जी जब तक दो बातों का स्पष्टीकरण नहीं दे देते तब तक उनकी कोई बात रिकॉर्ड न की जाये। कृष्ण पाल जी जो दो बातें मैंने कहीं हैं, उनमें कोई भी गलत बात नहीं है। (शोर एवं व्यवधान) यह मैं रूलिंग दे रहा हूँ। (शोर एवं व्यवधान) कृष्ण पाल जी, आप मेरे से बात करें।

श्री कृष्ण पालः ....

श्री उपाध्यक्षः कृष्ण पाल जी, सभी सदस्य जनता के नुमाइंदे हैं, जनता के नुमाइंदों को चोर कहने का लाईसेंस आपको किसने दिया? (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पालः ....

श्री उपाध्यक्षः कृष्ण पाल जी, आपको बजट रार बोलने के लिए 22 मिनट का समय दिया गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पालः ....

श्री उपाध्यक्षः कृष्ण पाल जी, आप जो भी आकड़े बतायेंगे, उनको सुना जायेगा लेकिन ब्लेकमेलिंग नहीं चलेगी। (शोर एवं व्यवधान) पहले आप स्पष्टीकरण दें (शोर एवं व्यवधान) आप दूसरों को चोर कैसे बता सकते हो? (शोर एवं व्यवधान)

श्री भगवान सहाय रावतः आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन गरिमामय है और हरियाणा की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इसके कुछ नियम और कानून बने हुए हैं। एक सदस्य

यदि किसी दूसरे पर दोषारोपण करता है तो उसकी पर्सनल एक्सप्लेनेशन के द्वारा यहां समाधान की व्यवस्था है। लेकिन जो इशारा इंगित करके या अपनी बात की इटेंशन क्लीयर न रखते हुए बार–बार अपनी स्टेटमैंट को बदले यह ठीक नहीं है। 40+1 यानि 41 आदमियों के बारे में इन्होंने कहा जिन्होंने इन्हें कुछ नहीं कहा। उपाध्यक्ष महोदय, यह अवमानना का प्रश्न है, यह बहुमत की अवमानना का प्रश्न है, यह हरियाणा की जनता की नैतिकता के अधिकार का प्रश्न है जिसने एक ऐसे व्यक्ति को यहां जन प्रतिनिधि के रूप में भेजा है। उनको ऐसी बात कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सदन द्वारा इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कृष्ण पालः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुझे धमकी न दें। ((विघन) मैं धमकी सहने का आदी नहीं हूँ। (विघन)

श्री उपाध्यक्षः औरों को आप कुछ भी कह लें। (विघन)

श्री कृष्ण पालः मैं धमकी सुनने का आदी नहीं हूँ।

श्री उपाध्यक्षः कृष्ण पाल जी, आपको मैंने दो बातें कही हैं उनमें से एक बात आप करो। मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूँ। (विघन)

श्री कृष्ण पालः उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बार–बार कहा है कि हरियाणा में जो चर्चा है। (विघन)

श्री उपाध्यक्षः आप फिर नहीं कह सकते। आप सीनियर मैम्बर हैं। आप यहां पर लोगों की बात इस ढंग से नहीं कर सकते। यहां पर आपकी बात कृष्ण पाल के नाम से दर्ज है। (विघन)

श्री कृष्ण पालः हम सदन में आये ही इसलिए हैं कि हम लोगों की बात कर सकें।

श्री उपाध्यक्षः नहीं, आप किसी को चोर नहीं बताएं। (विघ्न)

श्री कृष्ण पालः हम जनता की भावनाओं की तो बात कर सकते हैं। (विघन)

श्री उपाध्यक्षः आप समय बर्बाद नहीं करेंगे। (विघ्न)

श्री कृष्ण पालः मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा (विष्य)

श्री उपाध्यक्षः दो बातें जो मैंने कहीं हैं आप उनमें से एक बात पर बात करेंगे।

श्री कृष्ण पालः मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। (विघन) मेरे पास तो बहुत सी चीजें हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। आप समय बर्बाद कर रहे हो और सदन की अवमानना कर रहे हो। (विघ्न)

श्री कृष्ण पालः वह तो मैं मानता हूँ कि आपने मुझे वार्न करना ही है। पहले स्पीकर साहब वार्न कर गए अब आप वार्न कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्षः नहीं, नहीं। मेरी समझ में नहीं आता, आप अपने को सबसे ज्यादा अकलमंद मानते हैं। (विघ्न)

श्री कृष्ण पालः नहीं, नहीं मैं अपने को अकलमंद नहीं मानता। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः आप दो शर्तों में से एक शर्त पर बात करें। (विघ्न)

श्री कृष्ण पालः अकलमंदी का सर्टीफिकेट लेने की मुझे किसी से जरूरत नहीं है। (विघान)

श्री उपाध्यक्षः ये मैम्बर्ज भी आपसे सर्टीफिकेट नहीं लेंगे। आप किसी को चोर नहीं कह सकते। पूरे सदन को आप चोर नहीं कह सकते।

श्री कर्ण सिंह दलालः हरियाणा की जनता में जो चर्चा होती है (विघान)

श्री उपाध्यक्षः आप हरियाणा की जनता के अकेले कब से ठेकेदार बन गए?

श्री कृष्ण पालः मैं हरियाणा की जनता की बात कर रहा हूँ। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः ये बाकी 89 मैम्बर्ज हैं क्या ये जनता के नुमाइन्दे नहीं हैं?

चौ० भजन लालः हरियाणा की जनता ने हमें चुन करके भेजा है, उनकी दु:ख तकलीफ की बात हम कर सकते हैं। इन्होंने कह दिया। (विष्य)

श्री उपाध्यक्षः चौधरी भजन लाल जी, ये 25 मिनट बोले हैं। (विघ्न)

चौ० भजन लालः अगर इन्होंने कह दिया है तो आप उसको कार्यवाही से निकाल दो, उससे क्या फर्क पड़ता है? (विघन)

प्रो० सम्पत सिंहः सर, मैं यह कह रहा था कि पहले दिन से यह प्रयास है कि एक–एक मिनट कीमती है और उसका प्रोपर यूटीलाइजेशन होना चाहिए। जिस दिन से सैशन शुरू हुआ सरकारी पक्ष की तब से यही मंशा रही और हमको जितनी स्पोर्ट करनी चाहिए वह की है। हमारे हाउस के लीडर ने बार–बार ईवन हमारे एम०एल०एज० को भी टोका है कि इनके बीच में बोलते हुए मत खड़े हों, इन्ट्रप्ट मत करे और उनको बोलने दें। क्योंकि हमारा इन्ट्रैस्ट ऑफ डैमोक्रेसी है। इतना खर्चा हो रहा है और यह बजट अधिवेशन है। यह सबसे ज्यादा जरूरी अधिवेशन होता है।

हरियाणा प्रदेश की 2 करोड़ 10 लाख जनता की नजर आज इधर लगी हुई है। हम सभी लोग उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। चाहे वह किसी पार्टी विशेष के हैं, चाहे वह इन्डीपैन्डेंट हैं, ऐसे पीना घण्टा बर्बाद कर दिया। पौने घण्टे के अन्दर जिस तरह का वातावरण एक सदस्य विशेष ने बनाया है उसकी वजह से सारे हाउस का इतना समय बर्बाद हो रहा है, वह ठीक नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बात का तुरन्त फैसला करें ताकि हाउस की कार्यवाही चल सके। यह कोई एक मैम्बर का समय नहीं है और न ही एक मैम्बर का हाउस है। हरियाणा प्रदेश की 2 करोड़ 10 लाख जनता द्वारा भेजे गए 90 सदस्यों का हाउस है। और उन सभी 90 सदस्यों का टाईम है और ये समय बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बारे कोई फैसला करें और आप संबंधित सदस्य से पूछ करके कि उन्होंने जो सवाल पुट किया हैय उसके बारे में उनकी क्या राय है, वह स्पष्ट कर दें। उसके बाद आप जो फैसला करेंगे वह हमें मान्य होगा।

श्री कृष्ण पालः उपाध्यक्ष महोदय, मुझ से आप बार–बार पूछ रहे हैं और मैं यही कह रहा हूँ कि यह हरियाणा की जनता की भावनाओं की अभिव्यक्ति है (विघन) मैंने किसी एक पर्सन पर या एक आदमी पर आरोप नहीं लगाया। मैंने किसी का नाम लेकर कोई आरोप नहीं लगाया। (विघन)

श्री उपाध्यक्षः आप बताएं कि जो दो शर्तें मैंने आपको कहीं हैं उनमें से कोई मानने के लिए तैयार हैं या नहीं।

श्री कृष्ण पालः क्या?

श्री उपाध्यक्षः At page No. 818 of the Practice and Procedure in Parliament by Kaul and Shakdhar, it is mentioned :-

"A member has to be careful while making an allegation. He has to satisfy himself that the source is reliable and the allegation is based on facts. In fact, he is required to make prima facie investigation into the matter before he writes to the Speaker or the Minister and more so, before be speaks in the house."

यह जो आप कह रहे हैं कि पब्लिक की बात है, मैंने इस बारे में आपसे कहा है और कौल एण्ड शकधर की जो बुक है उसमें से भी मैंने आपको बता दिया है, अब आप अपनी बात कहिए।

श्री कृष्ण पालः उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि मैं हमेशा जनता की बात कहता हूँ लेकिन मुझ से पहले कम सें कम हम जिन दो साथियों को चोर कहा है उनकी भी बात करें, उन्होंने किस हक से कह दिया, कग उन पर यह कानून लागू नहीं होता है?

श्री उपाध्यक्षः उन्होंने तो नाम ले कर कहा है, आप उनकी बात को बार–बार दोहरा कर सदन का टाईम खराब न करें।

श्री कृष्ण पालः उन्होंने भी यह कहा है कि एक चोर दो चोर डबल चोरः उन्होंने भी नाम नहीं लिया। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः अब आप बैठिये (विघन) आपने तो कहा है और या आदमियों का जिक्र किया है। आप इन 41 आदमियों के नाम लीजिए या आप बैठिए। इसी बात को ले कर आप पीने दो घण्टे से सदन का समय बरबाद कर रहे हैं। उनकी और आपकी दोनों की बात समाप्त हो गई है (विघन) उन्होंने नाम ले कर कहा है। (विघन)

श्री कृष्ण पालः उन्होंने कहा एक चोर दो चोर डबल चोर। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः बड़ी सीधी बात है आप दोनों में से एक बात कर लें वरना मैं आपको दूसरी बार वार्न करता हूँ।

श्री कृष्ण पालः उपाध्यक्ष महोदय, आपने अगर मुझे वार्न करने की ठान ही ली है तो मैं इस बारे में क्या कह सकता हूं? (विघन)

श्री उपाध्यक्षः मेने नहीं आपने ठान रखी है आप दो में से कोई एक बात करें। आप बार– बार यही बात कह रहे हैं

(विधन) अगर आपने ऐसा करना हैं तो इस बोरे में मैंने आपको रूल की पोजीशन बता दी है और हाउस में जो कन्वैंशन है वह आपको सीनियर आदमियों ने बता दी है। अगर इसके बाद भी आपका यही रवैया रहता है तो मुझे आपके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी। (विधन) बिलकुल सीधी सी बात है। (विधन)

श्री कृष्ण पालः उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि आप या तो मुझे धमकी दे रहे हैं (विघन) **श्री उपाध्यक्षः** यह धमकी नहीं है मैं आपको वार्न कर रहा हूँ (विघ्न) आप बार–बार कैसे बोल रहे हैं, वार्न का क्या मतलब है अंग्रेजी में या हिन्दी में इसके अर्थ आप खुद लगा लें। मैं आपको दो बार वार्न कर चुका हूँ (विघन) अब तीसरी बार आपको वार्न कर रहा हूं। कृष्ण पाल जी, अगर आपने इस बात को वापिस नहीं लेना है तो मैं तीसरी बार और फाइनली आपको वार्न कर रहा हूँ। (विघन)

श्री कृष्ण पालः ऐसा है उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि उसके बाद मैं अपनी बात के बारे में कहूँगा पहले साथी बलबीर जी से कहलवाएं और उनके ऊपर भी यह कानून लाग होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः देखिए आप इसमें अन्तर समझें, उन्होंने एलिगेशन्ज लगाए हैं और बाई नेम लगाए हैं आपने सदन की गरिमा का कोई ध्यान नहीं रखा है तथा पूरे सदन का समय खराब किया ओर 41 आदमियों का जिक्र किया (विघन) I finally warn

you either you take your words back or give the names of the 41 members. (विघन)

श्री कृष्ण पालः मैं आपसे यह प्रार्थना कर रहा हूं कि मैंने हरियाणा की जनता की जौ भावनाएं है उनको प्रकट किया है। (विघन)

श्री उपाध्यक्षः भावना के बारे में मैंने अभी आपको रूलिंग दी हूँ इमसे स्पष्ट और कोई रूलिंग या बात नहीं हो सकती हैं। (विघन)

श्री कृष्ण पालः उपाध्यक्ष महोदय, फिर भी मेरे किसी सम्मानित साथी को लगता है कि उनकी भावना को ठेस पहुंची है तो मैं उनकी भावना की कद्र करता हूँ और अपने शब्द वापिस लेता हूँ। (विघन)

श्री उपाध्यक्षः इन्होंने अपने ऐलिगेशन वापिस लिए हैं (विघन) आप सभी लोग बैठिए। कर्ण सिंह दलाल जी, I warn you. आप बार–बार बीच में उठ रहे हैं। (विघन) आप बैठिए। गुज्जर साहब, अब आगे आप जो भी बोलें जिम्मेदारी के साथ बोलें। (विध्न)

श्री कृष्ण पालः उपाध्यक्ष महोदय, (विघन) मेरा निवेदन यह है कि आपने हमारे शब्द तो एक्सपंज कर दिए इनके शब्द भी एक्सपंज करें। (विघन)

श्री उपाध्यक्षः जब चोर का ऐलिगेशन आया था मैंने पहले ही उसे एक्सपंज कर दिया था आपने एक दूसरे पर ऐलिगेशन्ज लगाए हैं आपने विदड्रा किये हैं उनकी बात तो मैं पहले ही कार्यवाही सै निकलवा चुका हूँ।

श्री कृष्ण पालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा कर रहा था कि केन्द्र सरकार ने पिछले चार सालों में 50 साल की तुलना में जहां टैलीफोन कनैक्शन्ज डबल किए हैं (विष्य)

श्री उपाध्यक्षः आप हरियाणा विधान सभा के बजट से रिलेटिड बात कहें तथा समय सीमा का भी ध्यान रखें (विघन)

श्री कृष्ण पालः मैं कटु रहा था कि विदेशी मुद्रा भण्डार सन 1998 में 32 बिलियन अमरीकी डॉलर था वह 2002 में दुगना हो गया है। वर्ष 2002 में यह 64 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है। यह केन्द्र सरकार और अटल बिहारी जी की नीतियों का परिणाम है कि विदेशी मुद्रा भण्डार डबल हो गया है। (विघन) उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि यह हरियाणा में भी डबल हो। (विघन) जी, हां हम चाहते हैं कि वह हरियाणा में भी डबल हो। हरियाणा का जो बजट का घाटा है और जो ऋण है, वह कम हो। हरियाणा के भण्डार में भी विदेशी मुद्रा का भण्डार जमा हो।

श्री उपाध्यक्षः आप दो मिनट में अपनी बात खत्म करें।

श्री कृष्ण पालः उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अभी कहा ही क्या है। मैंने अभी तो बोलना ही शुरू किया है और कुछ कहा भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्षः अगर आपने कुछ नहीं कहा है तो सदन में किसी ने कुछ बात की ही नहीं है।

श्री कृष्ण पालः अध्यक्ष महोदय, बजट में जो सोर्सिज हैं वह कैसे बड़े, इस बारे में कहना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्षः आपने 12 बजकर 22 मिनट पर बोलना शुरू किया था और अब 1 बजकर 20 मिनट हो गया है।

श्री कृष्ण पालः उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में किस तरह से किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, बिजली का रेट कितना बढ़ा है इस बारे में मुख्य मंत्री ने कहा था कि भजन लाल जी के राज में 5 साल में 49 प्रतिशत बिजली के रेट बड़े, चौधरी बंसी लाल जी के तीन साल के राज में 35 प्रतिशत रेट बड़े। 1.1. 2001 को किसान की बिजली का रेट 60 प्रतिशत हरियाणा में बढ़ा है। 65 रुपये से 104 रुपये प्रति हॉर्स पॉवर बढ़ी है। फिर भी ये किसान की बात करते हैं, नहरी पानी का रेट डबल हो गया। इसकी तो ये चर्चा कहीं नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में सूखे की मार पड़ी है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर चौटाला साहब कहते हैं कि हरियाणा का खजाना लबालब भरा हुआ है। अगर यह लबालब भरा हुआ है तो सुखे की मार किसान

झेल रहे हैं उन्हें अढ़ाई रुपये एकड़ मुआवजा क्यों दिया जा रहा है? उनको ' करने का काम सरकार क्यों कर रही है उनके लिए क्यों नहीं अपना खजाना खोल देते है?

श्री उपाध्यक्षः यह जो इन्होंने ' शब्द कहा है इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए। आप बीफ करें।

श्री कृष्ण पालः इसी तरह से किसान की बात आई। आज किसान के ऊपर प्रति नलकूप प्रति हॉर्स पॉवर जुर्माना होता है वह चार हजार रुपये प्रति हॉर्स पॉवर होता है और जो उद्योगपतियों के ऊपर जुर्माना होता है वह 70 रुपये प्रति हॉर्स पॉवर। किसान की इनको कितनी चिन्ता है, दूसरे वर्गों की कितनी चिन्ता है? यह भी हमारी समझ में आता है। अगर इनका खजाना लबालब भरा हुआ है तो गन्ना पैदा करने वाले किसानों के अरबों रुपये बकाया है तो उनके लिए अपना खजाना क्यों खाली नहीं करते हैं? अगर हरियाणा सरकार का खजाना लबालब भरा हुआ है तो NHPC का एक हजार करोड़ रुपया हरियाणा सरकार पर बकाया है उसके लिए बांडज भर कर देने की क्या जरूरत है उनके उस ऋण को चुकाया क्यों नहीं जाता है? (विघ्न) इसके अलावा उद्योगों को जनरेटर पर सबसिडी दी जाती थी वह बंद क्यों कर दी है। मैं समझता हूँ कि हर बात का उल्टा अर्थ है। यह कहते हैं कि इनका खजाना लबालब भरा हुआ हे लेकिन मुझे तो यह लगता है कि इनका दिवालिया पिट गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जब ये कहते है कि इस सरकार में 20 हजार कर्मचारियों को नौकरियां दी

जाएगी तो मुझे लगता है कि 20 हजार कर्मचारियों की छंटनी होने वाली है। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूँ कि पिछले 3 सालों से विभिन्न बोर्डों से, निगमों से कितने कर्मचारियों को निकाला गया है? इस बारे में ये अपना उत्तर देते हुए बता दें। उपाध्यक्ष महोदय, उद्योगों की बिजली के रेट बड़े हैं।

श्री उपाध्यक्षः बैठिए बैठिए। आप अपना स्थान ले। (विघन) आपकी पार्टी के और मैम्बर्ज भी बोलना चाहते हैं क्या आप उनका समय भी ले लेगें? अगर आप ही उनका समय ले लेगें तो वे कब बोलेंगे?

श्री कृष्ण पालः उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो यह पता है कि केन्द्र सरकार से जो पैसा सड़कों के लिए आया है उससे सड्कों की हालत तो सुधरी है कि नहीं सुधरी है। लेकिन इस सरकार के कार्यकर्त्ताओं की और इनके लोगों की हालत जरूर सुधरी है और मैं यह मानता हूँ कि (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः अब आप बैठिए। आपका समय हो गया है। सरदार निशान सिंह जी आप बोलें। (विघन) बैठिए बैठिए।

श्री कृष्ण पालः ....।

श्री उपाध्यक्षः अब ये जो भी बोल रहे हैं वह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया जाए।

श्री कृष्ण पालः ....।

श्री उपाध्यक्ष: आप बैठिए बैठिए। निशान सिंह जी, आप बोलिए। (विघ्न) गुजर साहब, आप यह बताएं कि आप बजट का समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं।

श्री कृष्ण पाल: उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे बजट पर बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं नहीं, कृष्ण पाल जी, आप अब बैठें। आपको बोलते हुए 70 मिनट हो गए हैं। अब आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं। अब इनकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। गुज्जर साहब, मैं आपको तीन बार कह चुका हूं।

श्री कृष्णपाल: ....।

Prof. Sampat Singh : Sir, being a Finance Minister, I want to know whether he supports or opposes the Budget?

श्री कृष्ण पाल: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कच्छ तो करने दें। मैंने अभी बजट के बारे में कुछ नहीं बोला है। (विघन)

श्री उपाध्यक्ष: मैं कोशिश करूंगा कि दलाल साहब, आपके लिए और इनके लिए स्पेशल सैशन बुलाया जाए। 70 मिनट में अगर आपकी बात पूरी नहीं हो सकी तो और मैम्बर्ज यहां पर किस लिए बैठे हैं? आप या तो अपनी स्थिति स्पष्ट करें वरना आप बैठ जाएं।

श्री कृष्ण पालः आप मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मौका तो दें।

प्रो० सम्पत सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, कोई बात नहीं ये स्पष्ट न करें। सारी बात रिकार्डिंग में आपके पास है सारी बात रिकॉर्ड में आ रही हैं। मैं इनसे यह पूछना चाह रहा हूँ कि जो बजट हमने पेश किया है ये उसका समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं या कुछ और कह रहे हैं। इनकी सारी बातें रिकॉर्ड में आ जाएंगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह इनका अधिकार है कि ये समर्थन करें न करें, क्या करें यह इनका अपना काम है। लेकिन ये हमें बता तो दें कि ये क्या कर रहे हैं ? ये समझदार हैं इसलिए हम इनसे पूछ रहे हैं।

श्री कृष्ण पालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसका जबाव दे देता हूँ। आप मुझे बोलने के लिए समय देना चाहते हैं या नहीं? मैं समस्त हरियाणा की तस्वीर क्लीयर करना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्षः गुज्जर साहब, आप 75 मिनट बोल लिए हैं इसलिए अब आप बैठें।

श्री कृष्ण पालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं इनकी बात का जबाव दे देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये हर बार समर्थन मांगते हैं इसलिए मैं समर्थन करता हूँ लेकिन यह मैं किसी मजबूरी में ही करता हूँ। आप जानते ही हैं अब हालत यह है कि ....

प्रो० सम्पत सिंहः हालत हुलत कुछ नहीं, आप क्लीयर करें। उपाध्यक्ष महोदय, अब तो इनकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्षः गुज्जर साहब, आप बैठ जाएं अब आपकी कोई बात रिकॉर्ड नहीं हो रही है। यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय आधे घंटे के लिए बढा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री उपाध्यक्षः ठीक है, हाउस का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2003 – 2004 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

चौ० भजनलालः उपाध्यक्ष महोदय, अब तो खाने का समय हो रहा है।

श्री उपाध्यक्षः भजन लाल जी, आपको तब चिंता नहीं हुई जब गुज्जर साहब 70 मिनट तक बोल रहे थे। अब निशान सिंह जी बोलेंगे। (विघ्न)

सरदार निशान सिंह (टोहाना): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट रखा उसके लिए उनका

धन्यवाद। आपने जो मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए आपका भी धन्यवाद। जो बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन में रखा, उसकी जितनी सराहना की जाए वह कम है। अपने सीमित साधनों से सरकार ने जिस तरीके से पिछले तीन वर्षो में हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास किया और किसानों को, व्यापारियों को, कर्मचारियों को जिस तरीके से सहूलियतें दी और एक अच्छा प्रबन्धन, एक अच्छा मैनेजमैन्ट हरियाणा की जनता को देकर एवं खजाने से सीमित साधनों से जिस ढंग से चहुंमुखी विकास करने का काम किया है वह सराहना के योग्य है। कुछ लोगों का आलोचना करने का काम है। अभी सम्मानित साथी कृष्ण पाल जी बोल रहे थे कि मैं तीन महीने से लगातार बजट पर बोलने की तैयारी कर रहा हूँ और जब ये सरकार के खिलाफ बोलने के लिए खड़े होते हैं तो इनका शरीर गुस्से में कांपने लगता है। मैं समझता हूँ कि ये तीन महीने से गालियां बकने की तैयारी कर रहे थे न कि बजट पर बोलने की तैयारी कर रहे थे। मैं कह रहा था कि जिस तरीके से इन्होंने अभी जिक्र किया। माननीय मुख्यमंत्री जो हमेशा कहते हैं कि सरकार का खजाना लबालब भरा हुआ है मैं समझता हूँ कि भारत भर में एक मिसाल है कोई मुख्य मंत्री यह कहते सुना गया हो कि मेरा खजाना लबालब भरा हुआ है। अमुमन यही कहते हैं कि खजाना खाली है कहां से दें। माननीय मुख्य मंत्री जी सारे हरियाणा भर के क्षेत्रों में जाकर के जनता के बीच में बैठकर रू–ब– रू होकर के यह बात कहते हैं। हर मांग के ऊपर इस घोषणा को समयबद्ध किया जाता है और उस समय के

अंदर उसे पूरा करने का काम किया जाता है। इसके लिए मैं सरकार की सराहना करता हूँ। कुछ लोगों का काम होता है कि सरकार चाहे कितना अच्छा काम करे लेकिन उसका विरोध करना उनका काम होता है यह उनकी नैतिकता है। यह उनका अपना स्वभाव है। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि सरकार ने जिस तरीके से सड़क परिवहन के मामले में, बिजली का सुधार करने के मामले में और सूखा पड़ने के बावजूद किसान को नहरी पानी देने की बात की और जिस तरह से सरकार ने काम किया यह सराहनीय है। सारे हरियाणा में हमारे खेतों में पानी नहीं था और दक्षिणी हरियाणा में जहां पानी की बहुत ज्यादा कमी है वहां भी सरकार के प्रयासों से फसलें लहलहाती हुई खड़ी हैं। सरकार ने जमींदार को पूरा पानी दिया, बिजली दी। विशेषकर मैं यह कहूँगा कि पिछली सरकारों के समय में बिजली की बहुत कमी रही और किसान, उद्योगपति व व्यापारी उससे पीड़ित रहा। वहीं आदरणीय मुख्य मंत्री श्री चौटाला साहब ने आकर बिजली के बढ़िया प्रबंधन से किसान को रिकॉर्ड बिजली देने का काम किया। जिस तरह से बिजली के बकाया बिल और जो डिफाल्टिंग अमाउंट थी उसका सरचार्ज माफ करके जो बकाया बिजली के बिल थे, उनको वसूल करने का काम किया और पिछले कई वर्षों से लम्बित पड़े ट्यूबवैल कनैक्शन जो हैं 24 हजार से ज्यादा कनैक्शन देकर रिकॉर्ड बिजली देने का काम किया। नये सब–स्टेशन लगाने का काम किया, पुराने जो सब–स्टेशन थे उनकी क्षमता बढ़ाने का काम किया। लाइन के ऊपर जो पुरानी तारे थी उनको बदलकर

लाइन लौसिज को कम करने का काम किया। मैं सरकार की इस मामले में सराहना करता हूँ। माननीय वित्त मंत्री जी ने बिजली, सिंचाई और सड़क परिवहन के मामले में 911 करोड़ रुपये की राशि रखी है मैं समझता हूँ कि सरकार का जो पिछला रिकॉर्ड है साढ़े तीन साल का, उसी के अनुसार अपने सीमित साधनों से सरकार किसान को और सारी जनता को इस राशि से लाभ पहुंचायेगी। विपक्ष के साथी बहुत कुछ कह रहे थे जब इनकी सरकार थी तब ये कुछ नहीं कर पाये लेकिन इस सरकार द्वारा की गई प्रगति और विकास को ये सहन नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें इस सरकार ने रिकॉर्ड कायम न किए हों। परिवहन की बात लें तो हरियाणा के अंदर आज के दिन सारे भारत वर्ष से अच्छा इंतजाम, अच्छी बसें, अच्छी रोड्स और बहुत बढ़िया व्यवस्था है। हर सड़क के ऊपर नयी बसें चलती हुई नजर आती हैं। (इस समय सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री पूर्ण सिंह डाबरा पदासीन हुए।) इसी तरीके से नयी ड्रेनें, नये खाल और नयी माइनर बनाने से किसान को आखिरी छोर तक पानी मिला है। सभापति महोदय, मैं मानकर चलता हूं कि सरकार के अच्छे प्रबंधों की वजह से किसान खुशहाल है, किसान की फसल लहलहा रही है यह इसके बावजूद है जब हमने हरियाणा प्रदेश में एक कुदरती आपदा को सहन किया है। इसके अलावा सभापति महोदय, बिजली के मामले में जो पिछले तीन वर्षों में कुशलता से चलाने का काम किया है और 792 मैगावाट बिजली देने का काम किया है 1 उसकी मैं सराहना करता हूं। माननीय

वित्त मंत्री महोदय, ने जो सामाजिक सेवाओं के मामले में 890.23 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है उसमें शिक्षा, हैल्थ सर्विसिज और पेयजल के बारे में पिछले तीन वर्षों के अन्दर हमारी सरकार ने अच्छे तरीके से काम किया है। जिस तरीके से हर गांव में स्वस्थ पीने के पानी का प्रबन्ध किया है, हर गांव में ट्यूबवैल लगाकर हर गांव में वाटर वर्क्स लगाकर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 70 से 110 लिटर पानी देने का काम किया है वहां सीवरेज व्यवस्था सीमित साधनों के होते हुए भी ठीक करने का काम किया है, उसके लिए भी सरकार की सराहना करनी चाहिए। जहां तक शिक्षा की बात है जिस –तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में पहली कक्षा से गांव में अंग्रेजी का विषय लगाकर और कम्प्यूटर की शिक्षा देने का काम किया है। ये सब सराहनीय काम सरकार ने किए हैं। बजट के अन्दर माननीय वित्त मंत्री महोदय ने सड्कों का जिक्र किया। यह बात सही है कि हरियाणा की सड़कें पिछली सरकार के समय में जर्जर हालत में थी और जगह–जगह गड्ढे हो गए थे लेकिन पिछले तीन वर्षों में सड्कों के मामले में बहुत सुधार हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि हरियाणा की सभी सड़कें रिपेयर की जाएंगी और पिछले तीन वर्षों में सड्कों को बनाया गया, रिपेयर की गई इसके अलावा नई सड़के भी बनाई गई हैं और माननीय वित्त मंत्री महोदय ने सड्कों के प्रबन्धन के लिए और उनके रख–रखाव के लिए पुल बनाने के लिए जो राशि रखी है इससे मैं मानता हूँ कि यह सरकार हरियाणा की जनता को अच्छी सड़कें बनाकर देगी और यह बात लोग पहले से ही

महसूस करते हैं। इसके अलावा जन स्वास्थ्य के लिए कल्याणकारी योजना युग पुरुष चौधरी देवीलाल का अनुसरण करते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने लोगों के लिए अधिक राशि रखी है। इससे मैं समझता हूँ कि जन–स्वास्थ्य के बारे में हरियाणा के लोगों की सेवाओं के कार्य चल रहे हैं इससे इन कामों को और बढ़ावा मिलेगा। कृषि के बारे में जिक्र करना चाहूँगा। हर वर्ष चाहे गेहूँ का सीजन हो, चाहे रबी का सीजन हो या खरीफ का सीजन हो माननीय मुख्य मंत्री जी ने केन्द्र सरकार से निवेदन करके पुरजोर सिफारिश करके हर बार फसल के समर्थन मूल्य में बढ़ौत्तरी करवाने का काम किया है। हम यह मानकर चलते हैं कि अगर किसान की फसल का मूल्य न भी बढ़े लेकिन उसकी बिकवाली ठीक ढंग से होती रहे तो ठीक रहता है। यदि बिकवाली के मामले में मार्केटिंग ठीक ढंग से नहीं हो और उसकी फसल 5–7 दिनों तक मण्डी में रखी रहे तो उसका दसवां हिस्सा निकल जाता है 1 इस मामले में हमें माननीय मुख्य मंत्री जी की सराहना करनी चाहिए कि वे सिर्फ बड़ी मण्डियों में ही नहीं गये बल्कि छोटे से छोटे परचेज सैन्टर पर भी गये और वहां किसानों की बिकवाली के प्रबन्ध को जाकर देखा कि फसल ठीक से बिक रही है या नहीं? माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह बात कही कि चाहे सरकार का नुकसान भले ही हो जाये लेकिन किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए। इसलिए पिछले तीन वर्षों में किसानों को बहुत लाभ हुआ है। पिछले तीन वर्षों में हमने यह नहीं देखा कि माननीय मुख्य मंत्री किसी छोटे परचेज सैंटर पर किसानों की बिकवाली का

जायजा लेते नहीं देखे गये हों। किसानों की जो आज के दिन मोटी फसलें हैं जैसे गेहूं है, धान है आज उनमें उत्पादन बहुत अच्छा है और वह इस सरकार की वजह से ही हो रहा है। कैश क्रॉप में डायवर्सीफिकेशन के लिए मुख्य मंत्री जी ने बहुत प्रयास किए हैं। गन्ने की फसल हार्ड क्रॉप मानी जाती है, गन्ने की फसल सूखा भी सहन कर सकती है और फ्लड भी सहन कर सकती है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गन्ने का भाव 110 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दिया है। पिछली सरकारों में कोऑपरेटिव शुगर मिल्ज में जो किसानों का पैसा बकाया था, वह भी सरकार ने दिलवाने का काम किया है। इसके अलावा गन्ने की बढ़ौतरी के लिए नये–नये प्रोग्रामूज बनाए गए हैं जिससे गन्ने के उत्पादन में बढ़ौतरी हुई है। किसान ने ज्यादा गन्ना बीजा और जो हमारी 12 गन्ना मिल्ज हैं उनमें गन्ना पीडा गया और वे मिल्ज लाभ में आ रही हैं। फ्लोरीकल्चर, हौर्टिकल्चर, सब्जियों और फलों को डायवर्सीफिकेशन के तहत जो बढ़ावा दिया गया है उससे किसान नकदी फसलों की तरफ ज्यादा डायवर्ट हुआ है और किसान ने उसका लाभ कमाया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की सराहना करूंगा। जिस तरीके से हमारे वैज्ञानिकों ने ऐग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हिसार में फ्री हैल्प लाइन की योजना शुरू की है उससे किसान घर बैठे अपनी फसल की बीमारी के लिए फोन पर जानकारी ले सकता है और उसका समाधान करवा सकता है, इस योजना के लिए सरकार की सराहना करूंगा। सभापति महोदय, जिस तरीके से लिंग अनुपात में अन्तर पैदा हो गया है

उसके लिए देवीरुपक योजना सरकार ने लागू की उसके लिए मैं सरकार की सराहना करना चाहूंगा। इस सरकार ने भ्रूण हत्या को कम करने का काम किया। माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट रखा, मैं उसका समर्थन करता हूँ। बहुत बढिया बजट रखा गया है। सभापति महोदय, मैं थोड़ा टोहाना के विकास कार्यों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ' सरकार आपके द्वार ' कार्यक्रम के तहत टोहाना के अंदर शहीद उद्यम सिंह के नाम से पोलीटैक्निक खोले जाने की घोषणा की गई थी, मैं कहना चाहूँगा कि इसके लिए जमीन तैयार हो गई है, उसके लिए नींव रखी जाए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पलैक्स और जूडिशियल काम्पलैक्स की भी मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी, एक ताऊ देवी लाल पार्क टोहाना में बनाने की भी घोषणा की गई थी, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि यह तीनों घोषणाएं जो बहुत बड़ी और जरूरी हैं, उनका नींव पत्थर रखा जाए और उनको चालू किया जाए। इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि टोहाना में जो बस अड्डा बना है वह आबादी के बीच में आ गया है, वहां बसों के आने जाने की दिक्कत है और साथ ही लोगों को भी दिक्कत है। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि बस अड्डे को आबादी के बाहर बनाया जाए। 4 एकड़ जमीन उस बस अड्डे की है जिसको कॉमर्शियल करके बस अड्डे का निर्माण हो सकता है, इसके लिए पैसे की सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा टोहाना के अंदर सीवरेज व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने घोषणा की थी। पिछली सरकारों के समय में

टोहाना के अंदर सीवरेज व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जिसके कारण सीवरेज व्यवस्था की बहुत जर्जर हालत हो गई। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि उनकी घोषणा के मुताबिक टोहाना की सीवरेज व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है, उसके लिए जल्दी से जल्दी फंड मुहैया करवाया जाये ताकि टोहाना में सीवरेज व्यवस्था ठीक हो जाये और जनता को परेशानी न रहे। सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त टोहाना के वाटर वर्क्स की कैपेसिटी दुगुनी कर दी गई है इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूँ लेकिन जो पाईप लाइनें बिछाई हुई हैं वे पुरानी कैपेसिटी के हिसाब से बिछाई हुई हैं, जो काफी छोटी हैं। इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कैपेसिटी के हिसाब से नई पाईप लाइन बिछाई जाये ताकि लोगों को सुचारू रूप से पानी मिले। सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त टोहाना में स्टोर वाटर की भी बहुत समस्या है। वहां पर राम नगर कालोनी है, जिसकी आबादी 7000 के करीब है जो काफी नीची है, जिसके कारण वहां पानी खड़ा रहता है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस कालोनी के स्टोर वाटर की समस्या को दूर करने की घोषणा की थी और कहा था कि इसकी प्रोजैक्ट रिपोर्ट भिजवाये। सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि इसकी प्रोजैक्ट रिपोर्ट सरकार के पास आ चुकी है, वहां पर नाला बनाकर लोगों को इस समस्या से छुटकारा दिलवाये। सभापति महोदय, इसके अतिरिक्त मैं माननीय

मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि टोहाना शहर के अंदर की सड़कें जर्जर हालत में हैं। उनमें से कुछ सड्कों को बनाने के बारे में मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी और बनी भी हैं लेकिन कुछ छोटी–छोटी सड़कें रहती हैं। रेलवे रोड के बीच की सड़कें काफी जर्जर हालत में हैं, इन सड्कों को दोबारा रिपेयर करवाया जाये। इसके अतिरिक्त चण्डीगढ़ रोड जो शोरेवाला से पंजाब जाता है, काफी खराब हालत में है, इसकी भी दोबारा से रिपेयर करवाई जाये। सभापति महोदय, मैं फिर से जो बहुत ही बढ़िया और बड़ा ही संतुलित बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने रखा है, इसका समर्थन करता हूँ। इस बजट के तहत जिस बढ़िया मैनेजमैंट से सरकार ने काम किया है, इससे जनता को काफी लाभ होगा। धन्यवाद! (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादव (रेवाड़ी): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। वैसे तो मैंने सोचा था कि हमारे प्रो० सम्पत सिंह जी बहुत विद्वान हैं और इनसे उम्मीद थी कि ये बहुत बढ़िया बजट पेश करेंगे लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यह बजट पिछले बजट की नकल करके आकड़ों में कुछ हेरफेर किया गया है और नकल भी ठीक तरह से नहीं कर पाये। सभापति महोदय, इस बजट में कुछ भी नयापन नहीं है। यह बजट न तो प्रोग्रेसिव है और न ही ग्रोथ औरियन्टिड है बल्कि यह टोटली निरस्त और दिशाहीन बजट है 1 सभापति महोदय, इन्होंने अपने 2002– 03 के

बजट में बजट घाटे के बारे में लिखा था कि यह 487.06 करोड़ से शुरू होगा तथा 689.26 करोड़ रुपये के घाटे के साथ समाप्त होने की संभावना है। अब जो बजट पेश किया गया है इसमें बजट घाटे के बारे में कहा गया है कि यह as per the Reserve Bank के घाटे के मुताबिक होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने पिछले बजट घाटे के बारे में ऐसे ही हवा में बात की थी। इस बार के बजट घाटे के बारे में बजट में लिखा है कि यह 454.16 करोड़ रुपये से आरम्भ होगा और 780.53 करोड़ रुपये के घाटे के साथ समाप्त होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्ष के दौरान लेन–देन में 326.37 करोड़ रुपये का घाटा होगा। इसी प्रकार से पिछले बजट के अन्दर न तो किसी कर्मचारी को कोई राहत दी गई और न ही रोजगार देने के बारे में बात की गई। इन्होंने कहा कि वर्ष 2003– 04 के बजट के 780.53 करोड़ रुपये के घाटे के साथ आरम्भ होने और 670.96 करोड़ रुपये के घाटे के साथ समाप्त होने की संभावना है। इस बारे में मेरा कहना है कि इनका यह घाटा 670.96 करोड़ का घाटा नहीं होगा बल्कि 900 करोड़ रुपये के घाटे पर समाप्त होगा। इन्होंने अपना बजट लगातार घाटे का ही दिखाया है जिससे अब स्थिति यह है कि स्टेट दिवालियेपन के कगार पर आ गया है। (विघन) चेयरमैन महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस साल का जो प्लान ले आउट है उसमें इन्होंने 2100 करोड़ रुपया दिखाया है पिछली बार 2002– 03 में प्लान में 1972 करोड़ रुपये दिखाया है। फिर इन्होंने इसमें बाद में अमैंडमेंट करके उसको 2034 करोड़ रुपये कर दिया, जबकि यह

1838 करोड़ रुपये बैठता है। मेरा मानना है कि इस साल का जो बजट है वह इतना नहीं होगा बल्कि यह और कम होगा। मेरे हिसाब से यह 1600 करोड़ रुपये से ऊपर आने वाला नहीं है। इनका नाइन्थ फाइव ईयर प्लान 11 हजार 600 करोड़ रुपये का था। अब इन्होंने टैन्थ फाइव ईयर प्लॉन में इसको 12 हजार करोड़ रुपये का दिखाया है। कभी ये यहां पर एस०वाई०एल० की बात करते हैं तो कभी इरीगेशन की बात करते हैं। पिछली बार प्लांन आउट ले में इन्होंने इरीगेशन के लिए 300 करोड़ रुपये दिखाया है और इस बार 266 करोड़ रुपये इरीगेशन के लिए दिखाया है यानि यह पिछले साल से कम कर दिया है। चेयरमैन साहब, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो ओवरआल डैफिसिट है इसको ये कैसे मैनेज कर पायेंगे? मैं समझता हूँ कि इसे ये मैनेज नहीं कर पायेंगे क्योंकि जिस प्रकार से ये टैक्सिज इम्पोज करना चाहते हैं वह ठीक नहीं है। पिछली बार इन्होंने कह दिया कि हमारा जो बजट है, वह टैक्स फ्री है। मुझे पूरा अन्देशा है कि जैसे इन्होंने पिछली बार यह कहा था कि टैक्स नहीं लगेगा लेकिन बाद में टैक्स लगा दिये थे और ये टैक्स आर्डीनैस के माध्यम से लगा दिए गए। इसी प्रकार से बाद में ये आर्डीनेंस के माध्यम से टैक्स इम्पोज कर देंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो टैक्स ये अब नहीं दिखा रहे वे बाद में आर्डीनेंस के माध्यस से लगा देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये अपने बजट के घाटे की पूर्ति कैसे करेंगे? घाटे की पूर्ति के लिए ये कहते हैं कि हम 10 परसेन्ट टैक्स सेन्ट्रल गवर्नमैंट से लेंगे जबकि सेन्ट्रल गवर्नमैंट

से इनको एक पैसा भी मिलने वाला नहीं है, इस बारे में आप केवल सोचते रहना, आपका यह घाटा पूरा होने वाला नहीं है। दूसरे मैं यह कहना चाहता हूँ कि इनका जो कलैक्शन ऑफ स्टेट टैक्स प्रोजैक्ट बाई नियरली 125 परसेंट है उसमें वृद्धि होगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कहां बजट में लिखा है। दूसरे रेवैन्यू की जो रिसिप्टस 2001 – 02 की है उसमें इन्होंने 980.10 करोड़ रुपये दिखाया है जबकि यह राशि वर्ष 2002 –03 में 87891 करोड़ रुपये दिखाई है। मैं यह कहता हूँ कि इनका जो टोटल रेवैन्यू का ऐक्सपैंडीचर है वह हर साल बढ़ रहा है और आज हालत यह हो गई है कि इनका टोटल डैबिट 38 परसेंट है और इनका जी०एस०डी०पी० जो है उसको अगर डैबिट के मुताबिक करें तो उससे ज्यादा का डैबिट आता है। इसी प्रकार से इन्ट्रैस्ट भी इनको बहुत देना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं कि इनका लोन के लिए गए पैसे का इन्ट्रैस्ट हर साल बढ़ रहा है। मैं आपको बता रहा था कि 1998–99 में टोटल डैबिट 29.16 परसेंट था वह बढ़कर 2000–01 में इनकी सरकार जब आई तो उस वक्त यह 34. 37 परसेंट हो गया और उसके बाद अब 2001 –02 में यह बढ़ कर 35 परसेंट हो गया और 2002 –03 में यह बढ़ कर 37 परसेंट हो गया। चेयरमैन महोदय, अब यह डैबिट बढ़कर 38 परसेंट हो गया है। मैं कहना चाहता हूँ कि ग्रान्ट इन एड उल्टी बढ़नी चाहिए थी यानि जो पिछली बार 6 परसेंट थी वह अब 5 परसेंट हो गई इस प्रकार यह भी कम हो गई है। फिर भी ये कह रहे हैं कि हम अपने घाटे को पूरा कर लेंगे। इसी प्रकार से

इन्ट्रैस्ट की पेमेंट भी लगातार बढ़ती जा रही है। वर्ष 1998–99 में यह 11. 14 करोड़ रुपये की पेमेंट थी और अब बढ़ कर 14 परसैंट हो गई है। इसी प्रकार से लोन रिपेमैंट 2000–2001 के अन्दर 17.03 परसैंट थी अब वह बढ़ते–बढ़ते 26परसैंट पर आ गई है। सभापति महोदय, आप सोचिये अगर इस तरीके से चलता रहा और सरकार चाहती है कि डैफिसिट पूरा कर लें तो मुझे तो ऐसा नजर नहीं आता है। इन्होंने कहा है कि हम रैशनेलाईज करके और अपने इम्पलॉईज को कम करके घाटा कम करेंगे। मुझे लग रहा है कि ये कर्मचारियों की रिट्रैंचमैंट करेंगे ऊपर से इन्होंने यह भी कह दिया कि हम 20 हजार लोगों की रिक्रूटमैंट कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि सरकार की इच्छा क्या है। एक तरफ तो ये रिट्रैंचमँट करके अपना घाटा पूरा करना चाहते हैं दूसरी तरफ आप रिकूटमैंट करेंगे। एक तरफ तो ये रैशनेलाईज की बात कह रहे हैं दूसरी तरफ रिकूटमैंट की बात कर रहे हैं। घाटा कम कैसे हो सकता है जो फिस्कल डैफिसिट है वह तो बढ़ता जा रहा है। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) दूसरी तरफ इन्होंने यह रखा है कि कसिलरेटिड सिकिंग फण्ड के बारे में जिक्र कर दिया। स्टेट सिकिंग इन डैबिट है। अध्यक्ष महोदय, यह तो इन्होंने बता दिया कि इतना पैसा आएगा लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कहा कि यह पैसा कैसे और कहां से आएगा ?दूसरे इन्होंने गारन्टी के रिडक्शन ऑफ फण्डज के बारे में जिक्र कर दिया। (विष्य) आपका जो डैबिट है जो इन्ट्रस्ट की पेमेट जो है वह बढ़ती जा रही है। 2221 करोड़ रुपया आपके डैबिट

सर्विसिज का है दूसरे रिपेमेंट ऑफ लोन के बारे में है वह 37.79 है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो स्टेट की debit liability of guarantee है that is increasing day by day. आप देखें कि 2000– 2001 के अन्दर वह 8209 है उसके बाद यह 8601 है और इस बार का आपने टेबल के अन्दर दिया ही नहीं। आप इस बात को छिपा गए यानि सरकार यह बता नहीं पाई कि वर्ष 2003–04 की टोटल गारन्टी जो आपकी है, जो आपकी कॉपरिशन हैं एच०एस० आई०डी०सी का दिया है जितनी भी आपकी कॉर्पोरेशन हैं पॉवर सैक्टर है वह आपने इसमें दिखाया ही नहीं। इसके अलावा वर्ष 2003–04 में 20,695 करोड़ रुपया स्टेट डैबिट के अन्दर जा रहा है। वित्त मन्त्री जी, मेरा यह कहना है कि अब आपने इस में कह दिया कि इसकी पूर्ति दो कामों से करेंगे एक तो ऑन लाइन लॉटरी से यानि लोगों को लॉटरी खिलाओ और 20 परसैंट उसमें कमाओ दूसरा काम था कैसीनो का मामला लेकिन वह आप बना नहीं पाए।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय एक घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः ठीक है, हाउस का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2003 – 2004 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा
(पुनरारम्भ)

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, कैसीनों के बिल की बात तो बनी नहीं वह राष्ट्रपति महोदय के पास चला गया है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह घाटा कैसे पूरा करेंगे? अध्यक्ष महोदय, यह किताब है स्काउटस एट–ऐ–ग्लांस इसमें अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि साल के आखिरी महीने में यानि मार्च के महीने में किस प्रकार से धड़ाधड़ पैसा खर्च करते हैं। आप इनकी एकाउंटिंग देखेंगे तो पाएंगे कि इलैक्शन डिपार्टमैंट में 50 परसैंट पैसा आपने मार्च के महीने में स्पैंट किया है इसीलिए घाटा हो रहा है। इसके बाद जनरल सर्विसिज में 91 93 परसैंट है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मार्च के महीने में ही सरकार सारा पैसा क्यों खर्च करती है? माईनर इरीगेशन के लिए 72.58 करोड़ रुपया रखा है। नकली बिल बनवाओ और घाटा सिर करवाओ। इसी प्रकार से नॉन कन्यैंशनल ऐनर्जी के अन्दर 64.63 और टूरिज्म मे 64 परसैंट है। इसलिए मेरा यह कहना है किं अगर इस प्रकार से मार्च के महीने में फटाफट पैसा खर्च कर लिया और नकली बिल बनवा लिए यह जो स्टेट का घाटा बढ़ रहा है उसका मुख्य कारण यही है और साथ में मिस मैनेजमैंट भी। इसी प्रकार से कमाई का एक बड़ा साधन था माईन्ज का। अरावली हिल्ज में माईन्ज का खनन सुप्रीम कोर्ट ने बन्द करवा दिया। वह पैसा जो वहां से आता था वह भी बन्द हो गया। ....

श्री अध्यक्षः यहां पर बैठे हुए लोगों के बारे में जो बात कही गई है उसे रिकॉर्ड न किया जाए।

कैप्टन अजयसिंह यादवः स्पीकर सर, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में तो माईनिंग खोल दी है। स्थ शायद उनके दिमाग में होगा कि हमारी सरकार के द्वारा गलत करतूतें की जा रही हैं इसलिए हरियाणा में नहीं खोल रहे हैं। इसके अलावा मैं ऑक्शन ऑफ लिकर के बारे में कहना चाहता हूँ।

14.00 बजे

श्री राम पाल माजराः अध्यक्ष महोदय, ये हमें तो कुछ कहते हैं और यहां पर कुछ कहते हैं। मैं सदन में एक बात बताना चाहूँगा कि ये एक बार मेरे साथ. मीटिंग में थे, उस वक्त श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और भजन लाल जी अपोजीशन के लीडर थे। ये थोड़ा बहुत भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के साथ आने जाने लग गए थे। मैंने इनसे एक दिन पूछा कि आप कौन से यूप में हो तो इन्होंने मुझे कहा कि नहीं मेरा कोई तुप नहीं है। मैं तो भजन लाल के साथ हूँ। तो मैंने इनसे कहा कि क्या बात है उसका क्या अहसान है तेरे पास। तू तो बहुत बड़ा आदमी है, कई बार असैम्बली में आ लिया। अध्यक्ष महोदय, ये कहने लगे कि राम पाल इसका मेरे पर बहुत बड़ा अहसान है। मेरे को उसने माईन आउट आफ दि वे दी थी। मुझे एक लाख रुपये

पर मन्थ घर बैठे आ जाते हैं। (विघन) अध्यक्ष महोदय, ये औरों को तो कहते हैं और अपनी सोचते नहीं हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, ये जो हमारे आदरणीय मैम्बर हैं थोड़ा बहुत बात कहने से पहले सोच लिया करें।

श्री राम पाल माजराः अध्यक्ष महोदय, इनके पास माईन है कि नहीं, ये यह बताएं।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मेरे पास है, कोई माईन नहीं है।

श्री राम पाल माजराः अध्यक्ष महोदय, है, कोई नहीं ये दो बातें कह रहे हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मेरे नाम से कोई माईन नहीं है।

श्री राम पाल माजराः अध्यक्ष महोदय, इनके नाम पर नहीं है तो किसी और के नाम पर होगी (विघन) स्पीकर सर, अगर इन्होंने यह बात नहीं कही हो तो ये ऑन ओथ कह दें कि इन्होंने यह बात नहीं कही है। मैं ऑन ओथ यह कहता हूँ कि इन्होंने यह बात कही है।

श्री अध्यक्षः आप माईनिंग वाली बात छोड दें, आप बजट पर बोले। (विघन)

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे यह कहना चाहूँगा कि इस बात को जाने दो। मैं इसकी हरसौले वाली बात नहीं कह रहा हूँ अगर मैं बता दूंगा तो पता चलेगा कि तूने क्या करतूत की थी? (विघन)

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, आप बजट परं बोलें और पांच मिनट में वाइंड– अप करें।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने शुरू किया है। आप ऐसा न किया करें।

श्री अध्यक्षः आप दूसरी बार बोल रहे हैं। ऐसे भी मैम्बर्ज हैं जो एक बार भी नहीं बोलें हैं।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि ये एक्साईज के बारे में कह रहे हैं कि इन्होंने नई नीति ऑक्शन ऑफ लिकर के लिए बनाई है। यह तो इनका प्लॉन है कि किस तरीके से अपने आदमियों को ठेके दिये जाएं। अध्यक्ष महोदय, हमारी स्टेट में एक बार माईन्ज के बारे में ऑक्शन हुई थी और वहां पर जो लोग बोली देने के लिए गए थे उनको बोली देने ही नहीं दी गई थी। इसी प्रकार से मुझे लगता है कि इसमें भी सरकार की नीयत में खोट है। अगर ऐसा होगा तो कहां से पैसा आएगा?

प्रो० सम्पत सिंहः कैप्टन साहब, आप एक्साईज के बारे में कह रहे हो कि माइन्ज के बारे में कह रहे हो। मैं यह इसलिए

पूछ रहा हूँ कि आप एक्साईज की बात करते हुए अपने आपको माईन्ज पर कन्वर्ट कर गए हो।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं वही बात कह रहा हूँ कि माईन्ज वाला वाक्या यहां पर भी दोहराया जाएगा। जो माईन्ज में किया गया था वही काम यहां पर भी होगा और अपने आदमियों को ठेके दिए जाएंगे। आपको लोगों से प्रीपर टैण्डर लेने चाहिएं। ग्लोबल टैण्डर हों और बाकायदा जो हाईयस्ट बिडर हो उसको ही टैण्डर दिया जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने नई बात शुरू कर दी क्योंकि इन्होंने अपने आदमियों को, सरकार के लोगों को ये ठेके देने हैं। इसके साथ ही '' सरकार आपके द्वार '' के बारे में भी मैं यहां पर कहना चाहूँगा। जैसे पहले के जमाने में दरबार लगा करते थे उसी तरह से मुख्य मंत्री जी के दरबार आज लगते हैं। अध्यक्ष महोदय, वहां के बारे में एक पेपर में आया कि मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि ' सरपंच साहब तू पैसे को छोड़, मैं तेरे लड़के को नौकरी दे दूंगा। ' अब इस प्रकार से मुख्य मंत्री सरपंच को कहे कि नौकरी दे दूंगा, यह बात कुछ ठीक नहीं है। वहां पर आप जाकर अच्छी बात करें। '' सरकार आप के द्वार '' का मतलब है कि वहां के जो नुमायंदे हैं, हमारे जो एम०एल०एज० हैं उनको बाकायदा 50– 50 लाख रुपये दिए जाएं। हमारे वक्त में एम०एल०एज० डिवैल्पमैंट एरिया स्कीम हुआ करती थी। उसमें एम०एल०एज० अपने एरिया में अपनी मर्जी से पैसा लगाता था। इस स्कीम को आप दोबारा से चलाएं। आज डिसैन्ट्रलाइजेशन

ऑफ पॉवर है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि इनकी पार्टी के जो एम०एल०एज० हैं। वे अन्दर– अन्दर रोते हैं और हमें रोज कहते हैं कि यार तुम कहते क्यों नहीं। वे बेचारे बहुत दु:खी हैं क्योंकि आज उनकी जरा भी नहीं चल रही है। इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि '' सरकार आप के द्वार '' में टोटल पैसा जो कि HRDF का पैसा है और वह टोटली सैन्टर की स्पौंसर्ड स्कीम है, उसके द्वारा पैसा लगाया जा रहा है। स्पीकर सर, सी० ए०जी० की रिपोर्ट में जिस प्रकार से इस सरकार को इंडिक्ट किया है वह मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें यह कहा है कि against the budget provision of 9 to 9.36 crores और आखिर में यह लिखा है कि– Chief Engineer preprared the budget estimate without adequate data based on information. No timely action was taken to re-concile the department'sexpenditure with Accountant General's figures. कहने का मकसद है कि कोई प्लानिंग नहीं है। लिया और कर दिया काम। यह हालत है।

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, आप बैठें। आपका समय समाप्त हो गया है।

कैप्टन अजय सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई इररैलेवैंट बात नहीं की है।

श्री अध्यक्ष: कैप्टन साहब, आप अब बैठें। आप दो बार बोल चुके हैं। अब आप बैठें।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, मुझे कंकलूड तो करने दें। मैं तो सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता था।

श्री अध्यक्षः आप एक मिनट में अपने सुजैशंज दें।

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): कैप्टन तेरी और मेरी तो अब सूत आ रही हें क्योकि पहले तेरे को और मेरे को तो कोई बोलने ही नहीं देता था। मैंने तेरा एक एक शब्द सुना था अब तो तू दहाड़ रहा है।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, प्लानिंग की तरफ भी सरकार को देखना चाहिए। जो वायदे ये लोगों से करके आये थे कि बिजली और पानी हम लोगों को मुक्त देगें उन वायदों पर इनको खरा उतरना चाहिए। अगर ये अपने वायदों पर खरा उतरते तो कंडेला कांड न होता। **श्री ओम प्रकाश चौटालाः** कैप्टन साहब, आप तो बहुत पुराने इस सदन के सदस्य रहे हो। यहां पर लिखा हुआ है कि जो कुछ भी बोलो वह तथ्यों पर आधारित बोलो 1 हमारे घोषणा पत्र में कहीं यह जिक्र नहीं है कि हम बिजली–पानी मुफ्त देंगे। इनको अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए। ये अपने नेता भूपेन्द्र सिंह हुड्डा से पूछ लें, उनका अखबार में भी बयान है। लेकिन ये तो उनको अपना नेता मानते ही नहीं इनके नेता तो चौधरी भजनलाल जी हैं शायद। इस तरह से ये तो सात कांग्रेस हो गयी।

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी की केवल एक नेता है श्रीमती सोनिया गांधी जी जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हम उनको ही अपना नेता मानते हैं। अध्यक्ष महोदय, वैट के बारे में मेरा एक सुजैशन है। इस बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत से व्यापारियों में इसको लेकर बडा भारी अंदेशा है कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लग जाएगा, टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाएगा। इस बारे में कहा गया है कि मिनिमम 900 रुपये प्रति महीने देना पड़ेगा। मेरा इस बारे में कहना यह है कि इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनायी जानी चाहिए जिसमें सरकार की तरफ से मैम्बर्ज हों और व्यापारियों की तरफ से भी मैम्बर्ज हों। उसके बाद ही सलाह करके इसको लागू किया जाना चाहिए। हमारी दिल्ली की सरकार ने भी वैट प्रणाली लागू करने के लिए मना कर दिया है। वैट प्रणाली लागू करने पर इसके कई ऐसे आईटम्स एवं शैडयूल होंगे जैसे शिडयूल बी है तो इसके ऊपर बड़ा भारी टैक्स लग जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसमें पैनल्टी का प्रौविजन भी है और फिर उसके ऊपर टैक्स भी लग रहा है इसलिए इस बारे में जरुर विचार करें। मैं इस बारे में यह सुझाव दूंगा कि सरकार के जितने भी मंत्री हैं या मुख्य मंत्री हैं अगर वे फारेन टूरज को कम कर दें तो यह घाटा कम हो जाएगा। जिस प्रकार से विदेशों में यह घूमकर आए हैं तो ये बताएं कि ये कितने एम० ओ०यू० साईन करके आएं है अगर ये इसमें कटौती कर दें तो बहुत ज्यादा घाटा कम होगा। यह घाटा

ही इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये दुनिया भर में सैर करके आये हैं। ....

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, आप बैठिए। अब इनकी कोई बात रिकॉर्ड न करें। अब कृष्ण लाल जी बोलेंगे।

श्री कृष्ण लाल (असन्ध–अनुसूचित जाति): अध्यक्ष महोदय, 2003– 2004 के बजट के अनुमानों पर जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। वित्त मंत्री प्रो० सम्पत सिंह जी ने जो बजट पेश किया है वह एक कर रहित बजट है। इस बजट से पूरे प्रदेश के लोगों को लाभ होगा। मेरे से पहले बोलने वाले सभी वक्ताओं ने बजट के बारे में बोला है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश किसान प्रधान प्रदेश है इसके अंदर किसान को बिजली पानी सुचारू रूप से अगर मिलती रहेगी तो किसान खुशहाल होगा और अगर किसान खुशहाल होगा तो प्रदेश खुशहाल होगा। वर्तमान सरकार ने अपना कार्यकाल में किसान को अधिक सुविधाएं दीं, सुचारू रूप से बिजली दी, पानी दिया जिससे किसान की अच्छी प्रौडक्शन हुई और इसी वजह से हरियाणा प्रदेश के अन्न के भंडार काफी अधिक मात्रा में भरे यानी किसान को बहुत अधिक लाभ हुआ। अध्यक्ष महोदय सबसे पहले मैं बिजली के बारे में बोलना चाहूँगा। हरियाणा सरकार ने बिजली उत्पादन, ट्रांसमीशन और वितरण के लिए विशेष पग उठाए हैं मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बोलते हुए बताया कि सरकार ने बिजली प्रौडक्शन के लिए क्या किया है। वर्तमान सरकार ने 792.1

मैगावाट बिजली का अधिक उत्पादन किया है। यह इस सरकार की कुशल नीति है। पानीपत की छठी यूनिट 210 मेगावाट की चौधरी देवी लाल जी जब 1989 में मुख्य मंत्री थे तो उनकी योजना के तहत 100 प्रतिशत काम पायलिग का हो चुका था जिसमें 100 करोड़ का सामान आ गया था जो कि रेलवे स्टेशन पर पड़ा रहा 1991 में चौधरी भजन लाल जी की सरकार आई उस सरकार ने भी उस सामान को हाथ नहीं लगाया फिर साढ़े तीन साल तक बंसी लाल जी की सरकार रही, तब भी सामान पड़ रहा। भजन लाल जी की सरकार के समय में बी०एच०ई०एल० कंपनी ने जो सौ करोड़ का सामान था उसके रखरखाव के लिए दो करोड़ रुपये मांगे थे ताकि वह जनता का पैसा है और सौ करोड रुपये का सामान खराब न हो जाए लेकिन चौधरी भजन लाल जी की सरकार ने वह दो करोड़ रुपये रखरखाव के लिए भी नहीं दिए वह सामान पड़ा पड़ा जर खाता रहा। अब माननीय मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार के आने के बाद छठीं यूनिट का काम युद्ध स्तर पर हुआ और आज उस प्लांट का प्लांट लोड फैक्टर 92 प्रतिशत पर चल रहा है और यह इस बात का उदाहरण है कि वहां के जो कर्मचारी हैं उनको इंसैंटिव मिल रहा है। इसके साथ ही साथ पानीपत थर्मल पॉवर प्लांट की जो पहली और दूसरी यूनिट हैं उनकी ओवरहालिंग के लिए पहले ए०बी०बी० कंपनी को 300 करोड़ रुपये का ठेका दिया गया था उसमें उन्होंने इलैक्ट्रोस्टेटिक प्रैसिपिटेटर, मैकेनिकल प्रैसिपिटेटर, इन्डयुज्ड ड्रॉफ्ट फैन, फोर्सड ड्रॉफ्ट फैन, कोल बोल मिल, बॉयलर की टयूक

की मरम्मत और उनकी ओवरहालिंग करनी थी लेकिन उसके अंदर इतना ज्यादा कमीशन था कि वह कंपनी काम नहीं कर सकी। जिससे 1999 तक वह काम नहीं चल सका। बाद में माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने आकर एक नंबर और दो नंबर प्लांट की ओवरहालिंग कराई आज वह थोड़े से खर्च से 110 मेगावाट का यूनिट 114 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है। जहां पिछली सरकारें सिर्फ 7 मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए करोड़ों खर्च कर रही थीं 1 इस प्रकार वर्तमान सरकार कम पैसा खर्च करके अधिक बिजली का उत्पादन करना चाहती है। मैं मुख्य मंत्री जी के साथ एक दिन गाड़ी में जा रहा था हम पानीपत थर्मल पॉवर प्लांट के पास से गुजर रहे थे मैंने मुख्य मंत्री जी से कहा कि इतनी सरकारें आईं किसी ने यह प्रयास नहीं किया कि हरियाणा का नाम इंडिया में सुपर थर्मल पॉवर के मामले में फर्स्ट आए। जिस प्रदेश में एक हजार मेगावाट यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होने लगता है उसका नाम इंडिया के नक्शे पर आ जाता है। हमारी टोटल प्रौडक्शन 860 मेगावाट यूनिट का है यदि 210 मेगावाट का प्लांट और लगा दिया जाए तो हमारे प्रदेश का नाम भी इंडिया के नक्को पर आ जाएगा। मात्र दो दिन के बाद ही मुख्य मंत्री जी ने 250— 250 मेगावाट की दो यूनिट्स (यानी टोटल 500 मेगावाट की जो 1800— 1900 करोड़ रुपये की लागत से बनेंगी) की घोषणा कर दी और अब इन यूनिट्स का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है जिससे हरियाणा प्रदेश में और अधिक बिजली का उत्पादन होगा और हरियाणा प्रदेश की जनता 24 घंटे बिजली

यूज कर सकेगी और उसके बाद भी हम बिजली को अन्य राज्यों को बेच सकने की स्थिति में होंगे। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मुख्य मंत्री जी ने आई०ओ०सी० कंपनी से भी समझौता किया है जो कि 360 मेगावाट बिजली हरियाणा प्रदेश को देंगे उसका काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है आज ऐसी ऐसी योजनाएं बन रही हैं जिसमें हरियाणा प्रदेश को अधिक लाभ हो सके। इसके साथ ही हमारा जो स्थूल कंज्पशन है उसका मैं जिक्र करता हूँ। हमारी सरकार के समय में स्थूल कंज्पशन में कमी आई है जिससे कम से कम 200 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। राज्य में बिजली बोर्ड ने 1998–99 के 367 यूनिट बिजली के मुकाबले में 525 यूनिट बिजली दी है जो लगभग 43 प्रतिशत अधिक है। इसी तरह से 1998–99 की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में 48 प्रतिशत अधिक बिजली दी जा रही है। जिन किसानों की फसल को सूखे के कारण जो नुकसान हुआ था जिनकी 50 प्रतिशत से ज्यादा फसल खराब हुई थी उसके लिए एक जनवरी 2000 से छः महीने तक बिजली के बिल स्थगित कर दिये थे। इसके साथ ही जिन किसानों की 75 प्रतिशत फसल का नुक्सान हुआ था उनके बिजली के बिल माफ कर दिये। जनवरी 2002 से 30 सितम्बर 2002 तक ऐग्रीकल्चर के और नलकूपों के बिजली के बिल माफ किए गये। किसानों को राहत के लिये नलकूपों की अधिकता जो लोड एक्सटैंड कराने के लिए एक हजार से दो हजार पर बी०एच०क्यू० ली जाती थी उस पर मुख्य मंत्री महोदय ने बड़ी भारी राहत दी है उनको 100 रुपये प्रति बी०एच क्यू० के हिसाब से किसान अपना लोड एक्सटैंड करा

सकते हैं। ऐसी योजना माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बनाई है। इसके साथ–साथ किसानों की निरन्तर मांग पर उपभोक्ता को नलकूपों के कनैक्शन देने जारी किए हैं जिनके नलकूप कनैक्शन डिफाल्ट एमाउंट के कारण काटे जा चुके थे हमारी सरकार ने उन किसानों को दोबारा से कनैक्शन जारी करने की एक योजना बनाई और उन किसानों को दोबारा से कनैक्शन दिये गये। इसी तरह से 1450 वितरण ट्रांसफार्मर लगाये गये जिससे 1312 किलोमीटर एल०टी० लाइन को एच०टी० में डाइवर्ट करके लाया जाता है। उसमें 8312 किलोमीटर अलग से लाईन बिछाई गई है जिससे आम उपभोक्ता को सुचारू रूप से बिजली मिल सके। इसके साथ ही बिजली के उत्पादन, प्रसारण, वितरण पर 1850 करोड़ रुपये खर्च किए गये हैं पिछली सरकारों ने तीन वर्ष में 649 करोड़ रुपये खर्च किये थे। इसके साथ–साथ ये राशि पिछली सरकारों की तुलना में लगभग 285 प्रतिशत अधिक है। बिजली की प्रसारण और वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए न नये सब–स्टेशन लगाये गये हैं, 163 सब–स्टेशनों की क्षमता बढ़ाई गई है और 705 किलोवाट की नई लाइन बिछाई गई है जिससे लगभग 700 करोड़ रुपये की लागत से 75 नये सब–स्टेशनों का निर्माण वर्तमान सरकार ने किया, यह एक बहुत बडी उपलब्धि है। इसके साथ–साथ कृषि पर बिजली की 1950 करोड़ रुपये की सबसिडी दी गई। पिछली सरकार ने तीन साल की अवधि में केवल 623 करोड़ रुपये की सबसिडी दी थी। आज बिजली विभाग के कर्मचारी गांव में जाते हैं और वहां पर कैम्पस लगाते हैं जिससे

पूरे प्रदेश के अन्दर 2003 तक 2071 गांवों में 63000 ऐसे कनैक्शन दिये गये हैं मौके पर ही उनकी सिक्योरिटी ली जाती है, मौके पर ही उनकी टैस्ट रिपोर्ट लेकर उनके कनैक्शन रिलीज किए जाते हैं। पहले उपभोक्ता खुद बिजली के दफ्तर में जाता था। आज सरकार की नीति की वजह से खुद कर्मचारी गांव में जाकर कनैक्शन देते हैं यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ–साथ सरकार ने जो बकाया बिलों की वसूली के प्रयोग के लिए किसानों को छूट दी है जिससे सरचार्ज माफ किया गया। जनवरी, 2003 तक 1269.39 करोड़ रुपये बकाया बिलों की वसूली की गई और अप्रैल से जनवरी, 2003 के दौरान 367.83 करोड़ रुपये बकाया बिलों की वसूली की गई जिसमें 161.35 करोड़ रुपये की माफी की गई जो राशि है वह भी उसमें शामिल है। बिजली की कार्यकुशलता के क्षेत्र में देश भर में हरियाणा प्रदेश तीसरे स्थान पर रहा है। हरियाणा बिजली निगम ने 2001 –2002 में 115.93 करोड़ रुपये वाणिज्यिक लाभ प्राप्त किया और वर्ष 1999–2000 में जो वणिज्यिक घाटा हुआ जो उसमें 632.87 करोड़ रुपये हुआ है। एन०ए० वर्ष 2001 – 2002 में 204. 81 करोड़ रुपये घाटा था उसमें 67.63 करोड़ रुपये की कमी की गई, और वर्ष 2001 –2002 में 109. 79 करोड़ रुपये का घाटा था उसमें 153.61 करोड़ रुपये की कमी लाई गई। बिजली निगमों का प्रयास है कि अपने घाटे में कमी, खर्चे को कम करके उस घाटे को कम किया जा सके। इसलिए हरियाणा प्रदेश बिजली के मामले में जो आज की सरकार बहुत कोशिश कर रही है और भविष्य में कोशिश

करेगी जिससे प्रदेश की जनता को लाभ होगा। इसके साथ साथ ग्रामीण पंचायतों को विशेष अधिकार दिये गये हैं चौधरी देवी लाल जी जब प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो वे खुद गांवों के अन्दर जाते थे और कहते थे कि इनको अधिकार दिए जाएं ताकि इनको पता लगे कि ग्रामीण जनता जो ग्राम पंचायतें बनाती हैं उनके क्या अधिकार हैं। चौ० देवी लाल की नीतियों पर चलते हुए आज हरियाणा सरकार ने और चौ० ओम प्रकाश चौटाला जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए जो करोड़ों रुपये का धन उपलब्ध कराया जाता है उसका 87.67 प्रतिशत उपयोग करके हरियाणा देश भर में प्रथम स्थान पर आया है। राज्य सरकार ने राज्य में इन्दिरा विकास योजनाओं के तहत 56.35 करोड़ रुपये खर्च करके गांव में जो गरीब जनता है उसके लिए 28317 मकान बनाए। मकानों के सुधारीकरण के लिए 967.95 लाख रुपये की लागत से 93.26 मकानों की दशा सुधारी गई। राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण ग्राम योजना के तहत 253 करोड़ 67 लाख रुपये खर्च किए गए। देश भर में काम के बदले अनाज की स्कीम लागू की गई जो कि नया रिकॉर्ड है और जिसमें हरियाणा हिन्दुस्तान में पहले नम्बर पर आया है। इसके साथ–साथ सरकार ने '' सरकार आपके द्वार' ' कार्यक्रम के तहत 33 हजार कार्यों की घोषणा की और उनको पूर्ण करवाया। इसमें भी हरियाणा प्रदेश पहले नम्बर पर आया है। ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दिसम्बर, 2000 तक 6306 व्यक्तियों को लाभ हुआ। जिसमें 3414 महिलाएं हैं और 2905 अनुसूचित जाति के व्यक्ति शामिल हैं,

जिनको 708.59 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी गई और उनको ऋण दिए गए। वर्ष 2003–04 के दौरान ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के तहत जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को दिए गए अनुदान समेत 125.81 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई। ग्रामीण पंचायतें यदि कोई अच्छा कार्य करती हैं तो उनको 1 लाख 25 हजार पंचायत समिति और 3 लाख जिला परिषद् और 5 लाख तक बिना किसी विकास स्वीकृति के वे काम कर सकती हैं। इसके साथ–साथ जो ग्राम पंचायतें अच्छा कार्य करती हैं उनके लिए 20,30 और 50 हजार रुपये सरकार की तरफ से दिए जाते हैं जो राशन वितरण प्रणाली है उसमें भी ग्राम पंचायतों का विशेष योगदान है, उसमें ग्राम पंचायतों के पंचों और सरपंचों को शामिल किया गया है। जो राशन कार्ड वगैरह बनते हैं उनके सर्वे के लिए ग्राम पंचायतों के पंचों की एक समिति बनाई गई है जो इसमें शामिल किए गए हैं। इसके साथ–साथ राज्य में 6034 पंचायतों में से 6025 विकास समितियों का गठन किया गया है और जो बाकी हैं उनको भी शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। राज्य में एस०सी०बी०सी० चौपालों को पूर्ण रूप से बनाया गया है। यदि हम मानते हैं कि कांग्रेस सरकार ने सदा हरिजन और बैकवर्ड क्लास का यह कहकर 50 साल तक वोट लिया कि हम आपकी गरीबी दूर करेंगे, गरीबी दूर करेंगे। लेकिन विशेष कर कांग्रेस पार्टी ने कभी हरिजनों की तरफ कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। मैं ओम प्रकाश चौटाला जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने '' सरकार आपके द्वार '' कार्यक्रम के तहत कोई हरिजन बैकवर्ड चौपाल या

कोई नई चौपाल मांगी गई तो वह '' सरकार आपके द्वार '' में दी गई। इस बात का उदाहरण मेरे से पहले बोलने वाले साथियों ने भी दिया था। आज 17 में से 17 कांग्रेस के विपरीत हैं। सारे ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ हैं, केवल भाई रामकिशन फौजी जो बंसी लाल जी के साथ हैं। इस बात का उदाहरण आपके सामने है। इसके साथ–साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो कर नुकसान हुआ, बंसी लाल की सरकार ने जो शराबबंदी की उसमें हरियाणा प्रदेश को काफी नुकसान हुआ, उस समय 1,04,484 मुकद्दमें दर्ज हुए जिसमें से 874 मुकद्दमें ऐसे हैं जिनमें सरकारी कर्मचारी हैं, 300 मामले ऐसे दर्ज किए गए हैं जिन में पुलिस कर्मचारी भी शामिल थे। इस अवधि के दौरान 9,71 ,728 अंग्रेजी बोतलें पकड़ी गई और 21 ,84,925 थैलियां और 1,89,740 बोतलें बीयर की तथा 9882 क्विंटल लाइन, 1355 भट्टियां बरामद की गई। इस सारी शराब की कीमत जो जत्त की गई 17,08,67,445 रुपये बनती है। इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि वर्तमान सरकार ने 29696 मुकद्दमों को कैंसिल किया। शराबबंदी के दौरान वर्ष 1995 में 24848 जीपें, 32 टाटा सुमो, 16762 मारुति कारें, वर्ष 1996 में 2296 जीपें, 105 टाटा सूमों, 17487 मारुति कार, वर्ष 1997 में 5196 जीपें, 295 टाटा सूमों, 22472 मारुति कारें, वर्ष 1998 में 5457 जीपें, 530 टाटा शो, 10445 मारुति कारें परचेज की गई। उपरोक्त आकड़ों से साबित होता है कि जो गाड़ियां खरीदी गई वो सब उस समय शराब की तस्करी में यूज की गई। इस तरह पूर्व सरकार ने हमारे प्रदेश के युवाओं को गलत रास्ते पर ले जाने

का काम किया। मौजूदा सरकार ने भाई अभय सिंह चौटाला जी जो हरियाणा औलम्पिक संघ के प्रधान हैं, को जिम्मेवारी सौंपी कि जो नौजवान पहले वाली सरकार की गलत नीतियों के कारण गलत रास्ते पर चल पड़े थे उन्हें ठीक रास्ते पर लायें। हमारी सरकार ने उन नौजवानों को सही रास्ते पर लाने के लिए खेलों को बढ़ावा दिया। जिसका परिणाम यह निकला कि आज हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी चाहे एशियाड गेम हैं, चाहे कॉमन वैल्थ गेम हैं या नैशनल गेम हैं उनमें मैडल ला रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह हरियाणा सरकार की अच्छी नीतियों के कारण ही हो रहा है। इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 3 प्रतिशत का आरक्षण भी दिया है जिससे खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियाँ भी मिल सकेंगी। जबकि चौधरी बंसी लाल जी की सरकार के समय में जहरीली शराब पीने से 40 आदमियों की मौत हो गई थी। जिनमें 7 यमुनानगर जिले के 2 कुरूक्षेत्र जिले के, 6 हिसार जिले के, 11 जींद जिले के, 5 फरीदाबाद जिले के और 7 करनाल जिले के व्यक्ति थे। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त सामाजिक कल्याण के लिए भी स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी ने बहुत से कार्य किए थे और मौजूदा सरकार भी उन्हीं की नीतियों पर चल रही है। स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी ने हमारे बुजुर्गों को मान सम्मान देने के लिए बुढ़ापा पैंशन देने का काम किया था कि 65 वर्ष से अधिक जिनकी आयु होगी उनको बुढ़ापा पैंशन मिलगी और चौटाला साहब ने उस पैंशन को 100 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये किया। इसके अतिरिक्त

हमारी सरकार ने विधवाओं, विकलांगों की पैंशन भी 100 से बढ़ाकर 200 रुपये करने का काम किया जो कि बहुत ही सराहनीय काम है। लेकिन पूर्व की सरकारों ने उस पैंशन को काटने का काम किया था और अब दोबारा से हमारी सरकार आने पर जिनकी पैंशन पूर्व की सरकारों ने काट दी थी, उनको देने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी की नीतियों पर, चलते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने हरियाणा प्रदेश में 413 वृद्ध आश्रम बनवाये हैं और 202 वृद्ध आश्रम निर्माणाधीन हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति के छात्र और छात्राओं को हमारी सरकार ने छात्रवृति देने की नीति बनाई है। इस नीति के तहत जो गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा नहीं सकते उनको छात्रवृति दी जायेगी और जिला हैड क्वाटर पर ट्रेनिंग भी दी जाती है 1 अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी चाहते थे कि गरीब लोगों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। उनकी इसी बात को ध्यान में रखते हुए मौजूदा सरकार ने नीति बनाई कि गांवो में प्राइमरी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी सिखाई जायेगी और आज हरियाणा में हर प्राइमरी स्कूल में पहली से अंग्रेजी सिखाई जा रही है। ताकि गांवों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके। पहले लोगों की धारणा यह रहती थी कि गांवों में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती और वे अच्छे नागरिक नही बन सकते, आगे नहीं बढ़ सकते लेकिन अब उनको भी अच्छी शिक्षा मिलेगी वे भी अच्छे नागरिक बन सकेंगे। इसके अतिरिक्त माननीय

मुख्य मंत्री जी ने पूरे हरियाणा प्रदेश में जो भी स्कूल अपग्रेडेशन के नार्म्ज पूरे करते थे, उनको अपग्रेड किया है, मेरे हल्के में भी बहुत से स्कूलों को अपग्रेड किया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। स्कूल अपग्रेड करने से पहले जहां हमारी छात्रायें दस–दस कि०मी० दूर दूसरे गांवों में हायर शिक्षा लेने के लिए जाती थी अब उनको यह दिक्कत नहीं हो रही। अब उन्हें अपने गांवों में ही हायर शिक्षा मिल जाती है।

श्री अध्यक्ष: पंवार साहब, आप वाईड अप करें।

श्री कृष्ण लाल: अध्यक्ष महोदय, पहले की सरकारें जो वायदे करती थी वे वायदे कागजों तक ही सीमित रह जाते थे जबकि हमारी सरकार ने अपने वायदे पूरे किए हैं। और काम करके दिखाये हैं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के की एक दो मांगों के बारे में आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी ने 1987 में जब वे मुख्य मंत्री थे उस समय उन्होंने असन्ध में पफड़ाना गांव में एक शुगर मिल लगाने की घोषणा की थी। इस बारे में मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को भी सारा बताया है कि उस समय बोर्ड आफ डायरैक्टर्ज भी बन चुका था लेकिन बाद में दूसरी सरकार आने के कारण वहां शुगर मिल नहीं बन सकी। अध्यक्ष महोदय, असंध–जिला जींद, पानीपत, करनाल व कैथल इन सभी से 40 से 45 कि० मी० की दूरी पर पड़ता है। वहां पर पानी भी बहुत खराब है और गन्ने की फसल अधिक होती है। वहां छोटे किसान हैं यदि

वहां पर शुगर मिल लग जाये तो वहां के किसान को काफी फायदा मिलेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी वहां पर शुगर मिल बनाने की घोषणा करके सर्वे करवाने की घोषणा की थी, यह सर्वे पूरा हो चुका है इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां पर जल्दी से जल्दी शुगर मिल बनवाई जाये। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त थर्मल से जो आपके हल्के में पड़ता है वहा पर एक उपला ड्रेन निकलती है जहां वैसरी गांव भी है। वहां के किसानों को 6–7 कि०मी० घूमकर जाना पड़ता है। केवल मात्र अढ़ाई–तीन लाख रुपये की लागत से उस ड्रेन पर पुलिया बननी है। इस पुलिया के बनने से किसानों को बहुत लाभ होगा। यह पुलिया बनने से किसानों का 6– 7 कि०मी० का चक्कर बच जायेगा इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह पुलिया बनवाई जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया इसके लिए मैं आपका दोबारा से धन्यवाद करता हूँ और बजट का समर्थन करता हूँ। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री शशी परमार (मुण्डाल खुर्द): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि सदन का कीमती समय आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए दिया। सबसे पहले मैं माननीय सम्पत सिंह जी का धन्यवाद करता हूँ कि बहुत शानदार और कर रहित बजट और एक संतुलित बजट इन्होंने पेश किया है। इसमें 2100 करोड़ रुपये का एलोकेशन दिखाया गया है जो पिछले साल से 166 परसैंट अधिक है। इस बजट में सबसे खास

बात यह है कि सरकार की जो नीति है चौधरी देवी लाल की नीतियों पर यह सरकर चल रही है यानि उसी को फौलो करते हुए जिस तरीके से सामाजिक सेवा के लिए इस बजट में 890 करोड़ रुपये रखे गए हैं जो कि कुल बजट का 42 परसैंट हिस्सा बनता है जिससे वृद्धों, बुजुर्गों और विधवाओं को मान के तौर पर उन्हें सम्मान दिया जायेगा। इसी तरीके से जो इन्फ्रास्ट्रक्चर की मद में पिछले बजट में 43 परसैंट एलोकेशन की गई थी जैसी कि माननीय मुख्य मंत्री जी की मंशा है कि इस प्रदेश में इकास्ट्रक्यर मजबूत होगा। जिससे कि हमारे उद्योग धन्धे बढ़ेंगे और काम धन्धा भी बढ़ेगा। आज प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं इसके लिए जरूरी है कि आज हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए सबसे बड़ी बात हमारे नौजवान साथियों के लिए बजट में दिखाई गई है वह यह कि 20 हजार नौजवान साथियों को रोजगार देने के लिए बजट में एलोकेशन की गई है। यानि उनको रोजगार दिया जायेगा जिससे कि हमारे नौजवान साथियों को रोजगार मिल सकेगा और उनको लाईन मिलेगी जिससे देश तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ सकेगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जब इस प्रदेश की बागडोर संभाली थी उस समय प्रदेश की अर्थव्यवस्था काफी खराब थी और कानून व्यवस्था का भट्ठा बैठा हुआ था। उस वक्त मुख्य मंत्री जी ने सरकार की कमान संभालने के बाद एक विश्वास पैदा किया और जो बात थी यानि जिस तरीके से इस थोडे से समय में विकास कार्य किए गए हैं विशेष तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि '' सरकार आपके द्वार ''

कार्यक्रम हमारी सरकार का एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम सिद्ध हुआ है और राष्ट्रीय स्तर पर भी इस प्रोग्राम की सराहना की गई है। काफी स्टेट्स इस प्रोग्राम को फौलो कर रही हैं। इसी बात का नतीजा है कि यह 33 हजार के करीब जो मुख्य मंत्री जी ने घोषणाएं की हैं आज वे सारी की सारी पूरी हुई हैं और आज प्रदेश में ऐसा कोई गांव या ढाणी नहीं है जिसमें ओवर आल डिवैल्पमेंट न हो रही हो। इसी प्रकार से पब्लिक हैल्थ डिपार्टमेंट के तहत गांवों में और ढाणियों में वाटर वर्क्स के काम हो रहे हैं। यानि हर तरीके के काम इस प्रदेश में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी द्वारा करवाये जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत गौरव की बात है और यह पहली बार है कि मुख्य मंत्री की कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। चाहे जिस भाई ने भी '' सरकार आपके द्वार '' कार्यक्रम के तहत अपनी चिट पर भी लिखकर दे दिया, वही काम हुए हैं। आज उसी का नतीजा है कि मेरे अपने हल्के में भी तीसरा प्रोग्राम यानि '' सरकार आपके द्वार '' कार्यक्रम लगने जा रहा है। अब गांवों के इलाके के लोग चक्कर काटते फिर रहे हैं और कहते फिर रहे हैं कि चौटाला साहब अपना समय कब हमें देगे जब '' सरकार आपके द्वार '' कार्यक्रम होगा क्योंकि लोगों में एक विश्वास पैदा हो रहा है कि विकास के बहुत सारे कार्य यह सरकार कर रही है। आज उसी का नतीजा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुण्ढाल क्षेत्र में 50 करोड़ से भी ज्यादा विकास के काम हुए हैं। आज मेरे हल्के के हर गांव में मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि 50 लाख से लेकर 5–6

करोड़ रुपये तक के काम इस सरकार ने किए हैं। इसी तरह से मैं सड्कों के बारे में बताना चाहता हूँ। काफी सड़कें हमारे क्षेत्र में बनी हैं और 50 किलोमीटर के करीब मेरे हल्के में नई सड़कें बनी हैं। आज उसी का नतीजा है कि भिवानी जिले में विशेष तौर पर काफी लम्बे अर्से से जो सड़कें खराब पड़ी हुई थी जिन सड्कों पर माननीय बंसी लाल जी का भी काफी आना–जाना लगा रहता था। जैसे एक सड़क भिवानी से दिल्ली वाया रोहतक होते हुए हें। इस सडक पर पिछले 15–20 सालों से काम नही हुआ था उस पर माननीय चौटाला साहब ने काम करवाया। इसी प्रकार से कोट पुतली, महेन्द्रगढ़, नारनौल, भिवानी की जो सड़क थी, इस सड़क का जिक्र बंसी लाल जी ने पिछले सैशन में किया था और इसी सड़क का जिक्र नरेन्द्र जी ने भी किया था। मैं आभार व्यक्त करता हूँ चौटाला साहब का कि इन्होंने खण्डूरी साहब से मिलकर बात की और इस सड़क के लिए 40 करोड़ रुपये मन्जूर करवाये और अब इसके टैण्डर भी करवा दिए हैं। आज इसी का नतीजा है कि भिवानी जिले में तकरीबन सड्कों के काम हो गए हैं चाहे वह भिवानी से हांसी है, भिवानी से लोहारू है, भिवानी से दादरी है, भिवानी से रोहतक है या हल्कों के अन्दर की सड़कें हैं वे बहुत ही मजबूत और बढ़िया तरीके से बनी हैं, अन्य सड्कों पर भी काम चल रहा है। पिछले 15– 20 सालों में सड्कों पर ऐसा बढ़िया काम कभी नहीं हुआ है। इसी तरीके से शिक्षा के मामले में हरियाणा प्रदेश की सरकार ने एक नई शिक्षा नीति लागू की है जिसके तहत प्रथम क्लास से ही अंग्रेजी शिक्षा बच्चों के लिए लागू

की गई है तथा कम्प्यूटर शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया है। विशेष तौर पर जो स्कूल्ज अपने नॉर्म्ज पूरे करते हैं चौटाला साहब ने दरियादिली दिखाई है और बगैर किसी भेदभाव के उनको अपग्रेड किया है। हमारे हल्के में भी कई स्कूल अपग्रेड हुए हैं मिट्ठाथल का, मानहेरु का और अभी सरसा घोघडा का स्कूल अपग्रेड हुआ है। मैं सदन को बताना चाहूँगा कि कुछ स्कूल तो ऐसे थे जो बहुत पुराने थे और अपग्रेड नहीं हुए थे। बामला से सरसा घौघडा के स्कूल को बने हुए 50 साल हो गए हैं लेकिन वह प्राइमरी स्कूल ही था और आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को 8– 10 किलोमीटर तक चलना पड़ता था। हम आभारी हैं मुख्य मंत्री जी के उन्होंने इन स्कूलों को अपग्रेड किया है इससे इन गांवों के लोगों में एक नया विश्वास पैदा हुआ है। इसके अलावा उद्योगों के बारे में काफी विस्तार से चर्चा हुई और इस बात का जिक्र भी किया गया है कि मुख्य मंत्री जी बाहर गए थे। आज मार्कीटिंग का युग है प्रचार–प्रसार का युग है। जब तक हम किसी बात की ऐडवर्टाजईमैंट नहीं करेंगे किसी को कन्विंस नहीं करेंगे तब तक उद्योग धन्धे प्रदेश में नहीं आ सकते। किसी भी उद्योग धन्धे से इस बात का उदाहरण ले सकते हैं। हरियाणा प्रदेश में वर्तमान सरकार आने के बाद जहां निर्यात दुगुना हुआ है वहीं चार हजार के करीब नए छोटे उद्योग लगे हैं और बड़े उद्योग 140 के करीब नये लगे हैं। इसी प्रकार से हमारे डेढ़ हजार से ज्यादा नौजवान साथियों को इस सरकार की वजह से रोजगार मिला है, यह बहुत ही बड़ी बात है। विशेष कर इन्फर्मेशन टैक्नोलोजी में

गुडगांव को डिवैल्प किया गया है और सॉफ्टवेयर का निर्यात इस प्रदेश में जहां 3200 करोड़ रुपये का था इस साल के अन्त तक वह 4200 करोड रुपये तक होने का अनुमान है यह बहुत बड़ी बात है। गढ़ी हरसरु में एक इकोमिक जोन बनाया गया है जिसमें कि तीन हजार से ज्यादा एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। पीछे हम कई देशों में गए थे और चाईना में देखा कि वहां इक्योमिक जोन्ज बने हुए हैं जिनमें सिंगल विंडो सिस्टम है और विद इन थी डेज वहां पर सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। सिंगल विंडो सिस्टम को फौलो करते हुए मुख्य मंत्री जी ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमारे यहां गढ़ी हरसरु को डिवैल्प करने का जो फैसला किया है यह बहुत ही अच्छा प्रयास इस सरकार ने किया है। जिस तरह से हमारे नौजवान साथी पथभ्रष्ट हो गए थे, इस सरकार के आने के बाद उनको खेलों की ओर मोड़ा और 400 के करीब मैडल राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में हमारे नौजवान साथियों ने जीते हैं। इससे एक नया विश्वास और एक नया जोश हमारे नौजवान साथियों में माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की वजह से और चौधरी अभय सिंह जी की वजह से पैदा हुआ है। यह इस बात का नतीजा है कि आज शाहबाद में भी एस्ट्रोटर्फ का मैदान बन रहा है, गुड़गांव में भी बन रहा है। जौशी चौहान गांव में भी 83 एकड़ भूमि पर एक स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स चौधरी देवी लाल जी के नाम से बनाया जा रहा है जो कि एक बहुत बड़ी बात है। मैं इस बात में एक उदाहरण देना चाहूँगा। पिछले बुसान गेम्स में इण्डिया की टीम

कबड्डी में फर्स्ट आई थी उस टीम का जो कैप्टन था वह मेरे हल्के से था। मैंने आदरणीय मुख्य मंत्री जी से फोन कर बात की और कहा कि आप भिवानी आ कर उसको आशीर्वाद दें 1 चौटाला साहब अगले ही दिन भिवानी में आए और भाई अजय सिंह और मुख्य मंत्री जी उसके घर गए और उसकी हौंसला अफजाई की और दस लाख रुपये हौंसला अफजाई के रूप में उसको दिए। हमारे जो भी प्लेयर इस बुसान गेम्ज में जीते थे 10– 10 लाख रुपये उनको देने की घोषणा भी उन्होंने की। इस प्रकार से खिलाड़ियों की हौंसला अफजाई करके सरकार एक बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इसी तरीके से बिजली के क्षेत्र में इतने ज्यादा रिफौर्म्ब और सुधार इस सरकार ने किये हैं कि जितने गिनाए जाएं वे कम हैं। इसी तरह वर्ष 1998 के मुकाबले में यह रिकॉर्ड की बात है कि 43 प्रतिशत ज्यादा बिजली की सप्लाई की गई है और सूखा राहत के लिए 48 प्रतिशत ज्यादा बिजली देहातों में दी गई है जो कि एक रिकॉर्ड की बात है। 700 करोड़ रुपए से ज्यादा इलैक्ट्रिक सैक्टर में रिफौर्म के लिए रखे गए हैं। मैं तो अपने जिले से अन्दाजा लगाता हूँ कि हमारे जिले में जिस तरह से बहुत पुरानी डिमाण्डजू थीं वह हमारे मुख्य मंत्री जी द्वारा पूरी की गई हैं। भिवानी में सतनाली में बहुत पुरानी डिमाण्ड 132 के० वी० के बिजली घर की थी उसकी आधारशिला रखी और उसको कम्पलीट करवाकर उसका उद्घाटन भी हमारे मुख्य मंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया है। इसकी वजह से उस क्षेत्र को बिजली के क्षेत्र में बहुत फायदा हुआ है। इसी तरह से 132 के०वी० का

भिवानी के बहल में बिजली का सब–स्टेशन बनकर तैयार हो गया है और लोहारु में भी तैयार है। इसके साथ ही इन्डस्ट्रीयल एरिया भिवानी में उद्योगपति कहते थे कि पहले मुख्य मंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी से उनको बहुत उम्मीदें थीं, उन उद्योगपतियों ने काफी समय तक चौधरी बंसी लाल जी का साथ भी दिया था। उन उद्योगपतियों को वहां पर बिजली की काफी दिक्कतें रहती थी। वहां पर भी 132 के०वी० का बिजली घर की आधारशिला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने रखी है। वह अब बनकर भी तैयर हो गया है। इसी तरह से मेरे गांव में भी 33 के०वी० का सब स्टेशन बना है जिससे चांग और उसके आस–पास के 17 गांवों को जबरदस्त फायदा होगा। वहां पर भी आधारशिला आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने रखी है। अब मैं विशेषकर व्यापारी वर्ग के लिए भी बताना चाहूँगा। उनके साथ बैठकर मुख्य मंत्री जी ने उनकी मांगों को सुना और उनका समाधान किया है। वह समाधान चाहे हमारे हलवाई भाइयों के लिए किया है या किसी और के लिए किया है। उनकी मांगों का समाधान किया है। अब मैं करों के बारे में बात करना चाहूँगा। यह जो डिवैल्पमैंट टैक्स है, इसमें लोकल डिवैल्पमैंट टैक्स को 4 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंस्पैक्टरी राज को खत्म करने का प्रयास इस सरकार के द्वारा किया गया है। इसके अलावा जो नाके लगा करते थे, उनको इस सरकार ने कम किया है। इसके अलावा हमारे व्यापारी भाई सेल टैक्स के दफ्तर में जाते रहते थे और वहां के चक्कर काटते रहते थे। इस

सरकार ने उनको गिफ्ट के रूप में डिम– असैसमैंट करवाई है और यह इस सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसकी वजह से हमारे व्यापारी भाइयों को दफ्तरों के चक्कर काटने से छुट्टी मिल गई है। उनको अब रिटर्न की कोई जरुरत नहीं है और वे अब अपने हिसाब से भर कर देते हैं उसमें अगर कोई कमी हो तो उसी को ठीक करके मान लिया जाता है। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, इस प्रदेश में आज अमन और शांति है। आज हरियाणा में 36 बिरादरी के भाई इकट्ठे रहते हैं। हरियाणा .में आज कोई कम्यूनल वॉयलैंस नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई जातीय तनाव नहीं है। मिलों में किसी भी तरह का तनाव नहींहै, किसी भी तरह का अनरैस्ट नहीं है। हमारे मुख्य मंत्री जी की और सरकार की सोच है कि सबको लेकर के चला जाए। 5 हजार नौजवान साथियों को हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए पुलिस में भर्ती किया गया है, इसके अलावा 4 हजार पुलिस के सिपाहियों को और भर्ती करने की सरकार की योजना है। हमारी सरकार का यह एक बहुत ही अच्छा कदम है।

इसके अलावा मैं अपनी कुछ और बातें कहना चाहूँगा। मेरे हल्के मुंढाल में मुख्य मंत्री जी ने बहुत काम किए हैं। शायद ही आजादी के बाद हमारे हल्के में इतने काम हुए हों। लेकिन सर, फिर भी कुछ हमारी समस्याएं रह गई हैं इसके लिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि विशेषतौर से बौंद में जो ब्लॉक बना हुआ था, उसको चौधरी बंसी लाल जी के राज में वहां से दादरी

में शिफ्ट कर दिया गया था। हैरत की बात तो यह है कि दादरी में एक ही बिल्डिंग में दो ब्लॉक चल रहे हैं। जो ब्लाक बौद ब्लॉक के नाम से था वह भी उसी बिल्डिंग में चल रहा है। हमारे यहां पर थाना है, सब– तहसील है। स्पीकर सर, वहां पर एक यूनिट बनी हुई है। मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि उस ब्लॉक को वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए। सर, आल रेडी उस ब्लॉक का नाम बौंद ब्लॉक है। उसको शिप्ट किया जाए जिससे हमारे साथियों को, हमारे बुजुर्गों को जो परेशानी हो रही है, वह दूर हो सके। जब चौधरी बंसी लाल जी की सरकार पहले आयी थी तो उसी समय इसके ऑर्डर उन्होंने वहां के लिए किए थे। बौंद में हमारा जो कॉलेज बना हुआ है उसकी चारदीवारी नहीं है। मुझे तो हैरानगी है कि पूर्व हमारे जो इस विधान सभा के स्पीकर थे उन्होंने मुंढाल विधान सभा क्षेत्र के लिए कोई विशेष कार्य नहीं करवाए। मुझे हैरानगी इस बात की भी है कि वे बौंद गांव से ही संबंध रखते हैं लेकिन उन्होंने वहां से ब्लॉक और सब–तहसील को शिफ्ट करवा दिया। अध्यक्ष महोदय, बौंद कॉलेज में चारदीवारी न होने की वजह से वहां अवारा पशु घूमते रहते हैं इसलिए मैं चाहूँगा कि उस गवर्नमैंट कॉलेज की चारदीवारी को पूरा किया जाए। इसी तरह हमारे क्षेत्र के धनाना गांव में 33 के०वी० का जो सब–स्टेशन बनाने की घोषणा मुख्य मंत्री जी द्वारा की गयी है मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द उसको भी पूरा किया जाए।

श्री अध्यक्षः परमार साहब, अब आप वाईंड अप करें।

श्री शशी परमारः अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से कुछ रोड्ज भी हमारे हल्के में अधूरी पड़ी हैं हालांकि काफी नयी रोड्ज भी बनी हैं लेकिन फिर भी कुछ रोड्ज अभी भी बनने से रह गयी हैं ये रोड्ज हैं चांग से सह, बागला से रिवाड़ी खेडा। मैं चाहूंगा कि इनकी रिपेयर भी की जानी चाहिए। इसी तरह से इस सरकार के टेन्योर में कई नयी वाटर वर्क्स की स्कीम्ज बनायी गयी हैं फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि भुसाणी, बामला, हिंडौल एवं गुजरानी जो गांव हैं इनमें भी वाटर वर्क्स की स्कीम बनाने के लिए ऐस्टीमेट्स बनाकर केसिज आये हुए हैं। मैं चाहूँगा कि इनको भी मंजूर किया जाए। इसी तरह से बौंद, चांग एवं धनाना में जो परचेज सैंटर्ज बनाने की पहले मंजूरी दी गयी है मैं उनके बारे में कहना चाहूँगा कि उनकी फड़ अभी कच्ची है और उनमें वहां पर चारदीवारी भी नहीं है इसलिए मैं चाहूंगा कि इनके फड़ को पक्का किया जाए और वहां पर चारदीवारी भी की जाए। इन सैंटर्ज की मंजूरी देने के बाद वहां पर रिकॉर्ड तोड़ गेहूँ की परचेज हुई है। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं जो प्रो० सम्पत सिंह जी ने कर रहित और बहुत शानदार बजट प्रस्तुत किया है जिसमें 109 करोड़ रुपये के घाटे को कम करने का प्रयास किया गया है, पर बधाई देता हूँ और इस बजट का समर्थन करता हूँ। मैं चाहूँगा कि हमारे और साथी इसका समर्थन करके इसको पास करें। मैं सरकार को भी

इतना अच्छा बजट पेश करने के लिए बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री अन्ता राम बाल्मीकि (रादौर–अनुसूचित जाति): स्पीकर साहब, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे वित्त मंत्री जी द्वारा पेश कर रहित बजट पर बोलने का मौका दिया। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं बहादुर मुख्य मंत्री को इस बात की बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसे बढ़िया कॉलेज का इन्तजाम करके अच्छे कार्यकर्ताओं को जो ट्रेनिंग दी है और अच्छे कार्यकर्ताओं को तराश कर जो यहां पर विधान सभा में लाकर बिठाया है। आज उनको किसी बात की फिक्र नहीं है उन्हें अगर कोर्ट फिक्र है तो वह इस बात की कि हरियाणा प्रदेश का चहुंमुखी विकास कैसे किया जाए। इस सरकार से पूर्व जितने भी मुख्य मंत्री रहे हैं उनको केवल एक ही बात की फिक्र होती थी कि विधायकों को कैसे कवर किया जाये, कैसे उनको समझाया जाए कैसे उनको मनाया जाए कैसे किसी मंत्री को अच्छी खानें दी जाएं या कैसे उनको प्लॉट्स दिए जाएं किस तरीके से फुसलाया जाए। लेकिन आज हरियाणा प्रदेश के मुख्य मंत्री को मैं इस बात की दाद देता हूँ कि उन्होंने जो अच्छे– अच्छे अध्यापकों के रूप में प्रो० सम्पत सिंह एवं राम पाल माजरा जैसे विधायकों को राजनीति में तैयार किया है जिनकी पढ़ाई की वजह से, जिनके पड़ाने की वजह से आज अच्छे– अच्छे विधायक विधान सभा में बैठे हैं। स्पीकर साहब, आपके सामने मैं अगर विस्तार से एक–एक डिपार्टमैंट की बात

करूंगा तो इस सदन का बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। मैं चौटाला साहब का बहुत छोटा रग कार्यकर्ता हें। मेरे बहुत से वरिष्ठ साथी यहां पर बैठे हैं इसलिए मैं उनका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। जो कर रहित बजट पेश किया गया है, मैं अपनी बात उसके ऊपर ही रखूंगा। हमारे विद्वान वित्त मंत्री जी ने जो कर रहित बजट पेश किया है मैं इसका समर्थन करता हूँ। स्पीकर सर, हमारे बहादुर मुख्य मंत्री जी द्वारा '' सरकार आपके द्वार '' कार्यक्रम के तहत कार्य हो रहे हैं कहीं हरिजन चौपाल बन रही है, कहीं बाल्मीकि चौपाल बन रही है, कहीं बी०सी० चौपाल बन रही है, कहीं सड्कों का निर्माण हो रहा है, कहीं गलियों का निर्माण हो रहा है। कहीं वृद्ध विश्रामालय बन रहे हैं, कहीं पानी की व्यवस्था की जा रही हैं, कहीं नालियां बन रही हैं, कहीं रिटेनिंग वाल बन रही है, कहीं कच्ची सड्कों को पक्का करने का काम किया जा रहा है। कहीं स्कूल के कमरे बन रहे हैं कहीं पशुधन केन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है, कहीं पक्के मकानों का निर्माण करवाया जा रहा है। स्पीकर सर, यहां पर मेरे साथी सदन के सम्मानित सदस्य धर्मबीर जी और जय प्रकाश 50 लाख रुपये की ग्रान्ट की बात किया करते थे आज इन सम्मानित सदस्यों की हरियाणा प्रदेश के बहादुर मुख्य मंत्री ने बोलती बंद कर दी। क्या मांगे, क्या जिक्र करें, कोई मांग बाकी नहीं छोड़ी जिसको मांग सकें। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने हल्के रादौर की बात करना चाहूँगा जिस पर हरियाणा प्रदेश के मुख्य मंत्री की निगाहें लगी रहती हैं जो इनका सिर है, दिल है, कलेजा है उस क्षेत्र के लिए

पहले चरण में 2001 में 1 करोड़ 36 लाख 86 हजार रुपया दिया है और दूसरे वर्ष 2002 में 4 करोड़ 20 लाख 58 हजार रुपया दिया है और 2003 में 3 करोड़ 74 लाख 86 हजार रुपया दिया है और कुल मिलाकर 21 करोड़ 61 लाख 91 हजार 610 रुपया अब तक दिया है और यह मेरे हल्के रादौर के अन्दर दिया है। स्पीकर सर, सदन में बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं। मैंने अपने हल्के की बात कही है। (विघन) ठेका बहादुर मुख्य मंत्री जी के पास है। मैं सीमाओं को लांघना नहीं चाहता। मैं सीमाओं में रहकर बात करता हूँ जो आदमी प्रोटोकोल को और डैकोरम को मद्देनजर रखता है तो प्रदेश उसकी तरफ देखता है। महामहिम राज्यपाल महोदय जब अभिभाषण करके गए थे उस समय सदन के नेता मौजूद थे, विपक्ष के नेता भी मौजूद थे उस समय मेरा सम्मानित सदस्य साथी जय प्रकाश जो माननीय मुख्य मंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी की नर्सरी में ही सीखकर उनका कार्यकर्ता बना और मैम्बर ऑफ पार्लियामैंट भी रहा, उन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय को जाते–जाते कहा कि आपका धन्यवाद कि आपने अभिभाषण दिया है। ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। यह कोई शिष्टाचार की बात हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः नो इंटरवेंशन प्लीज।

श्री बता राम बाल्मीकिः अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी प्रदेश की कोई पंचायत नहीं है, इससे ज्यादा सम्मानित कोई पंचायत नहीं है जहां चुने हुए जनप्रतिनिधि आये हों। अगर वे ऐसी

बात करें तो उनको शोभा नहीं देता है मैं हरियाणा प्रदेश के बहादुर मुख्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बजट में संकेत दिया कि जिन हरिजन लड़कियों की शादी इस वजह से नहीं होती थी कि एक–एक पैसे के लिए उनको दिक्कत होती थी ऐसी गरीब, विधवाओं की लड़कियों की शादी करने में मुश्किल होती थी। हरियाणा के बहादुर मुख्य मंत्री ने वर्ष 2002 – 2003 में 5300 लड़कियों की शादी के लिए 2 करोड़ 70 लाख 30 हजार रुपये दिये हैं। स्पीकर सर, वर्ष 2001 –2002 में 3829 लड़कियों के लिए एक करोड़ 95 लाख 25 हजार रुपये दिए हैं। स्पीकर सर, मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि विपक्ष के लोग इस बात के लिए बोलते थे कि कांग्रेस पार्टी ही एस०सीज० और बी०सीज० की हमदर्द है। लेकिन मैं बधाई देता हूं हरियाणा के बहादुर मुख्य मंत्री जी को जिनकी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। इस सरकार ने एस०सी०और बी०सी० के प्रति हमदर्दी जताते हुए छात्रवृति की राशि को दुगना करने का काम किया है। वर्ष 2001 –2002 में छठी से आठवीं कक्षा के छात्रों के लिए छात्रवृति की राशि 15 रुपये से बढ़ा कर 30 रुपये प्रति माह करने का काम किया है। जिससे एक लाख 25 हजार 402 रुपये की राशि का खर्चा आया है और वर्ष 2001 – 2002 में नौंवीं और 12वीं कक्षा के लिए छात्रवृति की राशि को 20 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 4० रुपये प्रति माह किया गया है जिस से 64613 छात्रों को 3 करोड़ 56 लाख 80 हजार रुपये का लाभ हुआ है। स्पीकर सर, मैं भी विपक्ष के नेता को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने

कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इन्होंने इस बात को माना है कि हम किसानों के प्रति हमदर्दी रखते हैं। इसलिए इन्होंने कहा है कि किसानों के नेता किसानों द्वारा बनाई सरकार और कमेरे वर्ग की सरकार कहलाने वाली सरकार के समय में अगर एस०वाई०एल० नहर का पानी अब नहीं आयेगा तो कभी नहीं आयेगा। इनका कहना ठीक है मैं इस बात के लिए इनको धन्यवाद देता हूँ कि हरियाणा के बहादुर मुख्य मंत्री ने सारी कोशिश करके सुप्रीम कोर्ट से फैसला करवा कर यह प्रमाणित करके दिखा दिया। अब यह बात करते हैं कि बगल में छौरा और देश में ढिंढोरा। अगर वास्तव में एस०वाई०एल० नहर को बनाने के ये पक्षधर और हमदर्द हैं तो मैं इनको कहना चाहूँगा कि अपनी पार्टी की प्रैजीडैंट को जाकर के कहें कि वे पंजाब के मुख्य मंत्री का इस्तीफा मांगें उसने हमारे ऊपर कलंक का टीका लगाया है। इसलिए पंजाब की सरकार ही इसमें रुकावट है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए

आवाजें: ठीक है जी।

श्री अध्यक्षः ठीक है, हाउस का समय एक घण्टे के लिए और बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2003 – 2004 के बजट पर सामान्य चर्चा
(पुनरारम्भ)

15.00 बजे

श्री बता राम बाल्मीकिः स्पीकर सर, मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि गरीबों के उत्थान के लिए छठी से आठवीं के छात्रों कै। लेखन सामग्री देने के लिए 40 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 80 रुपये प्रति माह कर दिया है जोकि सराहनीय काम है और 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं के छात्रों के लिए 60 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 120 रुपये प्रति माह करने का काम किया है। स्पीकर सर, मुझे वह आकड़े याद हैं और मैंने पड़े है कि वे उस वक्त पैसे देते थे हरिजन बच्चों को जब मार्च का महीना आता था जब बच्चे पढ़कर कक्षा से निकल जाते थे और उस पैसे का कोई यूज नहीं होता था। आज हरियाणा प्रदेश में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व वाली सरकार शुरूआत में जब कक्षायें शुरू होती हैं तब पैसे देती है। शुरूआत में किताबें देती है। क्योंकि आत्मा से प्यार है। वास्तव में जो असली कमेरा वर्ग है जो किसान के, मजदूर के साथ जुड़े हुये हैं उन्हें वास्तव में ये प्यार करते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं। उनकी नर्सरी बनाना चाहते हैं अधिकारियों की नर्सरी बनाना चाहते हैं ताकि दलितों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें और दलितों का उत्थान हो सके। इस सरकार की नीयत में कोई खोट नहीं हैं। मैं इस बात के लिए हरियाणा सरकार और माननीय मुख्य मंत्री को धन्यवाद करता हूँ।

स्पीकर सर, कुलीन परिवारों के बच्चों की शिक्षा के लिए अनुदान की राशि 2001 – 02 में पहली से पांचवीं तक के बच्चों को 750 रुपये, 6वीं से 8वीं तक के बच्चों के 900 रुपये, 9वीं से 10वीं तक के बच्चों को 1000 रुपये आदि देने के कितने ही अच्छे–अच्छे काम इस सरकार ने किए हैं। अध्यक्ष महोदय, ये बजट पर खिल्ली उड़ाते हैं, पैसे की खिल्ली उड़ाते हैं। (शोर) इस सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए काम किए हैं। हमारी हरियाणा सरकार ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में काम कर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ चौधरी साहब को खुश कर रहे हैं, लेकिन आकड़ों की बात करना अच्छी बात है। प्रैस ऊपर बैठी है, अधिकारी बैठे हैं, सदन के साथी बैठे हैं, मैं रिकार्ड की बात करता हूँ। मैं कृष्ण पाल गुज्जर की तरह नहीं हूँ कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ठीक है वे हमारे सम्मानित साधी हैं लेकिन एक आदमी को अपना सन्तुलन बिगाड़ने का काम नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के साथियों का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूँ कि हमारी अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए वर्ष 2002 –03 से एक योजना आरम्भ हुई है। इस योजना में जो प्रावधान किया गया है वह इस प्रकार है। 2002 –03 में मैट्रिक में जो 55 प्रतिशत अंक लाएगा उसे 700 रुपये प्रति माह और पुस्तकें खरीदने के लिए 2000 रुपये देने का काम, साइंस सब्जैक्ट में जो 60 प्रतिशत अंक लाएगा उसे 1500 रुपये अनुदान राशि देने का प्रावधान किया गया है, अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी की फ्राख दिली है कि वे इतने

अच्छे– अच्छे कार्य करवा रहे हैं, मेरे हल्के की कुछ बातें ऐसी हैं, रादौर के अन्दर राजकीय महिला विद्यालय की बड़ी आवश्यकता है जहां इस सरकार में इतने कल्याणकारी कार्य हो रहे हैं वहां मैं हरियाणा के बहादुर मुख्य मंत्री से कहना चाहूँगा कि रादौर हरियाणा का अपना हल्का है अपने जिला यमुनानगर में है उसमें कोई राजकीय कन्या महाविद्यालय खोला जाए इसके लिए मेरी मुख्य मंत्री महोदय जी से अपील है। बड़े स्तर के सुन्दर पार्क के लिए मेरे हल्के के लोगों की निगाहें इस तरफ लगी हुई हैं कि चौधरी देवीलाल जी के नाम का पार्क हमारे यहां होना चाहिए। वह चौधरी देवीलाल जो न केवल हरियाणा में ही, न केवल हिन्दुस्तान में बल्कि संसार में एक केन्द्र बिन्दु के नाम से जाने जाते हैं। वह एक अवतार के रूप में, युग पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। रादौर–जठलाना तक की सड़क की हालत बहुत खराब है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से उस सड़क की मुरम्मत की अपील करता हूँ। गुमथला रादौर सड़क की हालत खस्ता है। मैं इस सड़क की मुरम्मत की भी अपील करना चाहूँगा कि इसकी मुरम्मत की जाए। मैं दो सड्कों के लिए सरकार का और बहादुर मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा। शाहबाद–लाडवा सड़क जिसकी डबल लाइन की घोषणा की गई थी, उसके टैण्डर्ज हो चुके हैं। इनकी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है, साथ ही बननी चालू भी हो गई हैं। उसके लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूँ। जी०टी० रोड से ईसरगढ से बाबैन को जाती हुई बराड़ा को जो सड़क जाती है उसको डबल करने की घोषणा की गई थी,

उसके टैण्डर्ज 4 तारीख को हो चुके हैं। उसके लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा। कल भी मेरा प्रश्न था कि फसल के भाव, गन्ने के भाव की बात करते हैं तो रादौर के बहादुर किसानों की जमीन कटाव से नष्ट हो चुकी है। अध्यक्ष महोदय, मेरा मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध है कि हर वर्ष यमुना नदी के कटाव से किसानों की सारी फसल नष्ट हो जाती है। किसान देखता रह जाता है यमुना नदी के कटाव को रोकने के लिए इस नहर के किनारे के साथ–साथ बांध, स्टड बनाए जायें। रादौर शहर के साथ–साथ डब्ल्यू.जे.सी. नहर गुजरती है। उसका पानी बहुत गंदा है, दूषित है, विषैला है, पशुओं के पीने योग्य नहीं है, इससे पशुओं में बीमारी फैलती है, इसका शुद्धिकरण तुरन्त किया जाए जिससे यह पानी पशुओं के पीने लायक हो सके।

श्री अध्यक्षः बता राम जी, आप वाइंड अप करें।

श्री बता राम बाल्मीकिः स्पीकर सर, मुझे पता है कि मुझे कितना टाइम मिलेगा। मैं सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ। मैं अपनी बात दो मिनट में खत्म करना चाहता हूँ। धन्य है यह सरकार। बधाई हो हमारे बहादुर मुख्य मंत्री जी को जो सरकार का हलवा, सरकार का इंसाफ, हमारे अधिकारियों के हाथों में सौंपी हुई हें, मैं बधाई दूंगा हरियाणा प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को जिन्होंने हमारे श्री बी०डी० ढालिया को प्रधान सचिव बनाया हुआ है जिनके पास ग्रामीण विकास और गृह विभाग भी है। इससे बड़ा प्रमाण

नहीं हो सकता। मैं विपक्ष के साथी सदस्यों से पूछना चाहता हूँ कि वे इस मुख्य मंत्री जी की तरफ जरा निगाह तो करके देखें, जरा बोलकर तो देखें, मेरे कहने का मतलब यह है कि इन लोगों के पास कहने को कुछ भी नहीं है, कोई भी जवाब नहीं है। ये तो सिर्फ प्रैस को दिखाने के लिए दबे शब्दों में कहते हैं कि हम इस प्रस्ताव का, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण और बजट का विरोध करते हैं। स्पीकर सर, मैं इससे आगे कहना चाहता हूँ कि हमारे बहुत ही बेदाग छवि के श्री भगवती प्रसाद जी को प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग बनाया हुआ है, हमारे श्री चन्द्र सिंह जी को प्रधान सचिव वित्त विभाग–आबकारी एवं कराधान विभाग बनाया हुआ है। हमारे श्री एच०सी० दिसोदिया को आयुक्त कृषि विभाग–खाद्य एवं आपूर्ति बनाया हुआ है। हमारे सज्जन सिंह जी को सचिव रैंक अधिकारी कृषि मार्केटिंग बोर्ड बनाया हुआ है। इसके लिए मैं हमारे बहादुर मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे श्री हरबखा सिंह जी को एम०डी०, एच०एस०आई०डी०सी० बनाया हुआ है। स्पीकर सर, इस तरह से यह सरकार दलितों की ही सरकार है। इससे आगे हमारे मानिक सोनावाणे जी को सचिव, नगर विकास विभाग बनाया हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अजय सिंह यादवः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः कैप्टन साहब, प्लीज आप बैठिये। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज आप सभी बैठिये। नो परमिशन। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बता राम बाल्मीकिः स्पीकर सर, मेरी दो मिनट की बात रहती है, ये मुझे बीच में डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंहः स्पीकर सर, क्या यह सवाल एस०सी० और ओ०बी०सी० के बीच में आ गया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बंताराम बाल्मीकिः स्पीकर सर, हमारे बहुत ही बेदाग छवि के धनी अधिकारी श्री एस०सी० चौधरी को आयुक्त, उद्योग विभाग बनाया हुआ है। बैकवर्ड क्लास से संबंधित श्री विद्याधर जी को ओ०एस०डी० बनाया हुआ हैं। मैं विपक्ष के सभी साथियों को कह देना चाहता हूँ कि हरियाणा के बहादुर मुख्य मंत्री जी ऐसा रोग काटेंगे कि हरिजन और बैकवर्ड क्लास की बस्तियों में कांग्रेसियों के जाने पर उनका घेराव होगा। आने वाले समय में चाहे ये देख लें, ऐसा ही होगा। आज मैं बता देना चाहता हूँ कि आज विपक्ष की पार्टी कांग्रेस के 'पास एक भी एस०सी० विधायक नहीं है। आज सारे के सारे एस०सी० विधायक चौटाला साहब के साथ हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं और मुख्य मंत्री जी से एक बात कहते हैं कि चौटाला साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। मैं उधर से गिनती करवाना चाहता हूँ ये बैठी हैं, वे बैठे हैं। हमारे

सीता राम जी बैठे हैं, बहन सरिता नारायण जी बैठी हैं, दरियाव सिंह जी बैठे हैं, यहां चौधरी अमर सिंह जी बैठे हैं, यहां रंग। साहब बैठे हैं, कृष्णलाल पंवार जी बैठे हैं। हमने बावले फौजी को इसलिए माफ कर दिया क्योंकि हम पुरानी परम्परा को, हिन्दू संस्कृति को मानते हैं। इन्हें माफ कर दिया कि चलो केपपर। फौजी है, ठीक बात करेगा और ८० प्रतिशत यह हमारे साथ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री राम किशन फौजीः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः राम किशन जी, प्लीज आप बैठिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बता राम बाल्मीकिः स्पीकर सर, हमारे नेता महिलाओं का भी सम्मान करते हैं और मुझे एक बात का बड़ा दुःख है कि हमारी बहन सरिता नारायण से कांग्रेस पार्टी की विधायिका अनीता यादव ने ऐसी बात की जैसे हाकिम मुजरिम से करता है। हमारे अधिकारियों और प्रैस ने भी देखा। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं इसकी निन्दा करता हूँ। स्पीकर साहब, यदि मुझे बोलने के लिए टाइम मिल जाये तो मेरे पास बोलने के लिए एक चिट्ठा है। लेकिन मैं सदन का ज्यादा समय न लेते हुए इस बजट का और कुछ रोज पहले जो अभिभाषण महामहिम जी यहां पर देकर के गए हैं मैं इन दोनों का समर्थन करता हूँ। इसके

साथ ही साथ मैं बधाई देता हूँ कि यह सरकार फलती–फूलती रहे, दिन दुगुनी और रात चौगुनी तरक्की करती रहे। हर घर में खुशहाली हो और हर खेत में हरियाली हो और सभी सदस्यों की आयु लम्बी हो, इन शब्दों के साथ मैं स्पीकर साहब पुनः आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूँ।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः स्पीकर साहब, अगर आज कोई सही मायने में बोले हैं तो वे श्री बता राम जी बोले हैं। (विघन) आप लोगों को इनसे कुछ सीखना चाहिए। आपको सिखाने के लिए ही ये बोले हैं। जो काम विपक्ष के नेता का था कि वे बजट पर आकडों के साथ अपनी बात कहते उन आकड़ों पर वे एक लक्स भी नहीं बोले। (विघ्न) आप लोगों को इनसे सीखना चाहिए। आप हरिजनों को अपमानित करते हैं तभी तो आपका यह दिवाला पिट गया। आज आपके पास एक भी हरिजन एम०एल०ए० नहीं है। आप इन्हें ऐसे अपमानित न करो, कुछ सीखो। स्पीकर साहब, इनको कहना चाहिए यानि आप लोग स्वयं कहो कि आज की डिबेट में हिस्सा लेने वाले विधायकों में अगर कोई मैन ऑफ दी डे है तो वह श्री बन्ता राम जी हैं।

डॉ० राम कुवार सैनी (गोहाना): अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने के लिए समय दिया और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने वित्त मंत्री प्रो० सम्पत सिंह जी का, जिन्होंने 10 मार्च, 2003 को अपना वर्ष 2003–2004 का बजट अनुमान सर्वेक्षण प्रस्तुत करते हुए अपना कर

रहित बजट सदन में रखा। यह बहुत ही संतुलित बजट है यह बहुत लोगों को लाभान्वित करने वाला बजट है। जो बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया है मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज जो बजट पेश किया गया है उसमें कृषि के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और दूसरे विभागों की मदों में काफी पैसा रखा गया है। इसी प्रकार से बजट में 20 हजार नौकरियां देने की बात कही गयी है जिससे हरियाणा के बेरोजगार नवयुवकों को अपना रोजगार मिल पायेगा, यह बहुत अच्छी बात इस बजट में कही गई है। जिस मुख्य मंत्री की नीति ठीक होती है उसकी नीयत भी ठीक होती है। आदरणीय जन–नायक चौधरी देवी लाल जी का आदर्श नारा था सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं बल्कि जन मानस की सेवा का माध्यम होता है। इसी परिपालन पर चलते हुए हमारे मुख्य मंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला ने अपने कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई महत्वपूर्ण योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के कारण प्रदेश में एक नई सामाजिक और आर्थिक क्रांति का सूत्रपात हुआ है जिसमें आज हरियाणा उच्च नैतिक मूल्यों को संजोए हुए है। आज हरियाणा आधुनिक प्रौद्योगिकी के बलबूते पर विकास की नई बुलन्दियों को छू रहा है। इन ३ सालों के कार्यकाल में हरियाणा के मुख्य मंत्री ने जो विकास के कार्य किए हैं वे सराहनीय रहे हैं और इन कार्यों के द्वारा मुख्य मंत्री जी आज 21वीं सदी के विकास पुरुष के रूप में सामने आये हैं। आज नई शिक्षा नीति, नई प्रौद्योगिकी नीति और नई औद्योगिक नीति से हरियाणा में आर्थिक,

क्रांति का सूत्रपात हुआ है। हरियाणा के मुख्य सेवक ने जिस वक्त हरियाणा की बागडोर सम्भाली उस समय हरियाणा का खजाना खाली था और कानून व्यवस्था ठप्प हो चुकी थी और हर व्यक्ति असुरक्षा की भावना से व्यास था। सारे हरियाणा में शराब माफिया फैल चुका था और युवा वर्ग अपराध जगत में प्रवेश कर चुका था इस स्थिति को पुनः बहाल करना और अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने का काम एक बहुत चुनौती भरा कदम था लेकिन धन्य हैं हरियाणा के मुख्य मंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और स्वर्गीय चौधरी देवी लाल जी के स्वप्न को साकार करने के लिए वचनबद्ध हुए और हरियाणा की जनता के सहयोग से हरियाणा के नव निर्माण में जुट गए। सरकार आपके द्वार जैसा लोकप्रिय कार्यक्रम ले कर घर–घर लोगों की दहलीज तक गए। पंचायती राज को मजबूत करने के लिए पंचायतों को प्रशासनिक तथा वित्तीय सुविधाएं दी जा रही हैं और ग्रामीण विकास के लिए सुविधाएं दे कर विकास के नये दरवाजे खोले जा रहे हैं। आज यहां पर कानून– व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और देश तथा विदेश के उद्योगपति यहां पर उद्योग लगाने के लिए उत्सुक हैं। आज चाहे कृषि की बात हो या कोई और क्षेत्र हो, हर जगह विकास हुआ है। राज्य में सूखे जैसे हालात होने के बावजूद भी 30.30 लाख टन धान की खरीद की गई। गत वर्ष के दौरान हरियाणा की मण्डियों में आये समस्त 64.7 लाख टन गेहूँ की सरकार द्वारा खरीद की गई। पन्नीवाला मोटा तथा गोहाना में दो नई चीनी मिलें स्थापित की गई हैं 1 डबवाली, साहा, राई और

नरवाना में चार खाद्य प्रसंस्करण निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है। चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों की समस्त बकाया राशि का भुगतान किया गया है। इसी प्रकार से सिंचाई के बारे में हाउस में पहले भी काफी चर्चा हो चुकी है। एस०वाई०एल० लिंक नहर हरियाणा की जीवन रेखा है। इसी नहर के माध्यम से हरियाणा रावी व्यास के पानी का अपना हिस्सा लेने के लिए कटिबद्ध है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री के प्रयत्नों के फलस्वरूप माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 15 जनवरी, 2002 को हरियाणा प्रदेश के हक में निर्णय देते हुए कहा था कि एक साल के अन्दर–अन्दर पंजाब सरकार इस नहर की खुदाई करके नहर बनवाए लेकिन एक साल तक उन्होंने कुछ नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि अगर पंजाब एक साल में नहर नहीं बनाती है तो फिर केन्द्र की सरकार इसको बनवा कर देगी। इस बारे में हमारे हरियाणा के मुख्य मन्त्री जी ने प्रधान मन्त्री जी से मिल कर इसके लिए भी पूरे प्रयत्न किए हैं और मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि आदरणीय चौधरी आम प्रकाश चौटाला जी के प्रयत्नों के द्वारा हरियाणा के अन्दर रावी व्यास का पानी एस०वाई०एल० के माध्यम से आएगा इसमें कोई दो राय नहीं है। बिजली के बारे में काफी चर्चा हुई है। बिजली की प्रतिस्थापित क्षमता में 792 मेगावाट की वृद्धि हुई है। गैस पर आधारित फरीदाबाद बिजली घर में 144–440 मेगावाट के दो यूनिट्स चालू हुए हैं। ताऊ देवी लाल थर्मल पॉवर प्लांट पानीपत की 210 मेगावाट की दो यूनिटें चालू की गई हैं और अब दो 250– 250 मेगावाट की 7वीं और 8वीं यूनिट स्थापित की जा

रही है। इसी तरह से बिजली के अन्दर भी पहली सरकार ने जो बिजली दिलाई थी स्पीकर सर, वह सबको पता है। कभी बिजली आती थी और कभी बिजली जाती थी, लेकिन हरियाणा के वर्तमान मुख्य मन्त्री ने हरियाणा के अन्दर आज बिजली का बहुत ज्यादा काम किया है तथा ज्यादा से ज्यादा बिजली हरियाणा को मिली है। यही कारण है कि बिजली ज्यादा देने से और बारिश न होने के बावजूद भी सूखा पड़ने के बावजूद भी आज किसानों के खेतों के अन्दर फसल लहलहा रही है। यह सब बिजली की वजह से हुआ है तथा हरियाणा के मुख्य मन्त्री जी तथा उनकी सोच की वजह से हुआ है। उन्होंने हरियाणा के किसानों को बहुत भारी मात्रा में बिजली दी ताकि उनके किसानों का कोई नुकसान न हो पाए क्योंकि वे किसान हितैषी हैं और किसानों की भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं इसलिए उन्होंने किसानों के भले के लिए किसी भी प्रकार से कहीं से भी बिजली प्राप्त की और भरपूर बिजली किसानों को दी जिससे सारे हरियाणा के अन्दर किसानों की फसल लहलहा रही है। उद्योगों के बारे में कहना चाहूँगा कि हरियाणा प्रदेश में 140 बड़ी और 4000 मध्यम दर्जे की यूनिट्स स्थापित हुई हैं। जिसके फलस्वरूप प्रदेश में 8000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। हमारे प्रदेश में 1. 54 लाख युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध हुआ है। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूँगा कि हरियाणा के मुख्य मन्त्री आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी की यह सोच रही है कि हरियाणा के बेरोजगारों को हरियाणा के अन्दर रोजगार मिले और हरियाणा के

अन्दर विदेशी मुद्रा का निवेश हो। इसको सोचते हुए ही ये विदेशों के दौरे पर गए थे ताकि हरियाणा के प्रत्येक आदमी का भला हो। इसलिए इन्होंने वहां पर जाकर के कहा है कि आओ और हमारे हरियाणा में उद्योग लगाओ। वहां पर आपको सस्ती बिजली मिलेगी, आपको सस्ती जमीन मिलेगी, वहां पर कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है और आपकी जान– माल की रक्षा की जाएगी। स्पीकर सर, आपको भी और सबको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आज हमारे हरियाणा के अन्दर विदेशों से उद्योगपति आकर अपने उद्योग यहां लगा रहे हैं। फ्रांस, चीन, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका से आकर उद्योगपतियों ने उद्योग लगाए हैं। इसका हमारे हरियाणा के मुख्य मंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला जी को श्रेय जाता है। इनकी सोच इतनी अच्छी है कि ये हरियाणा के प्रत्येक वर्ग को अपने साथ लेकर चलते हैं। हर वर्ग के लिए रात–दिन सोचते हैं। मेरे ख्याल से यह 24 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे ही सोते हैं। ये लोगों के हितों के कार्यों के लिए चण्डीगढ़ से सुबह उठकर चलते हैं। कहीं पर आयुवैंदिक कॉलेज का पत्थर लगाया जा रहा है, कहीं पर इंजीनियरिग कॉलेज का उद्‌घाटन किया जा रहा है, कहीं पर रिटेनिंग वॉल का उद्‌घाटन हो रहा है और कहीं पर स्कूलों का उद्‌घाटन हो रहा है। इस तरह से सुबह से शाम तक लोगों के काम करते हुए या तो दिल्ली जा कर सोते हैं या वापस चण्डीगढ़ आकर सोते हैं। अगले दिन फिर सुबह यही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हरियाणा प्रदेश के सच्चे हितैषी और 36 बिरादरी के मसीहा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला

जी के मन में अपने हरियाणा के प्रति अच्छी सोच है। ये यही सोचते हैं कि किस प्रकार से हरियाणा का चहुंमुखी विकास किया जाए और यह प्रदेश आगे चलता चला जाए। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए सड्कों के बारे में और परिवहन के बारे में कहना चाहूँगा। इसी प्रकार से समाज कल्याण से हरियाणा के अन्दर क्रान्ति का सूत्रपात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कर रखा है। इनके नेतृत्व मे हरियाणा दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करता जाएगा। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि ऐसे कुशल नेतृत्व करने वाले हमारे नेता श्री ओम प्रकाश चौटाला जी हैं और हम सारे हरियाणावासी इनके साथ लगे हुए हैं और साथ ही रहेंगे, ताजिंदगी इनके साथ ही रहेंगे। आज हरियाणा के अन्दर एक छत्र राज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का रहेगा क्योंकि ये लोगों के दिलों में छाए हुए हैं। 36 बिरादरी के लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। जब ये गांवों में जातें हैं वहां पर लोगों को नाम से जानते हैं, एक एक गांव के अन्दर कम से कम 15 –20 आदमियों के नाम जानते हैं। गांव वालों को आदर देते हैं, उनका बहुत मान करते हैं इसलिए आज लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी की लम्बी उम्र हो और इस तरह से ये हरियाणा के अन्दर विकास के कार्य करते रहें। मैं अंत में ज्यादा न कहते हुये यह जो हमारा बजट है जो कि कर–मुक्त है और वित्त मन्त्री जी ने एक संतुलित बजट रखा है इसका मैं अपने दिल की गहराई से समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री मांगे राम गुप्ता (जींद): अध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्री प्रो० सम्मत सिंह जी ने कल हाउस में इस साल 2003–2004 का बजट प्रस्तुत किया है। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, वैसे तो बजट पर चर्चा काफी देर से सुनी जा रही है, सुनायी जा रही है। हम तो यह सोचते थे कि आकड़ों के इस बजट का विरोध करने की शायद जरूरत न समझें क्योंकि यहां पर इसकी इतनी तारीफ के पुल बांधे गए हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। सब यहां पर बहादुर मुख्य मंत्री, बहादुर मुख्य मंत्री कहे जा रहे हैं मैं कहना चाहूँगा कि रोज तो रसगुल्ले खाकर सब छिक जाते हैं लेकिन ये मुख्य मंत्री जी छिकते ही नहीं हैं। अब तो इनको नमकीन खाकर खुश हो जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: गुप्ता जी, आप बजट पर बोलें।

श्री मांगे राम गुप्ता: मैं बजट पर ही बोल रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, बजट तो वित्त मंत्री ने पेश किया है इसलिए तारीफ इनकी होनी चाहिए लेकिन तारीफ मुख्य मंत्री की हो रही है। (विघन)

प्रो० सम्पत सिंह: अध्यक्ष महोदय, वही परिवार चलता है जिसमें एक मुखिया होता है अगर सारे मुखिया इनकी तरह से हों तो वह परिवार नहीं चलता।

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया इसलिए मैं इनकी तारीफ करता हूँ। इनके बजट

के बारे में इनकी काबलियत की लिहाज करते हुए जो प्रैस ने इनके बजट के बारे में लिखा है वह मैंने भी पड़ा है। एक–दो अखबारों में बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है कि हरियाणा के बजट में कोई नया कर नहीं। 109.57 करोड़ रुपये लाभ का बजट पेश किया गया। सम्पत सिंह जी, क्या यह ठीक बात है यह लाभ का बजट है? अध्यक्ष महोदय, कहना तो कुछ और चाहिए था क्योंकि वास्तविकता तो यह है कि इन्होंने यह बजट 780.53 करोड़ के घाटे से शुरू किया है। अध्यक्ष महोदय, 780.53 करोड़ का घाटा हो और सम्पत सिंह जी का यह प्रयास रहेगा कि यह घाटा 670.96 तक लाने की ये शायद कोशिश करें। क्यों सम्मत सिंह जी, ऐसा ही है न?

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, आप बोलते रहो आपको जवाब बाद में मिलेगा।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, अब तो कोई बदमजगी की बात नहीं रही है इसलिए अब तो ऐसे ही चलेगा। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी इस बारे में अपने जवाब में बता देंगे। इन्होंने यह चौथा बजट पेश किया है। जो शुरू से इन्होंने बजट पेश किए और उसमें जो नुकसान लेकर ये चले तो उसमें भी इन्होंने यही शब्द इस्तेमाल किए कि अब तो मैं 171 प्यायंट कुछ के घाटे का बजट पेश कर रहा हूँ और इसको मैं अपने प्रयासों से 54 प्यायंट कुछ पर ले जाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री रिर्सोसिज बढ़ाते हैं, खर्चों को घटाते हैं यानी इस तरह का

प्रयास करते रहते हैं लेकिन मेरी नालेज के मुताबिक जो इन्होंने चारों बजट पेश किए हैं उसमें इनका नुकसान नहीं घटा और जितना इनको डिक्लेयर करना चाहिए था उससे ज्यादा ही घाटा इनका बढ़ा है अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूँ कि अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो यह शायद अब तक हरियाणा का रिकॉर्ड रहा हो कि 780 करोड़ रुपये का एक साल में घाटा अगर किसी बजट में पेश किया गया होगा तो वह सम्पत सिंह जी के वित्त मंत्री रहते हुए ही हुआ होगा। अध्यक्ष महोदय, ये बातें अपने जवाब में बता सकते हैं। जब हमने 1996 का लास्ट बजट पढ़ा था तो उसमें हम बीस करोड़ रुपये का घाटा छोड्कर गए थे। उसमें हमने यह कहा था कि वह बीस करोड़ रुपये का घाटा भी पूरा हो जाएगा जबकि अब ये कह रहे हैं कि हम घाटे को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। मैं पूरी तरह से कंफर्म तो नहीं हूँ कि वह बीस करोड़ रुपये का घाटा पूरा हुआ या नहीं हुआ लेकिन मेरे ख्याल से वह पूरा हो गया होगा। अध्यक्ष महोदय, बीस करोड़ रुपये का वह घाटा अब 780 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। आज सरकार जो यह बात कह रही है कि इतना काम कर दिया, 33 हजार वर्क्स कर दिए चारों तरफ विकास के कामों की झड़ी लग रही है। सड़क, स्कूल और अस्पताल बन रहे हैं तो यह काम करना तो सरकार का फर्ज है, सरकार करती है, काम करने के लिए ही सरकार बनती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अगर आप इस बजट को थोड़ा सा देखें तो पाएंगे कि ये जो बजट ऐट ए ग्लांस है इसमें आपका ऐक्सपैंडीचर जो है उसमें से 14 परसैंट इंट्रैस्ट में चला

जाता है, 26 परसैंट जो लोन लेते हैं उसकी रीपेमैंट में चला जाता है। 1996 में हमने सरकार छोड़ी थी। (विष्य) उस समय हम 75 या 8 करोड़ का कर्जा छोड़कर गए थे। 1 मस से 1996 तक 30 साल में हरियाणा में 8 हजार करोड़ का कर्जा था और आज वह ३1 हजार करोड़ रुपये पर स्टैंड कर रहा है और उस पर 14 परसैंट इंट्रस्ट देना पड़ता है और 26 परसैंट की इस्टालमैंट लोन रीपे करने में देनी पड़ती है। इस प्रकार बजट का 4० परसैंट तो इसमें चला गया। बाकी इंप्लॉईज इतने हैं उनकी तनख्वाहों में चला गया, रह गया कितना? आप इरीगेशन पर 5 परसैंट खर्च कर रहे हैं, पॉवर पर 8 परसैंट, ट्रांसपोर्ट और रोड्स पर 7 परसैंट, वाटर सप्लाई पर 4 परसैंट, ऐजूकेशन पर 12 परसैंट, सोशल वैलफेयर पर 3 परसैंट, हैल्थ पर 3 परसैंट, अदर पर 1 परसैंट। अब आप बताएं अध्यक्ष महोदय, ये क्या खर्च करेंगे, क्या विकास होगा? यह विकास कहां से हो रहा है। यह जो आज स्टेट्स में लिमिट तोड़ दी, आज स्टेटों में सरकार की यह हालत हो गई कि अपने बजट को कुछ ही फिग्गर्ज में दिखायें। पहले हर वित्त मंत्री और मुख्य मंत्री यह महसूस करता था कि कल को बजट पेश करेंगे और बजट में इतना घाटा दिखाया गया तो लोग क्या सोचेंगे, जनता क्या सोचेगी? लोग नफरत की निगाह से देखेंगे और आज 780 करोड़ रुपये का घाटा दिखाकर वित्त मंत्री जी के चेहरे पर रौनक आ रही है जैसे बहुत बड़ा मैदान मार दिया हो। 780 करोड़ के घाटे पर मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी को बड़ा महसूस होना चाहिए था। (विघन)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): आप यह मानकर चलो कि हमारे अंदर कितना हौंसला है कि उस घाटे को भी बिना कोई कर लगाए कवर करेंगे।

श्री मांगे राम गुप्ताः आप तो बहादुर बाप के बहादुर बेटे हैं हमारे जैसे किसी गरीब बनिए के बेटे थोड़ी हैं। यह सारा काम जो दिखाई दे रहा है यह सारा कर्जा लिया जा रहा है। (विघन)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः कर्जा भी साहूकार को मिलता है, साख पर मिलता है।

श्री मांगे राम गुप्ताः मुख्य मंत्री जी की बात की मैं ताईद करता हूँ कर्जा हमेशा साहूकार को मिलता है। अब आप इतिहास भी देखें, जिसने साख के ऊपर कर्जा लेकर कोठियां बनाई, साख के ऊपर कर्जा लेकर ब्याह किए उन लोगों का बाद में दिवाला निकल गया। यह कोई अच्छी बात नहीं है। हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो है उसको ध्यान में रखना चाहिए। दो–दो कोठियां बनाओ, सात– सात कारें लो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है कमाई से बनाओ। लेकिन जो आदमी अपने घर का ब्योंत देखकर चलेगा वही आदमी हमेशा भविष्य में कामयाब रहेगा। इसी प्रकार वही प्रदेश हमेशा तरक्की करेगा जो सारी बात सोच समझकर चलेगा। यह एक फण्डामैंटल रूल है इसमें कोई कहने की बात नहीं और कोई पक्षपात की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय,

जब इतना कर्जा चढ़ जाए कि उसका व्याज और इंस्टालमैंट देने में ही बजट पूरा हो जाये तब भी क्या हम इस बजट की बड़ाई ही करें। एक बात मैं वित्त मंत्री महोदय को कहना चाहूँगा। (विघन)

श्री अध्यक्षः गुप्ता जी, आप पांच मिनट में वाईंड अप करें।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैं तो बोलना नहीं चाहता था आप बुलवाना चाहते हो।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब ने आपका नाम दे रखा है इसलिए आपकी पार्टी को मैं इन ऑर्डर ऑफ प्रिफ्रैंस बुला रहा हूँ।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, जब कहेंगे मैं तो तभी बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्षः आपके बाद रघुबीर सिंह कादियान का नाम है इसके बाद उनका नम्बर है।

श्री मांगे राम गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं मुख्य मंत्री जी की कहूँ या वित्त मंत्री जी की कहूँ। तो यह कहता हूँ कि बजट पर वित्त मंत्री की बात होनी चाहिये। एक तो खर्चा इन्होंने घटाने का प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, तीन साल से मुख्य मंत्री ने अपने मंत्रीमंडल पर पूरा ब्रेक लगा कर रखा है। इससे खर्चा घटा है यह बात सराहनीय है। इससे स्टेट पर बर्डन नहीं पड़ा है। लेकिन मैं एक सिफारिश भी मुख्य मंत्री जी से करता हूँ

कि हमारे दो साथी इन्होंने अपनी तरफ लिये थे एक तो मौ० इलियास जी जो हमारे पुराने मित्र हैं उनको तो आपने मंत्रीमंडल में ले लिया और दूसरे हमारे साथी लीला कृष्ण जी जो हमारे साथ मंत्रीमंडल में थे उनको मंत्रीमंडल में शामिल नहीं किया। वह बुढ़ापे में तड़प रहा है कोई खर्चा नहीं बढ़ता उसको मंत्री बना दो ओरों को चाहे बनाइयो या नहीं (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) (विघ्न) मैं खर्चा घटाने में मुख्य मंत्री जी की व इस सरकार की दाद देता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, बजट सैशन बहुत जरूरी है इसके माध्यम से सारे हरियाणा के 9० विधायक अपने हल्कों की, हरियाणा की जनता की और हर महकमे की बात सरकार के नोटिस में लाने का प्रयास करते हैं जैसे आप टाइम दे रहे हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय,बजट सैशन में कम से कम 20—25 मीटिंग तो होनी ही चाहिए। लेकिन यह खर्च बचाने के लिए मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि यह बड़ा कीमती टाइम है बहुत खर्चा होता है। (विघन)

श्री उपाध्यक्षः माननीय पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर साहब आपको बता देंगे कि आपके समय में कितनी मीटिंग होती थीं।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, यहां तो ऐसे लोगों की सरकार भी रही है जिन्होंने आधे घण्टे में ही बजट पास किया हैं।

श्री मांगे राम गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कमाल तो यह है कि खर्चा घटाने के लिए डबल शिफ्ट चला रहे हैं। रोज नॉन स्टॉप। मान लिया क्योंकि एम०एल०ए० को डबल शिफ्ट का पैसा नहीं देना पड़ता। (विघन) उपाध्यक्ष महोदय, खर्चा बताया सूखे के ऊपर अभी मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि हरियाणा प्रदेश के अन्दर बड़ा भयंकर सूखा पड़ा है। सम्पत सिंह जी काबिल हैं इन्होंने इस बात को समझा है पिछले साल नैचुरल कैलेमिटी को उस बजट में शो नहीं किया गया था तब मैंने कहा था कि नैचुरल कैलेमिटी कभी भी हो सकती है। गैंने ऐतराज उठाया था और मैंने कहा था भगवान न करें कि नैचुरल कैलेमिटी कभी भी हो सकती है लेकिन तब मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि हमारे राज में तो भगवान भी डरता है, हमारे राज में नैचुरल कैलेमिटी नहीं हो सकती। उसी वक्त हो गयी, उन्हीं दिनों में सूखा पड़ गया था। आप मानते हैं आपने शायद रिपोर्ट तैयार करवाई है कि 1000 या 11000 या 2000 करोड़ रुपये तक आपने सूखे के लिए, किसानों के लिए केन्द्र सरकार से मांगे थे, यह आपका फर्ज था, लेकिन पैसा पूरा नहीं मिला, थोड़ा मिला। उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा सबने बताया, ये बड़े फख्र के साथ कहते हैं कि एक कनाल के 6–6 हिस्सेदार हैं। लेकिन मुझे इस बात के लिए शर्म आती है 6 रुपये, 8 रुपये या न 2 रुपये देने का क्या फायदा, इतना मुआवजा देने से क्या फायदा, इससे तो अच्छा नहीं देना चाहिए था। 6–6 रुपये में किसान का

घाटा क्या पूरा हो जाएगा? यह ठीक है कि आपके पास पैसा नहीं था, लेकिन इसमें भी आपने पैसे बचा लिये। (विघ्न)

नगर एवं ग्राम आयोजना मंत्री (श्री धीर पाल सिंह): उपाध्यक्ष महोदय, दर्शक इनकी बात सुन जाते हैं, तीन दिन के बाद हमने रिप्लाई देना है बात अधूरी रह जाती है। विरोधी पक्ष के नेता जी ने कहा और मांगे राम जी जो बड़े सयाने हैं, कलाकारी से इस बात को कह गए। लेकिन मेरे पास रिकार्ड है। गांव नांगलकलां, जिला सोनीपत खेवट नम्बर 146, रकबा 2 कनाल 6 मरला उसके 21 हिस्सेदार हैं उपाध्यक्ष महोदय मैं आपसे अनुमति लेकर बताना चाहूँगा—जय नारायण 1/8, बिन्दरावन 1/8, ओमप्रकाश 1/16, दीपचन्द 1/16, सूरजभान 1/16, ढींगराम 1/16, लक्ष्मी 1/16, हुकमचन्द 1/ 6, चेतराम 1/6, इन्द्रवती 1/36, ओमपती 1/36, ओमपती देवी 1/36 (शोर), हेमचन्द्र 1/36, तेजपाल 1/36, संतोष 1/252, सुशीला 1/252, सविता 1/252, सुनीता 1/252, ज्योति 1/252, सुशील कुमार 1/252, अनिल 1/252, इस प्रकार जहां सूखा पड़ा वहां 2 कनाल 6 मरले जमीन थी और उसके 21 हिस्सेदार हैं।

चौ० भजन लाल: पैसा कितना दिया?

श्री धीरपाल सिंह: केन्द्र सरकार ने जो नार्म निर्धारित किए हैं। उसके हिसाब से ज्वार बाजरा मोटी खेती के लिए 400 रुपये प्रति एकड़ हैं। ये बातें भजन लाल जी कभी पढ़कर नहीं

आते और हुड्डा साहब भी कभी पढ़कर नहीं आए। हमें केन्द्र सरकार ने निर्देश दिए। जिस केन्द्र सरकार के अजीत सिंह के ये गीत गा रहे हैं उस केन्द्र सरकार के समय में भी यही मुआवजा था। हमारे समय में भी यह था जहां 75 प्रतिशत से above सूखे से फसल तबाह होगी वहां 400/– रुपये मिला। 400/– रुपये में से 2 कनाल 6 मरले में 21 आदमियों को रकबे के आधार पर पैसा बनेगा उसकी चर्चा पर बड़े–बड़े आसू गिराकर ये दिखाना चाहते हैं कि जमींदार मार दिए। हरियाणा सरकार ने अपने साधनों से 66 करोड़ रुपये उनको कैश दिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः इन्होने कहा कि 66 करोड़ रुपये कैश दिए और मुख्य मंत्री साहब ने बहादुरगढ़ में कहा कि पूरे प्रदेश में सूखा पड़ा, डेढ़ करोड़ एकड़ जमीन बीजी हुई थी उसको अगर भाग दें तो उसका 45 रुपए प्रति किला पड़ता है। 45 रुपये किला किसको मिला है। पूरे हरियाणा में आप सूखा मानते हैं।

श्री धीरपाल सिंहः पूरे हरियाणा में उस समय था जब आप सैशन में बैठे थे, उसके बाद 13 अगस्त को अच्छी बारिश हुई। (विघन)

श्री उपाध्यक्षः आप बैठिये, प्लीज।

चौ० जय प्रकाशः उपाध्यक्ष महोदय, कई जगह तो फसल की बिजाई भी नहीं हुई।

श्री धीरपाल सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, 13 अगस्त को बरसात हो गई थी और उससे ज्वार, बाजरा, गुवार आदि की जितनी बची हुई खेती थी, उसको लाभ मिला था। (शोर एवं व्यवधान)

चौ० जय प्रकाशः उपाध्यक्ष महोदय, धान और गन्ने की भी बहुत कम बिजाई हुई थी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धीरपाल सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, गेहूँ और चावल आदि जो मोटे अनाज हैं उनका उत्पादन बढ़ा है, कम नहीं हुआ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्षः हुड्डा साहब, प्लीज आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) प्लीज आप मेरी इजाजत के बगैर न बोलें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, पहले गिरदावरी करवाई गई और पूरे प्रदेश को सूखाग्रस्त घोषित किया गया। उसके बाद दोबारा गिरदावरी की गई लेकिन जिन किसानों की पहले फसल नष्ट हो गई थी उन किसानों को सूखे की राहत के लिए एक पैसा तक नहीं दिया गया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले पर कई मर्तबा बहुत खुलकर चर्चा हुई है। विपक्ष के लोगों को इस पर जिस ढंग से बात करनी चाहिए थी उस ढंग से नहीं की। कल चौधरी भजन लाल जी ने कहा कि इतने लोग हिस्सेदार हैं। हुड्डा साहब के तो समझ में आता नहीं है, मांगे राम जी आपकी समझ में आता है। जब इस बात को क्लीयर कर दिया गया कि जितने हिस्सेदार होंगे, सबको बराबर मुआवजा मिलेगा। फिर ये वही बात बार–बार रिपीट क्यों कर रहे हैं। हमारी सरकार ने केवल 66 करोड़ रुपये नगद मुआवजे के नहीं दिए हैं बल्कि कुल मिलाकर 240 करोड़ रुपये सूखे प्रभावित पीड़ितों को दिये हैं। चाहे वह पैसा बीज का था, ब्याज का था, खाद का था या बिजाई का था कुल मिलाकर 240 करोड़ रुपये दिए गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि एक दफा बिजाई हुई। मैं इनको बताना चाहूँगा कि जहां पहले बाजरा बोया गया था जेठ महीने में अर्ली बरसात होने के कारण और आगे बरसात न होने के कारण बाजरा जल गया और उसी गिरदावरी के आधार पर किसानों को प्रति एकड़ 400 रुपये के हिसाब से मुआवजा दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो शुगर केन काश्त करने वाले किसान हैं, जिन्होंने गन्ने की बिजाई की लेकिन बरसात न होने के कारण उनका गन्ना कमजोर रह गया उनको भी मुआवजा दिया गया है, तथा जिनकी दूसरी फसलों का नुक्सान हुआ है उनको भी मुआवजा दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जय प्रकाश जी कह रहे थे कि उस समय बोया नहीं गया, मैं इनको बताना चाहूँगा कि जो बोया गया था

हम उसकी बात कर रहे हैं। ये तो फसल काटते वक्त खेतों में जाते हैं, उससे पहले ये खेतों में नहीं जाते। इसलिए आदमी को थोड़ा समझना चाहिए और हिसाब से बात करनी चाहिए। ये न बोने वाली बात को बार–बार क्यों उठाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को ही नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश की पूरी जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि यदि हरियाणा में कोई भी कहीं भी प्रमाणित कर दे कि किसी का नुक्सान हुआ और उसे मुआवजा नहीं मिला तो हम उसकी पूर्ति करने के पक्षधर हैं तथा जिन अधिकारियों ने इस मामले में कोताही की है उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, 1995 में बाढ़ आई थी और उस समय चौधरी भजन लाल जी मुख्य मंत्री थे। उस समय लोगों को भेदभाव के दृष्टिगत मुआवजा दिया गया। उसके बाद जब अब हमारी सरकार आई तब हमने लोगों को सही मुआवजा दिया। चौधरी भजन लाल जी कहते है कि ये उस समय 300 करोड़ रुपये केन्द्र से लेकर आये थे, मैं बताता हूँ ये वे 300 करोड़ रुपये शॉर्ट टर्म स्कीम के तहत लोन के रूप में लेकर आये थे तथा उस समय केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी फिर भी इनको मुआवजे के रूप में एक पैसा भी नहीं मिला। उपाध्यक्ष महोदय, हमने अपने सीमित साधनों का सही प्रयोग करके, 43 प्रतिशत अधिक बिजली किसानों को देकर ज्यादा से ज्यादा खेती की बिजाई करवाने का काम किया है। यमुना में भी पहले के मुकाबले 25 प्रतिशत अधिक पानी दिया गया और भाखड़ा में भी 10 प्रतिशत अधिक पानी दिया गया ताकि लोग अधिक से अधिक भूमि

की सिंचाई कर सकें। इसके अतिरिक्त, हमने ड़ेनों में भी सिंचाई के लिए पानी डालकर सिंचाई करवाई। यदि हुड्डा साहब और चौधरी भजन लाल जी को यकीन नहीं है तो इनको निमन्त्रण देता हूँ मैं किसी से हैलीकॉप्टर मागूंगा और ये मेरे साथ चलें व देख लें कि सारे हरियाणा में एक–एक इंच जमीन में इस बार बिजाई हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, हम आस्तिक हैं इनकी तरह नास्तिक नहीं हैं, हम पर प्रभु की पूरी कृपा रही है और एक–एक इंच जमीन में इस बार बिजाई हुई है। मैं मानता हूँ कि हरियाणा के अंदर नांगल चौधरी और सिवानी के क्षेत्रों में बिजाई बहुत कम हुई है। केवल मात्र ये दो पोर्शन हैं जहां सूखे की भयंकर स्थिति है। इसके लिए मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि जहां कहीं भी ऐसी स्थिति है वहां सरकार गिरदावरी के आधार पर मुआवजा देगी और यदि कहीं से यह शिकायत आये कि उनके यहां गिरदावरी ठीक नहीं की गई और उन्हें मुआवजा नहीं मिला तो वहां पर अधिकारियों के खिलाफ शिकायत मिलने पर कार्यवाही की जायेगी और सबको पूरा मुआवजा दिया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप सब बैठिये। मैंने जय प्रकाश जी को बोलने के लिए कहा था। जय प्रकाश जी आप बोले। (विघ्न)

वैयक्तिक स्पष्टीकरण–

(1) चौधरी जय प्रकाश एम०एल०ए० द्वारा

चौ० जय प्रकाश: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर सी०एम० साहब बार–बार यह कह रहे हैं कि मुझे ही ज्ञान है। 13 अगस्त के बाद सी०एम० साहब ने किसी इलाके में जा करके नहीं देखा। न तो ये बरवाला में गये और न ही उचाना विधान सभा क्षेत्र में गए। जब दाने हो जाते हैं तो फिर '' सरकार आपके द्वार '' कार्यक्रम ये रख देते हैं और कुछ तो ये ले आते हैं ओर कुछ अधिकारी ले जाते हैं जिससे किसानों को कोई फायदा नहीं होता। जितनी .... इस सरकार में किसानों की हुई है उतनी कभी नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष: इनकी यह बात रिकॉर्ड न की जाये।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से बोलना चाहता हूँ। (विघन) मैं कोई ज्यादा जबाब नहीं दे रहा। जबाव तो डिटेल में सारा मुख्य मंत्री जी ने भी दे दिया। मैं तो सिर्फ एक बात जो जयप्रकाश जी ने कही है वह कहना चाहता हूँ। 14 अगस्त को ऑल पॉर्टीज की मीटिंग है, इस बारे में सभी को ध्यान है। यह मीटिंग एस०वाई०एल० नहर को बनाये जाने बारे और सूखे को ले करके यानि इन दो इशूज पर बुलाई गई थी। आप सभी को पता है कि इस पर डिटेल में बात हुई और एक रिजोल्यूशन एस०वाई०एल० पर तैयार हुआ। बाद में सारे इकट्ठे मिलकर वह रिजौल्यूशन देकर भी आये थे। जब सूखे की बात आयी तो जय प्रकाश जी, आप धर्म ईमान की बात दें कि

आपने यह नहीं कहा कि अब तो बरसात हो गई है अब सूखे का क्या जिक्र करें। (विघन) आपने कहा कि सूखे की बात को छोड़ो।

चौ० जय प्रकाश: मैंने नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष: जय प्रकाश जी, आपको बोलने का मौका दिया था। अब आप बीच में खड़े हो रहे हैं।

चौ० जय प्रकाश: सर, इन्होंनें मेरा नाम लिया है।

श्री उपाध्यक्ष: अगर नाम लिया है तो आपको बीच में बोलने का लाइसेंस किसने दे दिया? श्री रघुबीर सिंह कादियानः स्पीकर साहब, आप मेरी बात भी तो सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष: कादियान साहब, आप बैठिये। (विघन)

प्रो० सम्पत सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि सारे लोग वहां पर उस मीटिंग में बैठे हुए थे। इनके इतना कहने के बाद कि अब बरसात हो गई है, अब सूखे की क्या बात छेड़े तो सारे उठ करके चले गए और वह मीटिंग उठ गई। मैं यह बताना चाहता हूँ कि इनकी सूखे के प्रति कितनी सीरियसनैस है, यह इनकी इस बात से पता चलती है। अब ये घड़ियाली आसू बहाने के लिए और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए दुष्प्रचार के लिए कुछ भी कहें? 13 अगस्त को बरसात हो गई थी और 14 तारीख को मीटिंग थी। इन्होंने खुद कहा कि 13 तारीख को बरसात हो गई और इन्होंने यह बात अपने मुंह से कही कि इस

इशु पर अब बात करने की आवश्यकता नहीं है। आपने यह उस मीटिंग में कहा। आपने कहा कि अब तो सूखे के लिए नहीं बाढ़ के लिए पैसे मांगने पड़ेंगे। (विष्य)

कैप्टन अजय सिंह यादवः ये सूखे के बारे में बात करना चाहते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, सूखा पड़ा है और हमारे इलाके में करीब 50 गांव ऐसे हैं जिनमें सूखा पड़ा है और सरकार की तरफ से एक पैसा भी नहीं मिला। (विघ्न)

(2) चौ० भजन लाल एम०एल० ए० द्वारा

श्री उपाध्यक्षः कैप्टन साहब, आप बैठिये। आप बार–बार बीच में बोलने के लिए खड़े क्यों हो जाते हैं? (विघन) दूसरों को भी बोलना है। आप बैठिये। आपको बाद में मौका देंगे। (विघन)

चौ० भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। यहां पर बोलते हुए 1995 का जिक्र किया गया। डिप्टी स्पीकर साहब, जब 1995 में बड़ी भारी बाढ़ आई थी तो उस वक्त हमने सभी जगह किसानों की पूरी मदद की थी और 650 करोड़ रुपया केन्द्र से लिया और उस वक्त जो किसान बाढ़ की वजह से अपनी फसल नहीं बो पाये थे उनको 3 हजार रुपये पर एकड़ के हिसाब से फसल का मुआवजा दिया गया था। (विघन)

प्रो० सम्पत सिंहः आपने वह पैसा केन्द्र सरकार से लोन लिया था या ग्रान्ट ली थी? (विघ्न)

चौ० भजन लालः लोन उसको मिलता है, जिसकी गुडविल हो। ऐसे ही आपको कौन लोन देगा? (विघन) उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में भयंकर सूखा पड़ा हुआ है और नैचूरल कैलेमिटी का जो पैसा होता है उसमें से एक पैसा भी किसानों को नहीं दिया गया है। (विघ्न) एक महीने पहले तक तो कोई पैसा नहीं बांटा गया था और अगर बाद में बांट दिया हो तो मुझे पता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह मैं नहीं कहता केन्द्रीय कृषि मंत्री चौधरी अजीत सिंह जी ने कहा है कि हरियाणा की सरकार ने सूखा राहत के लिए पैसे की कोई मांग नहीं की। (विघन)

वर्ष 2003 – 2004 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा(पुनरारम्भ)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिए पुनः दोहरा देता हूँ कि केन्द्र सरकार की तरफ से पूरे भारतवर्ष में एक नया पैसा भी सूखा राहत के नाम पर नहीं दिया गया (विष्य)। इनके पास कुछ कहने के लिए तो है नहीं। ये साहब तो हर वक्त अजीत सिंह का नाम लेते हैं अपने पल्ले तो दो दाने हैं नहीं, किसी और की चर्चा करते रहते हैं (विघन) ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने सूखा राहत के नाम पर राशि किसी को नहीं दी। अगर वैसे ही कोई कहता फिरे यह उचित नहीं है और न ही हमारा ऐसा कोई ध्येय है कि कोई अनर्गल बात कहे और हम उसका जवाब देते रहें। हमें कहां से क्या मिलना है वह हम लेना जानते हैं लेकिन अन्धे के आगे रोए

और अपने नैन खोए। (विघन) उपाध्यक्ष महोदय, राहत का पैसा बंट रहा है लेकिन ये कह रहे हैं कि पैसा नहीं बंट रहा है। 241 करोड़ रुपये की मदद हमने दी है और पैसा बंट रहा है (विघ्न) गुप्ता जी तो कह रहे हैं कि पैसा थोड़ा बंट रहा है और ये कह रहे हैं कि बंट नहीं रहा है। (इस समय कई माननीय सदस्य अपनी सीटों पर खड़े हो गये।)

श्री उपाध्यक्षः आप सभी बैठें और मांगे राम गुप्ता जी को अपनी बात पूरी करने दें। (विघन)

श्री मांगे राम गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, मैं सूखे की बात को छोड़ देता हूँ। सरकार सूखा राहत दे रही है यह बड़ी अच्छी बात है (विष्य)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन में कहता हूँ कि अगर परमात्मा की अनुकम्पा रही तो पिछले साल के मुकाबले सवाई गेहूँ की पैदावार होगी आज किसानों के खेत गेहूँ से भरे पड़े है मैं फिर कहता हूँ कि यह इसलिए है किं हमने इसके लिए सार्थक प्रयास किए हैं (विघन) हमने पिछले साल के मुकाबले 53परसैंट बिजली ज्यादा दी है, पिछले साल के मुकाबले यमुना में 250 परसैंट ज्यादा पानी चलाया है भाखड़ा में हमने 10 परसैंट से ज्यादा पानी चलाया है। (विध्न) उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो यमुना का पानी खो दिया था इन्होंने जगह–जगह खुद स्टेट का बेड़ा बिठाया। जब ऐसे कोई स्टेट के बारे में महत्वपूर्ण

ऐग्रीमैंट होते थे ये चपड़ासी की तरह बाहर बैठे रहते थे और इनको कोई पूछता नहीं था और हरियाणा प्रदेश के बारे में अहम् फैसले हो जाते थे (विघ्न) अब इनको इस तरह की बात कहते हुए शर्म भी नहीं आती है (विघन) हम तो फिर भी गर्व से यह कहते हैं कि हमारे प्रयासों से ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ था इन्होंने तो अपने वक्त में कोर्ट से केस वापिस ले लिया था। (विक)

श्री उपाध्यक्षः चौधरी भजन लाल जी, आप अपनी सीट पर बैठें। बिना इजाजत के आप बार–बार बीच में खड़े न हों (विघन) अब आप बैठें।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः चौधरी भजन लाल जी, आपने हर स्तर पर प्रदेश का बेड़ा बिठाने का काम किया है। आपकी उन गलत बातों को ठीक करने में हम लगे हुए हैं। (विघ्न) दल बदलुओं की परम्परा आपने स्थापित की और अब आपने जोर लगा कर देख लिया क्या कहीं पर दल बदल हो रहा है। आप किसी की तरफ आख उठा कर तो देखो (विघन) आप 34 के 34 लोगों को ले कर चले गए थें आपकी गलत परम्परा को हमने समाप्त किया है। (विघ्न)

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्षः चौधरी भजन लाल जी, आप बैठें। (विघ्न) यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय' 'आधे घण्टे के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, हाउस का समय आधे घण्टे के लिए बढ़ाया जाता है। (विघन)

वर्ष 2003 – 2004 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): उपाध्यक्ष महोदय, इनको कुछ तो महसूस करना चाहिए मुझे तो यह बात समझ में नहीं आती है। (विघन)

श्री उपाध्यक्ष: मांगे राम गुप्ता जी, अब आप बोलें और दो मिनट में समाप्त करें। (विघन)

श्री मांगे राम गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा टाइम तो इन्होंने खराब किया है मैं तो कुछ ज्यादा बोला ही नहीं। (विघन)

श्री उपाध्यक्ष: मांगे राम जी, आप कच्छ करें। मैंने आपको कई बार उठने के लिए कहा परन्तु आप उठते ही नहीं।

16.00 बजे

श्री मांगे राम गुप्ता: जब मुख्य मंत्री जी खड़े हुए हों और आप मुझे कहें कि बोलू तो क्या मैं मुख्य मंत्री जी के खड़े रहते हुए बोलूंगा। (विघन) उपाध्यक्ष महोदय, एक आपत्ति इन्होंने की है। (विघन) मैं सुझाव दूंगा (विघन) बहुत जल्दी हो रही है,

तेरा घाटा यूं पूरा नहीं होना, न कर्जा कम होगा। (विघन) हमने न तो टोटा चढ़ने दिया और न ही कर्जा चढ़ने दिया है।

श्री उपाध्यक्षः मांगे राम जी, आप 3.24 बजे से बोल रहे हो।

श्री मांगे राम गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा तो लिहाज कर लिया करें। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि मुख्य मंत्री जी जब कल जवाब दे रहे थे तब बड़ी चालाकी से जवाब दे रहे थे।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः गुप्ता जी, आप कल की बात मत करें। वह तो मैं राज्यपाल महोदय, के अभिभाषण पर जवाब दे रहा था! उसके बारे में भी आप कल बोल चुके हैं आज बजट पर डिसकशन हो रही है। आप इस पर ही बात करें।

श्री मांगे राम गुप्ताः वित्त मंत्री जी ने किसानों के गन्ना खरीदने के बारे में कहा है कि हम किसानों का गन्ना 110 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ले रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में हमें आपत्ति है और वह आपत्ति इसलिए है कि जो सहकारी चीनी मिलों के नजदीक हैं उनको तो वह रेट मिल रहा है लेकिन जो प्राइवेट मिल में गन्ना देते हैं उनको तो 87 रुपए प्रति क्यिंटल के हिसाब से गन्ने का दाम मिल रहा है। (विघप) किसानों से आपका वास्ता है और मुख्य मंत्री जी कहते है कि पूंजीपतियों को कैसे दे दें? मैं मुख्य मंत्री जी से कहूँगा कि पूंजीपतियों की कौन

बात कर रहा है लेकिन जिस किसान का 87 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ना बिका है और उनका जो 23 रुपए डिफरैंस रह गया है वह इस सरकार को अपने खजाने से देना चाहिए।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में पहले भी कहा था और कल भी अपने जवाब में कहा है कि हमारी कोआप्रेटिव शुगर मिलों में जो किसान गन्ना बेचेगा उसको 104, 106 तथा 110 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का रेट दिया जाएगा 1 उपाध्यक्ष महोदय, गन्ना खरीद के मुनाफा सरस्वती शुगर मिल, जगाधरी के मालिक खा लें उसका बकाया पैसा हम क्यों दें? हरियाणा सरकार क्यों दे? (विघन) हम तो किसानों को कह रहे हैं कि जो किसान कोआप्रेटिव मिल में अपना गन्ना देगा उसको हम 104 तथा 106 और 110 रुपए प्रति क्यिंटल के हिसाब से गन्ने का रेट देंगे।

श्री मांगे राम गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, जीन्द का गला बांड से उपर है और वे पातड़ों जाकर 80 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बेचकर एक हफ्ते में वापिस आते हैं। शुगर मिल जीन्द में 50 क्विंटल की पर्ची एक्का लें तो 5 हजार रुपए की एन०ए०सी० लेनी पड़ती है।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः आपके पास कोई शिकायत है तो हमें दें। हम तुरन्त उसके खिलाफ इन्क्वायरी करेंगे और ऐक्शन लेंगे। आप जैसे सयाने आदमी को ऐसी अनर्गल बात कहना शोभा

नहीं देती है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह की शिकायत है तो वे हमें लिखित में दे और हम उस पर इन्क्वायरी करेंगे और कल ही ऐक्शन लेंगे। मांगे राम जी, अगर आपके पास ऐसी कोई शिकायत है तो हमें दें। (विघन) कल ले आना हम कल ही ऐक्शन लेंगे।

श्री मांगे राम गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, मै सदन में कभी गलत बात नहीं कहता हूँ। न कभी कही है और न हीं कभी कहूँगा। मैंने कोई गलत बात नहीं कही है और न हीं कभी कहूँगा। अगर मैंने कोई गलत बात कही है तो मैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। जहां तक मैंने जो बात कही है इस बारे में मैं इनको बता दूंगा।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः कल ला देना। हम कल ही इन्क्वायरी करवा देंगे।

श्री मांगे राम गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार को सुझाव देना चाहूँगा। तीन साल इस सरकार को बने हुए हो गए हैं। हरियाणा में पॉवर जनरेशन की बात करना चाहता हूँ। इसमें दो राय नहीं है कि पॉवर जनरेशन बढ़ी है। अब चाहे ये कहीं पर 6 घण्टे, 4 घण्टे या 2 घण्टे दें। एक प्रॉब्लम हरियाणा में बहुत है मैं इनके मैनीफैस्टो की बात नहीं करता हूँ इस बारे में तो इनको लोग देखेंगे। लेकिन यह फैक्ट्स की बात है

कि हरियाणा में लोगों पर बिजली के बिल इतने ज्यादा हो गए हैं कि वे बिजली के बिल नहीं दे पा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्षः मांगे राम जी, आप फिर से बात को रिपीट कर रहे हैं। आप सरकार को अपने सुझाव दें।

श्री मांगे राम गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, मैं सुझाव भी दूंगा। मेरी बात तो सुनें। (विघन) मैं रिपीट नहीं करूंगा। आप बात तो सुनें।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः गुप्ता जी, रैपिटिशन में आदमी थक जाता है इसलिए आप किसी भी बात को रिपीट न करके अपने सुझाव दें। आपने गवर्नर के अभिभाषण पर बोलते हुए भी यही बात कही थी।

श्री मांगे राम गुप्ताः उस समय वह बात मैंने दूसरे ढंग से कही थी और अब मैं सरकार को सुझाव देने के लिए यह बात कह रहा हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि किसी तरीके से यह जो आज भेदभाव हो रहा है वह दूर होना चाहिए। हरियाणा के नागरिकों को एक तरफ तो पैसा देकर बिजली न मिले वहीं दूसरी तरफ लोग अगर फ्री में बिजली लेते हैं तो क्या यह ठीक है? मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से सरकार इस बीमारी को हल कर दे। चाहे तो सरकार बिजली के बिल माफ कर दे या फिर फ्री पॉवर कर दे। वित्त मंत्री जी, इसको लाइन पर लाईये। कम से कम तीन सौ, चार सौ करोड़ रुपये पिछले रिकवरी के पैंडिंग हैं। अगर इनको आप

लीगलाइज कर देंगे, सबके लिए बराबर कर देंगे तो इससे आपका रैवेन्यू भी बढ़ेगा और 100– 150 करोड़ रुपये साल के आपको मिल भी जाएंगे और जो ये रोज के ऐजीटेशन होते हैं, झगड़े होते हैं गिरफ्तारियां होती हैं, गोलियां चलती हैं बहुत से लोग मारे जाते हैं तो वह समस्या भी आपकी मिट जाएगी। अगर कोई इस तरह की प्रौब्लम खड़ी होती है तो सरकार को इसको कंट्रोल करने के लिए काफी खर्चा करना पड़ता है पुलिस की अलग से सिरदर्दी बढ़ती है लोग पुलिस को पकड़ लेते हैं इसलिए ऐसी फिजा पैदा न हो, इसके लिए आपको सोचना चाहिए।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः गुप्ता जी, यह आपका सुझाव ठीक है। हमारी सरकार जिस दिन से बनी है उसी दिन से हम इस बारे में प्रयासरत हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि किसान के जिम्मे बिजली के बिलों का इतना बकाया हो गया है कि अगर वह अपनी धरती बेचकर भी अदा करना चाहे तो वह नहीं दे सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने समय–समय पर किसानों को रियायतें दी हैं, सुविधाएं दी हैं और आखिर में तो हमने यहां तक कहा कि उनका 75 परसेंट माफ यानी केवल चवन्नी रह गयी जबकि दिवालिया बनिया भी आठ आने में फैसला करता है लेकिन हमने चार आने में कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इन प्रयासों के बाद ही हमारी सरकार को 1500 करोड़ रुपये के लगभग या शायद इससे भी ज्यादा होगा, सही आकड़े मैं आपको बताऊंगा, हमें रुपया वसूल होकर मिला है।

आज भी मैं पूरे सदन के माध्यम से पूरे हरियाणावासियों को खुले दिल से एक निमंत्रण देता हूँ कि हम उनके इस मसले का समाधान करने के पक्षधर हैं। चाहे कोई किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ किसान क्यों न हो। चाहे राजनैतिक रूप से वह कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ किसान हो, चाहे बी०जे०पी० से जुड़ा हुआ किसान हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ा हुआ किसान हो या चाहे कम्यूनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ किसान हो, हम सबके लिए इस समस्या के समाधान के पक्षधर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार प्रोफार्मर्ज है किसानों की हितैषी सरकार है इसलिए हम इस मसले का हल निकालने के पक्षधर हैं। गुप्ता जी, मैं आपको भी कहता हूँ कि अगर आपके पास इसका कोई हल है तो आप इस समस्या का हल निकलवाए। मैं खुले दिल से कहता हूँ कि आप आईये और बात करिए। इसका जो कोई भी समाधान मिलेगा हम उसको करने के पक्षधर हैं।

चौ० भजन लालः उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी, ये भी बता दें कि किसानों को बिल न देने के लिए प्रवोक किसने किया था?

श्री ओम प्रकाश चौटालाः यह काम हमने नहीं आपने किया था।

चौ० भजन लालः यह काम तो आपने ही किया था हम यह काम नहीं करते।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: भजन लाल जी, अगर मैं पुराने आकड़े बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा। लोग पैसा भर रहे थे लेकिन आपने उनको रोका था। पैसा. इकट्ठा करने के लिए विपक्ष के नेता गए थे और बोला था कि मैं पद यात्रा करूंगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: यह काम तो आपका है। आप ही हरियाणा में .... मचा रहे हो। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: यह शब्द रिकॉर्ड न किया जाए।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: उपाध्यक्ष महोदय, ये चौधरी देवीलाल के नक्शे कदम पर चलना चाहते थे। कार में बैठकर चलना चाहते थे। इन्होंने आज सुबह इनकार किया कि मुझे पैसा नहीं मिला। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्ष: हुड्डा साहब, आप बैठें।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा: उपाध्यक्ष महोदय, ये इस तरह की बात कैसे कह रहे हैं। हम यह काम नहीं करते।

श्री उपाध्यक्ष: भूपेन्द्र जी, आप बैठें।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: विपक्ष के नेता नें आज यह कहा है कि मैंने पैसा किसानों को दिया है भजनलाल जी, आप गवाह हैं। इन्होंने कहा है कि इन्होंने किसानों को एक– एक लाख रुपया दिया है। मैं सुबूत के साथ कहता हूँ कि इन्होंने 75 लाख

रुपया इक्ट्ठा किया है जबकि अपनी पार्टी के कोष में केवल 4200 रुपये ही जमा करवाए है। सरकार इसकी भी इंक्वायरी करवाएगी। (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः हुड्डा साहब, आप बिना परमीशन खड़े होकर बोल रहे हैं, आप बैठें।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः भजन लाल जी, आप लिखकर दें हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे अगर आप लिखकर नहीं दे सकते तो फिर गुप्ता जी से लिखवाकर दें। हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे। ये पैसा तो ये खुद ही खा गए। (शोर एवं व्यवधान) लोगों को मरवा दिया, ऊंगली लगा दी जबकि लोग पैसा दे रहे थे लेकिन केवल पैसा इकट्ठा करने के लिए इस व्यक्ति ने पूरे हरियाणा को बर्बाद कर दिया था। इन्होंने 75 लाख रुपया खाने के लिए ऐसा किया था। पद यात्रा करते हैं लेकिन कारों में सफर करते हैं फाईव स्टार होटल में जाकर बैठते हैं। ये गरीब किसानों को लूटकर खा गए। (शोर एवं व्यवधान) मैं पूएर सदन में कहता हूँ कि ये बताएं कि जो 75 लाख रुपए इस व्यक्ति ने लोगों से लिए वह पैसा कहां जमा करवाया है। वह पब्लिक मनी है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः आपकी मर्जी है, आप जो चाहे करो मैं आपको चुनौती देता हूँ।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः आपकी चुनौती के बिना ही मैं इलाज करवाने लग रहा हूँ आप चिन्ता न करें। मैं भजनलाल जी के बिना भी आपका इलाज करूंगा। जनता का पैसा किसी को खाने नहीं देंगें यह हमारी सरकार का फैसला है।

श्री उपाध्यक्षः हुड्डा साहब, आप बैठें। आप पूछकर नहीं बोल रहे हैं। आप जब मर्जी आए उठकर खड़े हो जाते हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः उपाध्यक्ष महोदय, ये कैसे धमकी देते हैं। हम इनकी धमकी से डरने वाले नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्षः हुड्डा साहब, अगर आपको अपनी बात कहनी है तो आप पर्सनल एक्सप्लेनेशन मांगे, प्वायंट ऑफ ऑर्डर मांगे। आप कोई इजाजत तो मांगें, आप तो ऐसे ही खड़े हो जाते हैं आपको पूछकर तो खड़ा होना चाहिए। (विघ्न) (शोर एवं व्यवधान) मांगे राम गुप्ता जी, आप वाईंड अप करें।

श्री मांगे राम गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात की सराहना करता हूँ। मैं इस हक में था कि जो बिजली की 25 परसैंट की पालिसी सरकार ने ली है वह बहुत अच्छी है और मैंने उसको ऐप्रीशिएट किया है और उसका मैं सपोर्ट करता हूँ। इसको भरना चाहिए। लेकिन मुख्य मंत्री जी इसको भी लोग नहीं भर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) यह सरकार का काम है और किसी के रोकने से नहीं रुकना चाहिए। It is the function of the Govt.संपत सिंह जी, मैं एक बात कहकर समाप्त

करता हूँ। आपने शहरों के सुधार के लिए एक तजवीज निकाली थी कि किस तरह से कमेटियों का रेवेन्यू बढ़े और इसके लिए 110 रुपए प्रति गज के हिसाब से डिवैल्पमैंट चार्जेज लगाए थे।

श्री उपाध्यक्षः मांगे राम जी, आप समअप करें।

श्री मांगे राम गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, मैं समअप कर रहा हूँ। गोयल साहब बैठे हैं वे बताएंगे, उसमें यह कर दिया है कि किसी प्लांट या मकान की रजिस्ट्री तब तक नहीं हो सकेगी जब तक रजिस्ट्री करवाने वाला 110 रुपये प्रति गज के हिसाब से डिवैलपमैंट चार्जिज कमेटी में नहीं भर देगा, चार्जिज भरने के बाद उसकी एन०ओ०सी० लेकर तब रजिस्ट्री होगी (विघ्न) मुख्य मंत्री जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। यह तो फायदे की बात है 110 रुपये प्रति गज के हिसाब से आपने डिवैलपमैंट चार्जिज लगा दिये और एन०ओ०सी० देने लग गए लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला होने लग रहा है। इसमें फर्जी एन० ओ०सी० लेकर रजिस्ट्री की जाती है। दो नंबर में दो–चार हजार रुपये लेकर एन०ओ०सी० दे दी जाती है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास दोनों डिपार्टमैंट हैं। तहसील में जिस दिन से डिवैल्पमैंट चार्जिज लगाए गए हैं, जो टाउन्ज में रजिस्ट्री हुई है एन०ओ०सी० जारी हुई है उस पर आप तालमेल बैठाकर देख लें कि कितना पैसा मिला है? मैंने पहले ही कहा था कि 110 रुपये जो डिवैलपमैट चार्जिज लगाए हैं वह बहुत ज्यादा हैं और उनमें घोटाला होगा।

आपने हाउस टैक्स के बारे में भी मेरी बात नहीं मानी, आपने हाउस टैक्स लगाया और अब लोग पैसा नहीं दे पा रहे हैं। एन०ओ०सी० का बहुत बढ़िया तरीका लगा रखा है, थोड़ा बहुत सुविधा शुल्क दो और एन० ओ०सी० ले लो। वित्त मंत्री जी आपके पास रेवेन्यू कहां से आएगा? अफसोस इस बात का है कि पहले साल में 2300 करोड़ का प्लान बना कर के कोशिश की थी उस प्लान में 1800 करोड़ रुपये से ऊपर आपसे आज तक खर्च नहीं हुए। 1800 करोड़ रुपये से ऊपर आप नहीं पहुँच पा रहे हैं। रिसोर्सिज वही के वही है स्टेट गवर्नमैंट से 76 परसेंट पैसा आ रहा है और सैंटर गवर्नमैंट का 24 परसेंट है। चार साल से गवर्नमैंट कोई रिसोर्सिज जुटा ही नहीं पा रही है। वहीं घूम रही है कोल्हू के बैल की तरह। कर्जा ले लो घाटे में 100 करोड़ रुपया बता दो। एक करोड़ रुपये की स्कीम दे दो ऐसे तो मैं खुश कर दूं हरिजन को, बैकवर्ड क्लासिज को खुश कर दूं। (विघन)

श्री उपाध्यक्षः मांगे राम जी, आप बैठ जाइए। आपकी समय सीमा समाप्त हुई।

श्री मांगे राम गुप्ताः उपाध्यक्ष महोदय, 500 करोड़ रुपये का घाटा हर साल बजट में होता रहेगा तो कैसे काम चलेगा? मैं इस बजट का पुरजोर विरोध करते हुए अपना स्थान लेता हूँ। इस बजट को पास नहीं किया जाए।

प्रो० संपत सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मार्गे राम जी से बड़ी निराशा हुई है ये इतने सीनियर आदमी हैं, इतनी बार मंत्री रहे हुए हैं। वाणिज्य परिवार में इन्होंने जन्म लिया है। मैंने सोचा था कि कोई न कोई ये राय देंगे लेकिन इनकी बात सुनकर कोई स्वाद नहीं आया। मुझे इस बात का अफसोस है।

श्री उपाध्यक्ष: अब श्री रघुबीर सिंह कादियान जी बोलेंगे, कादियान साहब आप केवल बजट पर ही बोलिए।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान (बेरी): धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे समय बता दें कि कितना टाइम देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: दस मिनट में आप अपनी बात कहें।

डा० रघुबीर सिंह कादियान: धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, जैसे बजट में अच्छाई और बुराई दोनों को बोल्डली और बड़े अच्छे ढंग से दर्शाया गया है। फाईनैंस डिपार्टमैंट के आफीसरान इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं इस बात के लिए जब मोटे तौर पर बजट पर नजर डालते हैं क्योंकि हम कोई इकोनोमिस्ट तो हैं नहीं और न ही हमें कोई ऐसी महारत हासिल है। लेकिन फिर भी जब हम बजट पर नजर डालते हैं तो पाते हैं कि नये असैटस के लिए सरकार के पास कोई पैसा दिखाई दे नहीं रहा। लगभग पूरे का पूरा प्लान कर्जों से पूरा करने की नीयत साफ नजर आ रही है। डेटाज की जगलरी के सिवाए कुछ नहीं है। वही घिसीपिटी भाषा और वित्तीय प्रबन्धन के नाम के सिवाए कोई नयी बात नजर

नहीं आती। इसमें आप देखें उपाध्यक्ष महोदय, चौधरी सम्पत सिंह जी की काबलियत के चर्चे हैं और इन्होंने ये चौथा बजट पेश किया है। वर्ष 1999– 2000 के बजट का रिवाइज्ड एस्टिमेट 1811 करोड़ का था उस समय वार्षिक योजना का आकार 2530 करोड़ रुपये का था इस प्रकार वह 39 प्रतिशत बढ़ गया और उस समय बड़ी मेजें थपथपाई गई थी। डाउनफाल 700 करोड़ रुपये वार्षिक योजना का होकर के 1815 करोड़ रुपये उसका रिवाइज्ड एस्टिमेट रह गया है। फिर इन्होंने 2150 करोड़ रुपये रिवाईज्ड एस्टीमेट रखा और उसका डाऊन फाल 312 करोड़ रुपये होकर 1838 करोड़ रुपये रिवाइज्ड एस्टिमेट आया और फिर वर्ष 2002 –2003 के बजट में 1922 करोड़ रुपये का रिवाइज्ड ऐस्टीमेट रखा और उसका डाऊन फाल 122 करोड़ होकर 1800 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना रह गई और अब 2100 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना रखी है उसमें कितना डाऊन फाल होगा, उसकी कितनी इन्फलेशन है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है यह तो एक डिबेटेबल प्वायंट है लेकिन है यह सबसे बड़ी चिन्ता का विषय। उपाध्यक्ष महोदय पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट का घाटा जो हैं वह 780 करोड़ रुपये के करीब दिखाया गया है और उसमें ये कह रहे हैं कि नये टैक्स नहीं लगेंगे और जनता के ऊपर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। तो यह बात समझ में आ नहीं रही है कि ये स्टेट के रिसोर्सिज बढ़ाने की कोई प्लानिंग करने वाले हैं या नहीं? नॉन कन्वेंशनल जैसे ऑन लाइन लाटरी या कैसिनो जैसी नॉन कन्वेंशनल जो मैथड है उसको ऐडोप्ट करने की बात की जा रही

है। हरियाणा प्रदेश जो दूध दही के खाने की मिसाल के लिए जाना जाता था, आज वहां कैसिनो खोलने की क्या मंशा है? फण्डज इक्ट्ठा करने या रिसोर्सिज बढाने की कोई बात है या व्यक्तिगत किसी की क्या दिलचस्पी है कि इतना बड़ा प्रोजैक्ट जिस ढंग से सारे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है कि हरियाणा प्रदेश में कैसिनो खुलने जा रहा है इसके लिए गवर्नर साहब इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि इस संस्कृति को समझते हुए जिस ढंग से (विघन)

श्री उपाध्यक्षः आप जो कह रहे हैं इस बारे बजट स्पीच में कोई चर्चा है या प्रावधान है आप इस समय बजट की बात कर रहे हैं। बजट पर ही बोलें।

डा० रघुबीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल पास हुआ है।

श्री उपाध्यक्षः जिस पर आप बात कर रहे हैं। (विघन)

प्रो० सम्पत सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि बजट में क्या कोई कैसिनो के बारे में जिक्र है। बजट में इस बारे कोई जिक्र नहीं आया है लेकिन इन्होंने हाउस में जिक्र कर दिया। बजट की रिप्लाई में मैं नहीं समझता कि बजट से बाहर की बात की जाये। बजट की रिप्लाई तो मैं बाद में दूंगा लेकिन कैसिनो क्योंकि बजट से बाहर की बात है इसलिए इसका तो रिप्लाई अभी दे देता हूँ। बजट पर मैं बिलकुल इंटरवीन नहीं

करुंगा बाकी बातें मैं बजट के बारे में रिप्लाई देते वक्त कहूँगा लेकिन कैसिनो बजट के बाहर की बात है इसलिए मैंने जिक्र कर दिया। पिछली बार भी मैंने इनको कहा था कि कैसिनो है वह कोई गैम्बलिग नहीं बल्कि गेमिंग है और साथ ही यह भी कहा था कि हिन्दुस्तान में अगर पहली बार कही कैसिनो खुला है तो वह गोवा में खुला है और तब खुला था जब वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उन्होंने गोवा में खोला था। कांग्रेस कोई रीजनल पार्टी नहीं है, यह नेशनल पार्टी है और पार्टी लैवल पर फैसले होते हैं पालिसी मैटर नेशनल लैवल पर होते हैं चाहे वह कैसीनो के हैं, चाहे वे लॉटरीज के हों। चाहे कोई नीतिगत फैसले हों। नेशनल पार्टी के अधिवेशन होते हैं राजनौतिक और आर्थिक रैजोल्यूशन वहां पास किए जाते हैं। इनकी खुद की पार्टी ने गोवा में कैसिनो खोला और दूसरी तरफ बार–बार विधान सभा के बाहर कहते रहते हैं। वैसे बयान बाहर देते हैं लेकिन शुक्र है इन्होंने विधान सभा के अन्दर इस बार जिक्र कर दिया। पिछली बार तो नहीं किया था। इस बार मेरे बी०जे०पी० के साथी कृष्ण पाल गुज्जर ने भी कैसिनो का जिक्र किया था। आज बी०जे०पी० की सरकार गोवा में है और इनके मुख्य मंत्री हैं। आज ये उसको प्रमोट करें, दोनों ही नेशनल पॉर्टीज हैं। कम से कम कांग्रेस और बी०जे०पी० दोनों का कैसिनो के बारे में जिक्र करने का फर्ज नहीं बनता। पहले नम्बर पर तो मैं यही कहना चाहता हूँ। दूसरे नम्बर पर यह कहना चाहता हूँ कि ये इस तरह का प्रचार कर रहे हैं कि जैसे किसी गली में किसी मोहल्ले में, किसी फलाने में जुआ घर

खोला जायेगा। कैसिनो एंटरटेनमैंट का कम्पोजिट रिजौर्ट होगा। उसका एक स्मालर पार्ट है और यह फार गैमिंग परपज के लिए है और वह कोई यह नहीं है कि घर–घर में हो जायेगा। उसके अंदर फाईव स्टार होटल होंगे। उसके अंदर आर्टीफिशियल बीचिज होंगी और वर्ल्ड के टॉप क्लास गेम होंगे। अगर आप देखेंगे तो साऊथ अफ्रीका के अंदर जो सन सिटी हैं वहां वर्ल्ड की सबसे ज्यादा प्राईस मनी की जो लॉन टेनिस की टूर्नामैंट हैं, वहां होती हैं। वर्ल्ड की सबसे ज्यादा प्राईस मनी की गोल्फ की जो टूर्नामैंट होती है वह वहां होती है और वर्ल्ड यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स कान्टैस्ट वहां होते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस बात को यूं घुमाना और लोगों को गुमराह करना इनकी यह अच्छी बात नहीं लगती। इसलिए मैं इनको एक बार फिर क्लीयर करना चाहता हूँ कि वह कम्पलीट रिजोर्ट की बात है। आज लेजर का जमाना आ रहा है। इसलिए मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ। इसके बाद सारी बातें क्लीयर हो जाती हैं। अब किसी को शंका नहीं रहनी चाहिए।

चौ० भजन लालः ....

श्री उपाध्यक्षः भजन लाल जी जो कह रहे हैं वह रिकॉर्ड न किया जाये। आपको अलग से मौका मिलेगा। (शोर)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदय, बजट एट–ए–ग्लांस में जो रिवेन्यू रिसीट्स हैं टोटल रिवैन्यू रिसीट्स

का जो टैक्स रिवेन्यू रिसीट्स है वह 65 प्रतिशत है और नॉन टैक्स रिवैन्यू से जो रिसीट्स हैं वह 22 प्रतिशत है। इसमें साफ झलकता है कि जो टैक्स रिसीट्स बढ़ गया वह 13 प्रतिशत पिछले टाईम से ज्यादा बढ़ गया। तो ये जो प्रैजेंट टैक्स का स्ट्रक्चर है उसमें ये इन्क्रीज करेंगे या कोई नया टैक्स लगायेंगे तो इसमें सरकार की जो मंशा है वह साफ झलकती है कि टैक्स फ्री बजट कहकर और इन द मिडल जैसा इनकी प्रैक्टिसीज रही हैं कि बराबर जनता पर टैक्स के बोझ पड़े हैं इस तरह से इसमें भी लगता है कि भारी टैक्स का बोझ जनता के ऊपर पड़ने वाला है जैसा सभी साथियों ने उपाध्यक्ष महोदय, जिक्र किया कि जो ब्याज की पेमेंट है वह 2221 करोड़ रुपये है। यह जो टोटल टैक्स रेवैन्यू का 33 प्रतिशत है वह ब्याज की अदायगी में कन्यूम हो जाता है। जो रेवैन्यू एक्सपँडीचर है उसका 20 प्रतिशत के करीब इंट्रस्ट पेमेंट है। यह बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है। आप देख रहे हैं कि बजट का 40 प्रतिशत Debt Services में जा रहा है। कर्जे की अदायगी कर्जे लेकर की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ा भारी चिन्ता का विषय है कि किस दिशा में प्रदेश जा रहा है? क्योंकि जो रैवेन्यू एक्सपैंडीचर है वह 9800 करोड़ रुपए से 10730 करोड़ रुपये तक इनक्रीज हो गया। The increase of 900 crores rupees only is under the Head of Revenue expenditure during 1997 to 2000 जो डैचट लायबिल्टिजि हैं वे 6800 करोड़ रुपये से बढ़कर 20695 करोड़ रुपये हो गई हैं। यानि की डैचट लायबिल्टिजि में भी 300 प्रतिशत के करीब बढ़ौतरी हो गई और

इत्रमें स्टेट गारंटीज अलग से रह गई 1 (शोर एवं व्यवधान) वित्त मंत्री जी, आप उपाध्यक्ष महोदय के माध्यम से बात करें। बैठे–बैठे मुझे बीच में टोके नहीं। यदि आप बैठे–बैठे बात करोगे तो यह व्यवस्था का प्रश्न बनता है। आपके बजट एट–ए–ग्लांस में 6800 करोड़ रुपये ही दिखाया हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, जो स्टेट की डैबूट है i.e increasing faster than the rate of growth यानि जो डी०एस०डी०पी० है उसकी ग्रोथ फास्टर है।

श्री उपाध्यक्षः कादियान साहब, आप समय सीमा का भी ध्यान रखें।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर बोल रहा हूँ कोई दूसरी बात नहीं कर रहा और सुझाव भी दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय जो टोटल एरियर .आफ रैवेन्यू हूँ वे बहुत सालों से आउट स्टैंडिंग पड़े हैं और अनसैटिस्फैक्ट्री टैक्स प्लांज की तरफ इशारा करते हैं। जितने भी आउट–स्टैंडिंग एरियर्ज हैं

i.e ways and means allowances obtained by State and availing of over-draft increased since 1997-98, reflected the mismatch between the receipts and the disbursement of the Government.

उपाध्यक्ष महोदय, इन सभी मामलों में पर कैपिटा इनकम डाउन जा रहा है, रेट ऑफ ग्रोथ घटता जा रहा है और क्राइटइरिया बदलने के बाद भी जीरो पौवरटी लाईन से नीचे जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इस तरह ये किस दिशा में प्रदेश को

ले जा रहे हैं, यह हमारी समझ से तो बाहर है। शायद मंत्री जी जानते हों। यह डाटा की जो जगलरी है इस और सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः कादियान साहब, आपका समय समाप्त हो गया। प्लीज, अब आप बैठें।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर बोल रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्षः कादियान साहब, आपको 10 मिनट का समय दिया था और अब आपको बोलते हुए 10 मिनट हो गये हैं। अब आप दो मिनट में वाइंड अप करें। मैंने दूसरे माननीय सदस्यों को भी समय देना है।

डॉ० रघुबीरसिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदय, मैंने तो एक–एक लाईन में सारी बातें कहीं हैं कोई फालतू बात नहीं कह रहा और कोई एक्सप्लेनेशन भी मैंने नहीं दी। उपाध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त बिजली के बारे में भी बजट में बहुत कुछ कहा गया है लेकिन रूरल एरियाज मैं आज भी बिजली की पोजीशन बहुत खराब है। रूरल एरियाज में आज भी अन–डिकलेयर्ड कट लगते हैं। बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्षः यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजें: ठीक है जी।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है, हाउस का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाता जाता है।

वर्ष 2003 – 2004 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान: उपाध्यक्ष महोदय, 250–250 मेगावाट की दो यूनिट जिनके फाईल पर आर्डर हुए थे, उसमें ग्लोबल टैंडर नहीं हुआ और उसमें अंडर हैंड डील के तहत सिंगल आर्डर पर डिजनी कंपनी के साथ डील हो गई। जो डिजनी कंपनी थी उसके मालिक ने सबलैट किया बाम्बे सब अर्बन इलैक्ट्रिक सप्लाई को और बॉम्बे सब अर्बन ईलैक्ट्रिक सप्लाई ने बी०एच०ई०एल० को सबलैट किया। ठीक है, बी०एच०ई०एल०एक बहुत बड़ी कम्पनी है लेकिन बी०एच०ई०एल० ने भी उसको सबलैट किया और माजरा साहब ने सैक्शन कोट करते हुए कहा कि इस सैक्शन के तहत सबलैट किया जा सकता है। लेकिन फिर उसको भी उसने सबलैट किया 150 करोड़ रुपये में। यानि उसको उसने डिजनी को दे दिया। डिजनी के पास कोई वर्क नहीं है। (विघन)

श्री उपाध्यक्ष: कादियान साहब, आपने यही बात गवर्नर एड्रैस पर कह दी थी, यह कोई नयी बात नहीं है।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियान: स्पीकर साहब, इसमें बड़ा भारी ....

श्री उपाध्यक्षः इनकी यह बात रिकॉर्ड न की जाये।

डॉ० रघुबीर सिंह कादियानः उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर खुले दरबार की बहुत चर्चा होती है। इस बारे में मेरा कहना है कि खुले दरबार पर बहुत टाईम वेस्ट हो रहा है। डी०सीज० और एस०पीज० का 7–7 दिन का टाईम लगता है। (विघन) उपाध्यक्ष महोदय, सी०एम० साहब, बेरी में गए थे। मुख्य मंत्री जी वोटर लिस्ट को लेकर बैठ गए और कहने लगे कि आपने वोट नहीं दे रखी। (विघन) इन्होंने मुख्य मंत्री के पद की शपथ ले रखी है। गीता पर हाथ रखकर शपथ लेते हुए कहा है कि मैं प्रदेश के लोगों का विकास बराबरी के आधार पर करूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर बड़ा भारी ....

श्री उपाध्यक्षः इनकी यह बात रिकॉर्ड न की जाये। अब आप बैठ जाएं। (विघन)

श्रीमती अनीता यादव (साल्हावास): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है यह इनका चौथा बजट है और इसमें इन्होंने दो बातें कहीं हैं। एक तरफ तो इन्होंने इस बजट में 78053 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है और दूसरी तरफ कहा है कि योजनेत्तर खर्च पर अंकुश लगाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। मुझे इनकी ये दोनों बातें ठीक नहीं लगती। मुझे पता नहीं लगता कि कौन सी मंशा से इन्होंने बजट तैयार किया है? मैं जानना चाहती हूँ कि क्या इनका यह

प्रयास केवल कागजों तक ही सीमित है या ये कुछ कर भी पायेंगे। इस बारे में मुझे कहते हुए बड़ा खेद हो रहा है और यह शंका हो रही है कि पिछली बार जब बजट पेश किया तो इन्होंने वह बजट भी कर रहित पेश कर दिया, लेकिन बाद में कर लगा दिए थे। इसी तरह अब भी मुझे डर है कि ये बाद में टैक्स लगायेंगे। मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहती हूं कि आज के दिन यदि किसी व्यक्ति ने डैथ सर्टिफिकेट भी लेना है तो उसको भी उसके लिए 50 रुपये देने होते हैं इसी प्रकार से जो गरीब आदमी सरकारी अस्पताल में दिखाने के लिए जाता है तो उसको भी पर्ची के 5 रुपये फीस के देने पड़ते हैं। सरकार ने इसी प्रकार से हलवाइयों पर भी टैक्स लगा दिया है। इतना ही नहीं जो किसान खेत में मिट्टी उठाता है, उस पर भी कर लगता है। मैं कम समय में अधिक बातें कहना चाहूंगी। मुझे लगता है कि आप बोलने के लिए मुझे ज्यादा समय नहीं देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जो एम०एल०ए० दूसरे डॉक्टर्ज के पास कंसल्टेशन के लिए जाता है तो उसको भी 5 रुपये की पर्ची कटानी पड़ती है, यह बड़े दुख की बात है। इन सबके बावजूद ये कहते हैं कि हमारा यह कर मुक्त बजट है। उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सबसे पहले एजुकेशन के बारे में अपनी बात करूंगी। एजुकेशन हैड के अन्दर इन्होंने जो बजट रखा है वह 1881.4 करोड़ रुपये रखा है जो टोटल बजट का 12 परसेन्ट के करीब पड़ता है। मैं समझती हूँ कि यह एजुकेशन के लिए बहुत कम

मुख्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश चौटाला): उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नर एड्रैस पर बोलते हुए इन्होंने कहा था कि कौंसली रेलवे स्टेशन के पास प्राईमरी स्कूल नहीं है। उस वक्त मैंने कहा था कि वहां स्कूल बना देंगे। लेकिन मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि कौंसली में 400 गज के फासले पर प्राईमरी स्कूल है। (विघन) आपको सदन में गलत व्यानी नहीं करनी चाहिए।

श्रीमती अनीता यादव: आपने क्या कहा, मैं समझ नहीं पाई? (विघन)

श्री ओम प्रकाश चौटाला: आपने कौंसली रेलवे स्टोशन के पास एक प्राईमरी स्कूल मांगा था।

श्रीमती अनीता यादव: मांगा था।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: मैंने कहा था कि अगर कौंसली में रेलवे स्टेशन के पास स्कूल नहीं है तो बना देंगे।

श्रीमती अनीता यादव: वहां पर स्कूल नहीं है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: अनीता जी मैने पता किया है कि वहां पर 400 गज के फासले पर स्कूल है।

श्रीमती अनीता यादव: वहां पर स्कूल नहीं है।

श्री ओम प्रकाश चौटाला: वहां पर स्कूल है, आप गलत बयानी क्यों कर रही हैं।

श्रीमती अनीता यादवः वहां पर स्कूल नहीं, मैं वहा पर 20 साल से रह रही हूँ। (विघन) पोल पर जो लिखा है, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी बात करें (विघन)

श्री ओम प्रकाश चौटालाः वहां पर कौसली में 400 गज के फासले पर पहले ही एक प्राईमरी स्कूल है।

श्रीमती अनीता यादवः अगर वहां पर प्राईमरी स्कूल है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ।

ओम प्रकाश चौटालाः इसके लिए इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं है तो बना देंगे। इसके लिए इस्तीफा क्यों दे रहीं है। प्राईमरी स्कूल क्या मिडिल बना देंगे। दुबारा तो मैम्बर बन कर आपने आना ही नहीं है इसलिए अगर स्कूल नहीं है तो बना देंगे लेकिन मेरे पास यह सूचना आई है कि वहां पर 400 गज के फासले पर प्राईमरी स्कूल है।

श्रीमती अनीता यादवः जिस किसी ने आपको यह सूचना दी है, उसको सस्पेंड किया जाये। यदि मैं गलत कह रही हूँ तो आप मेरे खिलाफ ऐक्शन लें।

श्री उपाध्यक्षः अनीता जी, ऐसा तो नहीं कि कहीं प्राईवेट स्कूल और सरकारी स्कूल का मामला हो।

श्रीमती अनीता यादवः प्राईवेट स्कूल तो वहां पर 1000 खुल रहे हैं। हमने तो गरीब लोगों के लिए सरकारी स्कूल की

माग की थी। इसलिए मैं एजुकेशन के टौपिक को दोबारा ले रही हूँ। एक तरफ तो रैशनेलाईजेशन की बात कर रहे हैं कि टीचर्ज पर यह नीति लागू कर देंगे एक अनुपात 40 का जो रेशो था वह पहले ही अधिक था। एक क्लास में तो पहले ही 40 बच्चे एक टीचर के वश में नहीं आते थे। वहां अब 60 विद्यार्थी कर देने से शिक्षा में कोई सुधार नहीं हुआ है और आने वाले समय में सुधार होगा भी नहीं। क्योंकि एक–एक क्लास में 60–60 स्टूडेंटस होंगे तो शिक्षा में सुधार कैसे होगा? इसके अलावा मैं कुछ स्कूलों के नाम गिनाना चाहती हूँ कोहरड है, लिलोड़ है, भडंगी है, बहुझोलरी है वहां पर लड़कियों का महाविद्यालय खोला जाए। गिरोहड़ में भी लड़कियों का महाविद्यालय खोला जाए तो उससे शिक्षा के मामले में काफी सुधार हो सकता है। इससे हमें क्या क्रैडिट होगा वह बात भी मैं कहना चाहूँगी। आज हमारी लड़कियों की हत्याएं हो रही हैं, चाहे डॉवरी के कारण हो रही हों, चाहे दूसरे सिस्टम से हो रही हों, उन हत्याओं की रोकथाम में हमें इससे बल मिलेगा। इस सरकार ने ताऊ देवी लाल के नाम पर देवीरुपक योजना चलाई है। यह स्कीम तो केवल गरीब लोग ही एडॉप्ट कर पाएंगे कोई भी रिच आदमी इसे नहीं मानेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज के समाज में लड़का हर आदमी की जरूरत है। इसकी वजह यह है कि मेरी प्रोपर्टी की देखभाल कौन करेगा इसके लिए लड़का तो हर किसी रिच को चाहिए ही है। गुप्ता जी को तो सी०एम० साहब यह बात हर बार कहते हैं कि यह बनिया

है और पैसे की बात करता है लेकिन यह स्कीम तो उन लोगों को एडॉप्ट करने की जरुरत है जो पैसे के पीछे भागते हैं।

श्री उपाध्यक्षः अनीता जी, महिला होने के नाते कम से कम आप तो महिला प्रधान समाज की बात करें।

श्रीमती अनीता यादवः महिलाओं के नाते ही मैंने यह बात कही है। उपाध्यक्ष महोदय, कौंसली गांव के बारे में मैं विशेष बात कहना चाहूँगी। कौंसली इतना बड़ा गांव है और सैनिकों की खान है। यह मैं नहीं कह रही, आपके पूरे हरियाणा में और देश के दूसरे प्रदेशों में भी जहां भी जाते हैं तो वहां पर कहा जाता है कि कौंसली गांव सैनिकों की खान है। इसके बोर में एक मशहूर लोकोक्ति भी है –

बावन बंगले कोसली बांके कई हजार,

घर–घर सोहणें गाभरू घर–घर में सरदार।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूँगी कि सैनिकों के सम्मान में कौंसली में सैनिक स्कूल खोला जाए। इसके साथ ही साथ परम्परा को आगे निभाते हुए और आगे बढ़ाते हुए सैनिकों के सम्मान में एक फ्री ट्रैनिंग सैंटर खोला जाए तो इससे उनका सम्मान भी होगा और हमारे सैनिकों को और अधिक बल भी मिलेगा। शिक्षा के लिए जो बजट दिया गया है उसको थोड़ा और बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि इस मद में पैसा कम दिया गया है। अगर इसमें पैसा और बढ़ाया जाए तो हमारी सामाजिक प्रोग्रैस

और ज्यादा हो सकती है अन्यथा हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। किसी भी क्षेत्र के स्कूलों में पूरे टीचर्ज नहीं हैं। मेरे हल्के में कम से कम 10 ऐसे स्कूल हैं जिंनका उदाहरण दिया जा सकता है और जहां पर टीचर्ज का अभाव है जैसे बिरोड़ और मलेशाकस के गांव में प्राइमरी स्कूलों में सिर्फ एक ही टीचर पूरे स्कूल को कण्ट्रोल करता है। अगर ऐसी हालत रही तो शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कैसे हो सकता है। उपाध्यक्ष महोदय, हैल्थ के बारे में बार–बार चर्चा हुई है और इस समय हमारे डॉक्टर साहब चश्मा लगा कर सामने बैठे हुए बड़े खुश हो रहे हैं? जब भी किसी पी०एच०सी० या सी०एच०सी० की बात आती है तो ये कहते हैं हमने यहां पर खोल दी हमने वहां पर खोल दी लेकिन जो पैसा बजट में हैल्थ के लिए रखा गया है वह आबादी के हिसाब से बहुत ही कम है। अगर हम बिल्डिंग पर, स्टाफ पर और दवाइयों पर नजर दौड़ाएं तो सी०एम० साहब ने भी ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस क्वैश्चन आवर में यह बात मानी है (विघ्न)। सरकार ने 5 – 5 रुपये की पर्ची फीस लागू कर दी है। जैसे कि मैंने एम०एल०ए० होस्टल का भी जिक्र किया था कि हमें वहां पर भी पांच रुपये की पर्ची कटवानी पड़ती है लेकिन उस पैसे का सदुपयोग क्यों नहीं होता है। जो पैसा हैल्थ के लिए दिया गया है उसका सही उपयोग होना चाहिए और सही उपयोग न होने के लिए कौन जिम्मेदार है इसकी जांच भी करवाई जाए? इसके बारे में मैंने क्वैश्चन ऑवर में भी बात उठाई थी। उपाध्यक्ष महोदय, ट्रोमा सैंटरों की बात करते हैं तो ये कहते

हैं कि हमने हाईवेज पर ट्रोमा सैंटर्ज खोल दिए हैं। इस बारे में मैं माननीय हैल्थ मिनिस्टर के माध्यम से वित्त मंत्री महोदय को एक सुझाव देना चाहूँगी कि ट्रोमा सैंटर्ज ऐसी जगहों पर खोले जाएं जहां एक्सिडैंटल केसों के साथ साथ गरीब लोगों का इलाज भी हो सके और उनका कुछ भला भी हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, जब कांग्रेस का राज था, मुझे याद है कि उस समय हर सैमेस्टर में डी०डी०टी छिडकी जाती थी लेकिन पिछले तीन साल में जब से यह सरकार सत्ता में आई है इस दौरान डी०डी०टी के छिड़काव का प्रावधान नहीं हो पाया है। इसके साथ ही साथ पीने के पानी में लाल दवाई डाली जाती थी लेकिन आजकल पानी बहुत ज्यादा दूषित हो गया है और उसमें लाल दवाई नहीं मिलाई जा रही है इसलिए इस बारे में भी सुधार करने के लिए बजट में कुछ प्रावधान होना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, अब हरियाणा में लॉ एण्ड ऑर्डर की बात आती है। 1999–2000 में जब आपकी गवर्नमैंट आई थी तो उस समय कौंसली में रेलवे स्टेशन के पास एच०एस० सहगल रहते थे। उनके यहां से दो अंगूठियां, 40 हजार रुपए और असला चोरी हो गया था। मैंने इस बारे में पिछले सदन में भी कहा था और अब भी कह रही हूँ। आप यह कहते हैं कि हमारे अधिकारी यूं हैं, यूं हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको कहना चाहूँगी कि आज तक वह असला और बाकी का सामान नहीं मिला है, उसको अमलीजामा नहीं पहनाया गया है। यह सब .... का पुलिंदा है।

श्री उपाध्यक्षः यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्रीमती अनीता यादवः उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं यह भी बताना चाहूँगी कि 2 मार्च को 7 दुकानों के ताले टूटे हैं।

श्री ओम प्रकाश चौटालाः अनीता जी, यह सब्जैक्ट आपका नहीं है। आप बजट पर बोलें।

श्रीमती अनीता यादवः उपाध्यक्ष महोदय, बिसोवा में 8 जनरेटर सैट्स उठे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास आज की अखबार में यह ताजा खबर है कि पेट्रोल पम्प से 7 लाख रुपए लुटेरे लूट कर ले गए। आपके किसी पुलिस वाले ने उनको अभी तक पकड़ा नहीं है। आप यह बताएं कि आप उन पुलिस वालों पर किस तरह का पैसा खर्च करते हैं, वह पैसा कहां जाता है? इस बारे में ये सदन में बताएं। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं सदन में बताना चाहूँगी कि जब मैं विधायक बनी थी तब मैंने पिस्तौल का लाइसेंस बनवाने के लिए ऐप्लीकेशन लिखकर ऐप्लाई किया था। वहां पर जो ...... बैठा हुआ है।

श्री उपाध्यक्षः अनीता जी ने जिस आफिसर की पोस्ट का नाम लिया है उसको कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

श्रीमती अनीता यादवः मेरी उनसे तीन बार बात हुई। मैंने उनसे पूछा कि मेरी ऐप्लीकेशन का कग हुआ है? आप मेरा लाइसैंस क्यों नहीं बनाते हैं। तो वह कहता है कि हां जी मैडम, हां जी मैडम, आया जी। आज मुझे उस लाइसैंस के लिए ऐप्लाई

किए हुए तीन साल हो गए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही चिन्ता का विषय है 1 इस बारे में मैंने पहले भी कहा है। मुझे तो यह लगता है और मुझे इस बारे में उम्मीद है कि इस सरकार के होते हुए मेरी पिस्तौल का लाइसैंस बनेगा ही नहीं। लेकिन एक कहावत है कि जाको राखे साईयां मार सके न कोई।

श्री उपाध्यक्षः मेरे ख्याल से अनीता को पिस्तौल के लाइसेंस की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यह बहुत बोल्ड लेडी है।

श्रीमती अनीता यादवः उपाध्यक्ष महोदय, आज ये महिला सशक्तिकरण के बारे में कहते हैं और यहां पर हरिजनों के ठेकेदार बने बैठें हैं। मेरे पास आज कन्यादान राशि के लिए एक हजार महिलाओं के नाम हैं जो कि मैं आपको बता सकती हूँ। मेरे पास लेडीज आती हैं और कहती हैं कि बहन जी हमारी लड़की की मदद करो। लेकिन मैं उनकी क्या मदद करुं? जब हम विभाग में जाते हैं तो वे कहते हैं कि इसके लिए आप सोशल वैल्फेयर विभाग में जाओ और जब वहां पर जाते हैं तो वे कहते हैं कि हरियाणा हरिजन कल्याण निगम में जाओ। वे इधर उधर भेजते रहते हैं और इसी में 15– 15 और 20– 20 दिन निकल जाते हैं, उनको कन्यादान की राशि मिलती नहीं है। मुझे पता नहीं वे कहां पर कन्यादान राशि देते हैं, उसका क्या करते हैं? इसके लिए जो कोटा है उसको बजट में बढ़ा देना चाहिए। इसी तरह से महिलाओं को समानता का अधिकार एजुकेशन में भी दिया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः अनीता जी, अब आप बैठें। आपका समय हो गया है। धर्मबीर सिंह जी आप बोलें।

श्री धर्मबीर सिंह (तोशाम): उपाध्यक्ष महोदय, कल वित्त मंत्री प्रोफैसर सम्पत सिंह जी ने सदन में जो बजट पेश किया है मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कहने के लिए तो यह बजट कर रहित है लेकिन यह सरकार पिछले 3–4 वर्षों से कर रहित बजट पेश करती आ रही है लेकिन जब किसी आदमी ने मकान बनाना हो और वह रेत या रोड़ी लेने जाता है तो वह पाता है कि रेत महंगी होती है रोड़ी महंगी होती है। अगर वह डीजल लेने जाता है तो डीजल महंगा होता है। हमें यह पता नहीं लगा है कि जब कोई कर नहीं लगता है तो रेट कैसे महंगे हो जाते हैं। (विघ्न) आप डीजल पर सेल्ज टैक्स तो लगाते हो। आपके हरियाणा में पंजाब और चण्डीगढ़ से भी महंगा डीजल मिलता है। पहले ऐसा नहीं था। (विघन) उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से तो मेरा टाइम कम हो जाएगा। आप तो कम से कम मेरे टाइम का ख्याल रखा करें। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को कहना चाहूँगा कि ये इसे 2100 करोड़ रुपये का बजट कहते हैं जबकि 2221 करोड़ रुपये तो इंट्रैस्ट की पेमेन्ट में ही चले जाएंगे। इसलिए इस प्रकार के बजट को देखकर अफसोस होता है। सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है लेकिन मैं इनको कहना चाहूँगा कि फिर इन्होंने रूरल डिवैल्पमैंट और एग्रीकल्चर पर बजट का केवल मात्र तीन परसेंट ही खर्च करने का

प्रावधान बजट में क्यों रखा है? उपाध्यक्ष महोदय, तीन परसेंट पैसा ही इन्होंने पुलिस पर खर्च करने का प्रावधान किया है जबकि पुलिस वाले तो केवल वी० आई०पीज० या पुलिस के महारथियों के आगे पीछे ही घूमते रहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, चण्डीगढ़ से दिल्ली के रास्ते पर अगर आप जाएं तो रास्ते में पुलिस वालों की ड्यूटी आपको ऐसी जगहों पर भी लगी मिल जाएगी कि वहां सड़क पर कोई गधा न आ जाए। यहां पर भी सिपाही आगे पीछे दस–दस गाड़िया लेकर घूमते रहते हैं। तीन परसेंट पैसा ये उन पुलिस अधिकारियों और सत्ता पक्ष के लोगों पर खर्च करने जा रहे हैं जिनको आज कोई खतरा नहीं है जबकि तीन परसेंट पैसा कृषि प्रधान प्रदेश के रुरल डिवैल्पमैंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट पर खर्च किया जाना है। यह कहां तक ठीक है? उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़े अफसोस की बात है। सम्मत सिंह जी कहते हैं कि मैंने बड़ा अच्छा बजट पेश किया है उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि फिर आप कह देंगे कि मैंने ज्यादा समय ले लिया। मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा। मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि ग्रामीण क्षेत्र में केवल 127 करोड़ रुपये इस साल में खर्च करने के लिए बजट में रखे हैं जबकि मुख्य मंत्री महोदय अपने भाषण में कहते हैं कि हम 33 हजार योजनाएं पूरी करने जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर 127 करोड़ रुपये से ज्यादा पैसा नहीं होगा तो कहां से ये योजनाएं पूरी होंगी? ये तो केवल नाम की ही 33 हजार रह जाएंगी 1 पैसा तो है नहीं तो फिर कहां से ये काम पूरा करेंगे? इसी तरह से मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ई०एस० का

पैसा है तो ई०एस० का मतलब है कि ग्रामीण इलाके में गरीब आदमियों को रोजगार मिलें। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि यह काम भी ठेकेदारों के माध्यम से ट्रैक्टर्ज के द्वारा होता है। चाहे वह खुदाई का काम हो या चाहे वह जोहड़ का काम हो या कोई दूसरा काम हो। इसलिए इसको चेंज करके वापस मजदूरों को काम दिया जाए ताकि गरीब आदमी को काम मिल सके। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, सूखे के नाम पर मुख्य मंत्री महोदय ने ढिढौरा पिटवाया है कि 241 करोड़ रुपये की हमने मदद की है। बड़ी अच्छी बात है खुद मान लिया लेकिन नकद पैसा तो केवल 66 करोड़ रुपया ही दिया है। अगर आप गांवों में जाकर पूछें तो आपको पता लगेगा। आप नाम पूछना चाहते थे मैं आपको नाम बता देता हूँ। मैं आपको हल्के की बात बताता हूँ मेरे हल्के के आलमपुर गांव का रामनिवास जो कि कुम्हार है, ने 12 एकड़ जमीन में बाजरा बोया था, को बदकिस्मती से एक पैसा भी नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि इसमें नीचे के लेवल पर पटवारियों की कमी है या प्रशासनिक अधिकारियों की कमी है इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए जिन्होंने ऐसा काम किया है। इसी तरह से शिक्षा के बारे में एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। हमारा जिला भिवानी, महेन्द्रगढ़ या रोहतक से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर है। ठीक है सिरसा में नयी यूनिवर्सिटी बनायी जा रही है। अच्छी बात है, लेकिन भिवानी जिले के बच्चे 150 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए नहीं जा पाएंगे इसलिए हमारे जिले के कालेजों को रोहतक यूनिवर्सिटी के साथ ही जोड़ा जाना

चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से शिवालिक विकास बोर्ड, मेवात विकास बोर्ड बनाये हुये हैं उसी तरह से मेरी एक छोटी सी मांग हैं कि एक रेगिस्तान विकास बोर्ड भी इस प्रदेश के उन इलाकों के लिए बनाया जाए जहां पानी की कमी है। खुद मुख्य मंत्री जी जानते हैं कि सिवानी से बहल तक 50 गांव ऐसे हैं जहां पर आज से ही नहीं बल्कि चार साल से लगातार भयंकर सूखा पड़ा हुआ है और उसके साथ ही राजस्थान में भी सूखा होने की वजह से हर बार वहां के पशु भिवानी जिल्ने में आते हैं। इस बार भी हमने देखा है कि वहां से पशु आ रहे हैं। बड़े अफसोस की बात है जहां पर कुछ चारा है वहां के गांवों के लोग भी उन पर रहम नहीं करते। उनके पशुओं को, गऊओं को अपने खेतो में घुसने नहीं देते। चाहे राजस्थान से आयी हुई गऊएं हों या हमारे प्रदेश की गऊएं हों, लोग उनको अपने खेतों में घुसने नहीं देते। मैं वित्त मंत्री जी से कहूँगा कि इन गऊओं की रक्षा के लिए कुछ बजट रखा जाना चाहिए चाहे पैसा कहीं से भी लाना पड़े लेकिन इनकी रक्षा की जानी चाहिए। कम से कम एक कानूनगो सर्कल पर एक गऊशाला जरूर बनायी जानी चाहिए। इन तीन चार सालों में चाहे आपने अच्छे काम किए हैं या गलत काम किए हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इसका पुण्य भी मिलेगा कि आपने गऊओं को बचाने की कोशिश की। उपाध्यक्ष महोदय, आजकल आपको रास्ते में कई जगह पर गऊएं मरी हुई मिलेंगी। (विघन)

श्री पूर्ण सिंह डाबरा: धर्मबीर जी, आपके घर में कितने पशु बंधे हुए हैं यह बताएं।

श्री धर्मबीर सिंह: मैं यह बताना चाहता हूँ कि आप पब्लिक रिलेशन के माध्यम से या हैल्थ डिपार्टमैंट के माध्यम से, डॉक्टरों के माध्यम से एक आप प्रचार करवाईए कि गाय का दूध हर बीमारी में फायदा देता है। आप इसका जितना प्रचार करेंगे उतना फायदा रहेगा। कैंसर तक जैसी बीमारी में गऊ मूत्र काम आता है, इससे गऊओं को भी बचाया जा सकता है। 1987 जैसे भयंकर अकाल में भी पशु चारा होता था लेकिन इस बार चारे की बड़ी भारी कमी रही। रोहतक, जीन्द और हिसार के इलाके में कच्ची ईख और गन्ने को काटकर पशुओं को चारे के रूप में खिलाई गई है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि को–ऑपरेटिव सिस्टम के आधार पर जहां गन्ना ज्यादा पैदा होता है वहां कोई ऐसी सोसायटी बनाकर गन्ने का गोला और ईख भेजा जाए?

श्री उपाध्यक्ष: धर्मबीर जी, आप वाईंड आप करें।

श्री धर्मबीरसिंह: तो मैं कह रहा था कि गन्ने और ईख को पशुओं के लिए भेजा जाए तो उन पशुओं को मरने से बचाया जा सकता है 1 मेरे हल्के के कई गांवों में पीने के पानी की बहुत ज्यादा कमी है वहां कई–कई दिन तक पीने का पानी नहीं मिलता है। मैं इन गांवों के नाम गिनाना चाहता हूँ सिवानी के आसपास कालोद, दूधा, बख्तावरपुरा, मिटठी, मतानी यह जो बैल्ट है यहां

नगरों में पानी न होने की वजह से पीने का पानी नहीं मिलता है। इस बात पर आपको झूठ लगता है तो भिवानी के अन्य विधायक व मंत्री महोदय भी बैठे हैं वे खुद जाकर चौक कर लें हमारे यहां के 50–60 गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी का प्रबन्ध करना बहुत जरूरी है। मुख्य मंत्री जी ने खुद कहा है कि हमने भाखड़ा नहर से 10 परसेंट पानी ऐक्सट्रा लिया है लेकिन हमारे वहां तो कोई पानी नहीं आया, कहीं गया होगा, हमें नहीं पता। मेरी आपसे प्रार्थना है कि सूखे के नाम पर तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने एक हजार क्यूसिक पानी डैम से छोड्कर राजस्थान को अलग से दिया। मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सिवानी सिस्टम जो कभी भाखड़ा नहर से जुड़ा था लेकिन बदकिस्मती की बात यह रही कि वह पिछले कई साल से डब्लयू०जे०सी० से जोड़ दिया गया, लेकिन हमारा बना हुआ है आज भी 9० क्यूसिक पानी देते हो तो मेरी मांग है कि 300–350 क्यूसिक रैगुलर भाखड़ा नहर से दिया जाए जो लिंक बना हुआ है ताकि वहां पर जोहड़ों में पानी डाला जा सके और पीने का पानी मिल सके और आदमियों को बचाया जा सके।

श्री उपाध्यक्षः आप समअप करें।

श्री धर्मबीर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं समअप करने जा रहा हूँ। हम चार पांच साल से प्रार्थना करते आ रहे हैं कि लिफ्ट कैनाल के जितने भी पम्प हैं उनकी कैपेसिटी डाउन हो चुकी है, या खराब हो चुके है हमें हर बजट के बाद आश्वासन मिलता है

कि इस साल पम्प हाउस की कैपेसिटी ठीक करेंगे, आने वाले समय में पम्प हाउस को ठीक करके देंगे।

श्री उपाध्यक्षः धर्मबीर जी, आप 15 मिनट बोल चुके हैं आप का समय समाप्त हो गया है आप बैठ जाएं।

श्री धर्मबीर सिंहः उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का विरोध करते हुए अपना स्थान लेता हूँ। धन्यवाद।

चौ० जय प्रकाश (बरवाला): उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने कल अपने बजट का भाषण यहां पर दिया। ये पिछले तीन वर्षो से यहां कई पोजो के कागजात हमें मिले 1 इसी तरह का बजट ये लगातार तीन वर्षो से ला रहे है, यह कोई बजट नहीं है केवल आकड़ों का हेरफेर करके हरियाणा प्रदेश की जनता की आखों में धूल झोकने का काम कर रहे हैं। बजट वस्तुतः क्या है यह मुझे नहीं पता है और प्रो० सम्पत सिंह जी को भी नहीं पता है क्योंकि ये स्टेटिसटिक्स नहीं पढ़ें हैं। अर्थशास्त्र नहीं पड़े हैं लेकिन प्रौब्लम क्या है कि यह सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता को इस दस्तावेज के माध्यम से बरगलाना चाहती है। इस बजट में कृषि को बढ़ावा देने की कोई बात नहीं कही गई। आज जो सबसे बड़ी समस्या है उस पर यानी कृषि पर ही मैं पहले बोलना चाहूँगा। हरियाणा प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है मुख्य मंत्री जी ने बार–बार जगह–जगह पर जाकर कहा कि जो किसान जैसे दो फसल हरियाणा प्रदेश में ज्यादा बीज जाता है। पिछले वर्ष गेहूँ

ज्यादा तादाद में पैदा हुआ था और धान भी ज्यादा तादाद में पैदा हुआ था। उपाध्यक्ष महोदय, यह हालत थी कि स्वयं मुख्य मंत्री जी के इलाके से नरवाना के इलाके के सस्ते धान खरीदकर वही गेहूँ और धान पंजाब में बेच रहे हैं जिससे किसानों को बड़ी भारी मार पड़ी है। गेहूं ज्यादा तादाद में पैदा करने से यह हालत है वित्त मंत्री जी किसानों को अपनी फसल का पूरा पैसा न मिले तो उनके लिए क्या कोई मुआवजा या कोई सबसिडी दी जायेगी इस बारे में बजट में कोई जिक्र नहीं किया गया है। क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, कई बार–बार क्या होता है कि एक खेत गले का है उसमें दूसरी फसल पैदा करेगें तो वह फसल यदि पूरी पैदा नहीं हो तो क्या सरकार कोई सबसिडी का प्रावधान किसानों के लिए करेगी? इस बारे में बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। वित्त मंत्री महोदय ने दूसरी बात सड्कों के बारे में की है। यह बात बिलकुल सही है कि सड्कों की रिपेयर के लिए कहीं न कहीं से पैसा चाहे वह सैन्टर से आया हो, जरूर आया है और इन्होंने सड्कों की रिपेयर भी की है। लेकिन जीन्द के अन्दर एक बाई–पास 6 साल पहले मन्जुर हुआ था। पिछली चौधरी बंसीलाल जी की सरकार और अब की सरकार के समय में शायद दफा 4 और 6 के नोटिस हो चुके हैं इसके बावजूद भी वह जो बाई–पास मंजूर हुआ था मुझे पता लगा है कि रह कर दिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जब किसान सफीदों, गोहाना, रोहतक की तरफ से जीन्द आते थे तो इनको जींद शहर में से गुजरना पड़ता था जब गन्ना ट्रॉली में होता था और लोग ट्रॉली से गन्ना खींचते थे तो एक्सीडैंट हो

जाते थे और हर वर्ष 5–6 एक्सीडैंट जरूर हो जाते और जब कोई मर जाता तो ट्रैक्टर वाले के जिम्मे लग जाता था कि वह ट्रॉली पर चढ़ते समय मरा है। इस समस्या से बचाव के लिए जो बाई–पास बनना था अब उस बाई–पास को रह कर दिया गया है और लोगों को बरगलाने के लिए एक दूसरा रास्ता तय कर दिया गया है लेकिन इससे किसानों को लाभ होने वाला नहीं है इसलिए जो पहले बाई–पास मंजूर हुआ था उस को जरूर बनाना चाहिए ताकि किसानों को लाभ मिल सके। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र की जहां तक बात है। सिरसा के इलाके में शिक्षा का अभाव है यह बात मैं मानता हूँ। वहां अनपढ़ लोगों की तादाद ज्यादा है यह बात मैं मानता हूँ। सदन के नेता ने मार्च, 1991 में जीन्द में एक घोषणा की थी कि क्योंकि मुख्य मंत्री जी ये बार–बार कह देते हैं कि जो मैं घोषणा करता हूँ वह पूरी होंगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि 23 मार्च 1991 को जीन्द के अन्दर इन्होंने अपनी जुबान से यह कहा था कि जब भी मेरी सरकार आयेगी जीन्द में रीजनल सैंटर खोला जायेगा। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि शिक्षा की दृष्टि से हरियाणा प्रदेश में जिस तरह से रीजनल सैंटर भी सिरसा में, यूनिवर्सिटी भी सिरसा में, शुगर मिल भी सिरसा में, सईस मिल भी सिरसा में। जीन्द और कैथल के इलाके को इस बजट में क्या दिया गया है। (विघ्न) उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट को पढ़कर हमें शर्म महसूस होती है कि क्या यह पूरे हरियाणा प्रदेश की सरकार है या किसी एक इलाके की सरकार है।

श्री उपाध्यक्षः आप वाईंड अप करें।

चौ० जय प्रकाशः उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ये कहते है कि जो मैं जुबान करता हूँ वह पूरी करता हूँ तो क्या ये जीन्द में यूनिवर्सिटी बनाने या कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडीकल कालेज या रीजनल सैंटर खोलने का काम करेंगे।

श्री उपाध्यक्षः आप वाईड अप करें।

चौ० जय प्रकाशः उपाध्यक्ष महोदय, अगर दूबल में यूनिवर्सिटी बना दें तो मैं मुख्य मंत्री जी का अहसान मानूंगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री उपाध्यक्षः यदि हाउस की सहमति हो तो हाउस का समय दस मिनट के लिए बढ़ा दिया जाए।

आवाजेंः ठीक है जी।

श्री उपाध्यक्षः ठीक है, हाउस का समय दस मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

वर्ष 2003 – 2004 के लिए बजट पर सामान्य चर्चा
(पुनरारम्भ)

चौ० जय प्रकाश: उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। कल खुद मुख्य मंत्री जी ने और सी०पी०एस० महोदय ने कहा था कि कांग्रेस के राज में इतनी बिजली के दाम बढ़ गये, उनके राज में इतने बिजली के दाम बढ़ गये। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा में जिस दिन से यह सरकार आई है बिजली के दाम एक गुणा से ज्यादा बढ़ गये हैं यानी डबल कर दिए गये हैं। पहले किसानों को 65/– रुपये प्रति हॉर्स पावर मिलती थी और आज 104/– रुपये प्रति हॉर्स पावर दे रहे हैं।

वित्त मंत्री (प्रो० सम्पत सिंह): डिप्टी स्पीकर सर, मांगेराम गुप्ता जी बैठे हैं थोड़ा सा इनको समझा दें हमें तो पता नहीं एक गुणा कितना होता है। अगर दस रुपये दाम हो तो उसका एक गुणा करना हो तो कितना बन जाता है।

17.00 बजे

चौ० जय प्रकाश: मैं एक बात कहना चाहूँगा क्योंकि हमारे इलाके का प्रश्न है, बार बार त्त हाउस मैं जिक्र होता है कि हमने किसानों को इतनी बिजली दी लेकिन किसानों के जो बिजली के बकाया बिल हैं, उनके बारे में मेरा वित्त मंत्री को सुझाव है क्योंकि मुख्य मंत्री साहब कई बार यह कहते हैं कि किसानों को अगर नुकसान हो गया तो मैं अपना सर्वस्व कुर्बान कर दूंगा। हमें कुर्बानी नहीं चाहिए क्योंकि जो बिजली के बकाया बिल हैं उसके बारे में हमारे मुख्य मंत्री साहब भी मानते हैं और

हर कोई मानता है कि किसान बिल नहीं दे सकता चाहे उसकी सारी सम्पत्ति बिक जाए। इसलिए मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि जिस तरीके से केन्द्र की एन०डी०ए० की सरकार ने अभी 20 दिन पहले बहुत से साहूकारों का लोन जो अदा नहीं कर सकते थे, बट्टा खाता कर दिया था। इसी तरीके से यह सरकार भी बकाया बिलों को बट्टे खाते में लगाकर इसे दूसरी जगह से पूर्ति करने का काम करे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वित्त मंत्री इस सदन को बड़ा गुमराह करने की कोशिश करते हैं, क्यों करते हैं पता नहीं, अभी बात आई कि 14 अगस्त को बारिश हुई, हम मानते हैं कि 14 अगस्त को बारिश हुई लेकिन कहां हुई प्रो० सम्मत सिंह जी के इलाके में भट्टू में, बरवाला में, उचाना में अहीरवाल में नहीं हुई। जहां बारिश नहीं हुई वहां ये कैसे कह सकते हैं कि वहां बहुत अन्न पैदा हो गया। एक तरफ आप कहते हैं कि किसानों की सरकार है और दूसरी तरफ इस सरकार ने किसानों को इतनी मार–मारी है जितनी किसी सरकार ने नहीं मारी। जितने किसान इस सरकार के समय में गोलियों से मारे गए उतने किसी सरकार में नहीं मारे गए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री से निवेदन करुंगा कि ये जो पुलिंदा है कि कर मुक्त बजट, कर मुक्त बजट इसका पीछा छोड़ दो। कर की जहां तक बात है इन्होंने भट्टी वालों पर टैक्स लगाया, कुर्ता धोने वालों पर टैक्स लगा दिया, सांस लेने पर, हंसने पर यहां तक कि दाड़ी कटवाने पर भी टैक्स लगा दिया। इसलिए यह जो कागजों का पुलिंदा है मैं इसका

विरोध करता हूँ। मैं इस सदन के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूँ कि इस सरकार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। हर वर्ग, कर्मचारी, किसान, मजदूर, व्यापारी सब का इस सरकार से विश्वास उठ चुका है। इसलिए इन्होंने जो असत्य का पुलिंदा रखा है मैं इसका विरोध करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता है।

श्री कर्ण सिंह दलाल (पलवल): उपाध्यक्ष महोदय, पिछले साल सम्पत सिंह जी ने जब बजट प्रस्तुत किया था तो मैंने उम्मीद की थी और सदन में आपके माध्यम से इनसे अनुरोध भी किया था कि आज ग्लोबलाईजेशन का जमाना है, उपाध्यक्ष महोदय, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, बड़े– बड़े इकोनोमिस्ट, एजुकेशनिस्ट हैं और इतने अच्छे वित्त के मामले में हमारे पास एक्सपर्ट हैं उनको बुलाकर उनसे राय लेनी चाहिए थी कि हरियाणा प्रदेश को किस तरीके से अच्छा बजट प्रस्तुत किया जा सकता है लेकिन मुझे इस बात का खेद है कि सम्पत सिंह जी ने पिछले साल भी मेरी राय पर गौर नहीं किया था। पता नहीं इनकी सरकार रहे या न रहे, भगवान करे इनकी सरकार रहे लेकिन अगले साल ये इस बारे में विचार करें। उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने इस बजट को देखा, आज अखबारों ने इस पर अपनी राय प्रस्तुत की। हरियाणा के लोगों को इस बारे में मालूम हुआ कि इस बजट के माध्यम से हरियाणा का भविष्य उज्ज्वल नजर नहीं आ रहा। वही धिसी–पिटी बातें हैं अगर सम्पत सिंह जी इस पर विचार

करते तो उन्हें इस बात पर भयभीत होना चाहिए जैसा विपक्ष के माननीय साथियों ने भी दोहराया था कि ये सरकार सारा पैसा कर्ज और कर्ज की अदायगी में लगाती रहेगी तो प्रदेश के लोगों का भला कहां से होगा। मात्र कर लगाने या न लगाने से इस प्रदेश का भला नहीं होगा 1 प्रदेश का भला अगर यह सरकार चाहती है तो इन का यह कर्त्तव्य है, यह फर्ज है कि प्रदेश के लोगों को इस लायक बनाए कि वे कमाई करें। इस प्रदेश का नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इस प्रदेश का किसान अपने खेत में, जहां वह अपना खून पसीना बहाता है, कमाई करे। आज बिजली के बिल देने का मसला, टैक्स न देने का मसला दूसरे टैक्स न देने का मसला है उस की वजह यह है कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय घट रही है या वहीं की वहीं रुकी हुई है। हमारे छोटे–छोटे पड़ोसी राज्यों जैसे पंजाब में प्रति व्यक्ति आय को देखें, वहां के लोगों का रहन–सहन देखें तो वह अच्छा है। हरियाणा दिल्ली के साथ चारों तरफ लगता है आज कर्ज में डूबा हुआ है। आज नौजवान, किसान मायूस हैं। खुश कोई है तो वह है हरियाणा के मुख्य मंत्री, उनका परिवार, सरकार के मंत्री और सत्ता पक्ष के विधायक या हरियाणा के वे अधिकारी जो पद के लालची हैं, अपने ईमान को बेच रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहूँगा। (विघन)

श्री उपाध्यक्षः दलाल साहब, आप बजट पर बोलें। दूसरी बातें न करें।

श्री कर्ण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर ही आ रहा हूँ। जब पिछले दिनों हमारी सरकार थी तब हमने हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम बनाई थी, एक कंपनी बनाई थी और उसके एक्ट के अनुसार संपत सिंह जी एच०वी०पी०एन०एल० की परचेजिंग में सरकार का कोई दखल नहीं होता था। चौधरी बंसी लाल जी भी मुख्य मंत्री रहे हैं इनके समय में भी कभी ऐसा नहीं हुआ और चौधरी भजन लाल जी भी मुख्य मंत्री रहे हैं इनके' समय में भी बिजली बोर्ड की परचेजिग में सरकार ने कोई दखल नहीं की। अब एच०वी०पी०एन०एल० एक अलग कंपनी बन चुकी है उसकी परचेजिंग करने का मुख्य मंत्री जी को कोई अधिकार नहीं है। अभी पीछे हमने अखबार में पड़ा था कि हरियाणा की एक वरिष्ठ आई०ए०एस० अधिकारी जिसको बहुत ईमानदार माना जाता है उसको पद से इसलिए हटा दिया गया क्योंकि वे एच०वी०पी०एन०एल० को ईमानदारी से चलाना चाहती थी और मुख्य मंत्री जी के चहेतों को ऑर्डर नहीं दिए। आर्डर न देने के कारण ही उस महिला अधिकारी को मीटिंग में बेइज्जत किया गया और अपमानजनक तरीके से उसे पद से हटा दिया गया तथा मुख्य मंत्री जी ने मन–माने तरीके से उन कंपनीयों से परचेजिंग की जिनकी क्यालिटी अच्छी नहीं

श्री उपाध्यक्षः दलाल सहाब, यदि आप बजट तक सीमित रहें तो बहुत अच्छा होगा। दलाल साहब आपकी सरकार के समय की बात है आप मंत्री थे और चौधरी बंसी लाल जी मुख्य मंत्री थे।

उस समय गुड़गांव में बिजली की सारी परचेजिंग एक आदमी से होती थी। शायद आपको पता भी हो यदि न पता हो तो आप पता कर लें। केवल एक आदमी से बिजली की सारी परचेजिंग होती थी, चाहे वह प्राइवेट खरीद हो या सरकारी।

श्री कर्ण सिंह दलालः उपाध्यक्ष महोदय, चाहे मैं गलती करूं या कोई और करे? मेरा आपसे निवेदन यह है कि हम सब यहां हरियाणा के लोगों की भलाई के लिए आते हैं यदि कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए चाहे किसी ने किसी भी सरकार के समय में गलत काम किया हो। मैं यह नहीं कहता कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है इसमें पता नहीं इन्होंने अलग– अलग हैड में कितने हजार करोड़ रुपये के लोन लेने के प्रावधान किए हैं। (इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए) अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्षः कर्ण सिंह दलाल जी, बजट के हटकर जो कुछ भी बोल रहे हैं वे शब्द हाउस की कार्यवाही से निकाल दिए जायें। दलाल साहब, आप बजट पर बोलें।

श्री कर्ण सिंह दलालः अध्यक्ष महोदय, मैं बजट पर ही आ रहा हूँ। जहां तक वैट लागू करने की बात है मैं सम्पत सिंह जी को कहना चाहूँगा कि ये यह न समझें कि मैं विरोधी पक्ष के नाते कह रहा हूँ बल्कि मैं यह अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ

हिन्दुस्तान के बड़े–बड़े अखबारों में भी लिखा गया है कि डब्ल्यू०ओ० और एम०एन०सीज० के दबाव में आकर वैट लागू किया जा रहा है। केन्द्र सरकार और बड़े–बड़े घरानों के दबाव में आकर स्टेट्स में वैट लागू किया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

प्रो० सम्पत सिंहः अध्यक्ष महोदय, दलाल साहब ने कहा कि केन्द्र सरकार के दबाव में आकर वैट लागू किया जा रहा है। मैं इनको बताना चाहूँगा कि इसमें केन्द्र सरकार की कोई बात नहीं है। वैट के बारे में एक एमपॉवर्ड कमेटी सभी स्टेट्स के वित्त मन्त्रियों की बनी हुई है, इसमें केन्द्र की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं है। बंगाल के वित्त मंत्री श्री दीपदास गुप्ता उस कमेटी के कनवीनर हैं जो कि इस देश में सबसे ज्यादा अनुभवी वित्त मंत्री हैं, सबसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं और इकोनोमिस्ट भी हैं। इस कमेटी में सभी पार्टीज के कांग्रेस पार्टी के, सी०पी०एम० के, बी०जे०पी० के, इनेलो के यानि कि सभी पार्टीज के वित्त मंत्री हिस्सा लेते हैं, जिस पार्टी का जहां राज है रिप्रैजैंट करते हैं, उनके रिप्रजैंटेटिव जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि इन सभी ने आपस में बैठकर फैसला लिया है, न की केन्द्र सरकार के दबाव में आकर। गुप्ता जी, आपको तो इस बारे में सब मालूम है कि वैट आम राय से लागू हो रहा है, आप ही इन्हें समझायें।

Mr. Speaker : Now, the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 12 th March, 2003.

*** 17.10 hrs.**

(The sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Wednesday, the 12th March, 2003.)